भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

मई 2022

खंड 76 अंक 5

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देब प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितिकंठ पट्टनायक
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
तुषार बरन दास
पुलस्त्य बंद्योपाध्याय

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2022

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से **https://bulletin.rbi.org.in** पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 7

भाषण

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और आईबीसी

एम. राजेश्वर राव 9

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 17

भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह 2019-20 53

भारत का संवृद्धिवर्धक बाह्य ऋण 73

धारणीय कृषि के लिए सिंचाई प्रबंधन 87

वर्तमान सांख्यिकी **109**

हाल के प्रकाशन **162**

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

8 अप्रैल 2022 के अपने वक्तव्य में मैंने यूरोप में युद्ध के कारण हुए विवर्तनिक परिवर्तनों का उल्लेख किया था, जिसने वैश्विक संवृद्धि और मौद्रिक नीति के परिचालन के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न की थीं। जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है और प्रतिबंध और जवाबी कार्रवाई तेज हो रही है, कमोडिटी और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, कमी, आपूर्ति अव्यवस्था और, सबसे चेतावनीपूर्वक, सतत और बढ़ रहे मुद्रास्फीति के दबाव हर गुजरते दिन के साथ और अधिक तीव्र होते जा रहे हैं। विकासशील देशों में पूंजी बहिर्वाह और मुद्रा मूल्यह्रास के बीच ऋण संकट बढ़ रहा है। हाल ही के जीडीपी आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक आर्थिक बहाली गति खो रही है।

इन चुनौतियों के बीच, जिन्हें मैंने अपने अप्रैल के वक्तव्य में विशालकाय कहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था ने आघात-सहनीयता दिखाई है, जो इसके अंतर्निहित मूल सिद्धांतों की अंतर्निहित मजबूती पर आधारित है और एक विवेकपूर्ण और अनुकूल नीति मिश्रण द्वारा समर्थित है। मौद्रिक नीति के परिचालन में, हमने किसी भी नियम पुस्तिका से बंधे न रहने और पारंपरिक और अपारंपरिक उपकरणों की पूरी शृंखला को निर्णायक रूप से नियोजित करने की हमारी तैयारी के अपने संकल्प को साबित किया है। निभावकारी रहते हुए, मौद्रिक नीति, संवृद्धि का समर्थन करने और भू-राजनीतिक संकट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बढ़ावा देना जारी रखती है। परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक आघात का सामना करने में कामयाब रही है। आश्वस्त रूप से, हम कमोडिटी की कीमतों के समकालिक आघातों, आपूर्ति व्यवधानों और युद्ध से उत्पन्न उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद, समष्टि-वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। मुद्रास्फीति के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को ऊपर की ओर शिफ्ट करने वाले उच्च मुद्रास्फीति दबावों का सामना करते हुए, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप बनी रहे, निभाव को वापस लेने के अपने अपेक्षा की घोषणा की है। जैसा कि मैंने अप्रैल के मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा था, हमारे कार्यों को तेजी से विकसित हो रही स्थिति के अनुरूप बनाया जाएगा ताकि संवृद्धि के आवेगों को संरक्षित और मजबूत किया जा सके। हमारी यात्रा प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस के शब्दों में सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होती है: “आपको जितनी भी परीक्षाएँ देनी पड़ेगी, वे आपको आपकी ताकत से परिचित कराएंगे। दृढ़ रहो... और एक दिन तुम कुछ ऐसा बना लोगे जो सदा बना रहे।”[1]

जैसे-जैसे हम इस कठिन दौर से गुजरते हैं, नई वास्तविकताओं के प्रति सुग्राही होने और उन्हें अपने विचारों में शामिल करना आवश्यक हो जाता है। अप्रैल 2022 के अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है: “युद्ध के आर्थिक प्रभाव दूर-दूर तक फैल रहे हैं - जैसे भूकंपीय लहरें जो भूकंप के केंद्र से निकलती हैं - मुख्य रूप से कमोडिटी बाजारों, व्यापार और वित्तीय संबंधों के माध्यम से।”[2] तथापि, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हमारी मजबूती और हमारे बफर के बावजूद, भारत वैश्विक स्तर पर जुड़ी इस दुनिया से अलग नहीं है। अप्रैल के नीतिगत वक्तव्य के अनुमान के अनुरूप, मार्च 2022 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। अप्रैल के लिए प्रिंट में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। संपार्श्विक जोखिम इस बात का है कि यदि मुद्रास्फीति बहुत लंबे समय तक इन स्तरों पर बनी रहती है, तो यह मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को कम कर सकती है, जो परिणामस्वरूप, स्वयं -पूर्ति तथा संवृद्धि और वित्तीय स्थिरता के लिए अहितकर हो सकती है। अतः, हमें अर्थव्यवस्था की आघात-सहनीयता को बढ़ाते हुए समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सभी नीतिगत उपायों का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं दोहराता हूं कि स्थिति गतिशील है और तेजी से बदल रही है और हमें अपने कार्य उसी के अनुरूप करने होंगे।

मौद्रिक नीति समिति के निर्णय और विचार-विमर्श

इस पृष्ठभूमि पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2 और 4 मई 2022 को एक ऑफ-साइकिल बैठक आयोजित करने का

* गवर्नर का वक्तव्य, 4 मई 2022

1 स्रोत: एपिक्टेटस, यूनानी दार्शनिक 55-135 ईस्वी [द आर्ट ऑफ लिविंग]

2 विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2022, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।

गवर्नर का वक्तव्य

निर्णय लिया, ताकि मुद्रास्फीति-संवृद्धि की बढ़ती गतिशीलता और 6-8 अप्रैल 2022 की एमपीसी बैठक के बाद की गतिविधियों के प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। समष्टि आर्थिक स्थिति और संभावना के मूल्यांकन के आधार पर, एमपीसी ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से नीतिगत रेपो दर को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने हेतु मतदान किया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर को 4.15 प्रतिशत; तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत हो गया है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निभावकारी बने रहने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति, संवृद्धि का समर्थन करते हुए आगे लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

अब मैं एमपीसी के निर्णय और रुख की पृष्ठभूमि का तर्क बताना चाहूंगा। विश्व स्तर पर, मुद्रास्फीति चेतावनीपूर्ण रूप से बढ़ रही है और तेजी से फैल रही है। भू-राजनीतिक तनाव प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पिछले 3 से 4 दशकों में मुद्रास्फीति को अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ा रहे हैं, जबकि बाहरी मांग को कम कर रहे हैं। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चल रही हैं और अस्थिर बनी हुई हैं। वैश्विक खाद्य कीमतों ने मार्च में एक नया रिकॉर्ड छुआ और तब से यह और भी बढ़ीं हैं। खाद्य तेल जैसे भारत के लिए प्रासंगिक मुद्रास्फीति संवेदी वस्तुएं, यूरोप में युद्ध और प्रमुख उत्पादकों द्वारा निर्यात प्रतिबंध के कारण कमी का सामना कर रहे हैं। उर्वरक की कीमतों में उछाल और अन्य निविष्टि लागतों का भारत में खाद्य कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण में अब उल्लेखनीय रूप से गति प्राप्त होने की उम्मीद है – दोनों, दर में बढ़ोत्तरी और मात्रात्मक सहजता के खुलने के साथ-साथ मात्रात्मक सख्ती को रोल आउट करने के संदर्भ में। इन घटनाक्रमों का भारत सहित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इस बीच, कोविड-19 संक्रमण और प्रमुख वैश्विक उत्पादन केंद्रों में लॉकडाउन से संवृद्धि के कम होते हुए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को बढ़ने की संभावना है। वास्तव में, इस कैलेंडर वर्ष के लिए वैश्विक संवृद्धि अनुमानों को 100 आधार अंकों तक अधोगामी संशोधित किया गया है। ये गतिशीलता अप्रैल 2022 के एमपीसी के संकल्प में निर्धारित भारत के मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम उत्पन्न करती है।

इसके अलावा, एमपीसी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि घरेलू आर्थिक गतिविधि मोटे तौर पर अप्रैल में प्रत्याशित तर्ज पर आगे बढ़ रही है। रुकी हुई मांग से संपर्क-गहन सेवाओं को लाभ हो रहा है और निवेश गतिविधि में कर्षण बढ़ने के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही, एमपीसी ने निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति संभावना को दृढ़ और कैलिब्रेटेड कदमों के माध्यम से उचित और समय पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति पक्ष के दूसरे दौर के झटकों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सीमित रहें और दीर्घावधि की मुद्रास्फीति की प्रत्याशा मजबूती से स्थिर रहे। एमपीसी के विचार में, इस समय मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया, वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के बीच समष्टि-वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगी। तदनुसार, एमपीसी ने आज अपनी बैठक में नीतिगत रेपो दर में 40 आधार अंकों की वृद्धि करने का निर्णय लिया; इसने निभाव के वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निभावकारी बने रहने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे संवृद्धि को समर्थन देते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए संभावना

संवृद्धि

इस अत्यधिक तनाव वाले वैश्विक वातावरण में, घरेलू समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का जायजा लेना उपयोगी है। घरेलू आर्थिक गतिविधियों में वापसी, जो ओमिक्रोन लहर की कमी के साथ हुई थी, तेजी से वैविध्यपूर्ण हो रही है। संपर्क-गहन सेवाओं और बढ़ते विवेकाधीन खर्च के कारण निजी खपत फिर से बढ़ रही है। 2022 में लगातार चौथे वर्ष सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्वानुमान ने कृषि संभावनाओं के लिए शुभ संकेत दिया है और इसे ग्रामीण खपत का समर्थन करना चाहिए। निवेश चक्र में एक प्रारंभिक बहाली होने के भी संकेत हैं। यह, पूंजीगत वस्तुओं के आयात और उत्पादन; अनुकूल वित्तीय स्थितियों द्वारा समर्थित क्षमता उपयोग में वृद्धि; और मजबूत कॉर्पोरेट तुलन पत्र जैसे उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित होता है। निर्यात संवृद्धि में बढ़ोत्तरी बनी हुई है जबकि गैर-तेल गैर-स्वर्ण के आयात

गवर्नर का वक्तव्य

में लगातार उच्च वृद्धि घरेलू मांग में एक टिकाऊ बहाली को दर्शाती है।

भले ही घरेलू आर्थिक गतिविधि के चालक मजबूत हो रहे हैं, वे लंबे और तीव्र भू-राजनीतिक तनावों के रूप में वैश्विक स्पिलओवर; बढ़ी हुई कमोडिटी की कीमतें; कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन या प्रतिबंध; घटती बाह्य मांग; और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के कारण वैश्विक वित्तीय स्थितियों की सख्ती के कारण विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ये जोखिम अप्रैल 2022 के वक्तव्य में प्रत्याशित तर्ज पर विकसित हो रहे हैं और अभी भी बने हुए प्रतीत होते हैं।

मुद्रास्फीति

मार्च 2022 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में 7 प्रतिशत की तेज वृद्धि, विशेष रूप से, अभूतपूर्व उच्च वैश्विक खाद्य कीमतों से होने वाले प्रतिकूल स्पिलओवर के प्रभाव के कारण खाद्य मुद्रास्फीति द्वारा प्रेरित थी। बारह में से नौ खाद्य उप-समूहों ने मार्च में मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की। अप्रैल के लिए उच्च आवृत्ति मूल्य संकेतक खाद्य कीमतों के दबाव में बने रहने का संकेत दे रहे हैं। साथ ही, पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू पंप कीमतों में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव, जो मार्च के दूसरे पखवाड़े से आरंभ हुआ है, मूल मुद्रास्फीति के प्रिंटों में परिलक्षित हो रहा है और इसके अप्रैल में और बढ़ने की उम्मीद है।

आगे, खाद्य मुद्रास्फीति दबाव जारी रहने की संभावना है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व बैंक के खाद्य मूल्य सूचकांक ने मार्च में ऐतिहासिक ऊंचाई को छु ली और अभी भी उच्च बने हुए है। घरेलू आपूर्ति के सहज बने रहने के बावजूद वैश्विक स्तर पर गेहूं की कमी के कारण स्पीलओवर से घरेलू कीमतों पर असर पड़ रहा है। प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा निर्यात प्रतिबंधों और युद्ध के कारण सूरजमुखी तेल उत्पादन में कमी के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में और तेजी आ सकती है। खाद्य की लागत में बढ़ोत्तरी, पोल्ट्री, दूध और डेयरी उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं और इससे घरेलू पंप की कीमतों में तेजी आ रही है।। प्रसंस्कृत खाद्य, गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के एक और दौर में परिवर्तित होने वाले अभूतपूर्व निविष्टि लागत दबाव के जोखिम अब पहले की तुलना में अधिक मजबूत हैं। यदि मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो यह कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण शक्ति को मजबूत कर सकता है । संक्षेप में, प्रतिकूल वैश्विक मूल्य आघातों की निरंतरता के साथ-साथ मुद्रास्फीति संबंधी आवेगों का सुदृढ़ीकरण अप्रैल के एमपीसी के संकल्प में प्रस्तुत मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम उत्पन्न करता है।

इन परिस्थितियों में, मौद्रिक नीति को निभाव को वापस लेने पर ध्यान देना आवश्यक है। यह विदित है कि महामारी के जवाब में, मौद्रिक नीति ने 27 मार्च 2020 को नीतिगत रेपो दर में 75 आधार अंकों की बड़ी कटौती के साथ, एक अति-समायोज्य मोड में गियर्स को शिफ्ट किया था, इसके बाद 22 मई 2020 को 40 आधार अंकों की एक और कटौती की गई थी। तदनुसार, एमपीसी के आज के नीतिगत रेपो दर को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने के निर्णय को, अप्रैल 2022 में निर्धारित निभाव को वापस लेने के रुख की घोषणा को ध्यान में रखते हुए 22 मई 2020 की दर कार्रवाई के उलटाव के रूप में देखा जा सकता है।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

अप्रैल में, मौद्रिक नीति रुख में बदलाव के साथ संरेखण में कई चलनिधि प्रबंधन उपाय किए गए, जिसमें नीतिगत रेपो दर के आसपास एक सममित एलएएफ कॉरिडोर की बहाली और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरूआत शामिल है। ये उपाय संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए दी गई प्रधानता का संचालन करते हैं। मौद्रिक नीति को एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें मुद्रास्फीति की दृढ़ता टूट जाए और मुद्रास्फीति की उम्मीदें फिर से टिकी हों। जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हो रही है और पूर्व-महामारी के स्तर से आगे निकल रही है, प्राथमिकताओं के इस पुन: क्रम के लिए हेडरूम, महामारी के घटने और संवृद्धि के स्थिर व्यापक आधार के साथ उपलब्ध होता जा रहा है।

शेष अर्थव्यवस्था में चलनिधि स्थितियों का पूर्ण और कुशल संचरण सुनिश्चित करने के लिए उनको नीतिगत कार्रवाई और रुख के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है। अप्रैल की नीति की घोषणा के बाद से, बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि सहज बनी हुई है। बैंकिंग प्रणाली में औसत अधिशेष चलनिधि- एसडीएफ और परिवर्तनीय दर परिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों के माध्यम से कुल अवशोषण में परिलक्षित- 8-29 अप्रैल 2022 के दौरान ₹7.5 लाख करोड़ की राशि थी। एसडीएफ के तहत रखी गई दैनिक अधिशेष निधि के रूप में बड़ी चलनिधि (8-29 अप्रैल 2022 के दौरान ₹2.0 लाख करोड़ का औसत) के परिणामस्वरूप भारित औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - एसडीएफ दर से नीचे है। बैंकों की अनुकूल प्रतिक्रिया जो 14-दिवसीय और 28-दिवसीय वीआरआरआर नीलामियों के बोली-कवर अनुपातों के साथ-साथ 26 अप्रैल को आयोजित यूएसडी/आईएनआर की विक्रय-क्रय स्वैप नीलामी में विदित होती है, से यह भी पता चलता है कि प्रणाली -स्तरीय चलनिधि पर्याप्त बनी हुई है। अतः, निभाव को वापस लेने के रुख को ध्यान में रखते हुए और एकाधिक वर्षीय समय- सीमा में चलनिधि की क्रमिक निकासी की पूर्व घोषणा के अनुरूप, यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंक बढ़ाकर निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.5 प्रतिशत कर दिया जाए, यह बदलाव 21 मई 2022 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा। सीआरआर में इस बढ़ोत्तरी के माध्यम से चलनिधि की निकासी का क्रम ₹87,000 करोड़ होगा।

निरंतर उच्च मुद्रास्फीति अनिवार्य रूप से बचत, निवेश, प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादन वृद्धि को नुकसान पहुंचाती है। इसने आबादी के गरीब तबके पर उनकी क्रय शक्ति को कम करके प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसलिए, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि आज की हमारी मौद्रिक नीति कार्रवाई- जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करना है - अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को मजबूत और समेकित करेगी। हम उत्पादन पर उच्च ब्याज दरों के संभावित निकट-अवधि के प्रभाव के प्रति सचेत हैं। इसलिए, हमारे कार्यों को अंशशोधित किया जाएगा। मैं इस बात पर और जोर देना चाहूंगा कि मौद्रिक नीति निभावकारी बनी रहे और हमारी पद्धति यह होगी कि मुद्रास्फीति-संवृद्धि की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए महामारी से संबंधित असाधारण निभाव के सावधानीपूर्वक और कैलिब्रेटेड रूप से वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करना। यह दोहराया जाता है कि आरबीआई ऋण उठाव और विकास के समर्थन में अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करेगा।

बाह्य क्षेत्र

विकट वैश्विक बाधाओं के बीच भारत का बाह्य क्षेत्र आघात सहनीय बना हुआ है। अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का माल निर्यात अप्रैल 2022 में मजबूत बना रहा और मार्च 2022 में सेवाओं का निर्यात एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। भू-राजनीतिक स्थितियों और हाल के व्यापार करारों के कारण संभावित बाजार के अवसर खुल गए हैं। प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों द्वारा मजबूत राजस्व संचालन भी 2022-23 में समग्र बाह्य क्षेत्र की संभावनाओं के लिए शुभ संकेत है। कॉमोडिटी की उच्च कीमतों के कारण व्यापार की शर्तों के बिगड़ने से 2022-23 में चालू खाते के घाटे पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसके सहज रूप से वित्तपोषित होने की उम्मीद है। हाल ही में कुछ मंदी के बावजूद, निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह मजबूत बना हुआ है। बाह्य वाणिज्यिक उधार जैसे दीर्घकालिक प्रवाह भी स्थिर बने रहे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार निवल वायदा आस्तियों के साथ काफी अधिक है जो एक मजबूत बैक-अप प्रदान करती है। जीडीपी अनुपात की तुलना में विदेशी कर्ज 20 प्रतिशत पर न्यून बना हुआ है।

समापन टिप्पणी

पिछले दो वर्ष, पहले महामारी और अब युद्ध से उत्पन्न हतोत्साहित करने वाले चुनौतियों के खिलाफ हमारी दृढ़ लड़ाई की गाथा है। हमने अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को आघातों के बवंडर से बचाने के लिए इन चुनौतियों का सामना किया है। अब हम एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। हम, आरबीआई में, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और संवृद्धि को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को सतत और समावेशी संवृद्धि के पथ पर दृढ़ बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति

को अवश्य नियंत्रित किया जाना चाहिए। समग्र समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ सतत संवृद्धि में सबसे बड़ा योगदान मूल्य स्थिरता बनाए रखने के हमारे प्रयास से होगा।

चूंकि कई तूफान एक साथ आए हैं, आज के हमारे कार्य जहाज को स्थिर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। हम स्थिति और संभावनाओं का सतत पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं के प्रति सतर्क रहते हैं। हम अपने पद्धति में सक्रिय और लचीले रहेंगे। चुनौतियों के बावजूद, यह जानकर सुकून मिलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है और हम वैश्विक गतिविधियों से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। आईएमएफ ने भी हाल ही में यह भी कहा है कि भारत में महामारी के समष्टि आर्थिक प्रबंधन के परिणामस्वरूप एक मजबूत सुधार हुआ है और देश मौजूदा बाहरी आघातों का सामना करने के लिए एक अच्छी स्थिति में है।[3] मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगा, जो मैंने पहले कहा है - मैं एक शाश्वत आशावादी हूं। आरबीआई में मेरे सहयोगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो रास्ता चुना है वह हमें एक बेहतर और उज्जवल कल की ओर ले जाएगा। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है: “मैंने अत्यंत निराशाओं, घोर अंधकार का सामना किया है, ... लेकिन मैं यह कहने में समर्थ हूं कि मेरे विश्वास..... ने आखिरकार इन सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली है।”[4]

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ्य रहें। नमस्कार।

[3] *https://www.thehindu.com/news/national/india-in-much-better-place-to-face-ukrainian-crisis-imf-official/article65340653.ece*

[4] यंग इंडिया, 20-12-1928, p. 420

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प मई 2-4, 2022

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 2 और 4 मई 2022*

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (4 मई 2022) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया जाए।

परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत हो गई है।

- एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निभावकारी बने रहने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

ये निर्णय, संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय में अंतर्निहित मुख्य विचार नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त की गई हैं

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. अप्रैल 2022 में एमपीसी की बैठक के बाद से, भू-राजनीतिक तनावों और प्रतिबंधों से प्रेरित व्यवधान, कमियाँ और कीमतों में बढ़ोत्तरी स्थिर बनी हुई हैं और अधोगामी जोखिम बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने तीन महीने से भी कम अंतराल में 2022 के लिए वैश्विक उत्पादन संवृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 0.8 प्रतिशत अंक घटाकर 3.6 प्रतिशत कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने 2022 के लिए विश्व व्यापार संवृद्धि के अनुमान को 1.7 प्रतिशत अंक घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

3. मार्च-अप्रैल में कोविड-19 की तीसरी लहर के कम होने और प्रतिबंधों में ढील के साथ घरेलू आर्थिक गतिविधि स्थिर हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि शहरी मांग ने विस्तार बनाए रखा है लेकिन ग्रामीण मांग में कुछ कमजोरी बनी हुई है। निवेश गतिविधि जोर पकड़ती दिख रही है। वस्तु निर्यात ने अप्रैल में लगातार चौदहवें महीने दोहरे अंकों में विस्तार दर्ज किया। घरेलू मांग में सुधार के कारण गैर-तेल गैर-स्वर्ण के आयात में भी मजबूती वृद्धि हुई।

4. समग्र प्रणाली चलनिधि में वृहद अधिशेष बनी रही। 22 अप्रैल 2022 तक बैंक ऋण में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2022-23 में (22 अप्रैल तक) 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 600.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

5. मार्च 2022 में, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गई, जो बड़े पैमाने पर भू-राजनीतिक स्पिलओवर के प्रभाव को दर्शाती है। खाद्य मुद्रास्फीति 154 आधार अंक बढ़कर 7.5 प्रतिशत और मूल मुद्रास्फीति 54 आधार अंक बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गई। मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि ऐसे माहौल में हो रही है जिसमें दुनिया भर में मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ रहे हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि 2022 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 2.6 प्रतिशत अंक बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो जाएगी और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2.8 प्रतिशत अंक बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो जाएगी।

संभावना

6. अत्यधिक अनिश्चितता मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को घेर हुए है, जो उभरती भू-राजनीतिक स्थिति पर काफी निर्भर है। वैश्विक कमोडिटी मूल्य गतिशीलता भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का कारण बनी हुई है, जिसमें मुद्रास्फीति संवेदनशील वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं जो उत्पादन हानि और प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा

* 4 मई 2022 को प्रकाशित।

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23

निर्यात प्रतिबंधों के कारण हो रही वैश्विक कमी से प्रभावित हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें उच्च लेकिन अस्थिर बनी हुई हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभावों के माध्यम से मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के लिए काफी ऊर्ध्वगामी जोखिम पैदा कर रही हैं। आने वाले महीनों में मूल मुद्रास्फीति के उच्च बने रहने की संभावना है, जो उच्च घरेलू पंपों कीमतों और आवश्यक दवाओं की कीमतों के दबाव को दर्शाती है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 संक्रमण के फिर से बढ़ने के कारण पुनः लगने वाले लॉकडाउन और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान लंबे समय तक उच्च लॉजीस्टिक लागत को बनाए रख सकते हैं। ये सभी कारक एमपीसी के अप्रैल के वक्तव्य में निर्धारित मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्ध्वगामी जोखिम पैदा करते हैं।

7. जहां तक घरेलू आर्थिक गतिविधि के संभावनाओं का संबंध है, सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान खरीफ उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ा देता है। तीसरी लहर की कमी और बढ़ते टीकाकरण कवरेज के कारण संपर्क-गहन सेवाओं में सुधार जारी रहने की उम्मीद है। निवेश गतिविधि को मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय, क्षमता उपयोग में सुधार, सुदृढ़ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और अनुकूल वित्तीय स्थितियों से संवृद्धि मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण से अस्थिर प्रभाव-विस्तार के साथ बिगड़ते बाह्य वातावरण, वस्तुओं की उच्च कीमतें और लगातार आपूर्ति बाधाओं से विकट बाधाएँ पैदा होती हैं। सभी पहलुओं पर विचार करने पर, भारतीय अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक परिस्थितियों में गिरावट का सामना करने में सक्षम प्रतीत होती है, लेकिन जोखिमों संतुलन की निरंतर निगरानी करना विवेकपूर्ण है।

8. इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी का विचार है कि जबकि आर्थिक गतिविधि अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों और बफर के बल पर आघात सहनीयता के साथ दुनिया का सामना करने वाली ताकतों के भंवर को मार्ग निर्देशन कर रही है, निकट अवधि के मुद्रास्फीति संभावनाओं के जोखिम तेजी से मूर्त हो रहे हैं, जैसा कि मार्च के मुद्रास्फीति प्रिंट और उसके बाद की गतिविधियों में परिलक्षित होता है। इस परिवेश में, एमपीसी को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति उच्च बनी रहेगी, जिससे मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने और दूसरे दौर के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ और कैलिब्रेटेड कदमों की आवश्यकता होगी। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निभावकारी बने रहने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

9. एमपीसी के सभी सदस्य – डॉ. शंशाक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने नीतिगत रेपो दर को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.4 प्रतिशत करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।

10. सभी सदस्यों अर्थात् डॉ. शशांक भिड़े, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने सर्वसम्मति से निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निभावकारी बने रहने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

11. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 18 मई 2022 को प्रकाशित किया जाएगा।

12. एमपीसी की अगली बैठक 6-8 जून 2022 के दौरान निर्धारित है।

भाषण

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और आईबीसी

एम. राजेश्वर राव

*दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और आईबीसी**

एम. राजेश्वर राव

कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह, श्री राजेश वर्मा, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्री रवि मित्तल, अध्यक्ष, आईबीबीआई, श्री सुधाकर शुक्ला, पूर्णकालिक सदस्य, आईबीबीआई, विशिष्ट अतिथिगण, पैनल सदस्यों और शोधकर्ताओं, देवियो और सज्जनों,

सबसे पहले, मैं इस सम्मेलन में मुख्य भाषण देने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मेलन काफी उपयुक्त रूप से एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक - तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर केंद्रित है। यदि मैं यह कहूं कि भारत पिछले कुछ वर्षों में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में विनियामक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा है, तो यह कोई न्यूनोक्ति नहीं होगी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का भारत में लेनदार-देनदार संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। संहिता के तहत कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी रेसोल्यूशन प्रोसैस (सीआईआरपी) से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित और कार्यान्वित किए पांच वर्षों से भी अधिक समय हो गया है, और यह अब तक हुई प्रगति और भविष्य के बारे में अपेक्षाओं का जायजा लेने के लिए एक अवसर प्रदान करता है।

ऋण शोधन अक्षमता और उसका समाधान

किसी भी ऋणदाता के लिए, क्रेडिट जोखिम, यानी अनुबंधित राशि का समय पर पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं होने की संभावना या प्रतिपक्ष द्वारा क्रेडिट अनुबंध के संबंध में अपने दायित्वों का पूरा नहीं करने की संभावना, एक महत्वपूर्ण जोखिम का गठन करती है जिसके लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखने और जोखिम प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। सैद्धांतिक रूप में, एक उधारकर्ता तब चूक करता है जब वह अपने व्यवसाय से अपर्याप्त नकदी प्रवाह के कारण अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है या उसकी आस्तियों का बाजार मूल्य उसकी देयताओं के मूल्य से कम हो जाता है, जो उसकी आस्ति को परिसमाप्त करने और कोई चूक न हो- यह सुनिश्चित करने के लिए लेनदारों को भुगतान करने की उधारकर्ताओं की क्षमता में बाधा डालता है। ऐसी स्थिति में उधारकर्ता को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से, वास्तविक दुनिया की स्थितियों में यह पता लगाना आसान नहीं है कि क्या कोई उधारकर्ता डिफ़ॉल्ट होने तक दिवालिया हो गया है। प्रायः, तब तक उधारकर्ता की आस्ति का विपणन योग्य मूल्य उसकी देयताओं से पहले ही कम हो चुका होगा। चूंकि उधारकर्ता की देनदारियां ऋणदाता के लिए आस्ति के रूप में हैं, उधारकर्ता की अपनी देयताओं का भुगतान करने में असमर्थता से ऋणदाता की आस्ति का मूल्य कम हो जाएगा जिससे उनके लेनदारों को चुकाने की उनकी क्षमता प्रभावित होगी, जिसमें बैंकों के मामले में मुख्य रूप से जमाकर्ता शामिल हैं। यही मुख्य कारण है कि आरबीआई विनियमित संस्थाओं द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समय पर समाधान में रुचि रखता है। यहां तक कि जहां ऋणदाता कोई बैंक नहीं है, वित्तीय प्रणाली की परस्पर संबद्धता से अप्रत्यक्ष प्रभाव होंगे जो वित्तीय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

एक बार जब कोई उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है, तो लेनदारों की स्वाभाविक प्रवृत्ति संबंधित उधारकर्ता की बिक्री योग्य आस्ति के शेष हिस्से के सबसे बड़े संभव अंश के लिए जल्दबाजी करके अपने नुकसान में कमी लाना है। हालांकि, हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि दिवालियेपन की स्थिति का तात्पर्य यह नहीं है कि उधारकर्ता की भविष्य की संभावनाएं मौजूद नहीं हैं - कई मामलों में कर्ज का एक विवेकपूर्ण पुनर्संतुलन इसे वापस ट्रैक पर लाने के लिए पर्याप्त होगा - जब तक कि वित्तीय दबाव अत्यंत तीव्र न हो। एक कार्यशील संस्था लगभग हमेशा ही एक परिसमाप्त कंपनी की तुलना में एक लेनदार (ऋणदाता) के लिए अधिक मूल्यवान होनी चाहिए। इस संदर्भ में एक व्यापक दिवाला समाधान कानून महत्वपूर्ण बन पड़ता है।

इस प्रकार, एक प्रभावी ऋण शोधन अक्षमता कानून निम्नलिखित पांच स्तंभों पर आधारित होना चाहिए:

* आईआईएम, अहमदाबाद में आयोजित दिवाला और शोधन अक्षमता पर अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा 30 अप्रैल 2022 द्वारा की गई टिप्पणियां। हम श्री वैभव चतुर्वेदी, श्री सूरज मेनन और श्री प्रदीप कुमार द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

I. इसे परिसमापन पर कार्यशील संस्था की स्थिति को प्राथमिकता देनी चाहिए।

II. इसे लेनदारों को एक साथ मिलकर एक समाधान योजना तैयार करने के लिए बाध्य करना चाहिए जो कंपनी को चालू रखने के लिए विकल्पों को देखकर कार्यशील संस्था को संरक्षित करने का प्रयास करता है।

III. इसे एक समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना चाहिए ताकि एक दिवालिया एक्सपोजर के लेनदारों के मूल्य ह्रास को रोका जा सके।

IV. इसे चूककर्ता उधारकर्ता के वित्तीय दबाव में योगदान देने वाले संदिग्ध लेन-देनों का पता लगाना चाहिए,

V. अंत में, यदि बहुमत का निर्णय अनुमोदन की पूर्वनिर्धारित सीमा को कवर करता है, तो एक प्रभावी समाधान व्यवस्था को शोधन अक्षमता से अविकल्पी सौदे के रूप में बाध्य कर बहुमत की अल्पसंख्यकों से रक्षा करनी चाहिए।

उपरोक्त पांच सिद्धांतों के अलावा, समाधान फ्रेमवर्क को उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा की गुणवत्ता के आधार पर वित्तीय लेनदारों के विभिन्न वर्गों के बीच भी अंतर करना चाहिए क्योंकि क्रेडिट साधन के प्रारंभिक मूल्य निर्धारण ने सुरक्षा की उपलब्धता में फैक्टर किया हो सकता है, और यदि समाधान मूल्य में शेयर का निर्धारण करते समय ऐसी सुरक्षा की गणना नहीं की जाती है तो ऋणदाता को नुकसान होगा। इस तरह के एक व्यवस्था की अनुपस्थिति में, लेनदारों को उनके द्वारा उठाए जा रहे क्रेडिट जोखिमों के लिए उच्च मुआवजे की मांग करने की संभावना है, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र क्रेडिट लागत बढ़ जाती है।

जबकि किसी भी समाधान फ्रेमवर्क को फर्म के मूल्य को संरक्षित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही, "परिसमापन की कगार पर कार्यशील संस्था" एक पूर्ण प्राथमिकता नहीं हो सकती है। उत्पादन के अनुत्पादक या पुराने कारकों को नियोजित करने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, परिसमापन ऐसे उद्यमों में फंसे मूल्य को अनलॉक करने में मदद कर सकता है और फिर अधिक दक्ष और उत्पादक उद्यमों की सहायता के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। "बाहर निकलने में आसानी" के अभाव में, एक अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन क्षमता, अक्षम व्यावसायिक उद्यमों के लिए बंधक बन जाएगी और अर्थव्यवस्था को अपनी संभाव्यता तक पहुंचने से रोक देगी। इस प्रकार, एक प्रभावी शोधन अक्षमता कानून को उपक्रमों के परिसमापन से पीछे नहीं हटना चाहिए, जब उन्हें समाज के लिए महंगे साबित होते हैं और पुनर्नियोजन के लिए मूल्य को अनलॉक करना अधिक फायदेमंद होगा।

वर्ष 2016 से पहले शोधन अक्षमता समाधान

2016 में आईबीसी के अधिनियमन से पहले भारत में बहुत सारे कानून थे, जिनमें से प्रत्येक के पास एक उधारकर्ता के शोधन अक्षमता समाधान की प्रक्रिया पर आंशिक अधिकार क्षेत्र था। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए) 1985 में अधिनियमित किया गया था और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना की गई थी। इसके बाद, डीआरटी को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय कर्जों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया था (कर्जों की वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 के रूप में फिर से नाम दिया गया)। वर्ष 2002 में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी- एसएआरएफएईएसआई) को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति हितों के तेजी से प्रवर्तन के लिए अधिनियमित किया गया था।

हालांकि इन कानूनों का उनके लागू होने के बाद की प्रारंभिक अवधि में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, पर समय के साथ सुधार कम होते गए। इसके अलावा, पूर्व-आईबीसी समाधान प्रयासों का ध्यान कंपनियों और रोजगार के संरक्षण की ओर अधिक था, कभी-कभी क्रेडिट अनुशासन और अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता की कीमत को भी ताक पर रख दिया जाता था।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों का समय पर समाधान आरबीआई के लिए महत्वपूर्ण रुचि रखता है। एक व्यापक शोधन अक्षमता कानून के अभाव में, आरबीआई को ऐसी योजनाओं की एक श्रृंखला बनानी पड़ी, जो एक शोधन अक्षमता कानून की वांछनीय विशेषताओं का अनुकरण करती हैं। इस प्रकार, पहले के विनियमनों ने संयुक्त ऋणदाताओं के फोरम के गठन को अनिवार्य कर दिया, जिसकी आईबीसी के तहत

लेनदारों की समिति के समान भूमिका थी। आस्ति वर्गीकरण ठहराव आईबीसी के तहत घोषित अधिस्थगन के बराबर था। बहुमत के निर्णय के लिए असहमति वाले लेनदारों पर बाध्यकारी होने की आवश्यकता, आईबीसी के तहत अविकल्पी सांविधिक संकट के एक विनियामक समकक्ष थी।

हालांकि, वित्तीय प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए आरबीआई की सांविधिक शक्तियां आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं तक सीमित हैं, जबकि वित्तीय अनुबंधों के जटिल जाल को खोलना और उन्हें एक दिवालिया देनदार की आय सृजन क्षमताओं के अनुरूप पुनर्लेखन करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेनदारों पर व्यापक शक्तियों के साथ व्यापक वैधानिक ढांचे की आवश्यकता है। हालांकि, अच्छे अभिप्राय से आरबीआई द्वारा डिजाइन की गई योजनाएं कभी-कभी वास्तविक आस्ति वर्गीकरण को स्थगित करके उधारकर्ताओं में वित्तीय तनाव की पहचान में देरी करने के लिए उधारदाताओं के लिए एक माध्यम बन जाती हैं।

आईबीसी के तहत महत्वपूर्ण बदलाव

वर्ष 2016 में आईबीसी के अधिनियमन के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की दिशा में प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। संहिता ने प्रचलित दृष्टिकोणों से अलग एक क्रांतिकारी रुख अपनाया, जिसमें उसने "क्रेडिटर-इन-कंट्रोल" मॉडल को "डेटर इन पोसेशन" मॉडल के खिलाफ अपनाया, जो देश में क्रेडिट अनुशासन में कोई ठोस सुधार करने में विफल रहा था। इस प्रकार, संहिता मूल रूप से देनदारों और लेनदारों के बीच देनदारों द्वारा एक चूक की स्थिति में शक्ति संतुलन को रीसेट करती है। यह दृष्टिकोण आर्थिक रूप से सुदृढ़ है क्योंकि लेनदारों के पास केवल एक उधारकर्ता द्वारा बनाए गए आर्थिक अधिशेष का अनुबंधित हिस्सा होता है, शेष अधिशेष बिना किसी सीमा के इक्विटी धारकों के पास चूक (डिफ़ॉल्ट) न होने की स्थिति तक जाता है। उस समय इक्विटी धारकों को सीमित देयता द्वारा संरक्षित किया जाता है, जबकि लेनदारों को दिवालिया देनदार के प्रति अपने संपूर्ण एक्स्पोसर तक खोने का जोखिम होता है। एक ही बार में संहिता ने "प्रवर्तकों के नियंत्रण में बने रहने के दैवीय अधिकार" को हटा दिया जिससे अन्य हितधारकों, विशेष रूप से लेनदारों के हितों को बहाल होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था।

धारा 29ए के सम्मिलन ने इस धारणा को और बल प्रदान किया कि यदि आवश्यक हो, तो एक दिवालिया देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि देनदार से समग्र रूप से समाज के लिए मूल्य को अधिकतम किया जा सके। इस प्रकार, पहली बार यदि वित्तीय दबाव को समय पर और व्यापक तरीके से संबोधित नहीं किया जाता है, तो प्रवर्तकों (प्रमोटर) को अपनी संबंधित कंपनियों पर नियंत्रण खोने की संभावना का सामना करना पड़ा।

संहिता ने एक सार्वजनिक संस्था के रूप में लेनदारों की समिति की भी स्थापना की, जिसमें एक कॉर्पोरेट देनदार के समाधान के दौरान हितधारकों के लिए मूल्य का अधिकतमकरण सुनिश्चित करने की सर्वोपरि जिम्मेदारी थी। लेनदारों की समिति में केवल वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं, जिसे व्यापक सार्वजनिक हित के समक्ष अपने व्यक्तिगत हितों को गौण मानना पड़ता है, यह अन्य समान कानूनों की तुलना में संहिता की एक अनूठी विशेषता है।

संहिता ने परिचालन लेनदारों की बातचीत करने की शक्ति को भी बढ़ाया, जिससे उन्हें डिफ़ॉल्ट में परिचालन देनदारों के संबंध में सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन करने की अनुमति मिली। 31 दिसंबर 2021 तक कुल सीआईआरपी मामलों में से 51% से अधिक मामले परिचालन लेनदारों द्वारा दायर किए गए थे। ऐसे मामलों में आहरण का अनुपात भी अधिक था - 50% से अधिक, कुल आहरण मामलों का 71% - यह दर्शाता है कि एक बातचीत कार्यनीति के रूप में शोधन अक्षमता कार्यवाही दाखिल करना परिचालन लेनदारों के लिए कारगर प्रतीत होते दिखा रहा है।

आईबीसी के तहत हुए प्रस्तावों में लिये गए उच्च स्तर के हेयरकट के बारे में लेनदारों को कुछ चिंताएं हैं। इन चर्चाओं में, हम इस तथ्य को याद करते हैं कि सार्वजनिक बोली-आधारित समाधान मॉडल में, हेयरकट (मार्जिन) की सीमा एक दिवालिया उधारकर्ता में निवेश जारी रखने के लिए बाजार की मांग में छूट का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि दिवालिया उधारकर्ता की आस्ति में महत्वपूर्ण मूल्य गिरावट हो सकती है, बकाया राशि के साथ तुलना समाधान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक उचित संकेतक नहीं हो सकता है।

बल्कि, लेनदारों के लिए समाधान मूल्यों की तुलना अगले सर्वोत्तम विकल्प से की जानी चाहिए, जो इस मामले में परिसमापन है। जिन सीआईआरपी मामलों का समाधान हुआ है, उनमें से देनदारों के परिसमापन मूल्य की तुलना में वित्तीय लेनदार 166% की वसूली करने में सक्षम रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि लेनदार अगले तार्किक परिणाम से बेहतर रहे हैं।

संहिता के प्रभाव से संबंधित एक अन्य अक्सर उपेक्षित पहलू विश्वसनीय 'दिवालियापन का खतरा' है। इस प्रभाव का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण माप सीआईआरपी आवेदनों की संख्या है, जो प्रविष्ट होने से पहले वापस ले लिए जाते हैं। दिसंबर 2021 तक, सीआईआरपी शुरू करने के लिए 19,803 आवेदनों, जिनका कुल अंतर्निहित डिफ़ॉल्ट ₹6.1 लाख करोड़ था, का प्रवेश से पहले समाधान किया गया था। संहिता के अभाव में, इसकी अधिक संभावना रहती है कि ये चूक (डिफ़ॉल्ट) बहुत लंबे समय तक बनी रहे, जिससे मूल्य का ह्रास होता है।

आरबीआई और आईबीसी

भले ही संहिता के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की सीआईआरपी में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, लेकिन आरबीआई विनियमित ऋण प्रणाली एक प्रभावी दिवालियापन कानून का एक महत्वपूर्ण हितधारक है। क्रेडिट मध्यस्थहीनता के बढ़ते स्तरों के साथ, आईबीसी देनदारों के व्यापक समाधान के लिए उपलब्ध सबसे पसंदीदा साधन बन गया है।

यह तथ्य कि लंबे समय से चले आ रहे दबाव के समाधान को प्रोत्साहन देने के लिए संहिता का लाभ उठाया जा सकता है, इसे संहिता के तहत सीआईआरपी से संबंधित प्रावधानों की अधिसूचना के लगभग तुरंत बाद पहचाना गया था। इसकी परिणति बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 में हुई, जिसने आरबीआई को आईबीसी के तहत समाधान के लिए विशिष्ट डिफ़ॉल्ट मामलों को संदर्भित करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार दिया। इन शक्तियों के तहत, जैसा कि अब व्यापक रूप से विदित है, आरबीआई ने जून 2017 में बैंकों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत 12 सबसे बड़े देनदारों के संबंध में आईबीसी के तहत शोधन अक्षमता कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद अगस्त 2017 में फिर से निर्देश दिये गए, जहां बैंकों को डिफ़ॉल्ट रूप से अन्य 29 कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में समयबद्ध समाधान योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ शोधन अक्षमता कार्यवाही शुरू की जानी थी।

आईबीसी के अधिनियमन और क़ानून के तहत दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए ट्रिगर होने के कारण डिफ़ॉल्ट घटना ने अनिवार्य समाधान के लिए नियामकीय ट्रिगर पर भी पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। हमने <u>7 जून, 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्तियों (प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क) के समाधान के लिए</u> एक सरल और सामंजस्यपूर्ण विवेकपूर्ण ढांचे के साथ पुनर्गठन के लिए सभी प्रचलित योजनाओं को बदल दिया, जिसमें निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत शामिल थे:

- बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसी द्वारा बड़े उधारकर्ताओं के संबंध में चूक की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग।
- विनिर्दिष्ट समय-सीमा और स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन के अधीन, समाधान योजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन के संबंध में ऋणदाताओं के लिए पूर्ण विवेक का साथ।
- समाधान योजना के कार्यान्वयन या दिवाला कार्यवाही शुरू करने में देरी के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण के रूप में दंड की एक प्रणाली।
- पुनर्रचना पर आस्ति वर्गीकरण छूट को वापस लेना। उचित अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन के सार्थक होने पर भविष्य में आस्ति का उन्नयन।
- पुनर्रचना के उद्देश्य से, 'वित्तीय कठिनाई' की परिभाषा को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ जोड़ा गया था; तथा,
- सभी ऋणदाताओं द्वारा अंतर-ऋणदाता समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया था, जो बहुमत वाले निर्णय लेने का मानदंड प्रदान करेगा।

आईबीसी के बाहर दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की दिशा में आरबीआई का दृष्टिकोण समाधान प्रयासों को समय पर शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना रहा है; ऋण पुनर्रचना के रूप में दी गई रियायतों के कारण ऋणदाताओं को बढ़े हुए ऋण जोखिम की उचित पहचान; और उधारकर्ताओं को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि रियायतों ने ऋण पुनर्संरचना के बाद एक उचित अवधि के दौरान अपने ऋण दायित्वों पर संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करके उनकी व्यवहार्यता में सुधार किया है।

ऋण शोधन अक्षमता फ्रेमवर्क से अपेक्षाएं

आईबीसी जैसा आधुनिक दिवाला कानून को सभी हितधारकों के समर्थन और धैर्य की जरूरत है और नए कानून के प्रति रवैया केवल लंबे समय से दबाव वाली आस्तियों के समाधान के संबंध में होने वाले नुकसान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। साथ ही, यह आवश्यक है कि विनियमित संस्थाओं के विभिन्न वर्गों में व्यवस्थाओं के उपयुक्त सामंजस्य के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली में परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए ढांचे की आवधिक समीक्षा के माध्यम से अदालत के बाहर के प्रस्तावों के लिए नियामक व्यवस्था में सुधार जारी रखा जाए। मुझे लगता है कि संहिता को और मजबूत करने के लिए, हमें निम्नलिखित चार आयामों पर काम करने की आवश्यकता है:

ए. **समाधान में बड़ी तस्वीर:** आईबीसी जैसे व्यापक कानून को अक्सर ऋणदाताओं द्वारा अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है - एक ऐसा मार्ग जिसे सभी विकल्पों के निष्फल हो जाने के बाद प्रयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह दृष्टिकोण संकटग्रस्त उधारकर्ता के भविष्य के लिए एक व्यापक दृष्टि की कमी से उपजा है। ऋणदाताओं के विभिन्न वर्ग अदालत के बाहर के समाधान ढांचे के अलग-अलग सेट द्वारा शासित होते हैं जो ऋणदाता के प्रत्येक वर्ग पर अलग से लागू होते हैं। सभी ऋणदाताओं की भागीदारी के बिना, समाधान की दिशा में कोई भी प्रयास अधूरा होने की संभावना है और यह अपरिहार्य नुकसान का एक स्थगन मात्र होगा। इस तरह के अधूरे प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में लगने वाला समय लेनदारों को होने वाले नुकसान और वित्तीय प्रणाली की लागत को बढ़ाने वाले हैं। चूंकि यह एक शोध सम्मेलन है, इसलिए मैं एक शोध प्रश्न का प्रस्ताव देना चाहता हूं: एक उधारकर्ता द्वारा डिफ़ॉल्ट और लेनदारों द्वारा दिवाला समाधान के लिए आवेदन दाखिल करने के बीच औसत समय क्या है? आवेदन दर्ज कराने में इस तरह की देरी और मूल्य में गिरावट के बीच संबंध को देखना भी दिलचस्प होगा जिसे लेनदारों को बाद में ध्यान में रखना होगा।

बी. **दिवाला आवेदनों के दाखिल होने में देरी:** एक और विचलित करने वाला पहलू दिवाला आवेदन दाखिल करने और आवेदन के अंतिम स्वीकृति के बीच लगने वाला समय है। संहिता 14 दिनों की अवधि निर्धारित करती है। हालाँकि, वास्तव में, स्वीकृति में आमतौर पर उससे अधिक समय लगता है। आईबीबीआई द्वारा 13 अप्रैल, 2022 को जारी एक परामर्श पत्र में कहा गया है कि किसी परिचालन लेनदार के दिवाला आवेदन की स्वीकृति के लिए लिया गया औसत समय 2020-21 में 468 दिनों से बढ़कर 2021-22 में 650 दिन हो गया है। यह संहिता के तहत एक सीआईआरपी को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा से भी अधिक है। आवेदन स्वीकृति में इस तरह की देरी से व्यापक दिवालियापन कानून के रूप में आईबीसी की दक्षता कम होने की संभावना है और इससे लेनदार के अधिकार कमजोर हो सकते हैं और दिवालिया उधारकर्ताओं के लिए बाहर निकलने में आसानी हो सकती है। यहां एक और शोध प्रश्न है: दिवाला आवेदनों की स्वीकृति में देरी के लिए जिम्मेदार कारक और आईबीसी का सहारा लेने वाले उन लेनदारों की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की संभावना जिनके आवेदनों में देरी हुई है।

सी. **प्री-पैक समाधानों के कवरेज में वृद्धि:** किसी भी कानून की तरह, आईबीसी को भी बदलते आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ विकसित होने की जरूरत है। आईबीबीआई की सक्षम नियामक क्षमताओं द्वारा निर्देशित दिवाला कानून पर स्थायी समिति के रूप में

वर्तमान समीक्षा ढांचा, इसे सुनिश्चित करने का एक अनुकरणीय कार्य कर रही है। आईबीसी के लिए नए आयाम पेश किए जा रहे हैं जैसे कि प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (पीपीआईआरपी/प्री-पैक) का नया मॉड्यूल, जो कोर्ट के बाहर के समाधान प्रयासों और स्वीकृत समाधान योजनाओं की न्यायिक प्रक्रिया की पूर्णता को जोड़ती है, जो कि एक निर्णायक प्राधिकरण द्वारा स्वागत योग्य पहल है। भले ही पीपीआईआरपी को वर्तमान में केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के लिए अनुमति दी गई है, हम प्री-पैक की कल्पना गैर-सहकारी से जुड़े उस कठिन समाधान में सभी उधारकर्ताओं के संबंध में आरबीआई के विवेकपूर्ण ढांचे के प्राकृतिक पूरक के रूप में कर सकते हैं। उधारदाताओं को ऐसी पूर्व-पैकेज्ड योजनाओं का उपयोग करके समाधान किया जा सकता है। सभी उधारकर्ताओं के लिए पीपीआईआरपी का विस्तार करने पर विचार करना सार्थक होगा।

डी. **समूह के लिए समाधान:** एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम जिसे संहिता में शामिल करने की आवश्यकता है, वह है समूह के लिए समाधान की अवधारणा - ऐसा जिसमें एक ही कॉरपोरेट समूह से संबंधित उधारकर्ताओं का समाधान एक साथ किया जाता है। इसका एक उदाहरण हमने वीडियोकॉन समूह की समाधान प्रक्रिया के दौरान देखा; हालाँकि, इसे संहिता की एक विशेषता के बजाय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उपलब्ध विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से किया गया था। ऐसी प्रक्रिया भारत जैसी अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां परंपरागत रूप से ऋण अनुबंधों को परस्पर दायित्वों और उधारकर्ता की मूल और समूह कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए ऋण न्यूनीकरण कवर के साथ जोड़ा गया है। ऐसी प्रणाली में, उधारकर्ता द्वारा चूक से समूह की कंपनियों द्वारा परस्पर चूक को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे वित्तीय प्रणाली के लिए समग्र ऋण जोखिम बढ़ जाता है। इस प्रकार संहिता की प्रभावकारिता में और सुधार करने के लिए ऐसे परस्पर जुड़े कॉरपोरेट समूहों के सामूहिक समाधान के लिए एक व्यापक प्रक्रिया आवश्यक है।

ऋणदाताओं से अपेक्षाएं

भारत में ऋण जोखिम बाजार का गहरा होना वित्तीय प्रणाली को परिष्कार के अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। आरबीआई हाल के वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठा रहा है। ऋण जोखिम के हस्तांतरण को कवर करने वाले दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है और सभी ऋणदाता संस्थानों में सामंजस्य स्थापित किया गया है। दबावग्रस्त ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार को उन अंतरितियों के लिए खोल दिया गया है जो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं। भारत में आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति (अध्यक्ष: डॉ हर्षवर्धन) और कॉरपोरेट ऋण के लिए माध्यमिक बाजार के विकास पर कार्य बल (अध्यक्ष: श्री टीएन मनोहरन) की सिफारिशों को विभिन्न चरणों में लागू किया जा रहा है। कार्य बल की प्रमुख सिफारिशों में से एक - कॉरपोरेट ऋण हेतु द्वितीयक बाजार के लिए स्व-नियामक संगठन - माध्यमिक ऋण बाजार संघ की स्थापना के साथ लागू किया गया है। आरबीआई अतिरिक्त प्रकार के प्रतिभूतिकरण की अनुमति देने की व्यवहार्यता की खोज करके ऋण जोखिम बाजार को गहरा करने के लिए और रास्ते तलाश रहा है।

साथ ही, हम यह अपेक्षा करेंगे कि ऋणदाता समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए उधारकर्ता द्वारा चूक की प्रतीक्षा न करें। उधारदाताओं को अपने एक्सपोजर के विवेकपूर्ण जोखिम मूल्य निर्धारण को एक्सपोजर की निरंतर निगरानी और पर्याप्त पूंजी और जोखिम प्रावधानों के रखरखाव के साथ जोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी प्रतिपक्ष के दिवालिया होने के बिन्दु को सटीक रूप से इंगित नहीं किया जा सकता है, उधारदाताओं के जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को जोखिम कारकों में परिवर्तन को पकड़ने के लिए पर्याप्त रूप से परिष्कृत होना चाहिए जो उक्त ऋण जोखिम की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। ऋणदाताओं को संभावित प्रक्षेपवक्रों का अनुमान लगाने के लिए आवधिक दबाव परीक्षण भी करना चाहिए जो कि ऋण एक्सपोजर लेने की संभावना है और तदनुसार उनकी प्रतिक्रियाओं को परिवर्तित कर सके।

अंततः, वे अपने हित और अपने हितधारक के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में, हमने देश में ऋण अनुशासन में सुधार लाने में एक लंबा सफर तय किया है।

हालांकि, किसी भी सार्वजनिक नीति की तरह, यह हमेशा एक कार्य प्रगति पर स्थिति में होता है जिसमें किसी भी समय सुधार की गुंजाइश होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक समाधान ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखेगा और विभिन्न ऋण मध्यस्थों की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली प्रणालीगत चिंताओं का ध्यान रखने के लिए लगातार अधिक परिष्कृत और अद्यतन जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाएगा। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मैं चाहता हूं कि यह सम्मेलन अपनी तरह का पहला हो और अंतर्दृष्टिपूर्ण बहस उत्पन्न करे जो आने वाले समय में हमारा मार्गदर्शन करेगी।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह 2019-20

भारत का संवृद्धिवर्धक बाह्य ऋण

धारणीय कृषि के लिए सिंचाई प्रबंधन

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी बहाली को समेकित किया, जिसमें अधिकांश घटक गतिविधि के पूर्व-महामारी स्तरों को पार कर गए। कमजोर वृद्धि, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक स्पिलओवर के कारण आपूर्ति में व्यवधान और समकालिक मौद्रिक सख्ती से उत्पन्न वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न वैश्विक जोखिम निकट अवधि की चुनौतियां हैं।

परिचय

यूरोप में भू-राजनीतिक संघर्ष के बादल वैश्विक आर्थिक संभावनाओं को ढकेल देते हैं, जिसके साथ जोखिम कम हो जाते हैं। पण्यों की कीमतें ऊंचे स्तरों पर अस्थिर बनी हुई हैं, और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान खराब हो गया है। सभी भौगोलिक क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है, और केंद्रीय बैंक आक्रामक रूप से मौद्रिक नीति और चलनिधि की स्थिति को सख्त कर रहे हैं। जैसे-जैसे वित्तीय स्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, वित्तीय बाज़ार अस्थिर और अनिश्चित होते हैं, उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को वैश्विक निवेशकों के बीच जोखिम-प्रतिकूल भावनाओं में उछाल का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह भंडार के नुकसान के बीच पूंजी बहिर्वाह और मुद्रा मूल्यह्रास को ट्रिगर कर रहा है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को अपनी झिझक और अधूरी बहाली के जोखिम का सामना करना पड़ता है जो बदले में व्यापक वैश्विक सुधार की संभावनाओं पर वापस फैल सकता है। इन घटनाक्रमों को प्रतिबिंबित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) की अप्रैल 2022 की अपनी विज्ञप्ति में जनवरी 2022 के अनुमान के सापेक्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 0.8 प्रतिशत अंक (पीपीटी) घटाकर 3.6 प्रतिशत कर दिया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) की तुलना में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए डाउनवर्ड रिवीजन तेज है। एई और ईएमडीई के लिए मुद्रास्फीति 2022 में क्रमशः 5.7 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है, जो जनवरी 2022 के अपडेट से क्रमशः 1.8 पीपीटी और 2.8 पीपीटी अधिक है।

इस शत्रुतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहाली के मार्ग को समेकित किया। संपर्क-गहन सेवाओं में गतिविधि में तनाव आ रहा है, और महामारी के प्रकोप के बाद से उपभोक्ता विश्वास अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच रहा है। अप्रैल 2022 में आर्थिक गतिविधियों में तेजी उच्च आवृत्ति संकेतकों में स्पष्ट है। संक्रमण में कमी के साथ, गतिशीलता संकेतकों में सुधार हुआ है जबकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम भागीदारी बढ़ रही है। माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत राजस्व संग्रह अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा - जो इसके इतिहास में सबसे अधिक है।

हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अप्रैल 2022 में एक्सपेंशनरी जोन में रहा, जिसमें ज्यादातर कंपनियां नए ऑर्डर और प्रोडक्शन में तेजी दर्ज कर रही थीं। बढ़ते हुए पारे के स्तर के बीच मांग बढ़ने के साथ, बिजली उत्पादन ने महीने के दौरान दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की, भले ही कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण व्यवधान हुआ। नए व्यवसाय, बढ़ती मांग और रोजगार में नए सिरे से वृद्धि के कारण हेडलाइन सेवाएं पीएमआई लगातार नौवें महीने भी विस्तारक क्षेत्र में मँडरा रही हैं। बाहरी मोर्चे पर, अप्रैल 2022 में व्यापारिक निर्यात 40.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर मजबूत रहा, जिससे पिछले चौदह महीनों में लगातार 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निशान से ऊपर रहा।

इन घटनाक्रमों के बीच, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अप्रैल 2022 के प्रिंट में सभी कमोडिटी समूहों में मुद्रास्फीति के दबाव तेजी से सामान्यीकृत हो गए, जिसके परिणामस्वरूप हेडलाइन मुद्रास्फीति में 7.8 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई - ऊपरी टोलारेंस बैंड से काफी ऊपर। दिनांक 4 मई 2022 को आयोजित एक ऑफ-साइकिल बैठक में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से पॉलिसी रेपो दर को 40 बीपीएस बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। स्थायी जमा

* इस लेख को जीवी नाधानियल, शशिकांत, कुणाल प्रियदर्शी, राजीव जैन, विनीत कुमार श्रीवास्तव, हर्षिता केशन, रिगजेन यांगडोल, प्रशांत कुमार, डी. सुगंधी, रोहन बंसल, कृष्ण मोहन कुशवाहा, अभिनंदन बोराड, जितेंद्र सोकल, जिबिन जोस, अवनीश कुमार, आशीष संतोष खोबरागड़े, रमेश कुमार गुप्ता, आयुषी खंडेलवाल, विमल किशोर, रमेश गोलैत, देब प्रसाद रथ और समीर रंजन बेहरा ने तैयार किया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करें।

सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दरों को सममित रूप से क्रमशः 4.15 प्रतिशत और 4.65 प्रतिशत पर समायोजित किया गया था। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली से ₹87,000 करोड़ की चलनिधि को वापस लेते हुए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 50 बीपीएस बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत (21 मई, 2022 से प्रभावी पखवाड़े) करने का भी निर्णय लिया। इन उपायों ने नीतिगत रुख में समायोजन को वापस लेने पर जोर दिया।

एमपीसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अस्थिर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, नए सिरे से लॉकडाउन और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान एमपीसी की अप्रैल 2022 की बैठक में निर्धारित मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के लिए महत्वपूर्ण अपसाइड जोखिम प्रदान करते हैं। एमपीसी ने यह भी महसूस किया कि मुद्रास्फीति के दूसरे दौर के प्रभावों को नियंत्रित करना और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को प्रभावी ढंग से रोकना महत्वपूर्ण है ताकि इस समय मूल्य स्थिरता जनादेश को प्राथमिकता देते हुए विकास के लचीलेपन और गति को बनाए रखा जा सके। एमपीसी की त्वरित प्रतिक्रिया मूल्य स्थिरता के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है जो मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता के लिए अच्छा है। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया कि रिजर्व बैंक "मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और विकास को समर्थन देने की हमारी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सतत और समावेशी विकास के पथ पर दृढ़ बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। समग्र वृहद आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ सतत विकास में सबसे बड़ा योगदान मूल्य स्थिरता बनाए रखने के हमारे प्रयास से होगा। [1]

इस पृष्ठभूमि में, शेष लेख को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकास को दर्शाता है। घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में प्रस्तुत किया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करता है, जबकि अंतिम खंड लेख का समापन करता है।

[1] Governor's statement on May 4, 2022.

II. वैश्विक व्यवस्था

उत्पादन और कीमतों पर इसके प्रभाव के कारण वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण नकारात्मक जोखिमों के साथ घटा है। विश्व बैंक के नवीनतम कमोडिटी मार्केट आउटलुक के अनुसार, अधिकांश कमोडिटी की कीमतों में 2022 तक और आगे मध्यम अवधि में तेज वृद्धि का अनुमान है। फ्रंट-लोडेड मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और उच्च मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय स्थितियों का एक महत्वपूर्ण सख्त होना वित्तीय स्थिरता की चिंता पैदा कर रहा है। दुनिया के कुछ हिस्सों में संक्रमण और लॉकडाउन के फैलने से

सारणी 1: जीडीपी वृद्धि का अनुमान – चयनित एई और ईएमई

(प्रतिशत)

देश	2022		2023	
	January 2022	April 2022	January 2022	April 2022
विश्व	4.4	3.6	3.8	3.6
विकसित अर्थव्यवस्था				
यूएस	4.0	3.7	2.6	2.3
यूके	4.7	3.7	2.3	1.2
यूरो क्षेत्र	3.9	2.8	2.5	2.3
जापान	3.3	2.4	1.8	2.3
उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था				
ब्राज़ील	0.3	0.8	1.6	1.4
रूस	2.8	-8.5	2.1	-2.3
India	9.0	8.2	7.1	6.9
चीन	4.8	4.4	5.2	5.1
दक्षिण अफ्रीका	4.6	1.9	1.9	1.4

स्रोत : आईएमएफ़।

चार्ट 1: : वैश्विक पीएमआई

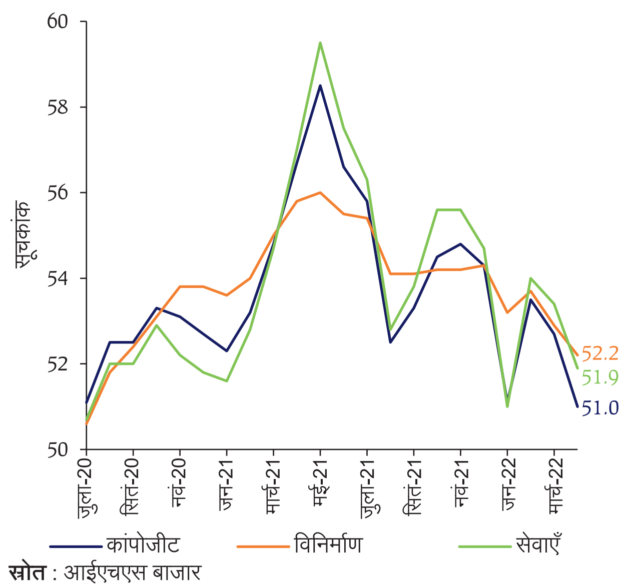

स्रोत : आईएचएस बाजार

वैश्विक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम भी बढ़ गए हैं। महामारी के विकास को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

उच्च आवृत्ति संकेतकों के बीच, वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अप्रैल में 22 महीने के निचले स्तर 51.0 पर आ गया, जो एक महीने पहले 52.7 था, क्योंकि नए ऑर्डर की वृद्धि धीमी थी, और व्यापार आशावाद 19 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया था (चार्ट 1)। जून 2020 के बाद पहली बार मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अनुबंध के साथ सेवाओं और विनिर्माण पीएमआई दोनों में 20 महीने के निचले स्तर पर फिसलन के साथ, दोनों में ढील दी गई। उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से चीन में लॉकडाउन को दर्शाती है। चीन को छोड़कर वैश्विक विनिर्माण उत्पादन सूचकांक में मार्च की तुलना में मामूली सुधार दर्ज किया गया।

व्यापार के मोर्चे पर, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने रूस-यूक्रेन संघर्ष और चीन में लॉकडाउन के बाद 2022 के लिए माल व्यापार की मात्रा में वृद्धि के लिए अपने अनुमान को 4.7 प्रतिशत से घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया। अप्रैल डब्ल्यूईओ में, आईएमएफ ने वस्तुओं और सेवाओं के विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि के अनुमान को 2022 में 5.0 प्रतिशत और 2023 में 4.4 प्रतिशत तक घटा दिया – 2022 के लिए पूर्ण प्रतिशत अंक कम और जनवरी 2022 के अनुमानों के सापेक्ष 2023 के लिए आधा प्रतिशत अंक कम। मासिक आंकड़े कुछ सकारात्मक गति दिखाते हैं लेकिन पांच महीनों में सबसे कमजोर (चार्ट 2 ए)। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, शुष्क थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग शुल्क का एक उपाय, अस्थिर रहा और अप्रैल में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 2 बी)।

चार्ट 2: विश्व व्यापार और नौपरिवहन लागत

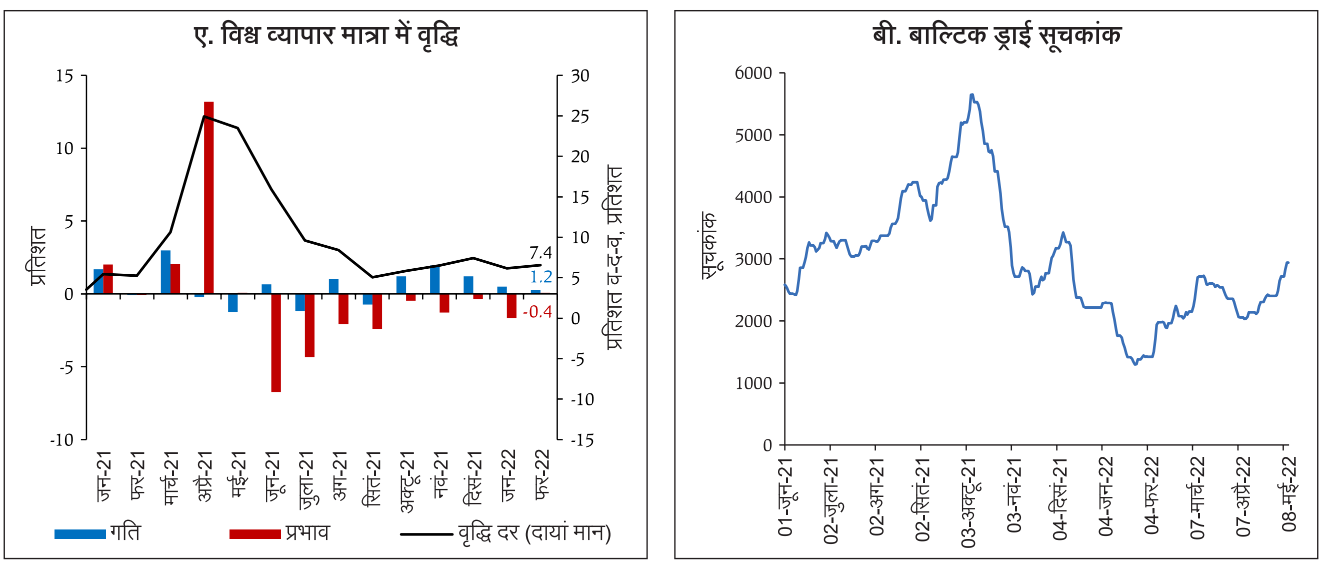

स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; और ब्लूमबर्ग।

ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स ने अपनी चल रही वृद्धि जारी रखी, अप्रैल के मध्य में 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया (चार्ट 3 ए)। कच्चे तेल की कीमतें हाल के शिखर से पीछे हट गईं, क्योंकि चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं सहित विश्व आर्थिक विकास को धीमा करने के बारे में चिंताओं ने आगे आपूर्ति व्यवधानों की आशंकाओं को पछाड़ दिया (चार्ट 3 बी)। बहरहाल, कच्चे तेल की कीमतों में अब तक (12 मई, 2022 तक) 37.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। छह महीने में रूस पर यूरोप की कच्चे तेल की निर्भरता को चरणबद्ध करने की योजना ने मई की शुरुआत में कीमतों पर और दबाव डाला। बॉन्ड पैदावार में सख्ती और अमेरिकी डॉलर के मजबूत कारोबार के रूप में सोने की कीमतों में हेडविंड्स का सामना करना पड़ा, जबकि सुरक्षित हेवन और मुद्रास्फीति हेज मांग ने बुलियन को समर्थन प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप रेंज-बाउंड मूवमेंट (चार्ट 3 सी)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य मूल्य सूचकांक अप्रैल में मामूली रूप से घटकर 158.5 पर आ गया, जो मार्च में दर्ज सर्वकालिक उच्च स्तर पर था, जबकि चीनी, मांस और डेयरी की कीमतों में तेजी जारी है (चार्ट 3 डी)।

लंबे समय तक रूस-यूक्रेन संघर्ष ने कई देशों में कई निर्यात प्रतिबंधों को जन्म दिया है, जिसने उच्च खाद्य कीमतों में योगदान दिया, विशेष रूप से गेहूं और मकई में (चार्ट 4)।

अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति बहु-दशकीय उच्च स्तर पर पहुंच गई है (चार्ट 5)। हालांकि, अमेरिकी सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में मामूली रूप से घटकर 8.3 प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 8.5 प्रतिशत थी, जिसमें 0.3 प्रतिशत की मासिक गति थी – अगस्त 2021 के बाद से सबसे कम क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में 2.7 प्रतिशत (एम-ओ-एम) की गिरावट आई थी। दूसरी ओर व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक मार्च में 40 साल के उच्चतम स्तर 6.6 प्रतिशत पर पहुंच गया।

चार्ट 3: कमोडिटी और खाद्य कीमतें

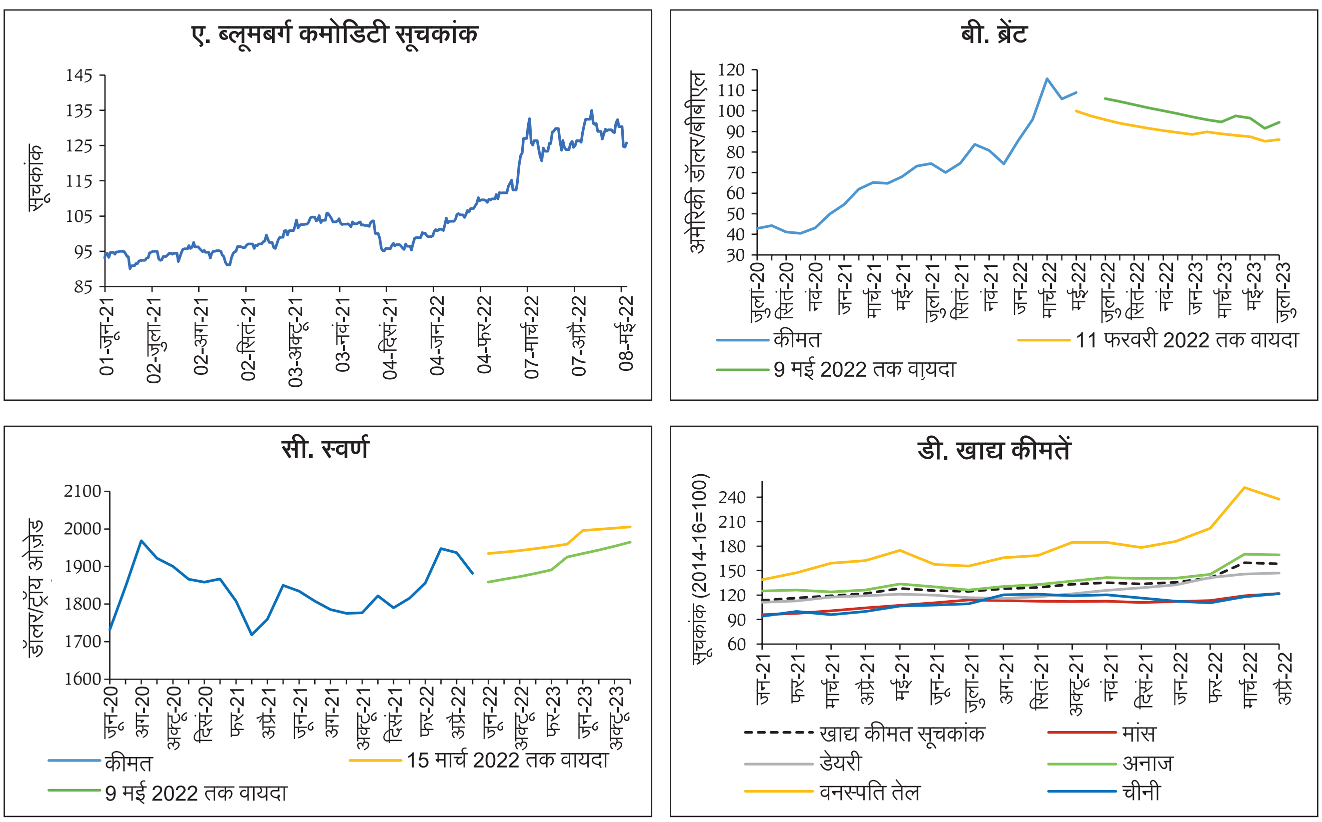

स्रोत : ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिंक शीट; और एफ़एओ।

चार्ट 4 : कीमतें और निर्यात प्रतिबंध

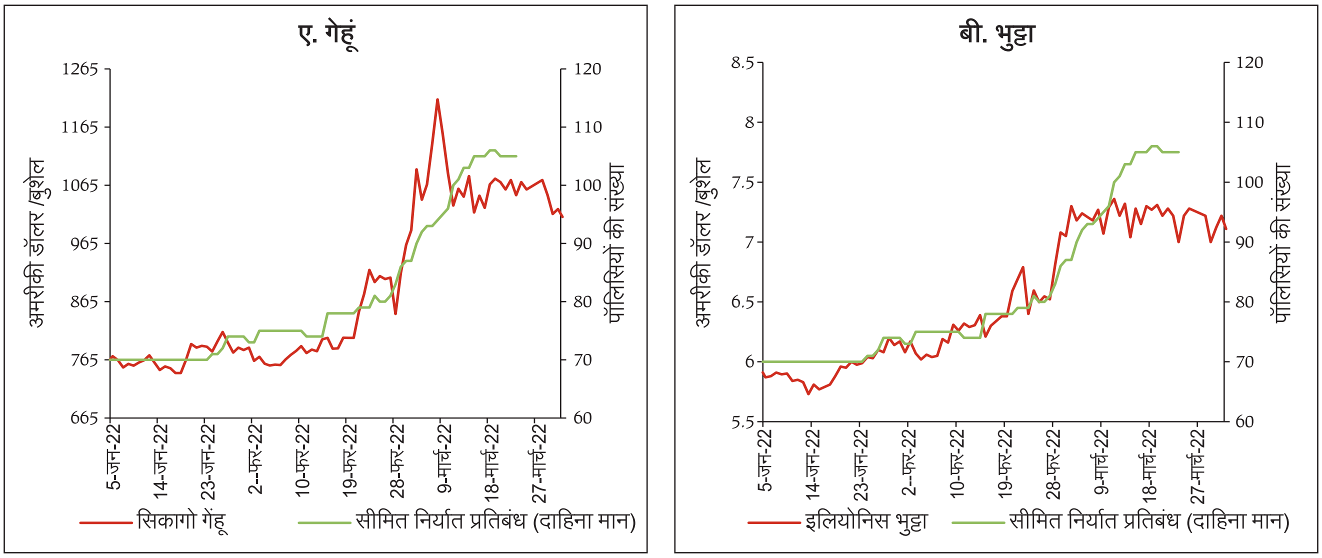

स्रोत : ब्लूमबर्ग

ब्रिटेन में सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गई, जो डेटा श्रृंखला में सबसे अधिक है, परिवहन घटक से 1.83 पीपीटी का सबसे बड़ा योगदान है। यूरो क्षेत्र की वार्षिक मुद्रास्फीति अप्रैल में 7.5 प्रतिशत के नए शिखर पर पहुंच गई, जो मुख्य रूप से ऊर्जा और उसके बाद भोजन, शराब और तंबाकू से प्रेरित थी। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में, चीन में मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर 2.1 प्रतिशत पर पहुंच गई क्योंकि व्यापक लॉकडाउन के कारण आपूर्ति का दबाव बढ़ गया (चार्ट 5 बी)।

अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति के अनुमानों में काफी वृद्धि की गई है। आईएमएफ ने अपने अप्रैल 2022 डब्ल्यूईओ में प्रमुख एई और रूस के लिए 2022 के अंत के लिए

चार्ट 5 : प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति

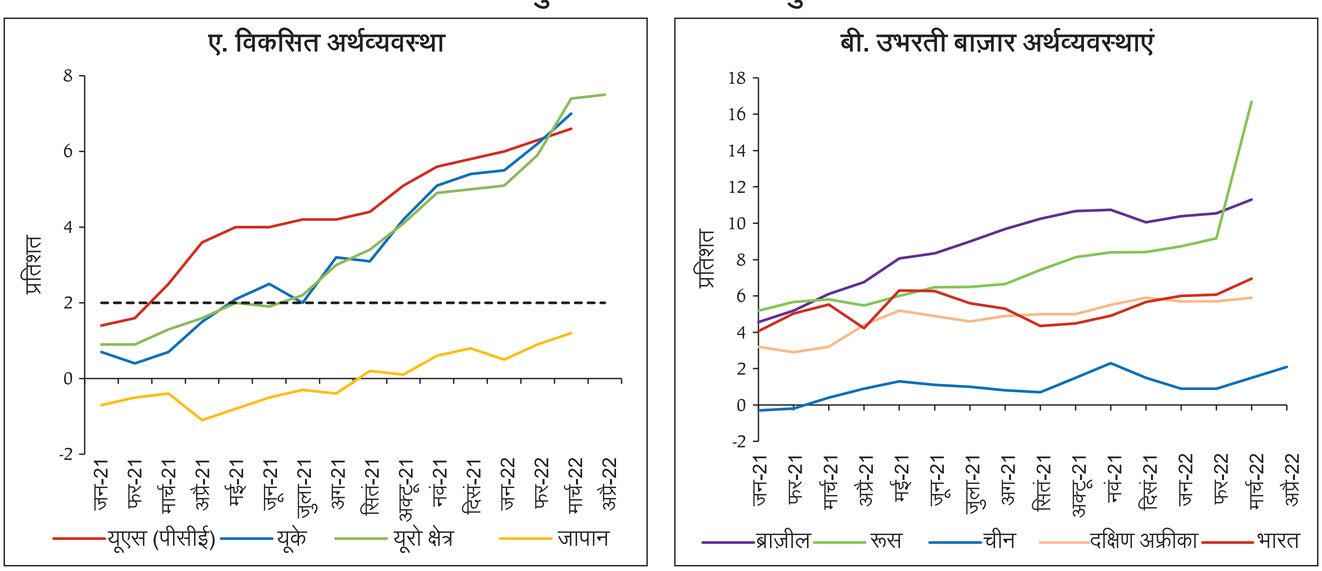

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 6 : वर्ष 2022 के अंत के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान में संशोधन

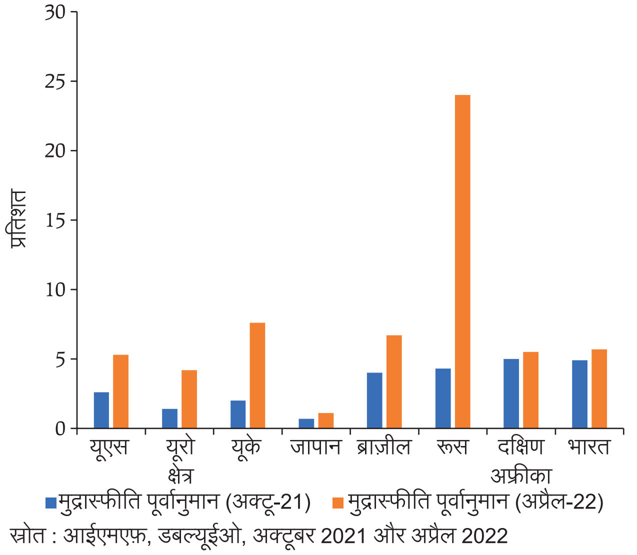

स्रोत : आईएमएफ़, डबल्यूईओ, अक्टूबर 2021 और अप्रैल 2022

मुद्रास्फीति के अनुमानों को भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक परिमाण तक संशोधित किया है (चार्ट 6)।

वैश्विक वित्तीय बाजारों में अप्रैल की शुरुआत से तेज बिकवाली देखी गई है क्योंकि प्रमुख केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अनवाइंडिंग की गति के बारे में अनिश्चितता के साथ-साथ बढ़ती वृद्धि चिंताओं ने निवेशकों की धारणा को झकझोर दिया है। एमएससीआई वर्ल्ड इक्विटी इंडेक्स अप्रैल में एई और ईएमई दोनों स्टॉक इंडेक्स (चार्ट 7 ए) में गिरावट के साथ 8 प्रतिशत गिर गया। बॉन्ड बाजारों में, यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई क्योंकि बाजार की कीमत पहले के अनुमान की तुलना में अधिक आक्रामक फेड कसने में थी। इसके अलावा, अल्पकालिक दरें भी एक साथ उछल गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप चापलूसी उपज वक्र (चार्ट 7 बी) है। अमेरिकी डॉलर में मजबूती जारी रही, फेड के आक्रामक रुख के जवाब में बहु-दशकीय ऊंचाई पर पहुंच गया। येन के 20 साल के निचले स्तर (चार्ट 7 सी) पर फिसलने के साथ देश-विशिष्ट कारकों पर अन्य मुद्राओं का मूल्यह्रास हुआ। अधिकांश ईएमई मुद्राओं का मूल्यह्रास हुआ, शुद्ध पूंजी बहिर्वाह डाउनट्रेंड (चार्ट 7 डी) को बढ़ा रहा है।

चार्ट 7 : वित्तीय बाज़ार

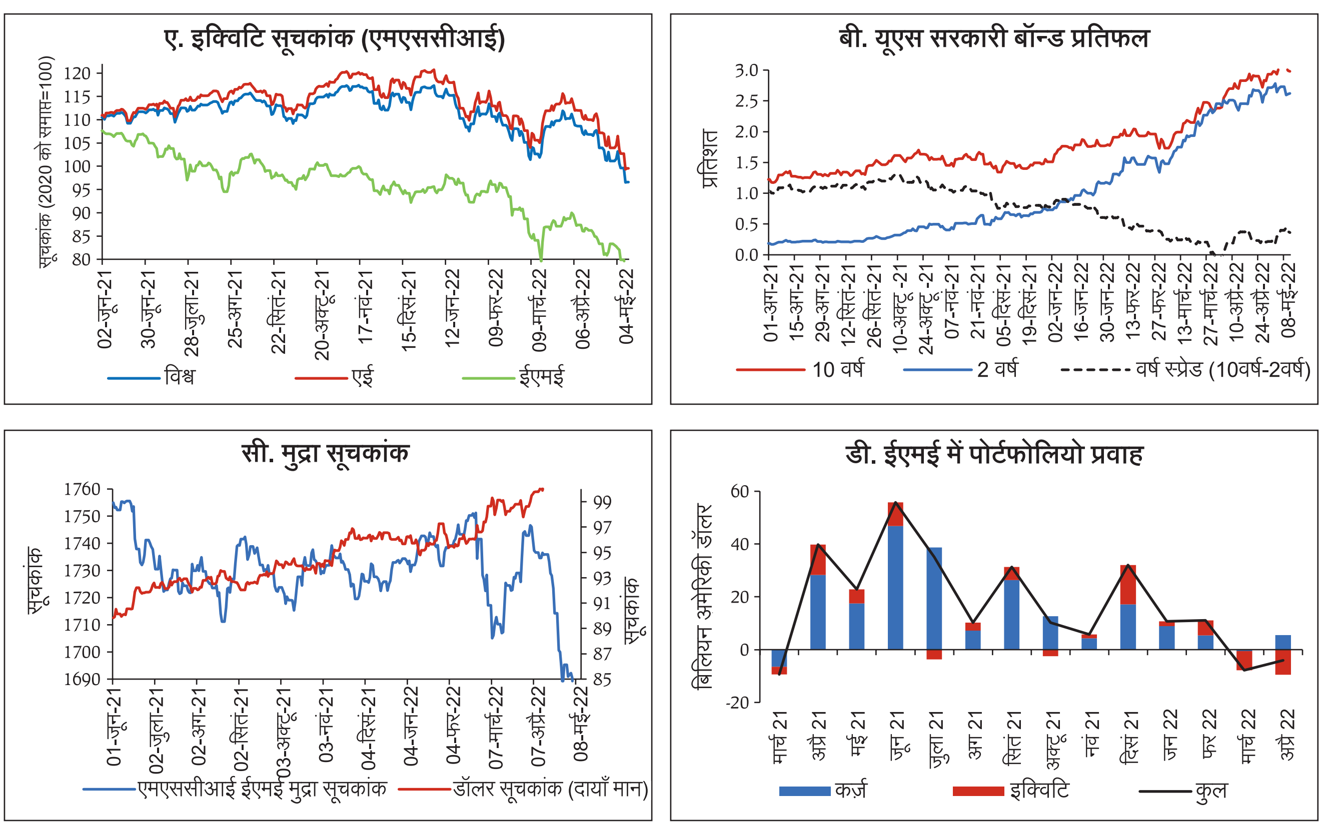

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ़।

मौद्रिक नीति की कार्रवाइयां और रुख देशों में सिंक्रनाइज़ हो रहे हैं, अधिक एई और ईएमई केंद्रीय बैंकों ने दरों में वृद्धि की है। बाजार की उम्मीदों के अनुरूप, फेडरल रिजर्व ने फेडरल फंड दर की लक्ष्य सीमा को 50 बीपीएस बढ़ाकर 0.75-1.0 प्रतिशत कर दिया, जो मई 2000 के बाद से पहली 50 बीपीएस वृद्धि है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने शुरुआती संबोधन में, चेयरमैन पॉवेल ने उल्लेख किया कि "अगली कुछ बैठकों में अतिरिक्त 50 आधार अंकों की वृद्धि की मेज पर होनी चाहिए"। फेड ने 1 जून से ट्रेजरी सिक्योरिटीज, एजेंसी डेट और एजेंसी मॉर्गेज-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) की अपनी होल्डिंग्स में कमी करके बैलेंस शीट के आकार को कम करने की योजना का भी अनावरण किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपनी नीतिगत दर को 25 बीपीएस बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत कर दिया - फरवरी 2009 के बाद से सबसे अधिक संचयी वृद्धि को दिसंबर 2021 में शुरू हुए अपने वर्तमान कसने के चक्र में 90 बीपीएस तक ले गया। बैंक ऑफ कनाडा और रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने अप्रैल में अपनी नीतिगत दरों में 50-50 आधार अंकों की वृद्धि कर क्रमश: 1.0 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत कर दी थी। बैंक ऑफ कोरिया ने भी अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 25 बीपीएस की वृद्धि की, जबकि सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने छह महीने में तीसरी बार मौद्रिक नीति को कड़ा कर दिया। बैंक ऑफ जापान एक दुर्लभ एई केंद्रीय बैंक है जिसने अपनी नवीनतम बैठक में 0.25 प्रतिशत उपज पर जापानी सरकार के बांडों की दैनिक खरीद के लिए प्रतिबद्ध होकर अपनी उपज वक्र नियंत्रण को मजबूत करते हुए एक डोविश रुख बनाए रखा है। अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने ब्राजील, पोलैंड और पेरू सहित नीतिगत सख्ती जारी रखी है, जो 2022 में अब तक क्रमशः 250 बीपीएस, 375 बीपीएस और 200 बीपीएस तक अपनी बेंचमार्क दरों में वृद्धि कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भी अप्रैल में अपनी प्रमुख दर को 700 बीपीएस बढ़ाकर 14.5 प्रतिशत कर दिया। दूसरी ओर, बैंक ऑफ रूस ने अप्रैल में अपनी नीतिगत दर को संचयी 600 बीपीएस घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया क्योंकि मूल्य और वित्तीय स्थिरता जोखिम कम हो गए। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने आरक्षित आवश्यकता अनुपात को 25 बीपीएस तक कम कर दिया, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 500 बिलियन रेनमिनबी (लगभग यूएस $ 78 बिलियन) तरलता इंजेक्ट की और अपनी अप्रैल की बैठक (चार्ट 8) में अन्य ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा।

चार्ट 8 : चुनिंदा देशों के केंद्रीय बैंकों की दर कार्रवाइयां (2021-22)

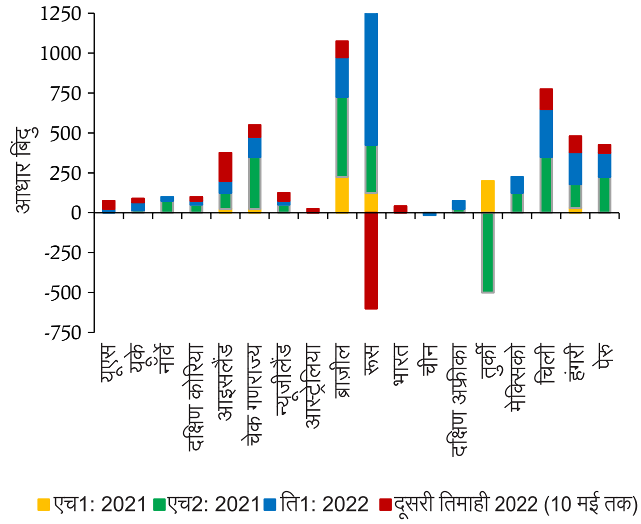

स्रोत : केंद्रीय बैंक वेबसाइट।

संक्षेप में, वैश्विक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम ों में वृद्धि हुई है, साथ ही वैश्विक मुद्रास्फीति के लिए ऊपर की ओर जोखिम कई देशों में स्टैगफ्लेशन के दृश्य को बढ़ा रहा है। ईएमई के लिए, दृष्टिकोण नाजुक है, और रोजगार और उत्पादन 2026 के माध्यम से पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे रह सकते हैं जो गहरे दाग को दर्शाता है।

III. घरेलू विकास

अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि के बावजूद गतिविधियां सामान्य होने के कारण घरेलू वृहद आर्थिक स्थितियों में मजबूती जारी रही (चार्ट 9ए)। 86 प्रतिशत से अधिक वयस्क आबादी (81 करोड़) को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और 10 मई, 2022 तक कुल टीकाकरण खुराक 190 करोड़ को पार कर गई है (चार्ट 9 बी)। 15-18 वर्ष आयु वर्ग के 4.3 करोड़ से अधिक बच्चों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि 12-14 वर्ष आयु वर्ग के 3.1 करोड़ बच्चों को पहली खुराक दी गई है। कोविड टीकों की एहतियाती खुराक उन सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और दूसरी खुराक के प्रशासन के 9 महीने पूरे कर चुके हैं।

कोविड के साथ जीना आम बात होती जा रही है। जबकि प्रारंभिक लॉकडाउन और कोविड की पहली और दूसरी लहर ने

चार्ट 9 : कोविड-19 के मामले और टीकाकरण

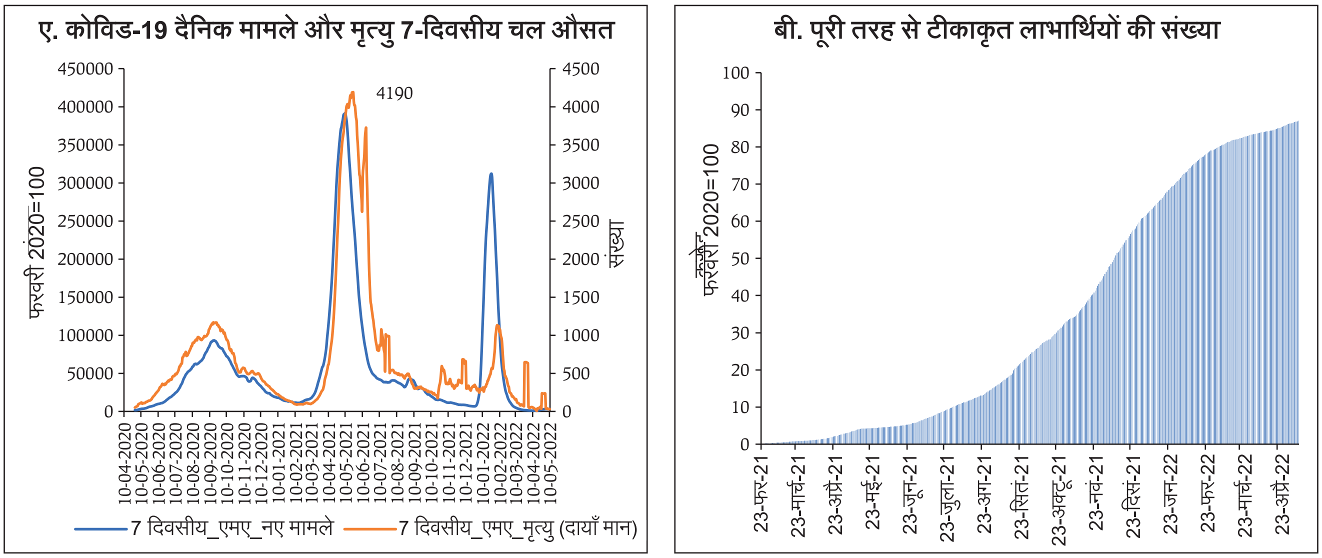

स्रोत : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डबल्यू), सीईआईसी,सीएमआईई

आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया, तीसरी लहर और संक्रमण में हालिया उछाल का समग्र आर्थिक गतिविधि पर अपेक्षाकृत सौम्य प्रभाव पड़ा है (चार्ट 10 ए)। डीकपलिंग लोगों की आवाजाही में भी दिखाई देती है, गूगल गतिशीलता अप्रैल में अधिकांश गतिविधियों के लिए बेसलाइन पूर्व-महामारी के आंकड़ों से परे बढ़ रही है। जबकि किराना, फार्मेसी और पार्कों के आसपास गतिशीलता बेसलाइन संख्या से 50 प्रतिशत से ऊपर थी, आवासीय इकाइयों के आसपास गतिशीलता बेसलाइन मीट्रिक के ठीक ऊपर मंडरा रही थी, शायद इंडिया इंक द्वारा तेजी से अपनाए गए वर्क-फ्रॉम-होम / हाइब्रिड मॉडल के कारण (चार्ट 10 बी)। इन घटनाक्रमों को प्रतिबिंबित करते हुए, राज्यों में व्यापक

चार्ट 10: आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 का प्रभाव

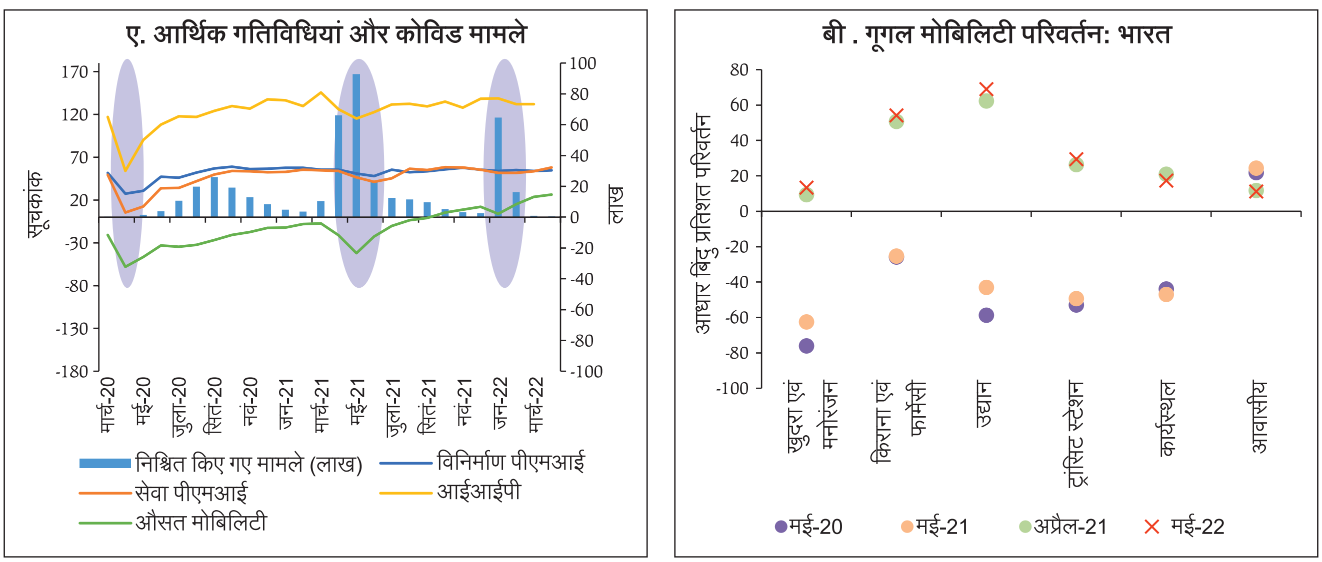

स्रोत : गूगल; आईएचएस;एमओएसपीआई; सीईआईसी

चार्ट 11 : राज्य-वार ग्राहक मत सूचकांक

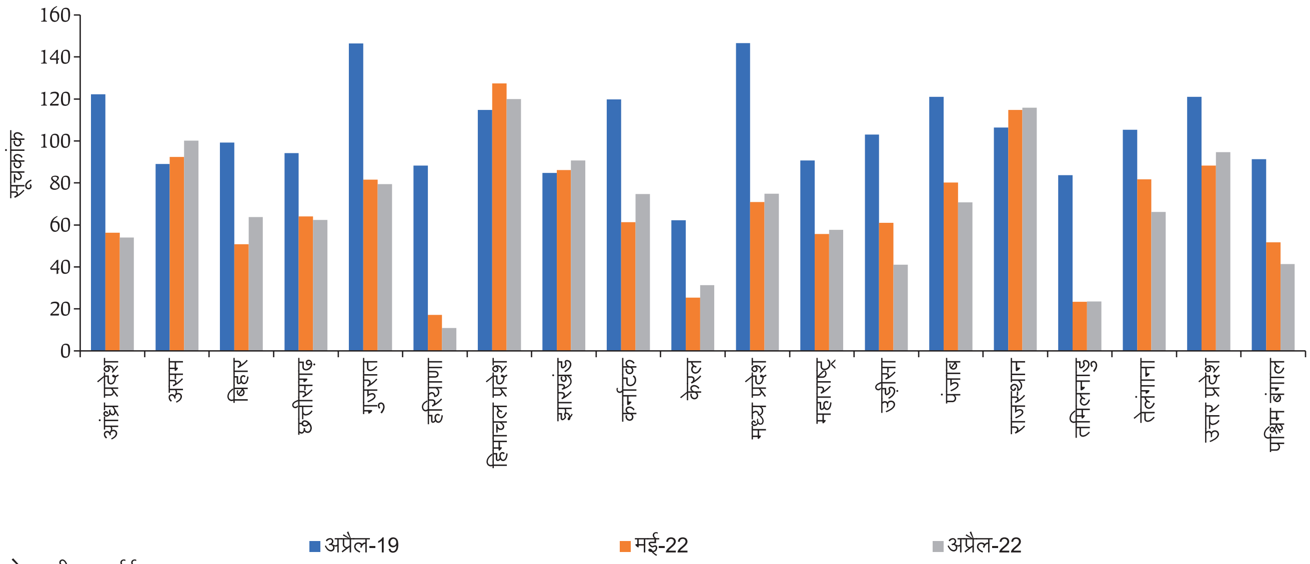

स्रोत: सीएमआईई।

विविधताओं के साथ अखिल भारतीय स्तर पर उपभोक्ता धारणा में सुधार हुआ (चार्ट 11)।

कुल मांग

समग्र मांग स्थितियों में सुधार के संकेत व्यापक हो गए। अप्रैल 2022 में कुल ई-वे बिल सृजन अप्रैल 2019 की तुलना में लगभग 43 प्रतिशत अधिक था (चार्ट 12ए)। वॉल्यूम बढ़ने के कारण टोल संग्रह में वृद्धि हुई, जबकि 1 अप्रैल, 2022 से राष्ट्रीय राजमार्ग टोल में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि से मूल्य के संदर्भ में तेजी से वृद्धि हुई (चार्ट 12 बी)।

दिनांक 22 मार्च से 16 अप्रैल के बीच लगातार कीमतों में वृद्धि से ईंधन की खपत को बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संचयी रूप से 10 रुपये

चार्ट 12 : ई-वे बिल और टोल संग्रह

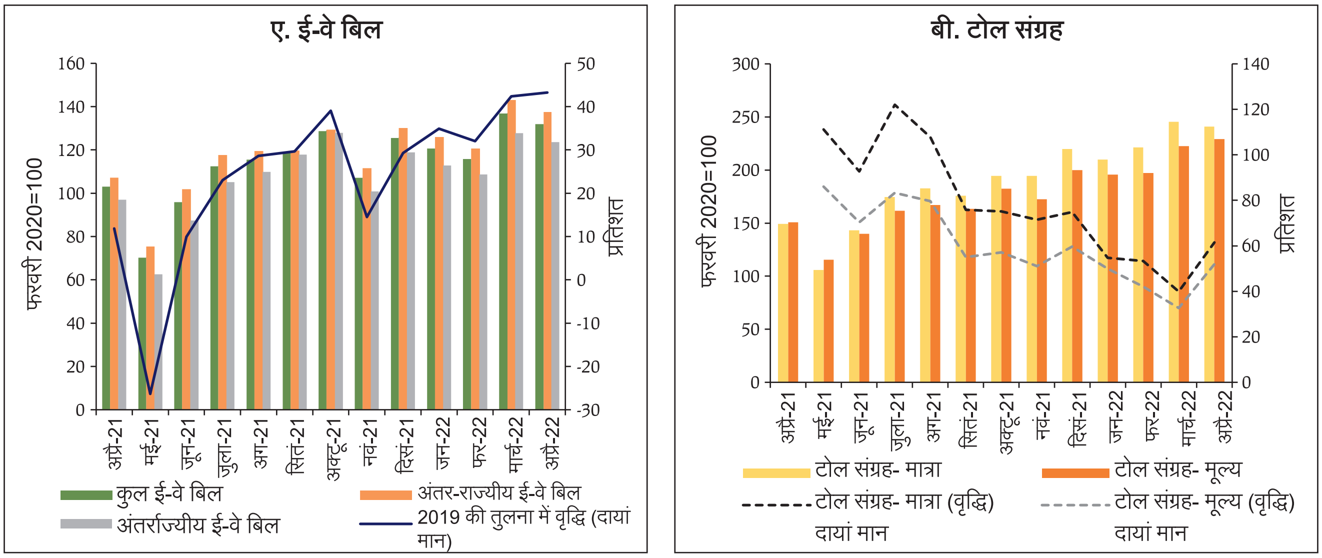

स्रोत: जीएसटीएन; भारतीय रिज़र्व बैंक; और लेखकों द्वारा स्वयं की गई गणना।

प्रति लीटर की वृद्धि हुई। ईंधन मुद्रास्फीति का प्रभाव डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) खपत की श्रेणियों में दर्ज किया गया था (चार्ट 13 ए)।

सेमीकंडक्टर की कमी, धातु की ऊंची कीमतों और चीन में लॉकडाउन ने अप्रैल 2022 में यात्री वाहनों के लिए प्रतीक्षा समय बढ़ा दिया। नतीजतन, यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री में नरमी आई, हालांकि महामारी से पहले की बेसलाइन (अप्रैल 2019 की तुलना में 1.6 प्रतिशत अधिक) पर सामान्य हो गई; चार्ट 13 बी)। वाहनों की खुदरा बिक्री स्थिर रही और परिवहन वाहनों के लिए पंजीकरण खिंच गया। अप्रैल 2019 के पूर्व-महामारी स्तरों पर, पंजीकरण में संकुचन जारी रहा (चार्ट 13 सी)। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में वाहन पंजीकरण उनके पूर्व-महामारी स्तर (चार्ट 13 डी) को पार कर गया।

चार्ट 13 : परिवहन क्षेत्र संकेतक

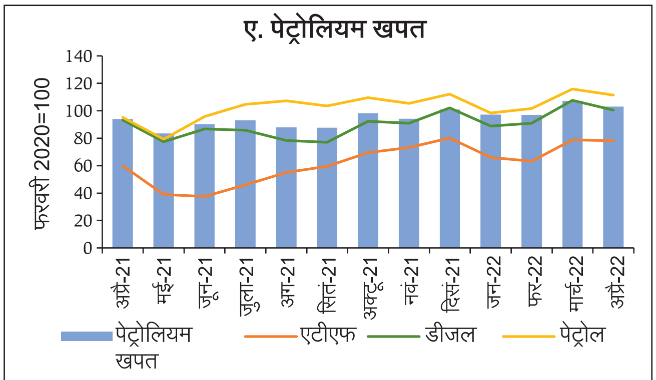

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ; और लेखकों द्वारा स्वयं की गई गणना।

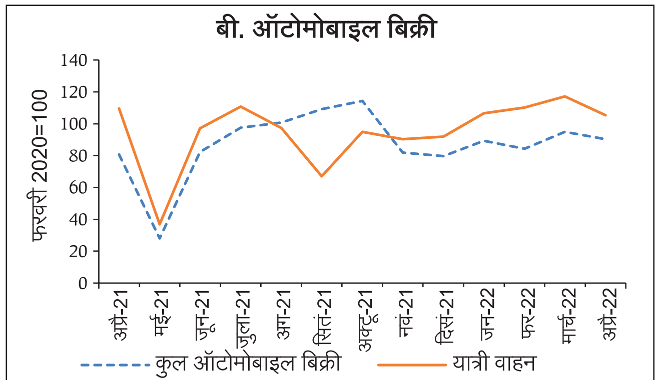

स्रोत: एसआईएएम; और लेखकों द्वारा स्वयं की गई गणना।

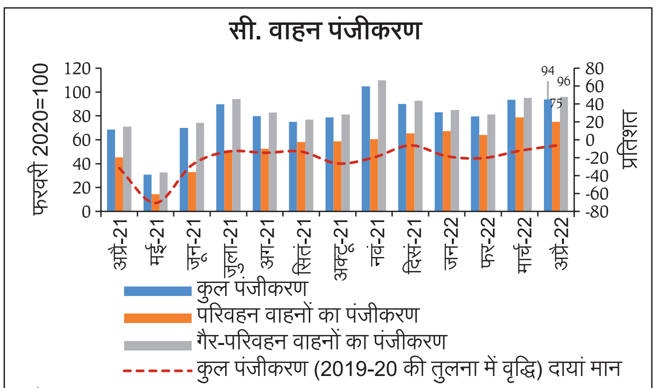

स्रोत: वाहन

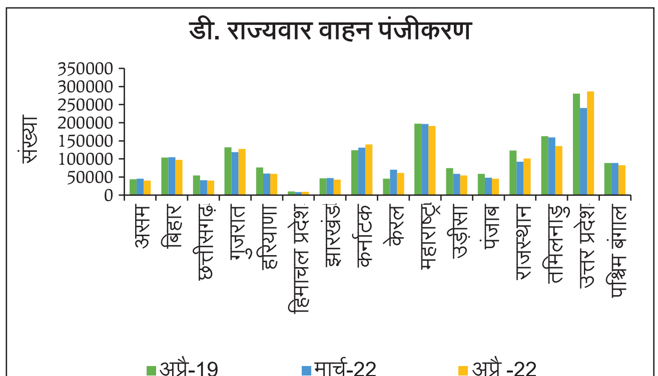

स्रोत: वाहन

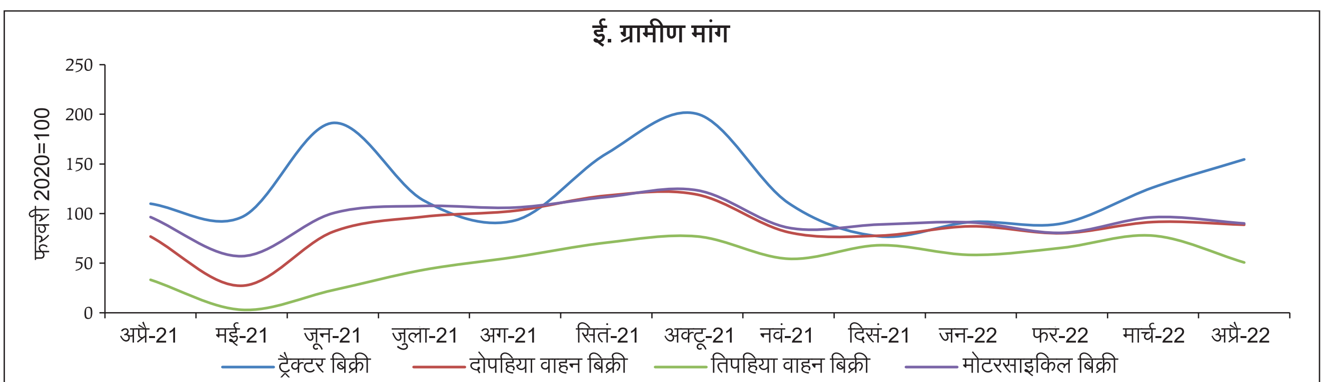

स्रोत: एसआईएएम; और टीएमए; और लेखकों द्वारा स्वयं की गई गणना।

सामान्य मानसून की उम्मीद में कृषि क्षेत्र के साथ ग्रामीण मांग मजबूत हुई, और अप्रैल 2019 की तुलना में ट्रैक्टर की बिक्री में 55.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दोपहिया और मोटरसाइकिलों की बिक्री स्थिर रही, जबकि तिपहिया वाहनों में गिरावट आई, जो सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में एक विषम वसूली का संकेत देता है (चार्ट 13 ई)।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, श्रम भागीदारी दर मार्च में 39.5 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 40.2 प्रतिशत हो गई। रोजगार दर (श्रमिक जनसंख्या अनुपात) भी अप्रैल में सुधरकर 37.1 प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 36.5 प्रतिशत थी। श्रम बल में पूरी वृद्धि, हालांकि, रोजगार में अवशोषित नहीं हुई थी, जिससे बेरोजगारी दर पिछले महीने 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट 14 ए)। यद्यपि अधिकांश राज्यों ने अपने पूर्व-महामारी स्तरों से नीचे रोजगार दर दर्ज करना जारी रखा है, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना ने अपनी पूर्व-महामारी रोजगार दर (चार्ट 14 बी) को पार करते हुए उल्लेखनीय सुधार दिखाया है।

सीएमआईई के रोजगार के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2022 में नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या में क्रमशः 7.2 मिलियन (एम-ओ-एम) और 12.2 मिलियन (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो पूर्व-महामारी स्तर (चार्ट 15 ए) को पार कर गई। पिछले महीने की तुलना में अप्रैल 2022 में अधिकांश राज्यों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में वृद्धि हुई; हालाँकि, यह अभी भी कई राज्यों में पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे है (चार्ट 15 बी)।

तीन महीने के संकुचन के बाद मार्च में विस्तार के बाद अप्रैल में विनिर्माण क्षेत्र में पीएमआई रोजगार सूचकांक में और सुधार हुआ। सेवा क्षेत्र में, लगातार चार महीनों के संकुचन के बाद अप्रैल में रोजगार विस्तार में वापस आ गया (चार्ट 16)।

चार्ट 14 : रोज़गार, बेरोज़गारी, और श्रम भागीदारी दरें

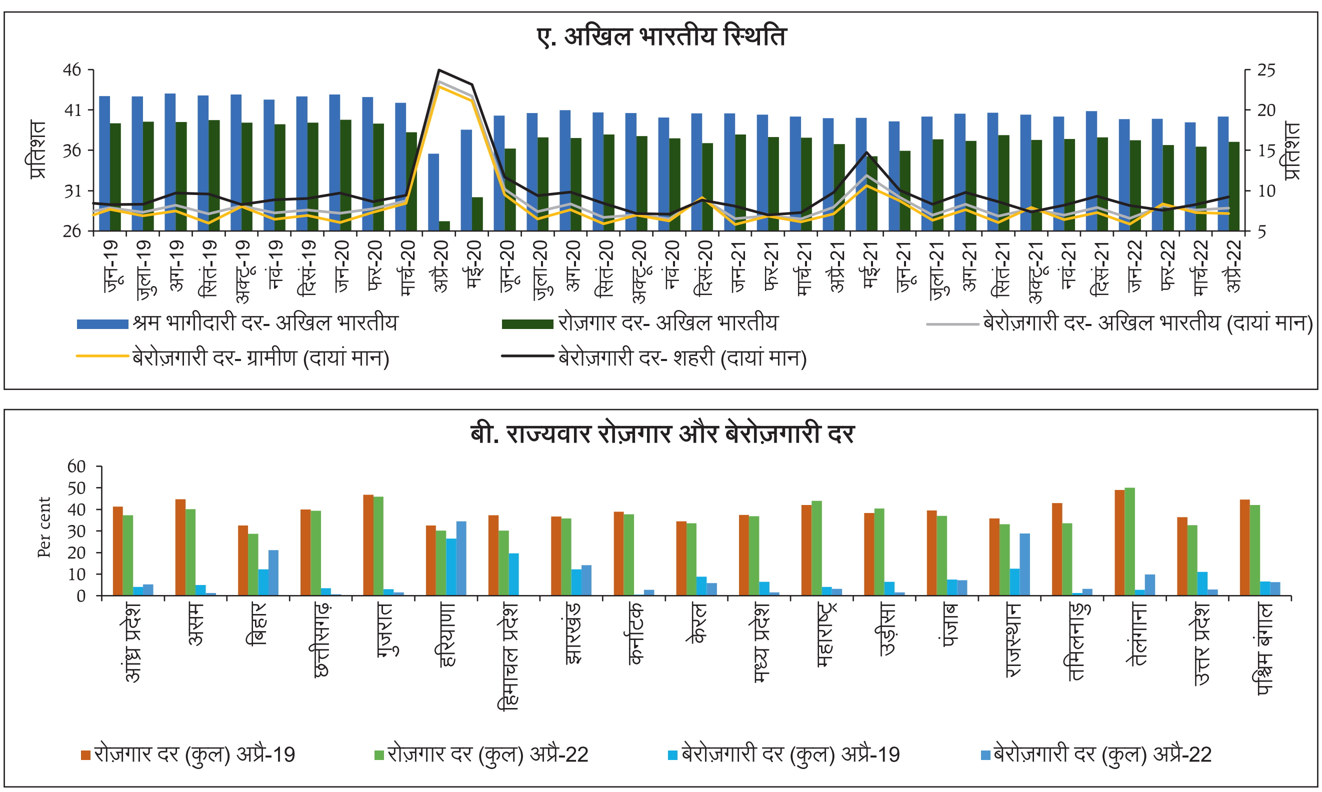

स्रोत: सीएमआईई।

चार्ट 15 : रोज़गार में श्रमिकों की संख्या और एलएफपीआर

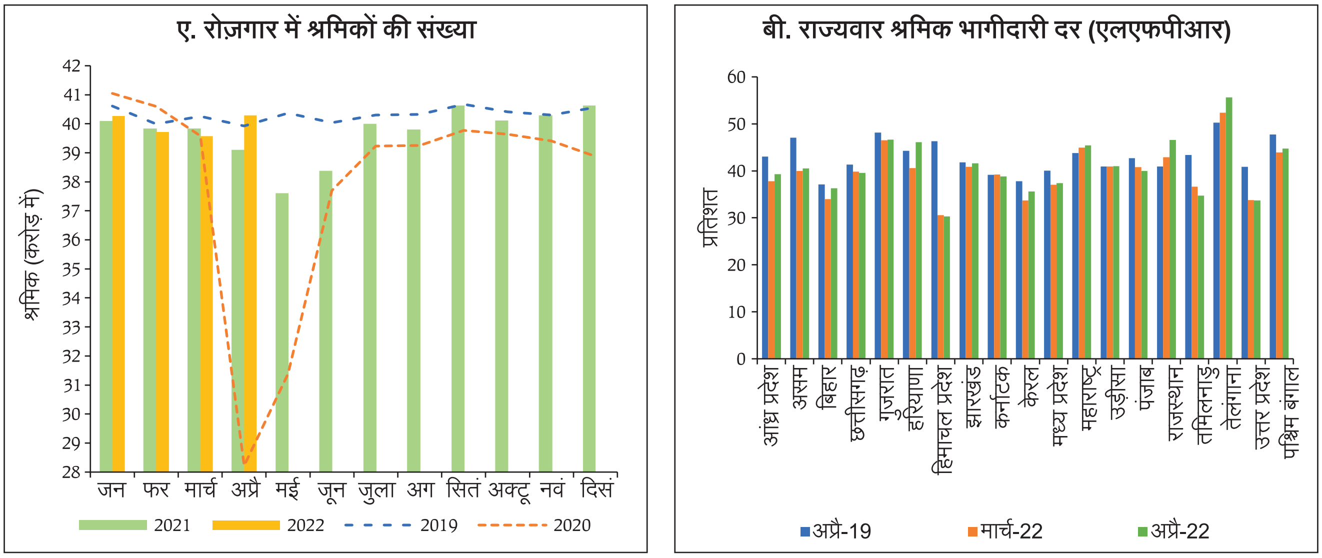

स्रोत: सीएमआईई।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 28 अप्रैल, 2022 को अपने त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) का तीसरा संस्करण जारी किया। अप्रैल और अक्टूबर 2021 के बीच, सर्वेक्षण [3] द्वारा कवर किए गए नौ संगठित क्षेत्रों [2] में कुल श्रमिकों की अनुमानित संख्या 3.08 करोड़ से बढ़कर 3.14 करोड़ हो गई। कुल रोजगार में संविदा कर्मचारियों, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों और स्व-नियोजित

चार्ट 16 : पीएमआई रोज़गार सूचकांक

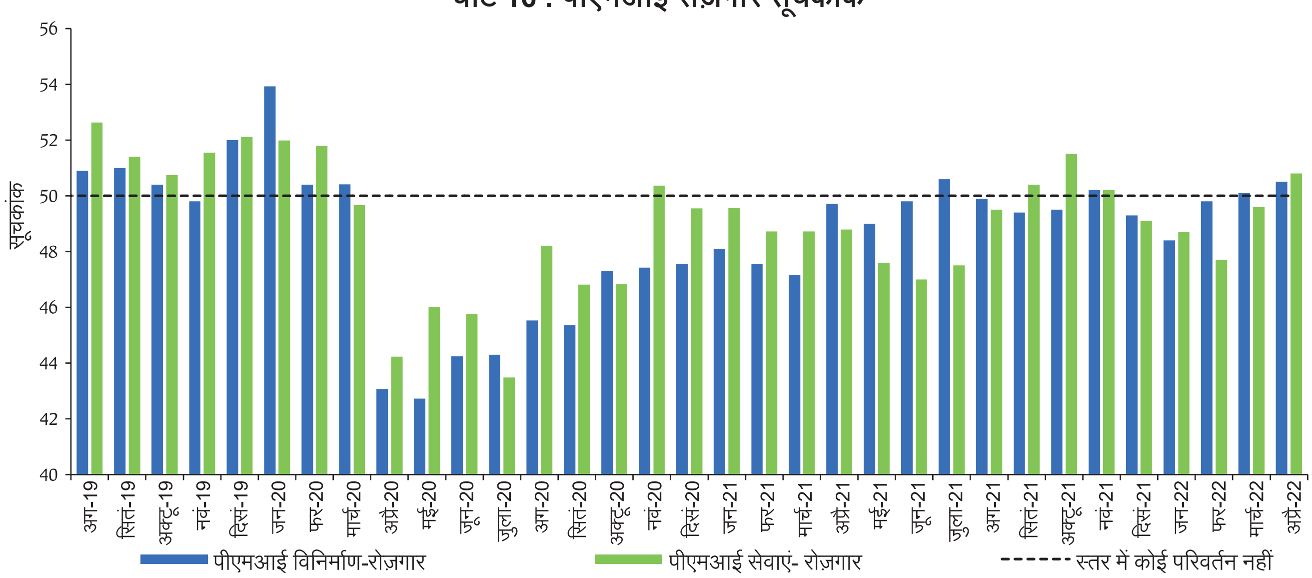

स्रोत: आईएचएस मार्किट।

[2] चयनित नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवाएं हैं।

[3] क्यूईएस का दायरा छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) द्वारा पहचाने गए 10 या अधिक श्रमिकों (संगठित खंड) को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों तक ही सीमित है और इसमें नौ क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो संगठित क्षेत्र में 85 प्रतिशत रोजगार के लिए जिम्मेदार हैं।

चार्ट 17: रोजगार की शर्तों के अनुसार श्रमिक वितरण

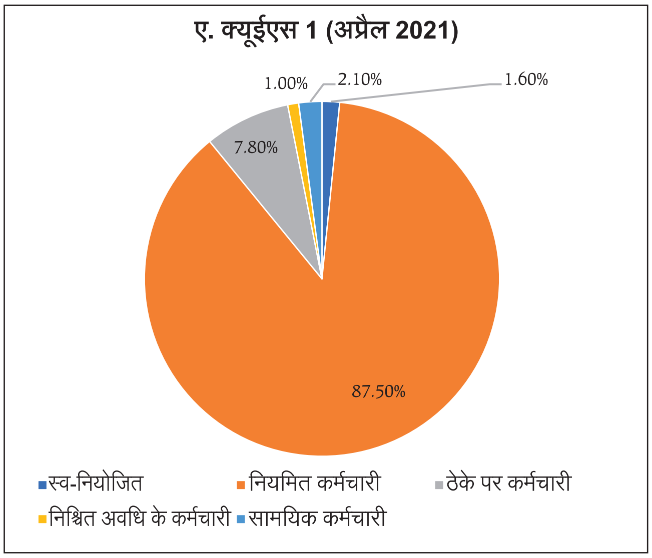

स्रोत: श्रम और रोजगार मंत्रालय।

कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि नियमित श्रमिकों की हिस्सेदारी 87.5 प्रतिशत से घटकर 85.3 प्रतिशत हो गई है (चार्ट 17)।

बाह्य मोर्चे पर, अप्रैल 2022 में भारत का वाणिज्यिक निर्यात 40.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो साल-दर-साल आधार पर 30.7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज करता रहा (चार्ट 18)। निर्यात वृद्धि व्यापक आधार पर थी, क्योंकि निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले 10 प्रमुख कमोडिटी समूहों में से 8 में साल-दर-साल आधार पर वृद्धि हुई। निर्यात प्रदर्शन में सुधार पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग सामानों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के शिपमेंट के उच्च मूल्य से उपजा है (चार्ट 19)। हालांकि

चार्ट 18: भारत का पण्य वस्तु निर्यात – अप्रैल 2022

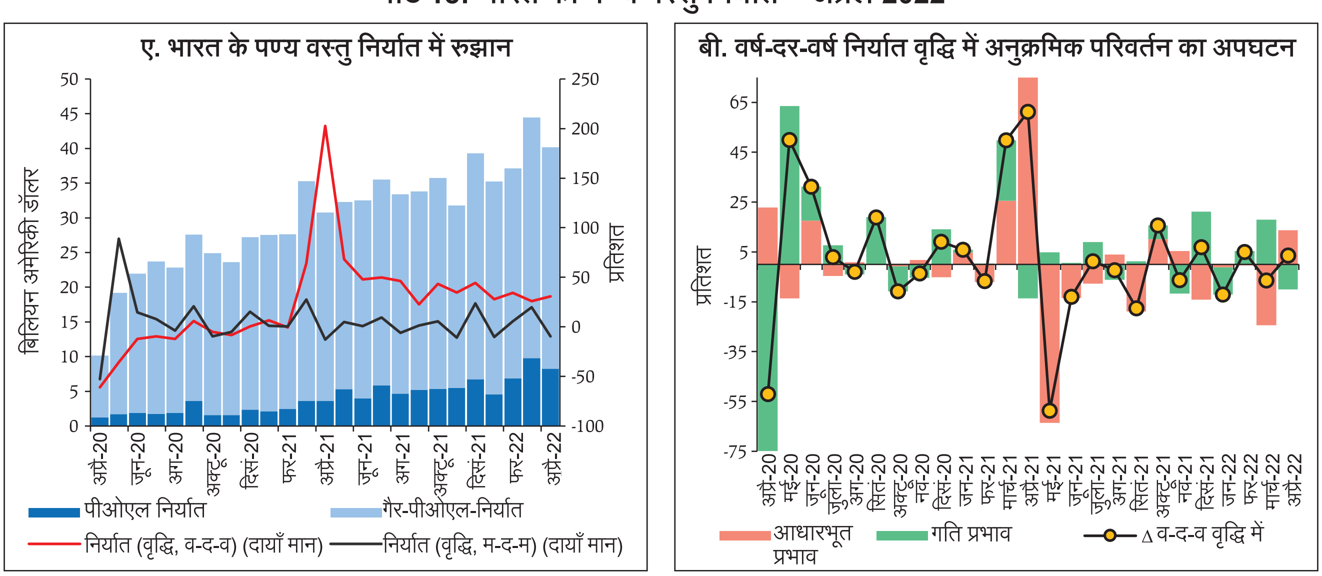

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; और लेखकों की अपनी गणना।

चार्ट 19: निर्यात वृद्धि में सापेक्ष योगदान

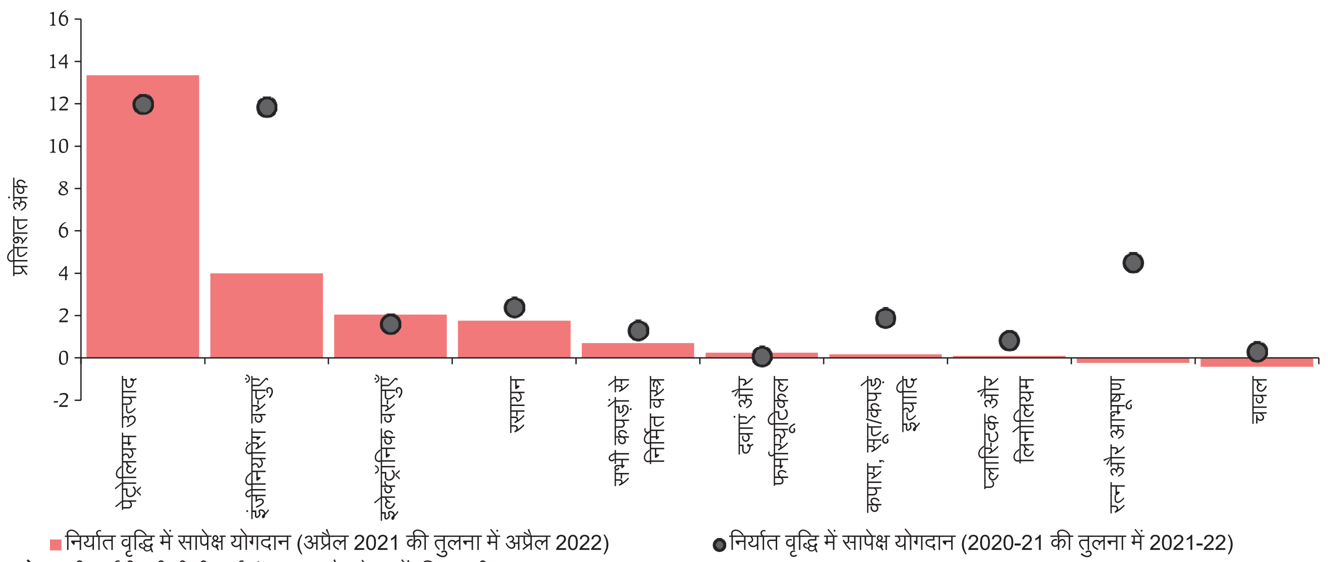

स्रोत : पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; और लेखकों की अपनी गणना।

क्रमिक आधार पर सभी प्रमुख निर्यात खंडों में वाणिज्यिक निर्यात में संकुचन देखा गया।

वर्ष 2022 में, भारत सरकार एक खुली सामान्य निर्यात लाइसेंस नीति शुरू करने, सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को लॉन्च करने और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु [4] में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना जैसी नीतियों के माध्यम से रक्षा निर्यात पर विशेष जोर दे रही है। दुनिया का सैन्य व्यय 2021 में पहली बार 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका था (चार्ट 20)। पिछले पांच वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात भी दोगुने से अधिक हो गया है।

भारतीय निर्यातक चाय और परिधान निर्यात में वैश्विक आपूर्ति अंतर को भरने के अवसर का भी लाभ उठा रहे हैं क्योंकि श्रीलंका से आपूर्ति चल रहे आर्थिक संकट से प्रभावित है। श्रीलंका की अपने निर्यात-गहन क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं और इनपुट के लिए भारत पर बढ़ती आयात निर्भरता को भारत से समर्थन मिल रहा है (चार्ट 21)।

अप्रैल 2022 में लगातार 8वें महीने 60.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वाणिज्यिक आयात 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा (चार्ट 22)।

चार्ट 20: वैश्विक सैन्य व्यय

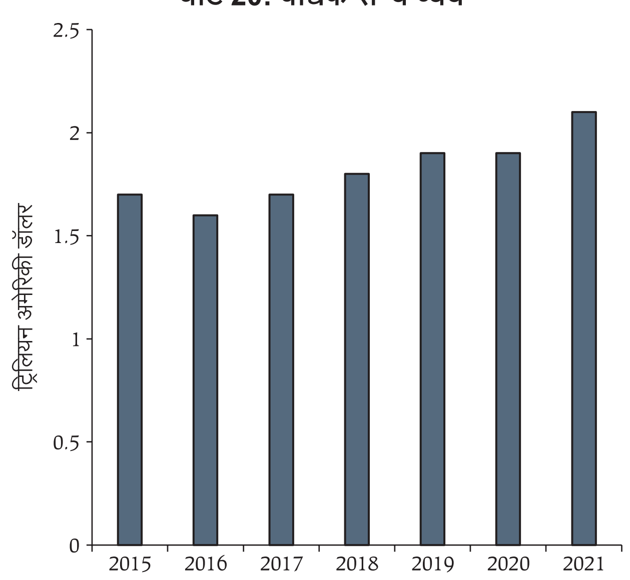

स्रोत: एसआईपीआरआई; और आईटीसी व्यापार मानचित्र।

[4] https://www.makeinindia.com/defence-industrial-corridors-india

चार्ट 21: भारत पर श्रीलंका की आयात निर्भरता

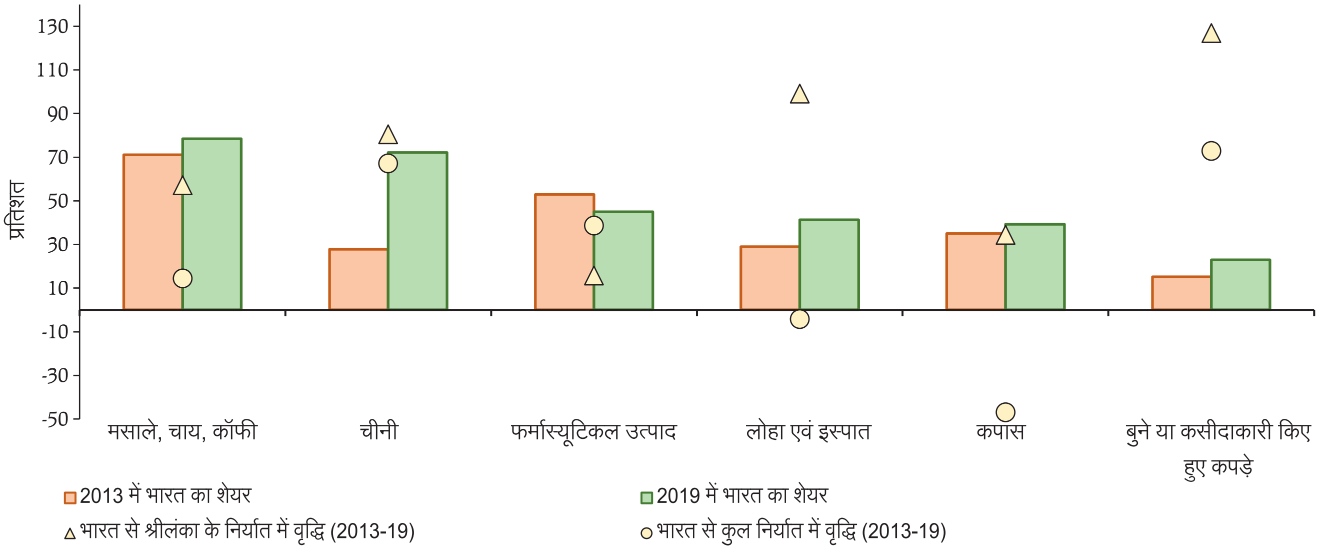

स्रोत: आईटीसी व्यापार मानचित्र।

आयात वृद्धि व्यापक आधार पर थी, क्योंकि 75 प्रतिशत से अधिक आयात के लिए जिम्मेदार 10 प्रमुख कमोडिटी समूहों में से 9 ने साल-दर-साल आधार पर वृद्धि दर्ज की। मजबूत आयात मांग पेट्रोलियम उत्पादों[5], कोयला, कोक, ब्रिकेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान (चार्ट 23) द्वारा संचालित थी।

वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल के परिणामस्वरूप कोयले के आयात में मात्रा के संदर्भ में गिरावट आई (चार्ट 24 ए)। ऊर्जा संकट ने रूस-यूक्रेन युद्ध (चार्ट 24 बी) द्वारा विश्व स्तर पर कोयले की कीमतों में एक अभूतपूर्व रैली का नेतृत्व किया है। मूल्य के लिहाज से कोयले का आयात अप्रैल 2022 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दोगुने से अधिक हो गया।

चार्ट 22: भारत का पण्य वस्तु आयात - अप्रैल 2022

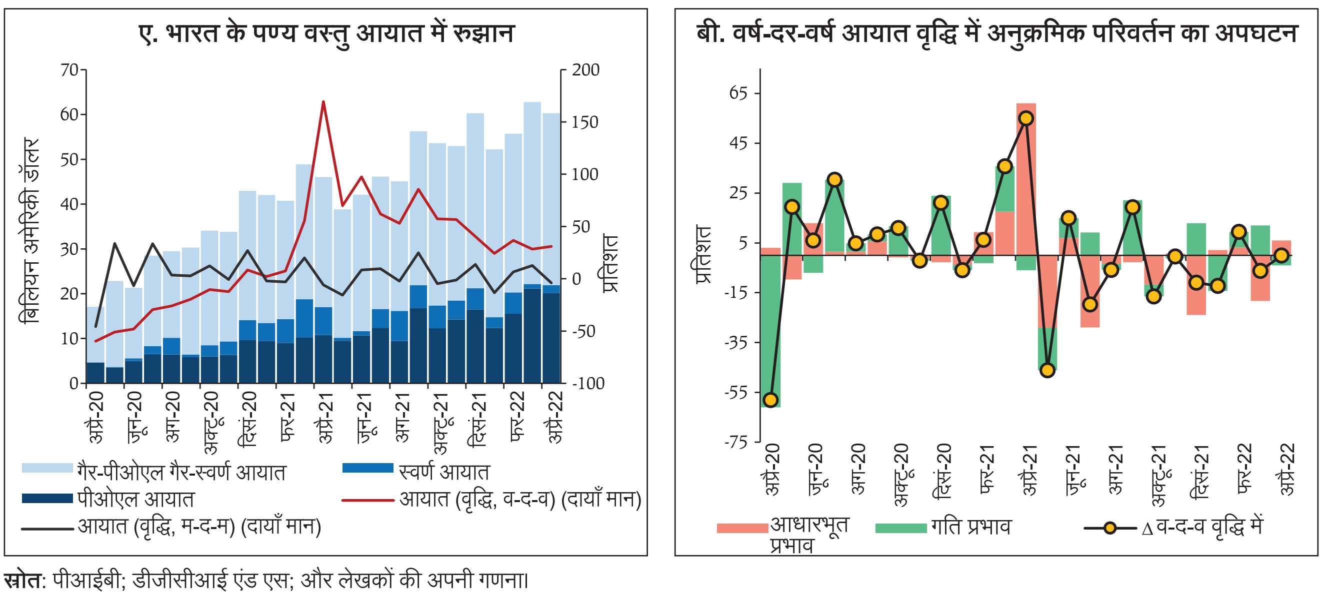

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; और लेखकों की अपनी गणना।

[5] एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटी इंटेलिजेंस फर्म / केप्लर के अनुसार, अप्रैल 2022 में भारत का रूसी यूराल क्रूड का आयात बढ़कर 6.3 मिलियन बैरल / दिन हो गया, जो मार्च 2022 में 2.7 मिलियन बैरल / दिन था, जिससे कच्चे तेल की कीमतों (भारतीय टोकरी) में क्रमिक मॉडरेशन हुआ। अप्रैल 2022.

चार्ट 23: आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान

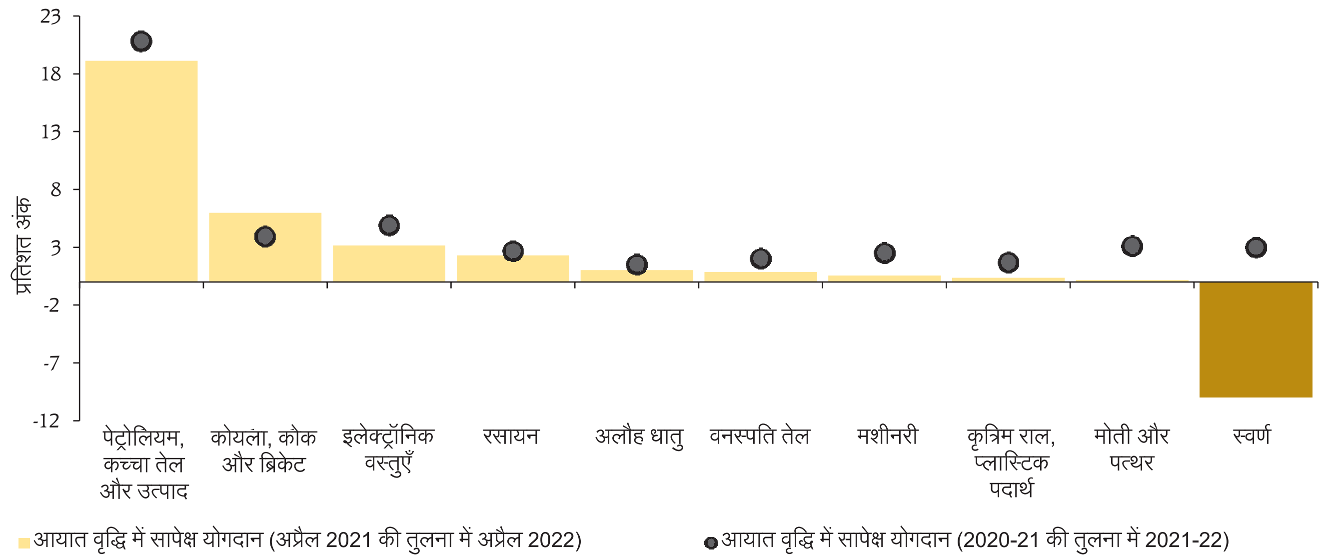

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; और लेखकों की अपनी गणना।

अप्रैल 2022 में वनस्पति तेलों के आयात में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। शीर्ष वनस्पति तेल उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सूरजमुखी जैसे क्षेत्रों में मांग-आपूर्ति के अंतर और ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के इंडोनेशिया के फैसले ने वनस्पति तेलों की उच्च कीमतों को जन्म दिया है। वनस्पति तेल खंड में कुल आयात में पाम तेल का योगदान आधे से अधिक है। इंडोनेशिया भारत के खाद्य तेल आयात के आधे से अधिक की आपूर्ति करता है (चार्ट 25)। हालांकि, भारत के पास पर्याप्त खाद्य तेल भंडार है – लगभग 21 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) – और

चार्ट 24: भारत का कोयला आयात और इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव

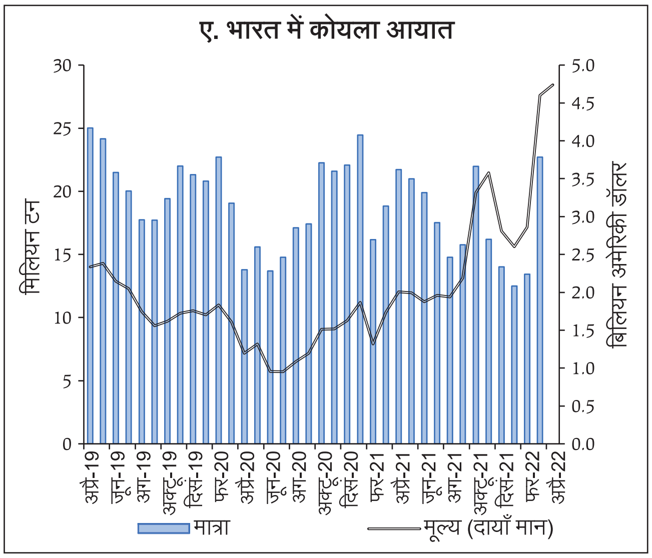

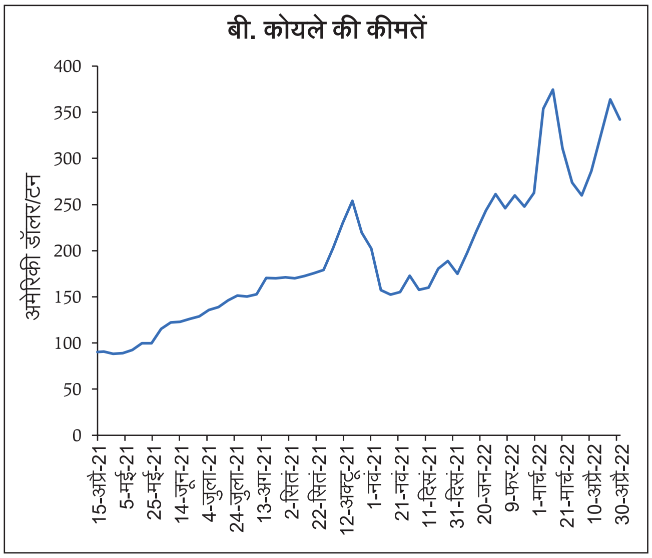

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस।

चार्ट 25: ताड़ के तेल का आयात और उसके स्रोत

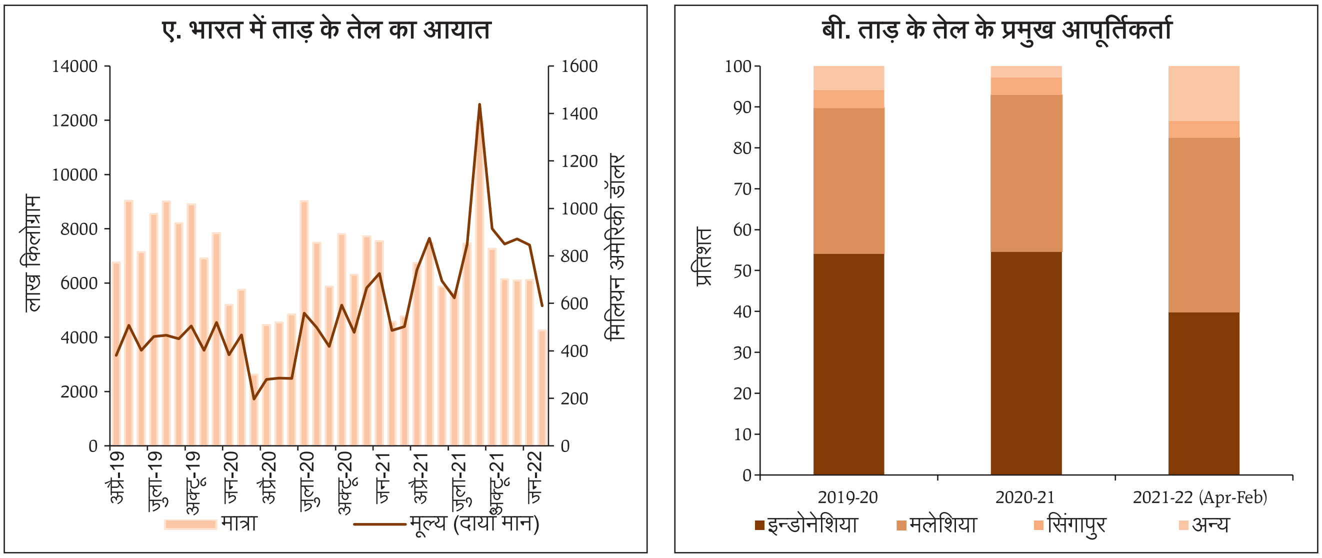

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस।

पारगमन में लगभग 12 एलएमटी मई 2022 में आने वाले लीन अवधि को कवर करने के लिए।[6]

अप्रैल 2022 में भारत का वाणिज्यिक व्यापार घाटा 20.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार (15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के साथ-साथ क्रमिक आधार (18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर बढ़ा।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से 25 राज्यों के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य अप्रैल-फरवरी 2021-22 के दौरान अपनी प्राप्तियों और व्यय में वृद्धि की गति को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं (चार्ट 26)। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत परिव्यय ने 2019-20 (महामारी से पहले के वर्ष) की तुलना में 2021-22 में उच्च वृद्धि दर्ज की, जो उनके वित्त में तेजी से सुधार का संकेत देता है।

केंद्रीय बजट 2022-23 में, केंद्र ने राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) पर 4 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों की दिशा में उनके प्रयासों से जुड़ा हुआ है। 20 राज्यों के नवीनतम बजट के अनुसार, वे अपने जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 2021-22 (संशोधित अनुमान) में 3.7 प्रतिशत से घटाकर 2022-23 (बजट अनुमान) में 3.2 प्रतिशत कर सकते हैं। जीएफडी में कमी उच्च राजस्व संग्रह और कम राजस्व व्यय से उत्पन्न हो रही है। राज्यों ने 2022-23 (बजट अनुमान) में राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय में उच्च वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास संभावनाओं के लिए अच्छा संकेत है और राज्यों के व्यय की गुणवत्ता में सुधार करता है।

चार्ट 26: राज्यों का राजस्व और व्यय (अप्रैल-फरवरी 2021-22)

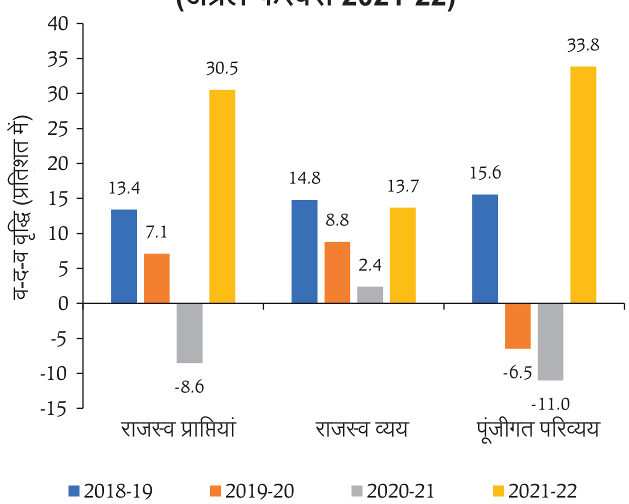

टिप्पणी: डेटा 25 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक।

6 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1821727

पूंजीगत व्यय

कुल आपूर्ति

सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) के आधिकारिक पूर्वानुमान और केंद्र सरकार द्वारा घोषित गैर-यूरिया उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्र आगामी खरीफ सीजन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। प्रत्याशा में, 19 अप्रैल, 2022 को आयोजित खरीफ अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन ने 2022-23 के दौरान 328 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ग्रीष्मकालीन या जैद फसल7 ने 13 मई, 2022 तक 73.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया है, जो एक साल पहले की तुलना में 5.4 प्रतिशत अधिक है, जो दलहन के तहत काफी अधिक रकबा के कारण है (चार्ट 27 ए)। 12 मई, 2022 को 140 प्रमुख जलाशयों में कुल संग्रहण पिछले वर्ष के दौरान 31 प्रतिशत और दशकीय औसत 26 प्रतिशत की तुलना में पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) का 33 प्रतिशत अधिक था (चार्ट 27बी)।

मार्च और अप्रैल के दौरान भारत के उत्तर-पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में लू की स्थिति बनी रही, जिससे आजीविका और आर्थिक गतिविधि के लिए जोखिम पैदा हो गया। मार्च 2022 के दौरान देश में दर्ज औसत अधिकतम तापमान पिछले 122 वर्षों (1901-2022) में सबसे अधिक 33.10 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह, अप्रैल में दर्ज औसत अधिकतम तापमान 1901 के बाद से 35.30 डिग्री सेल्सियस पर तीसरा सबसे अधिक था (चार्ट 28)। गेहूं की कटाई से पहले बेहद शुष्क और गर्म मौसम द्वारा चिह्नित शुरुआती गर्मियों के परिणामस्वरूप 'टर्मिनल हीट स्ट्रेस' नामक एक स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने फसलों को मुरझा दिया है और विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सूखे अनाज का कारण बना है।

रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 के दौरान अब तक (अप्रैल 2022 से) गेहूं की खरीद कम रही है, जो पैदावार में नुकसान, निजी व्यापारियों की खरीद, कृषि थोक बाजारों (मंडियों) में बेचने वाले किसानों और मिस्र, तुर्की और अन्य अफ्रीकी देशों से मजबूत निर्यात मांग को पूरा करने के लिए फार्मगेट बिक्री को दर्शाता है। 12 मई, 2022 तक खरीद 17.9 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी) है, जो पिछले साल की 35.4 मिलियन मीट्रिक टन की

चार्ट 27: बुवाई और जलाशय के स्तर की प्रगति

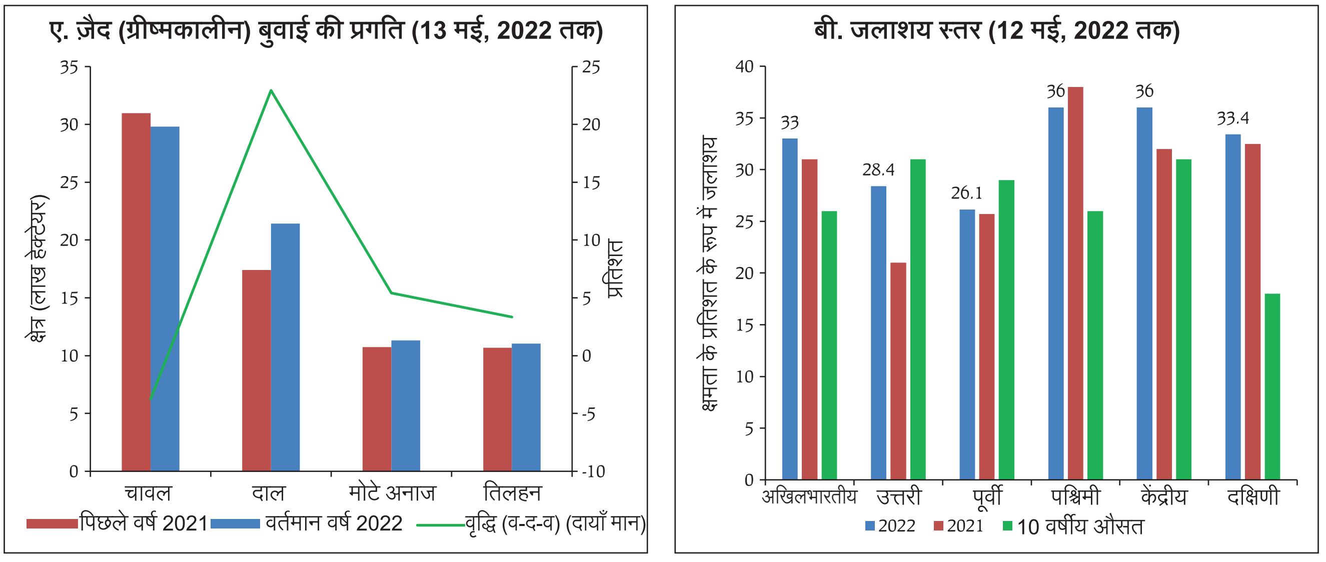

स्रोत: एमओए एंड एफडब्ल्यू, केंद्रीय जल आयोग।

7 फसलें जो मुख्य रूप से मार्च और मई के बीच बोई जाती हैं।

चार्ट 28: मार्च और अप्रैल के दौरान अखिल भारतीय अधिकतम तापमान और रैंकिंग

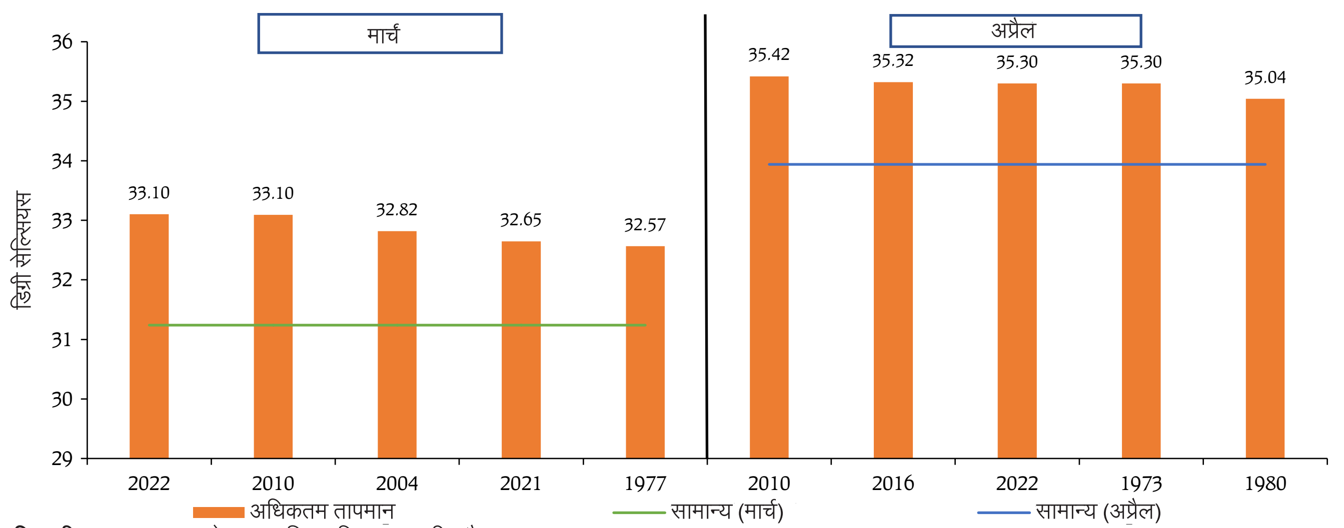

टिप्पणी: सामान्य 1981 से 2010 की अवधि पर आधारित है।

स्रोत: आईएमडी।

खरीद से 49.3 प्रतिशत कम है। हालांकि, खरीद कार्यों से 20,150 रुपये प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 36,208 करोड़ रुपये के अनुमानित बहिर्वाह के साथ 16.83 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय पूल के तहत कम गेहूं की खरीद और एमएसपी की तुलना में उच्च बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने 13 मई को पड़ोसी / खाद्य-घाटे वाले देशों से अपरिवर्तनीय साख पत्र और अनुरोधों को छोड़कर गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया (चार्ट 29)।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के 99 प्रतिशत (दीर्घावधि औसत (एलपीए) का ± 5 प्रतिशत) पर सामान्य वर्षा की भविष्यवाणी के साथ, सोयाबीन और मक्का को छोड़कर *खरीफ* फसलों के लिए बीज की पर्याप्त उपलब्धता से उत्पादन की

चार्ट 29: अखिल भारतीय बाजार में आमद और गेहूं की कीमतें

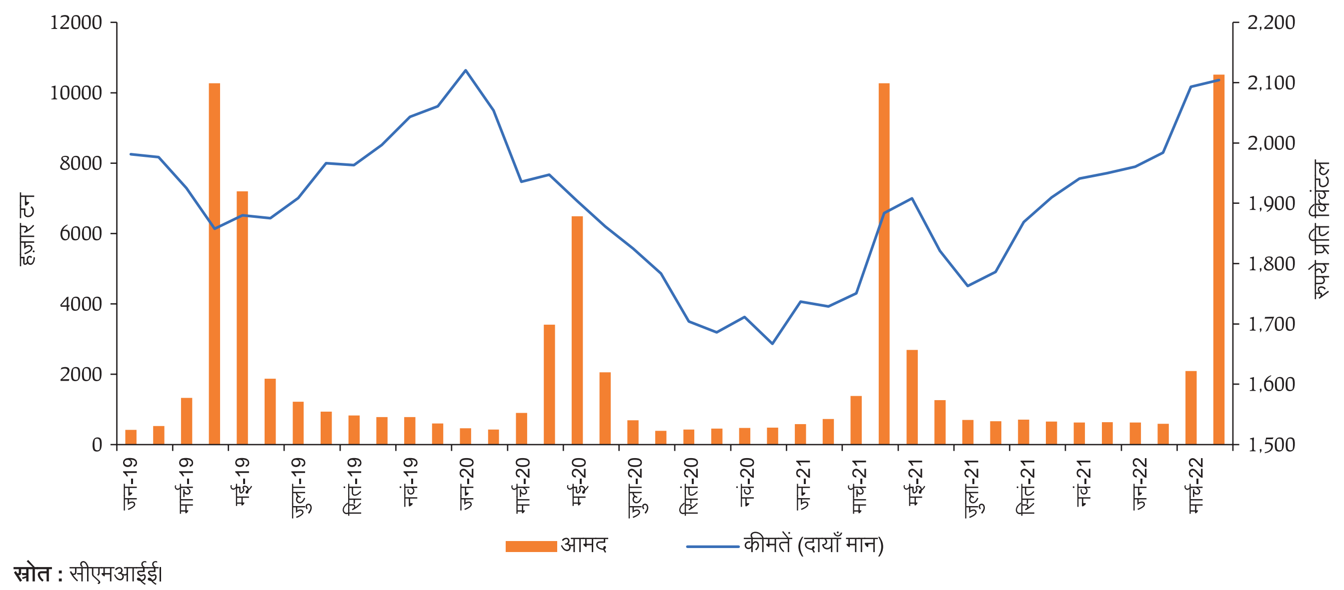

स्रोत : सीएमआईई।

चार्ट 30: फसल की स्थिति

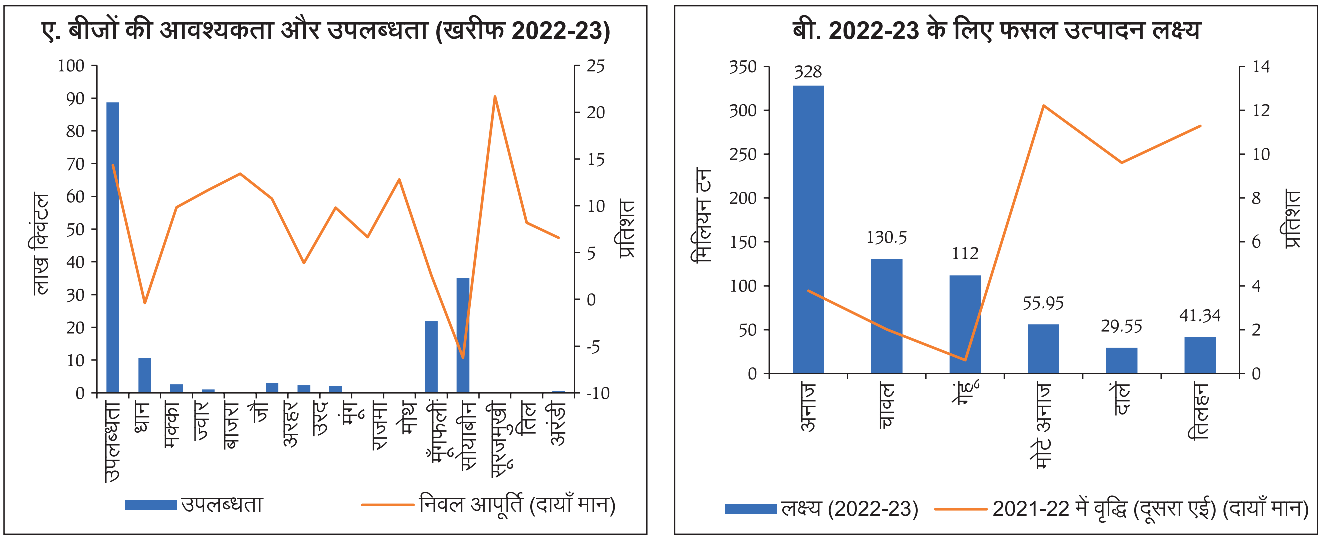

टिप्पणी: निवल आपूर्ति उपलब्धता के प्रतिशत के रूप में उपलब्धता और आवश्यकता के बीच का अंतर है।
स्रोत: कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन (खरीफ अभियान-2022)।

संभावनाएं उज्ज्वल हैं (चार्ट 30ए)। संयोग से, एसडब्ल्यूएम के लिए एलपीए (या सामान्य) वर्षा को भी 1971-2020 की अवधि के लिए 868.6 मिमी में संशोधित किया गया है, जो पहले के एलपीए (1961-2010 के लिए 880.6 मिमी) से 12.0 मिमी कम है। मोटे अनाज, दलहन और तिलहन का उत्पादन लक्ष्य 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान (चार्ट 30बी) की तुलना में क्रमशः 12 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 11 प्रतिशत अधिक है।

औद्योगिक क्षेत्र में, हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अप्रैल में एक महीने पहले के 54.0 से बढ़कर 54.7 हो गया, क्योंकि आउटपुट और नए ऑर्डर में बढ़ोतरी हुई। भू-राजनीतिक तनाव वाले क्षेत्रों के आसपास अनिश्चितता कम होने के बावजूद फ्यूचर आउटपुट इंडेक्स बढ़कर 54.3 हो गया, भले ही यह अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे रहा। अप्रैल में पीएमआई सेवाएं भी मार्च में 53.6 से बढ़कर 57.9 हो गई, जिसमें नवंबर 2021 के बाद से सबसे मजबूत विस्तार दर्ज कर रही है। सेवाओं के लिए कारोबार प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई) एक महीने पहले 53.7 से अप्रैल 2022 में 51.9 तक कमजोर हो गया, मुद्रास्फीति की चिंताओं के साथ प्रत्याशाएँ कम रही (चार्ट 31)।

कोविड-19 की तीसरी लहर के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार ने अप्रैल में बिजली उत्पादन को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया, जो एक महीने पहले दर्ज किए गए स्तरों पर बना रहा और पूर्व-महामारी के स्तर (चार्ट 32ए) को पार कर गया। देश में बढ़ते तापमान और गर्मी की लहरों ने बिजली की मांग को और बढ़ा दिया। इसने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बढ़ी हुई मांग को पूरा करने का दबाव डाला है, जिससे दैनिक अधिकतम कमी में वृद्धि हुई है (चार्ट 32 बी)। बिजली की कमी ने औद्योगिक उपभोक्ताओं और डिस्कॉम को भी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) (भारत का ऊर्जा व्यापार मंच) से बिजली खरीदने के लिए मजबूर किया है, जिससे एक्सचेंज पर बिजली की हाजिर कीमत बढ़ गई है (चार्ट 32 सी)। लेकिन बिजली की अधिकतम कमी और मई 2022 के दूसरे सप्ताह में बिजली की हाजिर कीमतों में नरमी के साथ स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की कमी से बिजली की कमी और बढ़ गई थी। कोयला स्टॉक (एक सप्ताह या उससे कम) के महत्वपूर्ण स्तर वाले थर्मल पावर प्लांटों की संख्या एक साल पहले के 32 से बढ़कर 11 मई 2022 तक 104 हो गई। आम तौर पर, कोयले की घरेलू कमी की पूर्ति आयातित कोयले से होती है, लेकिन चल रहे भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति व्यवधानों के बीच, कोयले का आयात अपेक्षाकृत कम रहा है। चूंकि बिजली उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई ईंधन के रूप में कोयले पर निर्भर करता है, इसलिए कोयले की आपूर्ति में कोई भी व्यवधान

चार्ट 31: क्रय प्रबंधकों का सूचकांक

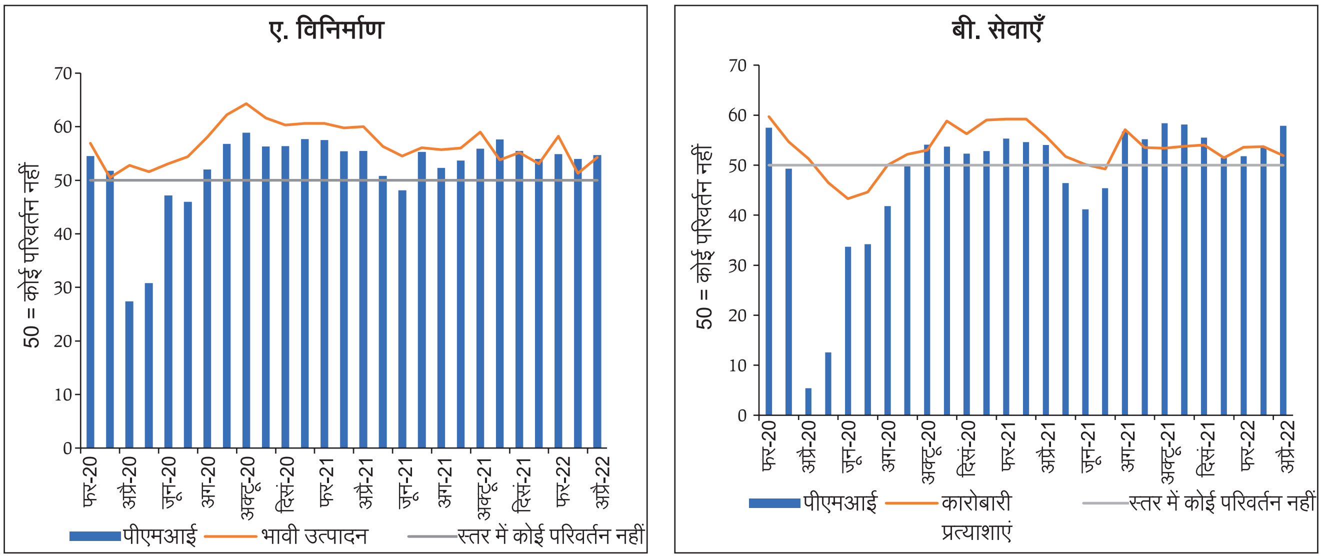

स्रोत: आईएचएस मार्किट।

का असर बिजली की आपूर्ति पर पड़ता है। यह आपूर्ति नेटवर्क में सुधार और अतिरिक्त क्षमता बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सेवा क्षेत्र में, उच्च आधार के बावजूद अप्रैल 2022 में रेलवे माल ढुलाई में 9.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ परिवहन संकेतकों में सुधार हुआ (चार्ट 33ए)। उच्च आधार पर

चार्ट 32: विद्युत उत्पादन, विद्युत की कमी और हाजिर कीमतें

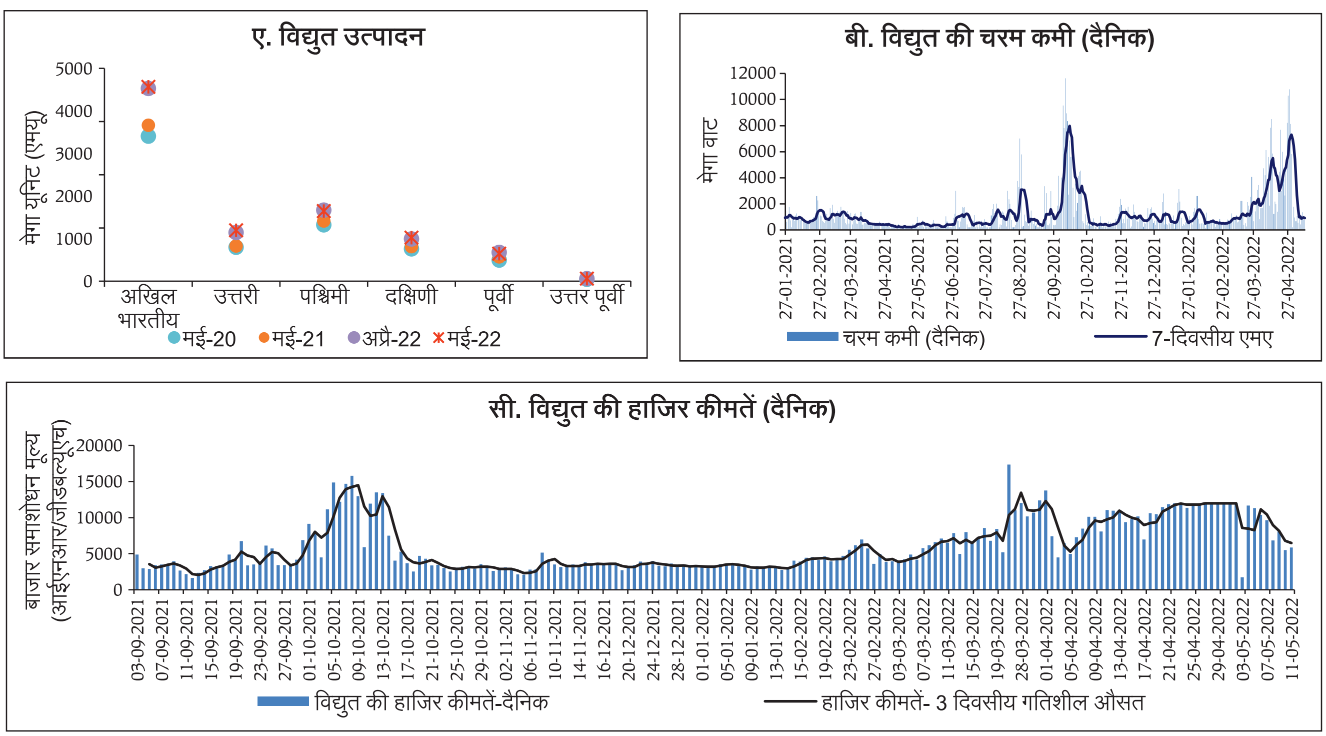

स्रोत: पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड; और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज।

चार्ट 33: रेलवे और कार्गो यातायात

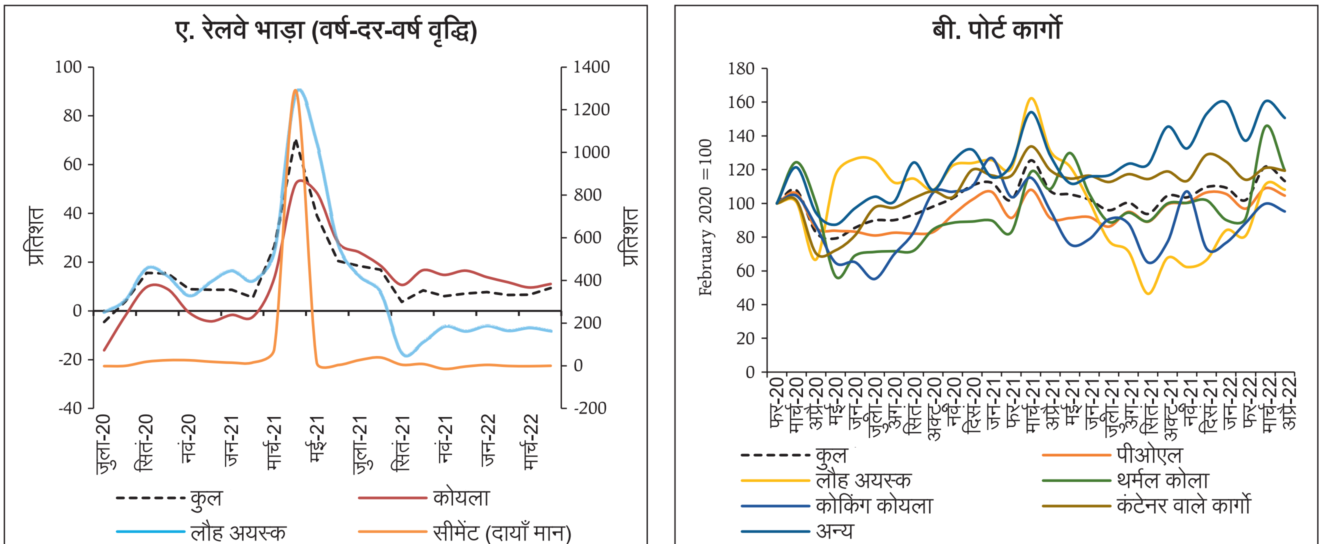

स्रोत : रेल दृष्टि। **स्रोत :** इंडियन पोर्ट एसोशिएशन।

लौह अयस्क और सीमेंट में गिरावट के बावजूद कोयले के भाड़े में भी वृद्धि दर्ज की गई। प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो ने अप्रैल में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसमें सभी वस्तुओं में कमी के कारण पिछले महीने की तुलना में मात्रा में कुछ कमी आई (चार्ट 33बी)।

सेवा क्षेत्र के फिर से खुलने के साथ, मार्च 2022 में होटल अधिभोग दर में सुधार हुआ, जो महामारी के प्रकोप के बाद से अपने उच्चतम स्तर को दर्ज कर रहा है। औसत कमरे की दर और प्रति उपलब्ध कमरे के राजस्व में वृद्धि हुई, हालांकि दोनों पूर्व-महामारी औसत से नीचे रहे (चार्ट 34)।

चार्ट 34: होटल उद्योग सांख्यिकी

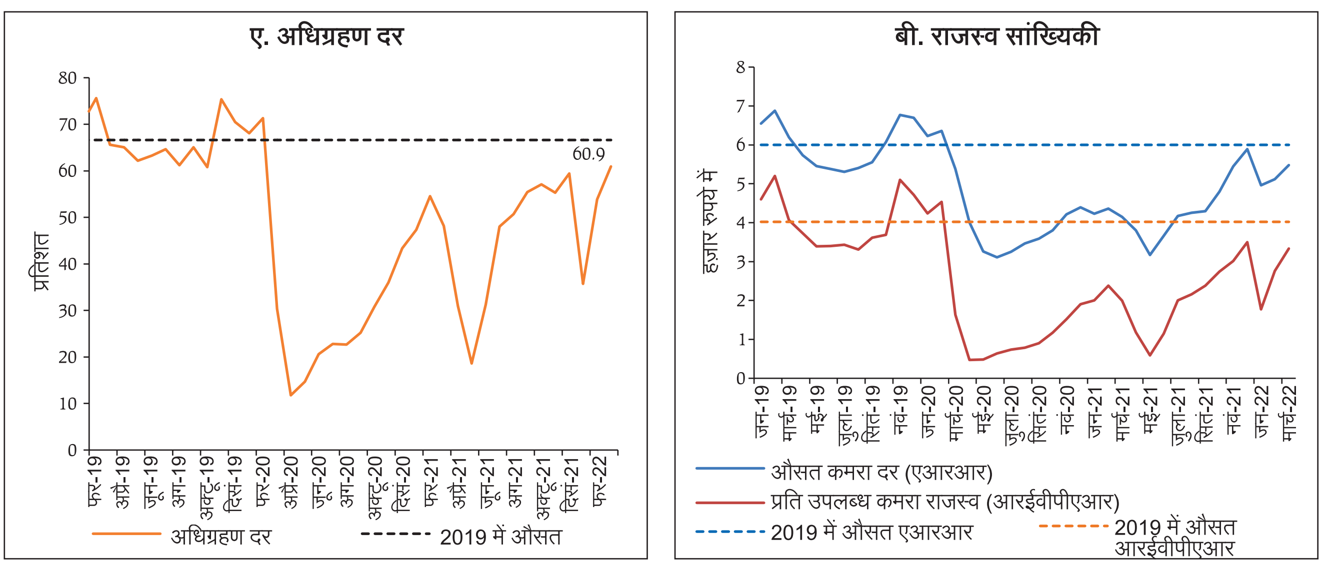

स्रोत: एचवीएस एनारॉक।

चार्ट 35: निर्माण क्षेत्र संकेतक

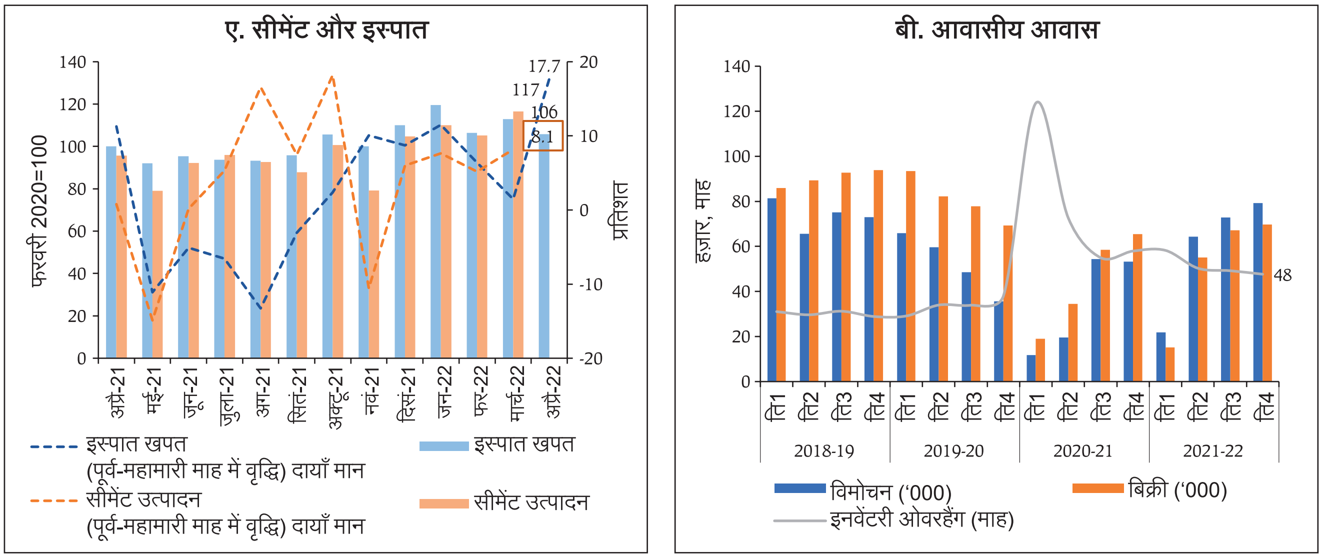

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; और प्रॉपटाइगर।

निर्माण क्षेत्र में गतिविधि मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान तेज हुई, जिसमें महामारी से पहले के महीने में सीमेंट उत्पादन और स्टील की खपत में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 35ए)[8]। वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में नए लॉन्च और आवासीय इकाइयों की बिक्री में बढ़ती मांग भी परिलक्षित हुई। इन्वेंटरी ओवरहांग 48 महीने के आठ-चौथाई निचले स्तर तक गिर गया (चार्ट 35 बी)।

विमानन क्षेत्र ने अप्रैल 2022 में विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्री खंड में अपनी वसूली को बनाए रखा। दैनिक घरेलू हवाईअड्डों की संख्या औसतन 6.9 लाख प्रति दिन थी, जो पिछले महीने की तुलना में 1.0 प्रतिशत बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों की संख्या में क्रमिक रूप से 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कार्गो खंड में घरेलू कार्गो के लिए 2.6 प्रतिशत (माह-दर-माह) की वृद्धि हुई और अंतरराष्ट्रीय कार्गो के लिए 6.2 प्रतिशत (एम-ओ-एम) का संकुचन हुआ। मई के पहले पंद्रह दिनों में, अप्रैल में इसी अवधि की तुलना में घरेलू हवाईअड्डों की संख्या में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो विमानन की निरंतर मांग का संकेत है।

प्रतिबंधों को हटाने के जवाब में, सेवा क्षेत्र ने गति बरकरार रखी जो कि अधिकांश व्यापार और परिवहन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज करने वाले उच्च आवृत्ति संकेतकों में प्रतिध्वनित हुई। संपर्क-गहन विमानन और पर्यटन क्षेत्रों में क्रमिक सुधार दर्ज किया गया, लेकिन बहाली पिछड़ी हुई है (सारणी 2)।

[8] जनवरी और फरवरी 2022, 2020 में इसी महीने की तुलना में, मार्च 2019 से मार्च 2022 तक आधार वर्ष के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए।

सारणी 2: उच्च आवृति संकेतक- सेवाएँ

क्षेत्र	संकेतक	उच्च आवृति संकेतक-सेवा वृद्धि (व-द-व, प्रतिशत)						पूर्व-महामारी माह में वृद्धि		
		नव-21	दिस-21	जन-22	फर-22	मार्च-22	अप्रै-22	फर22/ फर 20	मार्च 22/ मार्च 19	अप्रै 22/ अप्रै 19
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	-18.6	-13.3	-8.1	-6.5	-3.9	-3.8	10.2	-4.2	1.6
ग्रामीण मांग	दो पहिया वाहन बिक्री	-34.4	-10.8	-21.1	-27.3	-20.9	15.4	-19.8	-17.8	-29.9
	तिपहिया वाहन बिक्री	-6.6	27.0	-8.5	-1.1	0.5	52.5	-34.5	-51.6	-54.7
	ट्रैक्टर बिक्री	-22.5	-27.5	-32.6	-31.3	-14.3	40.6	-10.0	17	55.5
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री			26.0						
	रेल मालभाड़ा यातायात	6.1	7.2	7.7	6.6	6.7	9.4	12.4	16.3	20.9
	बंदरगाह नौभार यातायात	-0.2	-0.4	-2.9	0.0	0.7	5.6	2.0	7.7	8.1
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	-1.7	2.0	-6.1	-6.3	-1.0		-12.5	-4.4	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	11.7	10.5	5.2	-0.4	1.1		-10.2	-10.7	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	65.5	53.3	-16.2	-1.0	37.7		-36.6	-5.3	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	140.2	121.7	67.5	66.6	105.7		-56.0	-43.8	
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	5.9	11.6	9.5	8.3	9.7	28.0	20.9	42.4	43.3
	जीएसटी ई-वे बिल(आंतर राज्यीय)	7.3	13.4	11.4	10.3	11.8	28.4	26.3	49	50.8
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतरराज्यीय)	3.9	8.9	6.6	5.3	6.6	27.4	13.3	33	32.9
	पर्यटक आगमन	255.0	235.5	140.4						
निर्माण	इस्पात खपत	-7.1	-8.3	0.5	-5.3	-0.5	1.0	0.4	1.5	17.7
	सीमेंट उत्पादन	-3.6	14.2	14.3	5.0	8.8		5.2	8.1	
पीएमआई सूचकांक	विनिर्माण	57.6	55.5	54.0	54.9	54.0	54.7			
	सेवाएँ	58.1	55.5	51.5	51.8	53.6	57.9			

मुद्रास्फ़ीति

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 मई 2022 को जारी अप्रैल 2022 के अनंतिम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़ों से पता चला है कि हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) अप्रैल में बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 7.0 प्रतिशत थी। सभी प्रमुख समूहों में तेजी के कारण (चार्ट 36ए)। अप्रैल में 143 बीपीएस की एक सकारात्मक कीमत गति (माह-दर-माह कीमतों में बदलाव) 64 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभावों (एक साल पहले कीमतों में माह-दर-माह परिवर्तन) से आंशिक रूप से ऑफसेट थी, जिससे एक मार्च और अप्रैल के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 80 बीपीएस की वृद्धि हुई।

खाद्य और पेय पदार्थ मुद्रास्फीति मुख्य उत्प्रेरक था, जो मार्च में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 8.1 प्रतिशत हो गया। मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले उप-समूह अनाज, दूध, फल, सब्जियां, मसाले और तैयार भोजन थे। दूसरी ओर, अंडे, मांस और मछली, दालें, चीनी और गैर-मादक पेय पदार्थों के संबंध में कीमतों में नरमी आई है। खाद्य तेलों और वसा में मार्च की तुलना में अप्रैल में कीमतों में माह-दर-माह मध्यम वृद्धि दर्ज की गई, जो कि वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति में गिरावट में परिलक्षित हुई।

पिछले पांच महीनों में नरमी के बाद, मुख्य रूप से केरोसिन (पीडीएस) और एलपीजी मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण ईंधन मुद्रास्फीति मार्च में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 10.8 प्रतिशत हो गई। अप्रैल में मार्च की तुलना में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद बिजली की कीमतों में वार्षिक आधार पर (-0.6 प्रतिशत) ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर्ज की गई। ईंधन (सीपीआई बास्केट में 6.84 प्रतिशत का भार) ने अप्रैल में हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 9.3 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 36बी)।

खाद्य और ईंधन[9] को छोड़कर मुद्रास्फीति अप्रैल में 70 बीपीएस बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 6.4 प्रतिशत थी

9 सीपीआई शीर्षक से 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश' समूहों को हटाकर खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई की गणना की जाती है।

चार्ट 36: सीपीआई मुद्रास्फीति

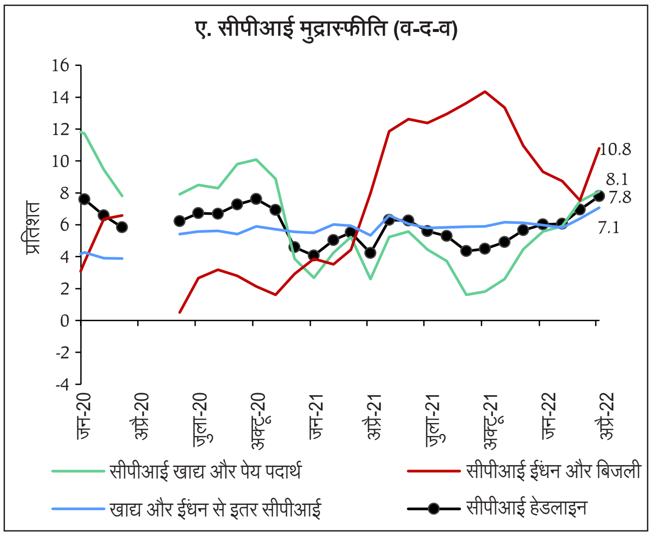

टिप्पणी: अप्रैल-मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल-मई 2020 के लिए इम्प्यूटेड सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

(चार्ट 36ए)। यह मुख्य रूप से परिवहन और संचार, शिक्षा, कपड़े और जूते, आराम और मनोरंजन, घरेलू सामान एवं सेवाओं, स्वास्थ्य और आवास उप-समूहों से उत्पन्न दबावों के कारण था। पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों में मुद्रास्फीति और व्यक्तिगत देखभाल एवं प्रभाव उप-समूहों में नरमी आई।

उच्च मुद्रास्फीति के साथ-साथ, मार्च के स्तर[10] पर अप्रैल में मानक विचलन और मुद्रास्फीति की विषमता दोनों में वृद्धि हुई है, कुछ वस्तुओं के साथ समग्र मुद्रास्फीति में अनुपातहीन रूप से योगदान दिया गया है(चार्ट 37)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलों विभाग) के मई के लिए अब तक (1-12 मई 2022) के उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा अनाज की कीमतों में वृद्धि का संकेत देते हैं, मुख्य रूप से गेहूं की कीमतों में वृद्धि के कारण दालों की कीमतें स्थिर रहीं, हालांकि अरहर की कीमतों में नरमी आई है जबकि मसूर की कीमतों में तेजी आई है। खाद्य तेलों की कीमतों में व्यापक आधार पर वृद्धि दर्ज की गई। प्रमुख सब्जियों में टमाटर की कीमतों में तेजी आई, जबकि प्याज की कीमतों में नरमी आई। मई में अब तक आलू की कीमतों में भी तेजी आई है (चार्ट 38)।

मई में अब तक (12 तारीख तक) चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें स्थिर रहीं। 7 मई 2022 को रसोई गैस की कीमतों में ₹50 प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई। अप्रैल में तेजी से बढ़ने के बाद मई में किरोसिन की कीमतें स्थिर रहीं (सारणी 3)।

चार्ट 37: सीपीआई मुद्रास्फीति के क्षण

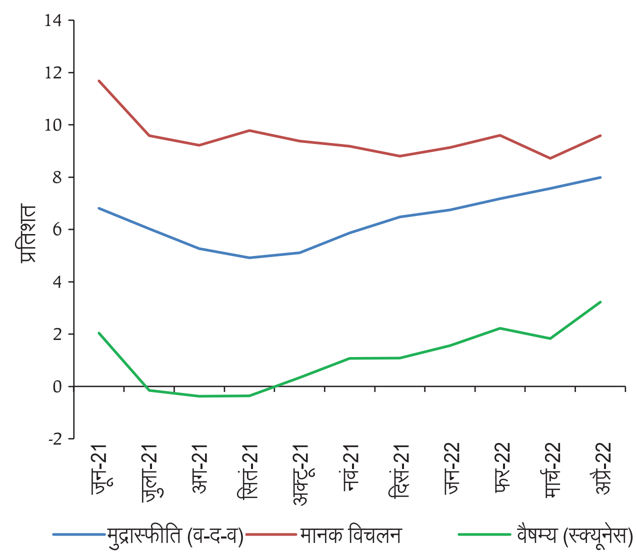

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

10 अखिल भारतीय आइटम स्तर के सीपीआई डेटा का उपयोग करके मापा गया। मानक विचलन वस्तुओं में मुद्रास्फीति में परिवर्तनशीलता को इंगित करता है जबकि विषमता औसत के आसपास विषमता को मापती है।

चार्ट 38: डीसीए आवश्यक पण्य कीमतें

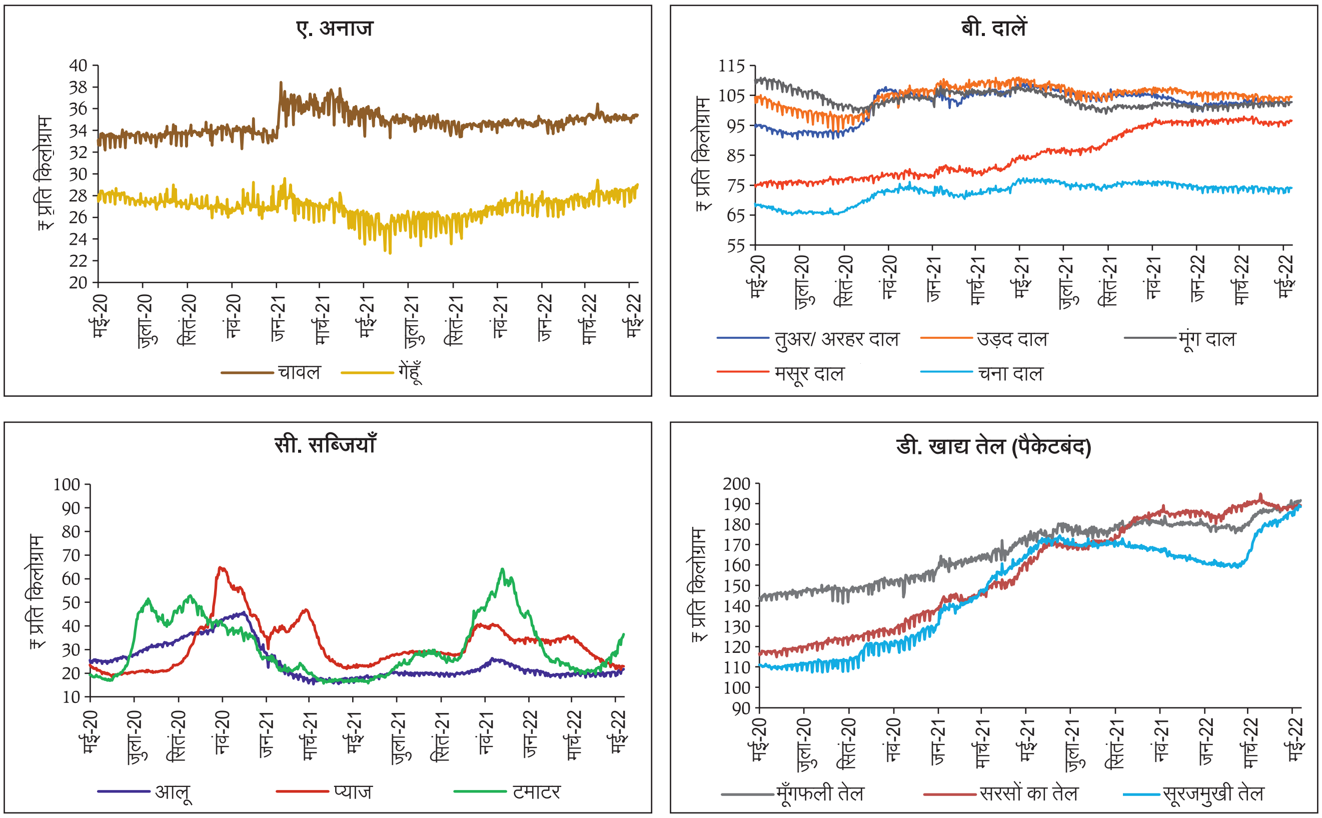

स्रोत: उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

अप्रैल 2022 में विनिर्माण और सेवाओं में इनपुट लागत में तेजी से वृद्धि हुई, जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है। अप्रैल में, विनिर्माण में बिक्री मूल्य ने मुद्रास्फीति को अपने उच्चतम वार्षिक स्तर पर पहुंचा दिया, जबकि सेवाओं में बिक्री मूल्य जुलाई 2017 के बाद से सबसे तेज दर से बढ़ा।

सारणी 3: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मदें	इकाई	घरेलू कीमतें			महीने दर महीने (प्रतिशत)	
		मई-21	अप्रै-22	मई-22 ^	अप्रै-22	मई-22
पेट्रोल	₹/लीटर	94.37	112.61	112.97	8.3	0.3
डीज़ल	₹/लीटर	86.68	100.19	100.55	9.4	0.4
मिट्टी का तेल (सब्सिडी- प्राप्त)	₹/लीटर	30.38	56.99	56.99	21.6	0.0
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	819.63	960.13	985.13	3.7	2.6

^: 1-12 मई 2022 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

IV. वित्तीय स्थितियां

चलनिधि की स्थिति मौद्रिक नीति के समग्र रुख के अनुरूप विकसित हुई, जिसमें अप्रैल नीति में निर्धारित निभाव की वापसी पर ध्यान केंद्रित किया गया और 4 मई 2022 को घोषित रीपो दर और सीआरआर वृद्धि के माध्यम से प्रबलित किया गया। चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत दैनिक चलनिधि अवशोषण (एलएएफ़) अप्रैल 2022 की दूसरी छमाही में 12 मई के माध्यम से औसतन ₹6.8 लाख करोड़ हो गया, जो मार्च के दूसरे पखवाड़े के दौरान अप्रैल 2022 के मध्य तक ₹7.5 लाख करोड़ से कम था। एसडीएफ़ की शुरुआत से, एसडीएफ़ के तहत औसत दैनिक अवशोषण (जिसने 8 अप्रैल को एलएएफ कॉरिडोर के फर्श के रूप में फिक्स्ड रेट रिवर्स रीपो (एफआरआरआर) को बदल दिया) ₹2.0 लाख करोड़ था, जबकि अधिशेष चलनिधि का बड़ा हिस्सा

परिवर्तनीय दर रिवर्स रीपो (वीआरआरआर) नीलामी (मुख्य और फ़ाइन ट्यूनिंग दोनों) के माध्यम से निकाला गया था। जैसे ही चलनिधि अधिशेष लगभग ₹9 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर से कम हुआ, एकदिवसीय मुद्रा बाजार दर एसडीएफ दर की ओर बढ़ गई, त्रि-पक्षीय दर ने संक्षेप में इसे भंग कर दिया (चार्ट 39)। अप्रैल की नीति में गुंजाइश की निचली सीमा के रूप में एफआरआरआर से उच्च एसडीएफ दर में परिवर्तन के बाद 4 मई, 2022 को ऑफ-साइकिल बैठक में नीतिगत दर में वृद्धि ने एकदिवसीय दरों को वापस ले लिया है। आउटर टर्म मनी मार्केट सेगमेंट के साथ, मई में 3 महीने के टी-बिल्स पर प्रतिफल अधिक रही। म्यूचुअल फंड में स्थिर प्रवाह के बीच कम जारी होने के कारण अप्रैल की दूसरी छमाही में रुक-रुक कर नरम होने के बाद 3 महीने के डिपॉजिट सर्टिफिकेट (सीडी) और 3 महीने के कमर्शियल पेपर (सीपी) पर ब्याज दरें ऊपर की ओर फिर से शुरू हुईं, इसके बाद एमएसएफ दर तेजी से बढ़ीं।

रिज़र्व बैंक की 4 मई की मौद्रिक नीति के निर्णय के बाद, अप्रैल 2022 की दूसरी छमाही से बॉन्ड प्रतिफल ने एक सख्त पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया। पॉलिसी रीपो दर में बढ़ोतरी और एक ऑफ-साइकिल बैठक (चार्ट 40ए) में सीआरआर की घोषणा के बाद 4 मई को 10-वर्षीय जी-सेक यील्ड 7.42 प्रतिशत के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गई। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि का भी बाजार धारणा पर असर पड़ा। जी-सेक यील्ड कर्व का शॉर्ट-एंड एफआरआरआर से एसडीएफ में संक्रमण के साथ सिंक में बढ़ गया, जो समान परिपक्वता (चार्ट 40 बी) की प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन को दर्शाता है। इसके बाद, नीतिगत दरों में वृद्धि से प्रतिफल वक्र में ऊपर की ओर बदलाव आया।

सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में मंदी का असर कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में फैल गया, जहां प्रतिफल में परिपक्वता प्रोफाइल और रेटिंग स्पेक्ट्रम (चार्ट 41) में समकालिक सख्तता का अनुभव हुआ। 3 साल के एएए रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड पर प्रतिफल 58 बीपीएस बढ़कर 13 अप्रैल को 6.41 प्रतिशत से 10 मई 2022 को 6.99 प्रतिशत हो गया।

मौद्रिक और ऋण समुच्चय ने अप्रैल में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया। रिज़र्व मनी (आरएम), सीआरआर बहाली के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, 6 मई 2022 (एक साल पहले 13.5 प्रतिशत) की स्थिति के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें मुद्रा प्रचलन में थी, जो आरएम का सबसे बड़ा घटक था, जो 9.9 प्रतिशत (एक साल पहले 14.4 प्रतिशत) की दर से बढ़ रहा है। दूसरी ओर, मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) ने 22 अप्रैल 2022 (एक साल पहले 11.1 प्रतिशत) की स्थिति में

चार्ट 39: मुद्रा बाजार दर और चलनिधि स्थितियां

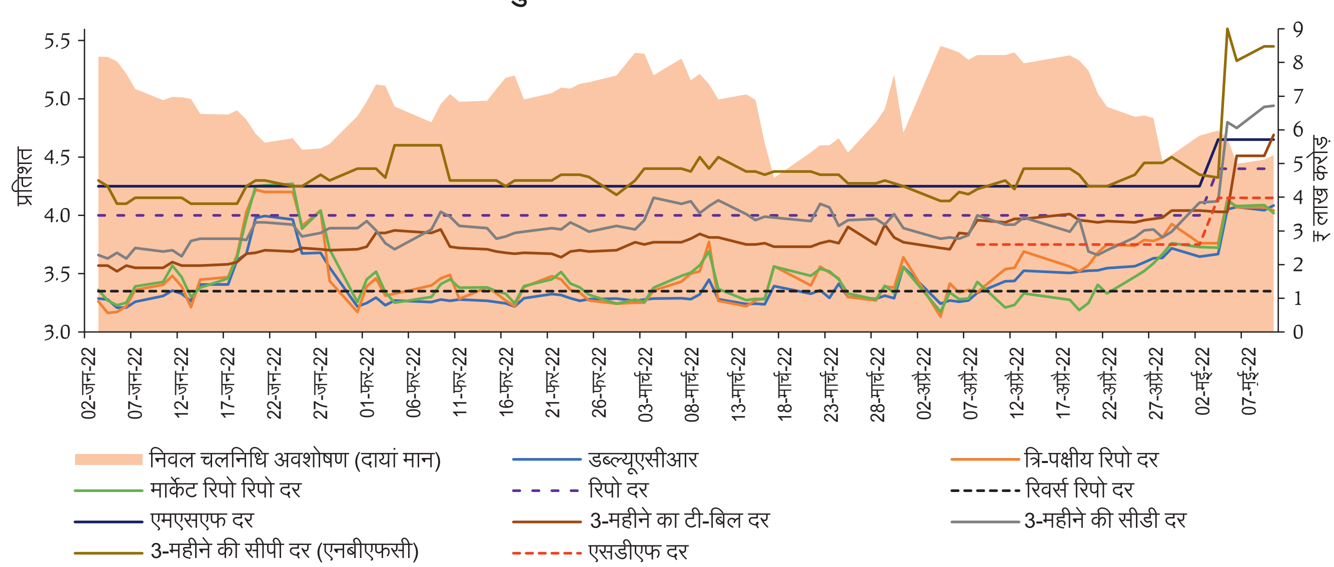

स्रोत: आरबीआई; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट 40: जी-सेक बाजार

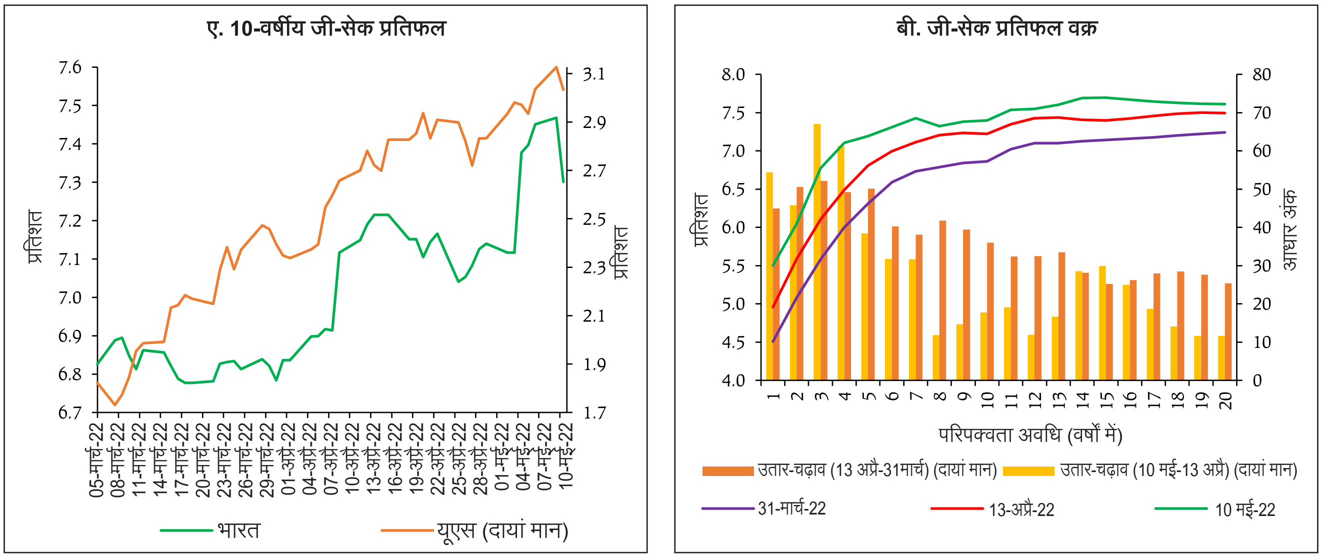

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और एफआईएमएमडीए।

10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से कुल जमा में 10.0 प्रतिशत (10.3 प्रतिशत एक वर्ष पहले)) की वृद्धि से प्रेरित है। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण में वृद्धि अगस्त 2019 के बाद पहली बार दोहरे अंकों को पार कर गई और 22 अप्रैल 2022 को 11.1 प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले यह 5.7 प्रतिशत थी (चार्ट 42)

पिछली मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के कम प्रभाव, मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख पर भावी मार्गदर्शन और प्रणाली में अधिशेष चलनिधि ने नीतिगत दरों को उधार दरों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 (चार्ट 43) के दौरान ताजा और बकाया रुपये के ऋण पर भारित औसत उधार दरों में क्रमशः 26 बीपीएस और 36 बीपीएस की गिरावट

चार्ट 41 : कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल

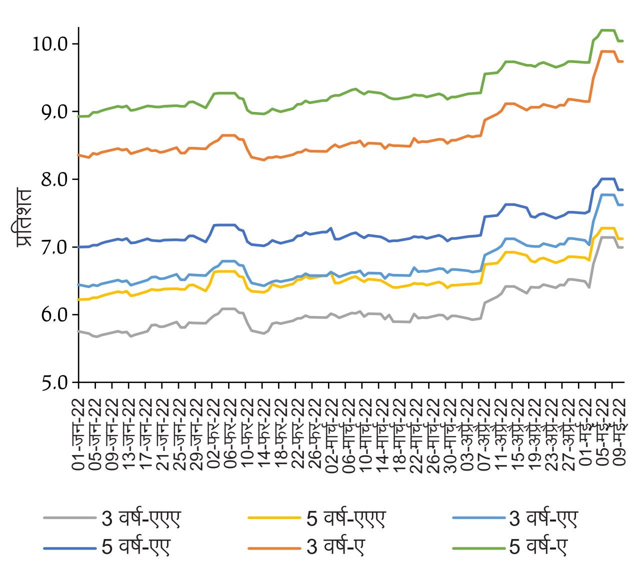

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 42: समग्र मौद्रिक और क्रेडिट

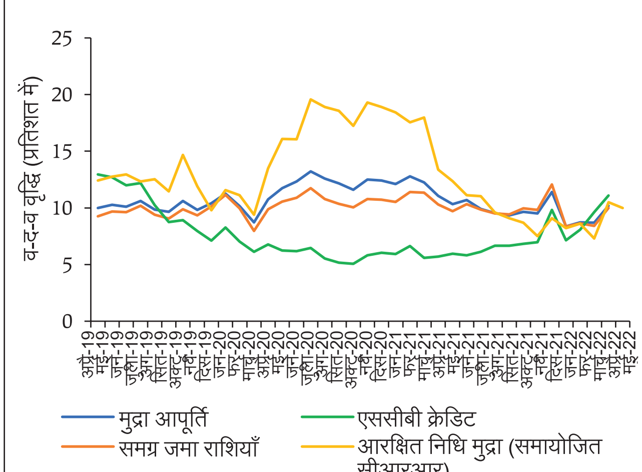

टिप्पणियां: 1. ये आंकड़े धन आपूर्ति, सकल जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं; और आरक्षित निधि के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

2. तथापि, मई के लिए आरक्षित निधि से संबंधित आंकड़े 6 मई 2022 की स्थिति के अनुसार हैं।

स्रोत: आरबीआई।

आई। बकाया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) के लिए पास-थ्रू की सीमा नए रुपये के ऋणों की तुलना में अधिक थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की औसत सीमांत लागत में केवल 2 बीपीएस की गिरावट आई, जबकि नए ऋणों पर उधार दरों में मामूली गिरावट आई। हालांकि, आधार दर और एमसीएलआर से जुड़े बकाया ऋणों के शेयरों में गिरावट और बाहरी बेंचमार्क से जुड़े बकाया ऋणों की हिस्सेदारी में सहवर्ती वृद्धि के साथ, जिनकी कीमत कम दर पर है, बकाया रुपये के ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर को पास-थ्रू बहुत अधिक[11] था।

दिसंबर 2021 से जमा अनुपात में वृद्धि के साथ, बैंकों ने ऋण की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए स्थिर धन जुटाने के लिए सावधि जमा पर दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है।[12] औसत सावधि जमा दर (यानी, ताजा जमा पर औसत कार्ड दरें) एससीबी के सभी कार्यकाल) दिसंबर 2021 में 4.04 प्रतिशत से बढ़कर

चार्ट 43: उधार और जमा दरों में अंतरण (अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022)

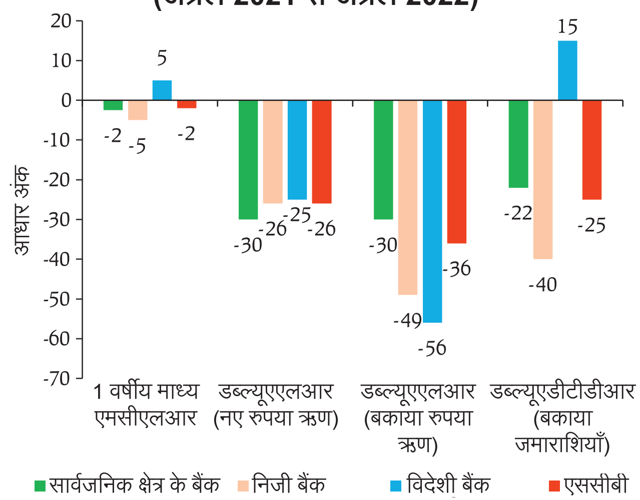

टिप्पणी: डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर आंकड़े मार्च 2022 से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

अप्रैल 2022 में 4.10 प्रतिशत हो गए (चार्ट 44)। 4 मई को रिज़र्व बैंक की रीपो दर में 40 बीपीएस की वृद्धि के जवाब में, बैंकों ने ऋण मूल्य निर्धारण, यानी एमसीएलआर और बाहरी बेंचमार्क लिंक्ड उधार दरों (ईबीएलआर) के लिए अपनी बेंचमार्क दरों को ऊपर की ओर समायोजित करना शुरू कर दिया है।

अप्रैल 2022 में, दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पांच निजी बैंकों सहित सात घरेलू बैंकों ने अपने एमसीएलआर को 5 से 13 बीपीएस की सीमा में बढ़ाया। कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा बेंचमार्क दरों में वृद्धि का कदम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की उधार और जमा दरों की दिशा का मार्गदर्शन कर रहा है। कुछ प्रमुख गैर-बैंकों ने अप्रैल 2022 में अपनी जमा और उधार दरों में वृद्धि की है।

वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 409 सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा घोषित आय, जो सभी सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों का लगभग 56.3 प्रतिशत है, अधिकांश प्रमुख मापदंडों के संदर्भ में एक स्वस्थ प्रदर्शन का संकेत देता है (चार्ट 45)। तिमाही के दौरान निवल बिक्री वृद्धि मजबूत रही, जो आंशिक रूप

चार्ट 44: वृद्धिशील सीडी अनुपात और सावधि जमा दरें

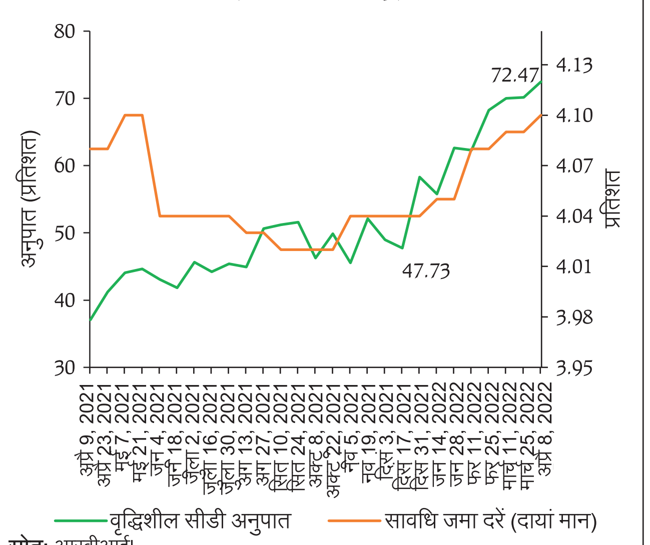

स्रोत: आरबीआई।

[11] बेस रेट और एमसीएलआर से जुड़े बकाया फ्लोटिंग रेट रुपये के ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2021 में क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 62.8 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2021 में क्रमशः 5.3 प्रतिशत और 53.1 प्रतिशत हो गई। उसी के दौरान कुल बकाया ऋणों में बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड ऋणों की हिस्सेदारी 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 39.2 प्रतिशत हो गई (RBI बुलेटिन, अप्रैल 2022 https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20939)

[12] एक उच्च सीडी अनुपात, कैटेरिस परिबस, बैंकों की मूल्य निर्धारण शक्ति को उनकी उधार दरों को बढ़ाने की अनुमति दे सकता है, जबकि उनके सीडी अनुपात में एक मॉडरेशन, कमजोर क्रेडिट मांग की स्थिति को दर्शाता है, जिससे उनकी उधार दरों पर नीचे की ओर दबाव पड़ने की उम्मीद की जा सकती है।

से उत्पादन कीमतों में वृद्धि से प्रेरित थी। विभिन्न जिंस कीमतों में वृद्धि के प्रभाव के कारण तिमाही के दौरान फर्मों के कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई। बढ़ती इनपुट लागत के प्रभाव को कम करने के लिए, कुछ फर्मों ने अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की, जबकि अन्य ने लागत में कटौती के उपायों को अपनाया, जैसे कि विज्ञापनों पर विवेकाधीन खर्च को कम करना, आदि। इसके अलावा, वेतन और वेतन में तिमाही के दौरान वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर, परिचालन व्यय में बिक्री की तुलना में तेज दर से वृद्धि हुई, जिसका भार फर्मों के परिचालन मार्जिन पर पड़ा। फिर भी, तेल और गैस कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन के कारण परिचालन मुनाफे में वृद्धि मजबूत रही। अन्य आय, जिसमें ट्रेजरी संचालन आदि से आय शामिल है, एक मजबूत दर से बढ़ी, हालांकि, उच्च कर व्यय के कारण निवल लाभ वृद्धि में कुछ कमी आई।

120 कंपनियों के विश्लेषण के आधार पर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, जो सभी सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का लगभग 73.7 प्रतिशत है, ने वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के दौरान मजबूत परिचालन प्रदर्शन दर्ज की (चार्ट 46)। निवल बिक्री, जिसमें मुख्य रूप से ब्याज आय शामिल है, ने ऋण वृद्धि में तेजी के साथ तीव्र वृद्धि दर्ज की। अन्य आय, जिसमें ट्रेजरी संचालन से लाभ/हानि, शुल्क और कमीशन शामिल हैं, हालांकि, इस अवधि के दौरान गिरावट दर्ज की गई। टॉपलाइन की तुलना में व्यय कम दर से बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन लाभ में दो अंकों की वृद्धि हुई। इसके अलावा, बेहतर आस्ति गुणवत्ता से लाभ, प्रावधान लागत में तिमाही के दौरान तेजी से गिरावट आई, जिससे निवल लाभ में तेज उछाल आया।

अप्रैल 2022 में 2.6 प्रतिशत की गिरावट के बाद, वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों को देखते हुए, भारतीय इक्विटी बाजार बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स मई 2022 (12 मई 2022 तक) में 7.2 प्रतिशत की और गिरावट आई। वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई, अमेरिका में मौद्रिक नीति की सख्ती और चीन में कोविड-19 से जुड़े लॉकडाउन को लेकर चिंता के बीच बाजार धारणा सतर्क रही। फेड द्वारा 50 बीपीएस की वृद्धि के लिए इक्विटी बाजार की प्रारंभिक प्रतिक्रिया ठंडी थी, हालांकि, बाद में इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई क्योंकि निवेशक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति को सख्ती को लेकर चिंतित थे। भले ही इक्विटी बाजारों से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रत्याशा है, लेकिन मजबूत मांग की स्थिति और बेहतर लाभप्रदता एक काउंटर फोर्स के रूप में कार्य करेगी। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2000 के बाद से यूएस फेड द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि के दो प्रकरणों के दौरान - पहला 2004 के

चार्ट 45: सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों का कार्य-प्रदर्शन

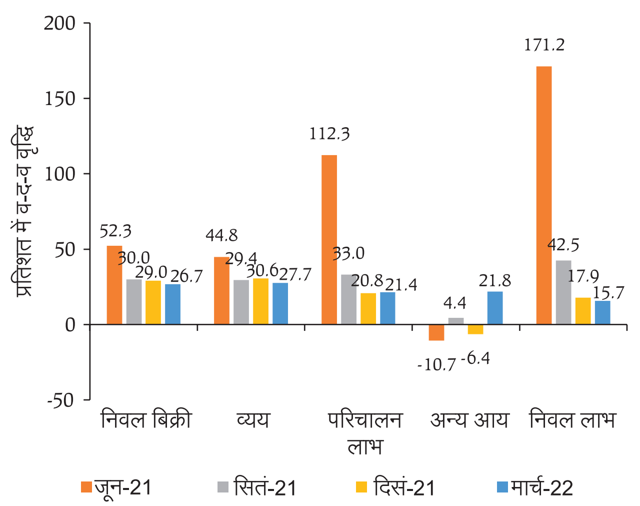

टिप्पणी: असाधारण वस्तुओं को छोड़कर।
स्रोत: प्रोवेस; और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।

चार्ट 46: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का कार्य-प्रदर्शन

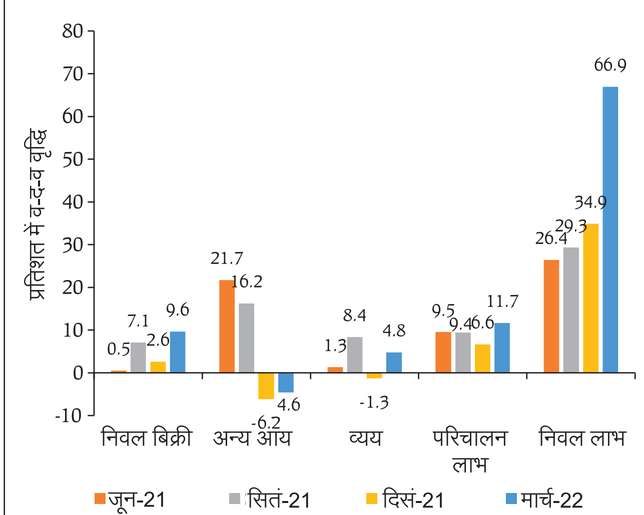

टिप्पणी: असाधारण वस्तुओं को छोड़कर।
स्रोत: प्रोवेस; और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।

चार्ट 47: यूएस और इक्विटी बाज़ारों में मौद्रिक नीति में सख्ती

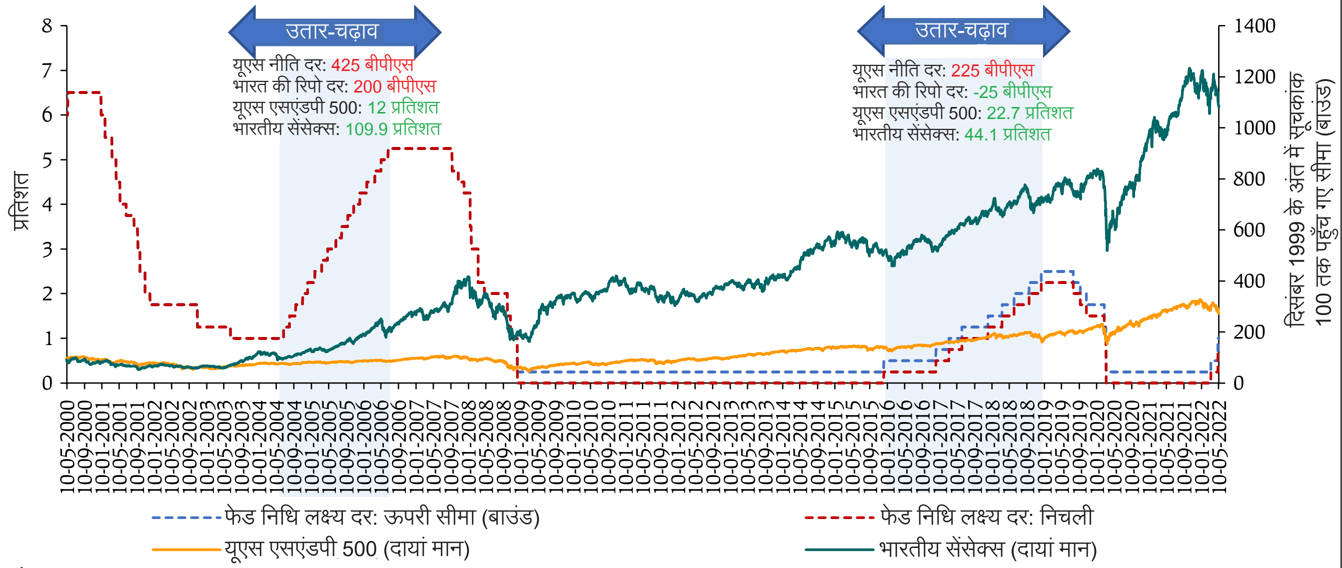

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

मध्य से 2006 के मध्य के दौरान और दूसरा दिसंबर 2015 के अंत से दिसंबर 2018 के अंत तक - भारत और अमेरिका में इक्विटी बाजारों के रूप में लाभ हुआ क्योंकि कॉर्पोरेट आय में वृद्धि हुई (चार्ट 47)।

हाल के महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारी बिक्री के विपरीत, घरेलू निवेशक प्रत्यक्ष निवेश के साथ-साथ म्यूचुअल फंड के माध्यम से अप्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से शेयर बाजारों में परिवारों द्वारा विविधीकरण में वृद्धि के मद्देनजर एक मजबूत प्रतिसंतुलन बल के रूप में उभरे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की संयुक्त हिस्सेदारी, जिसमें घरेलू म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं; एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों में खुदरा निवेशक और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति (एचएनआई) मार्च 2022 के अंत में 23.3 प्रतिशत तक पहुंच गए। इसके विपरीत, मार्च 2022 के अंत में एफपीआई 20.2 प्रतिशत था (चार्ट 48)।

भारत 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना रहा। वर्ष 2021-22 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 83.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक साल पहले दर्ज किए गए 82.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया (चार्ट 49)। हालांकि, भारत द्वारा अधिक जावक एफडीआई और विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यावर्तन के कारण, निवल एफडीआई 2021-22 में घटकर 39.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो एक साल पहले 44.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2021-22 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा रहा।

चार्ट 48: एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों का शेयरधारिता का स्वरूप

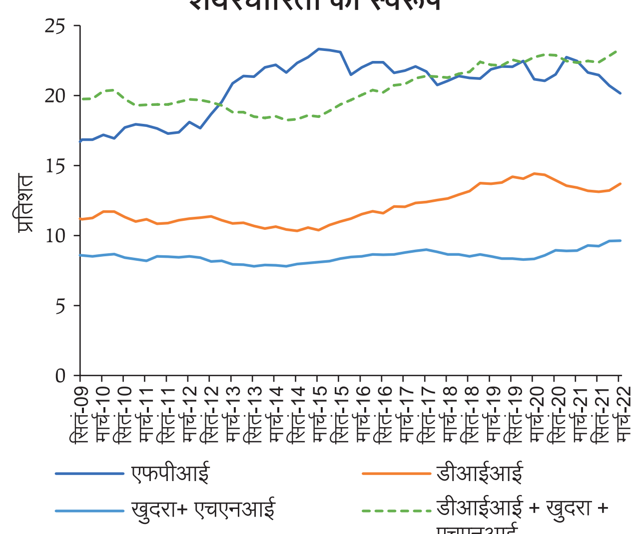

स्रोत: प्राइम डेटाबेस।

चार्ट 49: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

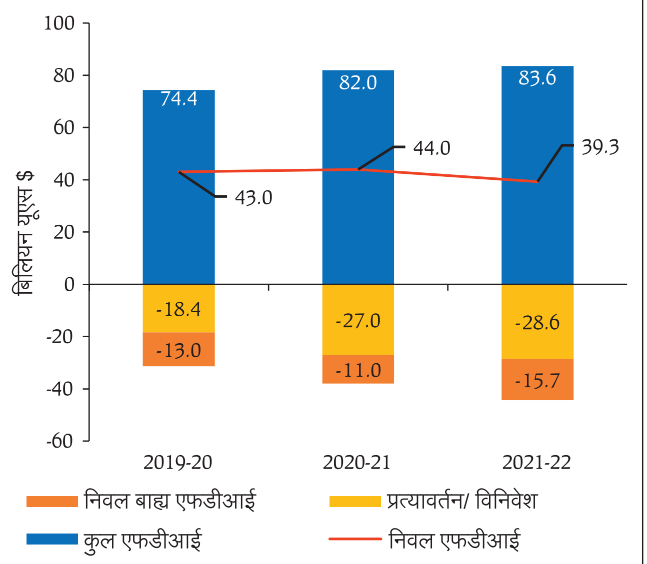

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 50: निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

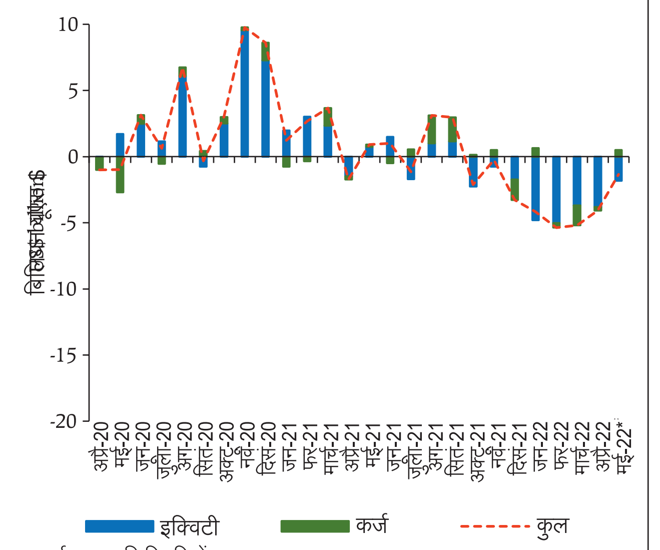

* 10 मई 2022 की स्थिति में।
स्रोत: नेशनल सिक्युरिटीज डिपोसिटोरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।

मुद्रास्फीति के दबावों, तेल की कीमतों में उछाल, प्रमुख एई में नीति सामान्यीकरण पर आने वाली सूचनाओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच, घरेलू बाजार में एफपीआई अप्रैल 2022 में निवल विक्रेता बने रहे। महीने में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफपीआई बहिर्वाह बड़े पैमाने पर इक्विटी बाजार में बिकवाली से प्रेरित था (चार्ट 50)। महीने में एफपीआई के बहिर्वाह का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दर्ज किया गया।

अंतर-कंपनी उधार को छोड़कर, भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का निवल संवितरण, एक वर्ष पहले के 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021-22 के दौरान 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जबकि अंतर-कंपनी उधार सहित निवल संवितरण, इस अवधि के दौरान एक साल पहले के 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे। मार्च 2022 में ईसीबी का एक बड़ा हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, स्थानीय पूंजीगत वस्तुओं के खर्च और पहले के ईसीबी के पुनर्वित्त के लिए भेजा गया था।

6 मई 2022 को 596.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 2022-23 के लिए अनुमानित लगभग 10 महीने के आयात के बराबर था (चार्ट 51)।

विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) अप्रैल 2022 में अमेरिकी डॉलर (माह-दर-माह) की तुलना में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह 40-मुद्रा आईएनआर की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के उतार-चढ़ाव में परिलक्षित हुआ, जो महीने में 0.2 प्रतिशत बढ़ी (चार्ट 52)।

चार्ट 51: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

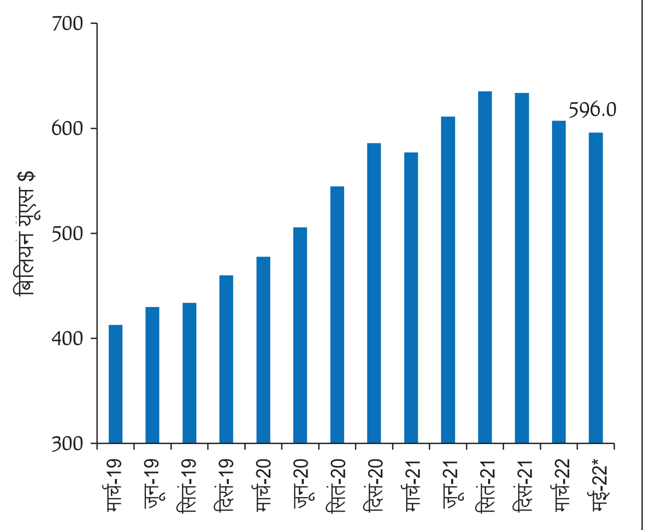

6 मई 2022 की स्थिति में।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 52: 40-मुद्रा समूह के वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में मासिक उतार-चढ़ाव

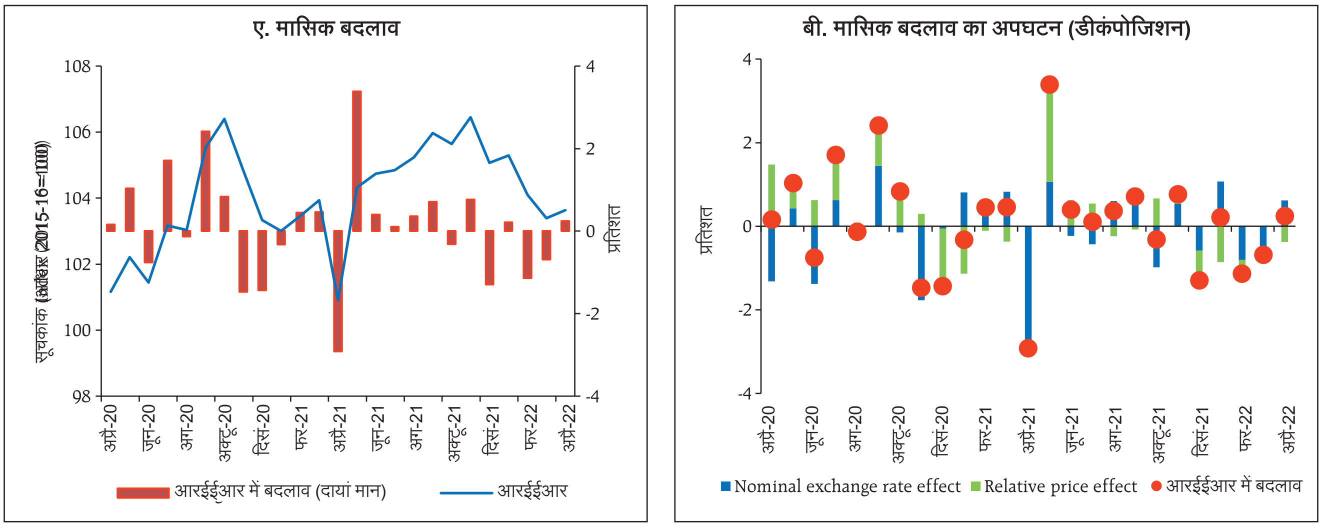

टिप्पणी: अप्रैल 2022 के लिए डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: आरबीआई।

उच्च मुद्रास्फीतिकारी दबावों के कारण यूके और कनाडा में आरईईआर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि आरईईआर अमेरिका में स्थिर बना हुआ है (चार्ट 53ए)। इसके विपरीत, यूरो क्षेत्र में आरईईआर में कमी के साथ मूल्य वृद्धि होती है। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रास्फीति संबंधी दबावों ने अर्जेंटीना में आरईईआर में उल्लेखनीय वृद्धि को प्रेरित किया है (चार्ट 53बी)। इसी तरह, आरईईआर बड़े पैमाने पर ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में घरेलू मूल्य दबावों से प्रेरित हैं। इसके विपरीत, उच्च मुद्रास्फीति दबाव तुर्की में आरईईआर में एक महत्वपूर्ण कमी के साथ हैं।

चार्ट 53: वर्ष 2021-22 में घरेलू मुद्रास्फीति और आरईईआर

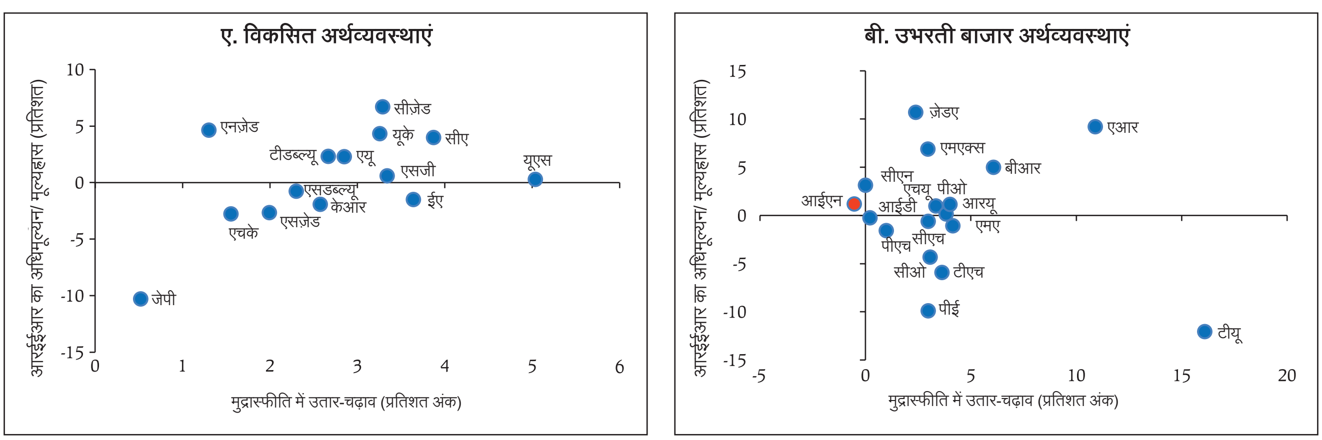

एआर: अर्जेंटीना; एयू: ऑस्ट्रेलिया; बीआर: ब्राजील; सीए: कनाडा; सीएच: चिली; सीएन: चीन; सीओ: कोलंबिया; सीज़ेड: चेक गणराज्य; ईए: यूरो क्षेत्र; एचके: हांगकांग; एचयू: हंगरी: आईडी: इंडोनेशिया; आईएन: भारत; आईएस: इज़राइल; जेपी: जापान; केआर: कोरिया; एमए: मलेशिया; एमएक्स: मेक्सिको; एनजेड: न्यूजीलैंड; पीई: पेरू; पीएच: फिलीपींस; पीओ: पोलैंड; आरयू: रूस; एसजी: सिंगापुर; एसडब्ल्यू: स्वीडन; एसजेड: स्विट्जरलैंड; टीएच: थाईलैंड; टीयू: तुर्की; टीडब्ल्यू: ताइवान; यूके: यूनाइटेड किंगडम; और अमेरिका: संयुक्त राज्य अमेरिका।

टिप्पणियां: 1. मुद्रास्फीति में परिवर्तन 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वार्षिक मुद्रास्फीति (प्रतिशत बिंदु) में वृद्धि या कमी का प्रतिनिधित्व करता है।
2. आरईईआर का अधिमूल्यन (+) और मूल्यह्रास (-), 2020-21 की तुलना में 2021-22 में आरईईआर में प्रतिशत परिवर्तन है।

स्रोत: आरबीआई; बीआईएस; आईएमएफ; थॉमसन रियूटर्स; और सीईआईसी।

भुगतान प्रणाली

डिजिटल भुगतान ने अप्रैल 2022 में एक स्वस्थ विस्तार बनाए रखा। तत्काल सकाल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से बड़े मूल्य के अंतरण ने दोहरे अंकों की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की। खुदरा क्षेत्र में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से लेनदेन ने मजबूत मात्रा और मूल्य वृद्धि को बनाए रखा, जिसमें मूल्य 10 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी), और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) ने भी लेनदेन में तेजी दर्ज की (सारणी 4)। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) ने एक महीने में सबसे अधिक लेनदेन (7.4 करोड़) दर्ज किया, जो इसके लोकप्रिय स्वीकरण को दर्शाता है। बिजली बिलों के भुगतान, गर्मी के मौसम में मांग में वृद्धि के साथ ऋण चुकौती के कारण उछाल आया। हवाई यात्रा और आतिथ्य के पुनरोद्धार के कारण, नए कारोबारियों के उद्भव और निचले स्तर के शहरों में विस्तार के कारण क्रेडिट कार्ड लेनदेन ने और अधिक कर्षण प्राप्त किया।[13] मार्च 2022 में बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या बढ़कर 7.36 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत अधिक है।

उपभोक्ता-अनुकूल और मजबूत भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने भारत में कार्ड जारी करने वालों द्वारा कार्ड जारी करने और परिचालन की प्रणाली से संबंधित दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया है।[14] ये विनियम कार्ड प्रणाली, जारीकर्ताओं को कार्ड से संबंधित सेवाओं के प्रावधान और उनके डेटा को संभालने के संबंध में ग्राहकों की स्पष्ट सहमति लेने के लिए, रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के विषयाधीन एनबीएफसी को बिना बैंकिंग पार्टनर के क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति देने, और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने संबंधित मौजूदा विनियामकीय वातावरण को सरल बनाते हैं। यूपीआई के अंतरराष्ट्रीयकरण में नए छाप छोड़ते हुए, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में नियोपे (NEOPAY)[15] सक्षम स्टोरों में भीम यूपीआई की स्वीकृति को सक्षम बनाया है।[16] डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उपाय के तौर पर बीबीपीएस ने पूरे भारत में किसानों के लिए आवर्ती भुगतान की सुविधा के लिए एफ़एएआरएमएस (FAARMS)[17] के साथ भागीदारी की है।

सारणी 4 : चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

भुगतान प्रणाली	लेनदेन मात्रा वृद्धि (व-द-व, प्रतिशत)				लेनदेन मूल्य वृद्धि (व-द-व, प्रतिशत)			
	मार्च-2021	मार्च-2022	अप्रैल-2021	अप्रैल-2022	मार्च-2021	मार्च-2022	अप्रैल-2021	अप्रैल-2022
आरटीजीएस	70.1	13.7	178.8	28.9	7.8	11.4	36.6	26.1
एनईएफ़टी	32.7	23.9	62.7	30.6	33.4	14.6	56.6	22.1
यूपीआई	119.1	97.9	164.2	111.4	144.5	90.3	226.6	99.2
आईएमपीएस	67.5	35.5	163.7	46.0	62.0	41.3	147.3	48.4
एनएसीएच	-22.0	9.0	-43.0	19.0	16.0	-8.0	24.0	14.3
एनईटीसी	128.6	39.9	1500.8	61.5	117.2	32.7	1021.6	51.9
बीबीपीएस	122.4	102.4	175.2	110.9	165.9	120.7	279.4	117.7

स्रोत: आरबीआई।

13 https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/financial-services/fintech/payments-transformation/the-indian-payments-handbook-2021-2026.pdf

14 मास्टर निर्देश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचरण करने के निर्देश, 2022।

15 NEOPAY मशरेक बैंक, संयुक्त अरब अमीरात की एक भुगतान सहायक कंपनी है। यह व्यवसायों को डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदान करता है।

16 https://www.npci.org.in/PDF/npci/press-releases/2022/NIPL-Press-Release-BHIM-UPI-goes-live-at-NEOPAY-terminals-in-UAE.pdf

17 FAARMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी विभिन्न जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करना है।

कुल मिलाकर, ई-कॉमर्स अपनाने, फिनटेक ऐप इंस्टॉल[18], सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या[19], और स्मार्टफोन की संख्या[20] में वृद्धि होने से डिजिटल भुगतान बाजार का विस्तार हो रहा है और इसके साथ फिनटेक खिलाड़ियों द्वारा इंडिया स्टैक[21] का लाभ उठाया जा रहा है। मौजूदा डिजिटल मोड की बढ़ती स्वीकार्यता और नवीन भुगतान पेशकश जैसे कि बाय-नाउ-पे-लेटर योजनाओं और ऑफलाइन भुगतान के बूते भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार के 2026 तक 21,700 करोड़ लेनदेन तक पहुंचने की उम्मीद है।[22]

निष्कर्ष

भू-राजनीतिक दबाव के बने रहने, जिंसों की कीमतें ऊंचे बने रहने और मौद्रिक निभाव की वापसी में तेजी आने से वैश्विक संवृद्धि परिदृश्य गंभीर दिखाई दे रहा है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पूंजी के बहिर्वाह और उच्च पण्य कीमतों के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जो मुद्रास्फीति प्रिंट को बढ़ा रहा है। इस बीच, महामारी निकट अवधि की आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित कर रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली नमनीय बनी हुई है, हालांकि वैश्विक घटनाक्रम से उत्पन्न जोखिमों ने गति को रोक दिया है। हाल के महीनों में मुद्रास्फीति के जोखिम और अधिक बढ़ गए हैं। अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में वृद्धि से व्यापार आघात के निवल संबंध भी सामने आती हैं, जो व्यापार और चालू खाता घाटे को बढ़ा रहा है।

भारत को मानव पूंजी के स्वास्थ्य और उत्पादकता में बड़े निवेश के माध्यम से महामारी के निशान से निर्माण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटलीकरण की गति में तेजी के साथ, भारत में यूनिकॉर्न इकोसिस्टम की मौजूदगी का विस्तार हो रहा, जो तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। टिकाऊ आधार पर उच्च संवृद्धि पथ प्राप्त करने के लिए, सरकार द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो निजी निवेश में अंतर्गमन करती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना, कम और स्थिर मुद्रास्फीति सुनिश्चित करना और समष्टि-आर्थिक स्थिरता बनाए रखना स्वाभाविक उत्साह को पुनर्जीवित करने और संवृद्धि को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है।

[18] CY2021 में फिनटेक ऐप इंस्टॉल की कुल संख्या में लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिनमें से 81 प्रतिशत भुगतान ऐप इंस्टॉल थे। https://www.thehindubusinessline.com/companies/indias-fintech-market-projected-to-touch-150160-billion-by-2025-affle-report/article65334947.ece

[19] https://www.business-standard.com/article/economy-policy/45-growth-in-active-internet-users-in-rural-india-since-2019-study-122050501161_1.html

[20] https://indianexpress.com/article/technology/mobile-tabs/indian-smartphone-market-up-2-percent-in-q1-2022-as-supply-bottlenecks-loom-large-canalys-7880190/

[21] इंडिया स्टैक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (आधार, यूपीआई, ई-साइन, डिजिलॉकर आदि) का एक सेट है जो हितधारकों को पेपर-लेस और कैशलेस सेवा वितरण के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

[22] https://www.business-standard.com/article/economy-policy/upi-to-stay-on-top-digital-currency-to-drive-payments-in-next-5-years-122041700252_1.html

*भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह 2019-20**

वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण से वित्तीय देयताओं में निवल वृद्धि को घटाने से प्राप्त हाउसहोल्ड अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधन अंतराल 2019-20 में संकुचित हुए। जबकि हाउसहोल्ड और वित्तीय निगम निवल ऋणदाता बने रहे, वर्ष के दौरान गैर-वित्तीय निगमों और सामान्य सरकार की निवल उधारी में वृद्धि हुई। हालांकि, विदेशी संसाधनों पर निर्भरता एक साल पहले की तुलना में 2019-20 में कम हुई है। अन्य निक्षेपागार निगमों और अन्य वित्तीय निगमों से सामान्य सरकारी क्षेत्र में निवल प्रवाह 2019-20 में बढ़ा। अन्य वित्तीय निगमों के निवेश का एक बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूति में था। मुद्रा और जमा हाउसहोल्ड के लिए निवेश के पसंदीदा साधन बने रहे।

भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय स्टॉक और निधियों के प्रवाह (एफएसएफ) को शामिल करने वाले खातों को संकलित करने के लिए इस्तेमाल किया गया व्यापक फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए), 2008 के अनुसार, पांच संस्थागत क्षेत्रों[2] के 'किसी से-किसी के लिए' (एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू) आधार पर लिखत-वार वित्तीय खातों[1] को प्रस्तुत करता है (अनुबंध I)। खातों का सेट एक सुलभ लेकिन कठोर प्रारूप में अंतर-क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक समष्टिआर्थिक जानकारी प्रदान करता है, और आर्थिक परिवर्तन और विकास के साथ-साथ महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं की वजह से पोर्टफोलियो समायोजन के कारण क्षेत्रों में पोर्टफोलियो बदलाव के बारे में बताता है। कोविड-19 और रुक-रुक कर होने वाले लॉकडाउन के मद्देनजर, डेटा संग्रह प्रणाली कुछ समय के लिए बाधित हो गई थी[3], विशेष रूप से गैर-सरकारी गैर-वित्तीय क्षेत्र के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, पद्धतिगत सुधारों के साथ संकलन को बढ़ाने और डेटा के स्रोत में सुधार करने के प्रयास निरंतर किए गए हैं[4]।

पिछले एक दशक में पांच संस्थागत क्षेत्रों में वित्तीय प्रवाह के बदलते स्वरूप ने कुल वित्तीय आस्तियों में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी को बदल दिया है, हालांकि यह मामूली है। वित्तीय आस्तियों और देयताओं दोनों में क्षेत्रीय हिस्सेदारी के मामले में, वाणिज्यिक बैंकों के प्रभुत्व वाले वित्तीय निगम (एफसी) सबसे बड़े क्षेत्र का गठन करते हैं। आस्ति के आकार के मामले में हाउसहोल्ड और निजी गैर-वित्तीय निगम (पीवीएनएफसी) उसी क्रम का पालन करते हैं, जबकि पीवीएनएफसी और सामान्य सरकार (जीजी) क्षेत्र कुल देयताओं के मामले में एफसी का पालन करते हैं। कुल आस्तियों में उनके हिस्से की तुलना में, कुल देयताओं में हाउसहोल्ड का हिस्सा बहुत कम रहता है। कुल आस्ति में सार्वजनिक एनएफसी (पीयूएनएफसी) की हिस्सेदारी 2019-20 में घटकर 1.3 प्रतिशत रह गई, जो 2011-12 में 2.0 प्रतिशत थी, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी स्थिर रही। आस्तियों और देयताओं दोनों में शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) क्षेत्र का अपेक्षाकृत मामूली हिस्सा अर्थव्यवस्था के प्रमुख हाउसहोल्ड अभिविन्यास को दर्शाता है (चार्ट 1)।

यह आलेख, संस्थागत क्षेत्रों के बीच लिखत-वार उधार और उधार संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण समझ प्रदान करने के अलावा, 2019-20 के लिए एफ़डबल्यूटीडबल्यू आधार पर वित्तीय प्रवाह

* भारतीय रिज़र्व बैंक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, राष्ट्रीय लेखा विश्लेषण प्रभाग के अनुपम प्रकाश, कौस्तव के सरकार, ईशु ठाकुर और, सपना गोयल द्वारा तैयार किया गया। लेखक पूर्व कार्यकारी निदेशक, डॉ. मृदुल के सागर और परामर्शदाता, श्री संजय हांसदा के मसौदे पर व्यावहारिक चर्चा के लिए आभारी हैं। श्री कुणाल प्रियदर्शी और श्रीमती चैताली भौमिक के योगदान की सराहना की जाती है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] वित्तीय खातों में वित्तीय आस्तियां और देयताएँ शामिल होती हैं जिनमें अचल संपत्तियां, भंडार, प्रावधान और आस्थगित कर शामिल नहीं होते हैं।

[2] पांच संस्थागत क्षेत्रों में शामिल हैं: (i) वित्तीय निगम (एफसी); (ii) गैर-वित्तीय निगम (एनएफसी); (iii) सामान्य सरकार (जीजी); (iv) हाउसहोल्ड (एचएच) जिसमें गैर-लाभकारी संस्थाएं जो हाउसहोल्ड के लिए काम कर रहीं हैं (एनपीआईएसएच) शामिल हैं; और (v) शेष विश्व (आरओडब्ल्यू)।

[3] भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और प्रवाह: 2016-17 से 2018-19 तक जुलाई 2020 आरबीआई बुलेटिन, में प्रकाशित किया गया था।

[4] विस्तृत विवरण 1 से 9, संशोधित श्रृंखला 2011-12 के साथ भी इस आलेख के साथ जारी किए गए हैं।

चार्ट 1: कुल वित्तीय आस्तियों और देयताओं की क्षेत्रीय संरचना – 2019-20

(कुल का प्रतिशत)

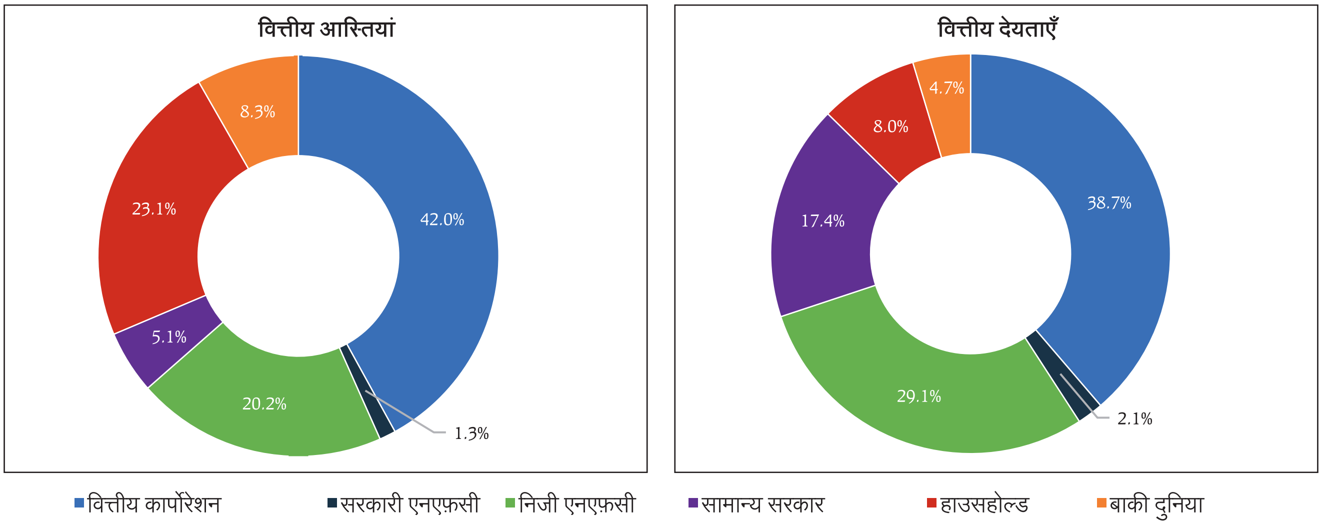

स्रोत : आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

प्रस्तुत करता है। आलेख को पांच खंडों में व्यवस्थित किया गया है - खंड II जी -20 डेटा अंतराल पहल -2 (डीजीआई -2) में प्रगति को प्रस्तुत करता है और इसके बाद खंड III क्षेत्रीय वित्तीय संसाधन अंतराल का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। खंड IV वित्तीय प्रवाह के क्षेत्रीय मानचित्रण पर चर्चा करता है, और खंड V नीतिगत दृष्टिकोणों के साथ समाप्त होता है। अनुबंध I में संकलन की रूपरेखा और कार्यप्रणाली की रूपरेखा दी गई है, जबकि अनुबंध II संकलन के इस दौर में शुरू किए गए प्रमुख सुधारों को प्रस्तुत करता है।

II. डेटा अंतराल पहल-2 के तहत प्रगति

डीजीआई-2 की छठी प्रगति रिपोर्ट, अक्टूबर 2021- 'दिसंबर 2021 तक उलटी गिनती'[5] ने महामारी के कारण डीजीआई-2 कार्य कार्यक्रम में देरी को स्वीकार किया। फिर भी, भाग लेने वाली अर्थव्यवस्थाओं को सलाह दी गई थी कि वे सहमत सिफारिशों[6], विशेष रूप से, क्षेत्रीय खातों पर सिफारिश II.8 को आगे बढ़ाना जारी रखें, जिसमें कहा गया है, "जी -20 अर्थव्यवस्थाओं को तिमाही और वार्षिक आधार पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत टेम्पलेट पर आधारित क्षेत्रीय खातों के प्रवाह और तुलन पत्र को संकलित और प्रसारित करना है, जिसमें अन्य (गैर-बैंक) वित्तीय निगम क्षेत्र के डेटा भी शामिल हैं, और तुलन पत्र विश्लेषण का समर्थन करने के लिए लेनदेन और स्टॉक दोनों के लिए किसी-से-किसी के लिए मैट्रिक्स विकसित करते हैं।

प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, छह जी -20 देशों, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की और अमेरिका ने स्व-मूल्यांकन[7] के आधार पर वार्षिक और त्रैमासिक वित्तीय खातों और तुलन पत्र के लिए लक्ष्य आवश्यकताओं को पूरा किया है। स्पेन ने वार्षिक और त्रैमासिक दोनों खातों को पूरा कर लिया है और नीदरलैंड ने विस्तृत जानकारी के साथ अपने त्रैमासिक खातों को पूरा कर लिया है। इंडोनेशिया ने 2015-19 के लिए वार्षिक और त्रैमासिक

[5] 2021 ने जी-20 डीजीआई-2 के दूसरे चरण के अंतिम वर्ष को चिह्नित किया, और जी-20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर (एफ़एमसीबीजी) ने जब जीएफसी 2007-09 के दौरान पहचाने गए डेटा अंतराल को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफ़एसबी) द्वारा तैयार बीसवीं सिफ़ारिश का समर्थन किया तब से 12वां साल।

[6] वित्तीय खातों के उपयोग के लिए प्रासंगिक जी-20 डीजीआई सिफारिशें, सेंट्रल बैंक सांख्यिकी, बीआईएस, 2019 पर इरविंग फिशर कमेटी में पीटर वैन डे वेन द्वारा प्रस्तुति।

[7] आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों पर अंतर-एजेंसी समूह (आईएजी), राष्ट्रीय खातों पर अंतर-सचिवालय कार्य समूह (आईएसडब्ल्यूजीएनए) के सहयोग से, जी -20 अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रगति को प्रोत्साहित करने और निगरानी करने के लिए सौंपा गया है।

क्षेत्रीय खातों और तुलन पत्र के संकलन और समन्वय को पूरा कर लिया है, जबकि चीन ने वार्षिक स्तर पर वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन दोनों के लिए निधियों के प्रवाह (एफओएफ) खाते को प्रकाशित किया है, जिससे त्रैमासिक रिपोर्टिंग की ओर धीरे-धीरे प्रगति हुई है। । रूस ने वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर मुख्य वित्तीय लिखतों को प्रकाशित किया और निकट भविष्य में क्षेत्रीय और लिखत-वार विश्लेषण का विस्तार करने को प्राथमिकता दी है। वित्तीय खातों के अलावा, अमेरिका क्षेत्रीय स्तर पर गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए त्रैमासिक डेटा विकसित करने की दिशा में भी प्रगति कर रहा है।

भारत पांच संस्थागत क्षेत्रों के लिए वित्तीय तुलन पत्र का प्रसार कर रहा है और वित्तीय प्रवाह को लेनदेन और मूल्यांकन परिवर्तन (हाउसहोल्ड म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन और भविष्य निधि और केंद्रीय बैंक के लिए) में 2019[8] के बाद से वार्षिक आधार पर विभाजित कर रहा है, जबसे निधियों के प्रवाह में पहली बार क्षेत्र-वार बकाया के हिसाब से वृद्धि की गई। रिज़र्व बैंक 1951-52 से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एफओएफ लेखा प्रकाशित कर रहा है, और 1964 से एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू के आधार पर। भारत में काम, उद्विकासी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, समय-समय पर स्थापित विभिन्न समितियों के तहत आगे बढ़ा है। वर्तमान कार्य योजना वित्तीय क्षेत्र सांख्यिकी समिति, 2018 (अध्यक्ष: आर.एच. ढोलकिया) की सिफारिशों द्वारा निर्देशित की जा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: (i) उच्च आवृत्ति डेटा जारी करना – तिमाही और साथ ही कम अंतराल के साथ वार्षिक; (ii) नए चरों का कवरेज; और (iii) प्रवाह बनाम स्टॉक और लेनदेन बनाम मूल्यांकन जैसे नए पहलुओं का कवरेज।

2019-20 में, हाउसहोल्ड क्षेत्र के लिए तिमाही खातों का संकलन और प्रसार शुरू हुआ, जिसमें सकल हाउसहोल्ड उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में हाउसहोल्ड[9] की वित्तीय आस्तियों और देयताओं के स्टॉक और प्रवाह शामिल थे। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के केंद्र सरकार (सीजी) के वित्तीय खाते से ऋण और अग्रिम और इक्विटि निवेश डेटा; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रकाशित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख सांख्यिकी और वित्तीय विवरणों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की आस्तियों और देयताओं के बारे में अपेक्षाकृत विस्तृत जानकारी; राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ (एनएएफ़एससीओबी) रिपोर्ट से ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) पर जानकारी – एसटीसीबी, डीसीसीबी, पीएसी, एनएएफ़एससीओबी[10] के प्रदर्शन पर मूल डेटा (अनुबंध II) इत्यादि की वजह से कुछ और सुधार संभव हुए हैं। इसके अलावा, व्यक्तिक (खुदरा), उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति (एचएनआई) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ़[11]) श्रेणियों की निवल बिक्री को जोड़कर हाउसहोल्ड क्षेत्र से म्यूचुअल फंड में संसाधनों का निवल प्रवाह निकाला जाता है।

III. क्षेत्रवार वित्तीय संसाधन अंतराल

हाउसहोल्ड अर्थव्यवस्था का वित्तीय संसाधन अंतराल - वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण से वित्तीय देयताओं में 2019-20 में आयी कमी में निवल वृद्धि को घटाकर मापा गया (चार्ट 2)। जबकि हाउसहोल्ड और वित्तीय निगम निवल ऋणदाता बने रहे, 2019-20 के दौरान सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगमों और सामान्य सरकार की निवल उधारी में वृद्धि हुई।

प्रत्येक क्षेत्र की वित्तीय कीमत बकाया वित्तीय आस्तियों से बकाया बाह्य वित्तीय देयताओं को घटाकर निकाली जाती है। अर्थव्यवस्था में प्रमुख बचतकर्ता और अन्य क्षेत्रों के ऋणदाता

[8] ऋण प्रतिभूतियों, ऋणों और इक्विटी के लिए ब्रेक-अप के साथ-साथ जीजी क्षेत्र के लिए समेकित डेटा को एफओएफ खातों के टेम्पलेट के अनुरूप रिपोर्ट किया जाना है।

[9] आरबीआई बुलेटिन, मार्च 2022 वर्तमान सांख्यिकी, समसामयिक श्रृंखला के तहत।

[10] ग्रामीण सहकारी समितियों में, अल्पकालिक संस्थानों में राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) शामिल हैं।

[11] बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स (बीएसआर) सर्वेक्षण के अनुसार, क्रेडिट और जमा में हाउसहोल्ड के हिस्से में 'हाउसहोल्ड - अन्य' के हिस्से के रूप में एचयूएफ शामिल है। तदनुसार, हाउसहोल्ड क्षेत्र के म्युचुअल फंड में निवल प्रवाह के लिए, एचयूएफ श्रेणी को शामिल किया गया है।

चार्ट 2: वित्तीय संसाधन संतुलन

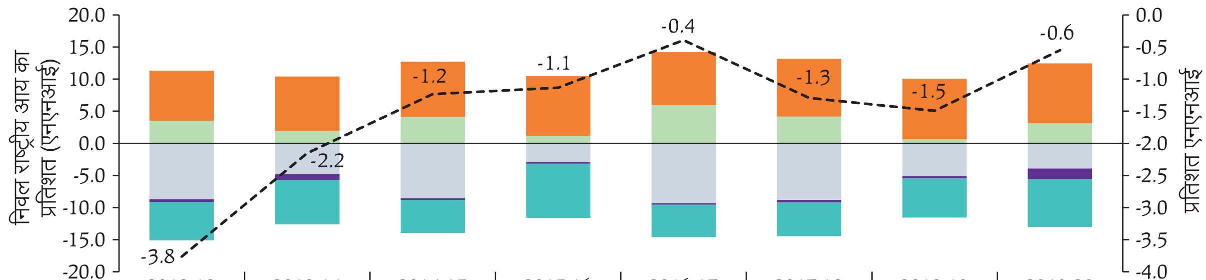

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
एचएच	7.8	8.5	8.6	9.3	8.2	9.0	9.4	9.3
जीजी	-6.0	-6.8	-5.1	-8.4	-5.0	-5.2	-6.1	-7.5
सरकारी एनएफ़सी	-0.4	-0.9	-0.3	-0.3	-0.2	-0.4	-0.4	-1.6
निजी एनएफ़सी	-8.7	-4.8	-8.6	-2.9	-9.3	-8.8	-5.1	-3.9
एफ़सी	3.5	1.9	4.1	1.2	6.0	4.2	0.6	3.1
कुल (दायाँ मान)	-3.8	-2.2	-1.2	-1.1	-0.4	-1.3	-1.5	-0.6

टिप्पणी: वित्तीय संसाधन संतुलन को वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण से वित्तीय देयताओं में निवल वृद्धि को घटाकर मापा जाता है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

होने के कारण, हाउसहोल्ड को एफसी के बाद उच्चतम वित्तीय निवल कीमत का आनंद मिलता है, जबकि जीजी और एनएफसी लगातार अर्थव्यवस्था में घाटे की स्थिति में बने हुए हैं (सारणी 1)।

सारणी 1: क्षेत्रीय वित्तीय निवल कीमत
(मौजूदा बाजार कीमतों पर एनएनआई का प्रतिशत)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वित्तीय आस्तियां									
1 **एफ़सी**	**222.5**	**224.3**	**224.3**	**227.4**	**227.0**	**226.8**	**230.0**	**230.0**	**235.6**
2 **एनएफ़सी**	**162.7**	**150.9**	**123.9**	**120.6**	**122.8**	**109.3**	**125.8**	**111.2**	**120.8**
2.1 सरकारी एनएफ़सी	11.7	10.7	9.8	8.9	8.0	7.5	7.5	7.5	7.4
2.2 निजी एनएफ़सी	151.0	140.2	114.0	111.7	114.9	101.8	118.3	103.8	113.4
3 **जीजी**	**29.3**	**28.9**	**27.5**	**27.1**	**25.7**	**26.5**	**27.4**	**27.7**	**28.5**
4 **एचएच**	**123.9**	**121.7**	**120.3**	**122.0**	**122.5**	**122.2**	**124.5**	**127.6**	**129.6**
5 **आरओडबल्यू**	**46.0**	**48.0**	**50.1**	**50.6**	**49.7**	**45.6**	**45.2**	**44.6**	**46.4**
वित्तीय देयताएँ									
1 **एफ़सी**	**192.9**	**193.6**	**194.1**	**196.3**	**196.3**	**194.1**	**195.6**	**197.0**	**200.3**
2 **एनएफ़सी**	**165.4**	**162.9**	**145.0**	**144.7**	**136.5**	**129.6**	**139.1**	**129.3**	**133.8**
2.1 सरकारी एनएफ़सी	12.8	12.0	11.7	10.8	10.1	9.4	9.5	9.6	11.0
2.2 निजी एनएफ़सी	152.6	151.0	133.2	134.0	126.4	120.2	129.6	119.7	122.9
3 **जीजी**	**85.2**	**84.2**	**83.4**	**82.5**	**84.2**	**83.7**	**84.1**	**85.2**	**90.2**
4 **एचएच**	**39.9**	**39.1**	**38.3**	**37.9**	**37.4**	**37.0**	**38.0**	**39.0**	**41.3**
5 **आरओडबल्यू**	**21.5**	**20.8**	**22.5**	**23.4**	**23.5**	**21.4**	**21.8**	**21.0**	**24.1**
वित्तीय निवल कीमत									
1 **एफ़सी**	**29.7**	**30.7**	**30.2**	**31.1**	**30.8**	**32.8**	**34.3**	**33.0**	**35.3**
2 **एनएफ़सी**	**-14.4**	**-19.1**	**-20.3**	**-26.6**	**-25.9**	**-30.6**	**-36.4**	**-37.5**	**-40.4**
2.1 सरकारी एनएफ़सी	-1.2	-1.2	-1.9	-1.9	-2.1	-1.9	-2.0	-2.1	-3.5
2.2 निजी एनएफ़सी	-13.2	-17.8	-18.4	-24.7	-23.8	-28.6	-34.4	-35.3	-36.8
3 **जीजी**	**-55.8**	**-55.3**	**-55.8**	**-55.4**	**-58.5**	**-57.2**	**-56.8**	**-57.5**	**-61.7**
4 **एचएच**	**84.0**	**82.6**	**82.0**	**84.1**	**85.1**	**85.2**	**86.5**	**88.6**	**88.3**
5 **आरओडबल्यू**	**24.5**	**27.2**	**27.6**	**27.2**	**26.2**	**24.2**	**23.4**	**23.7**	**22.3**

टिप्पणी: वित्तीय निवल कीमत की गणना बकाया वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं (शेयरधारकों की इक्विटी को छोड़कर) के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 3: क्षेत्रीय बकाया वित्तीय देयताएं* - 2019

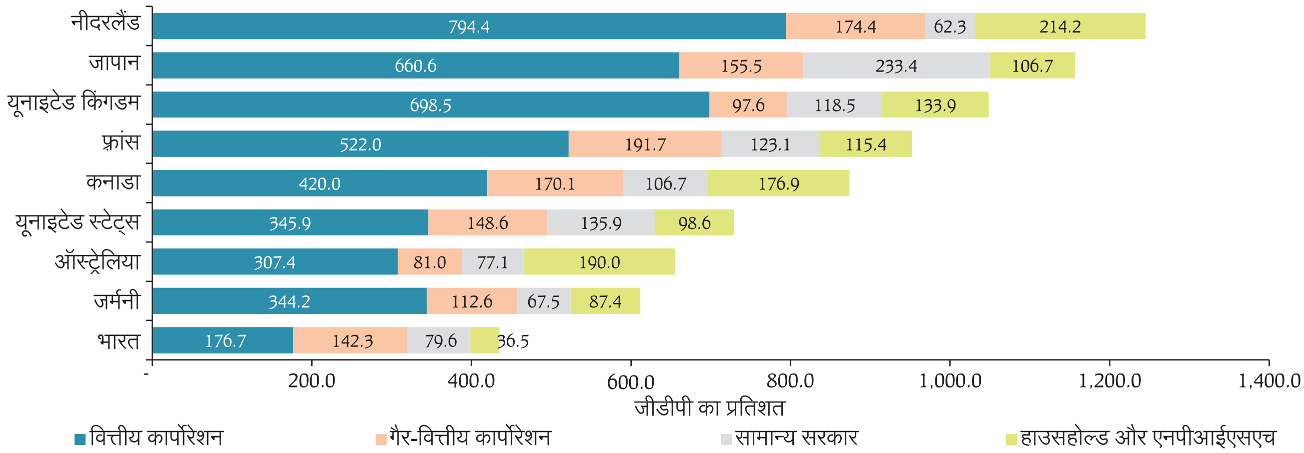

*: देयताओं में विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर), मुद्रा और जमा, कर्ज़ प्रतिभूतियां, ऋण, बीमा, पेंशन और मानकीकृत गारंटी और अन्य देय खाते शामिल हैं।
टिप्पणी: ए) हाउसहोल्ड क्षेत्र के आंकड़े सकल प्रयोज्य आय के प्रतिशत के अनुसार हैं।
बी) भारत के लिए डेटा 2019-20 के लिए हैं।
सी) ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हाउसहोल्ड का शेयर 2019 के लिए है जबकि जापान के लिए 2018 के लिए है।
स्रोत: ओईसीडी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

हमारी गणना के आधार पर भारत के लिए मार्च 2020 के अंत के डेटाबेस की तुलना में ओईसीडी डेटाबेस[12] के आधार पर दिसंबर 2019 के अंत में बकाया वित्तीय देयताओं की स्थिति अन्य देशों की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऋणग्रस्तता के उच्च स्तर को दर्शाती है (एई)। चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं के लिए, एफसी कुल बकाया वित्तीय देयताओं में अधिकतम हिस्सेदारी का योगदान करते हैं (चार्ट 3)।

IV.सभी क्षेत्रों में वित्तीय प्रवाह: 2019-20

क्षेत्रीय वित्तीय प्रवाह का मानचित्रण अनिवार्य रूप से संबंधित आर्थिक संस्थाओं के विशिष्ट तुलन पत्र से एकत्रित जानकारी पर आधारित है। वित्तीय वर्ष के अंत में विभिन्न वित्तीय लिखतों को जारी करने और धारण करने के स्नैपशॉट से और प्रतिपक्ष की स्थिति से क्षेत्रीय प्रवाह का पता लगाया जाता है। यह संस्थागत क्षेत्रों और निवासियों और गैर-निवासियों के बीच वित्तीय संबंधों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है, यह व्याख्या करता है कि कौन किसे, किस प्रकार के लिखत द्वारा और कितनी राशि में वित्तपोषित करता है।

[12] वित्तीय खाते, ओईसीडी, https://stats.oecd.org/

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवल प्रवाह (ऋण स्रोतों का उपयोग करता है) एक नेटवर्क प्लॉट में प्रस्तुत किया जाता है (चार्ट 4)। सापेक्ष हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद, हाउसहोल्ड और जीजी क्रमशः अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े ऋणदाता और उधारकर्ता बने हुए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में, अन्य निक्षेपागार निगमों (ओडीसी) और अन्य वित्तीय निगमों (ओएफ़सी) से जीजी में निवल प्रवाह; और 2019-20 में आरओडबल्यू से पीवीएनएफ़सी में वृद्धि हुई, जैसा कि मोटे दिशात्मक किनारों में दिखाई देता है।

वित्तीय आस्तियों में लिखत-वार निवेश

2019-20 के दौरान संसाधनों की तैनाती के लिए ऋण और अग्रिम सबसे पसंदीदा लिखत रहे, इसके बाद मुद्रा और जमा राशि का स्थान रहा। ओएफसी और रिज़र्व बैंक के निवेश का एक बड़ा हिस्सा ऋण प्रतिभूतियों में था - जबकि पूर्व की सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक हिस्सेदारी थी, रिज़र्व बैंक ने ज्यादातर विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश किया (चार्ट 5)। इक्विटी और निवेश निधियों के माध्यम से निवेश पर कॉर्पोरेट्स और आरओडबल्यू के निवेश का बोलबाला था। बीमा, पेंशन और भविष्य निधि के बाद मुद्रा और जमा हाउसहोल्ड के लिए पसंदीदा निवेश साधन बने रहे।

चार्ट 4: क्षेत्रीय प्रवाह

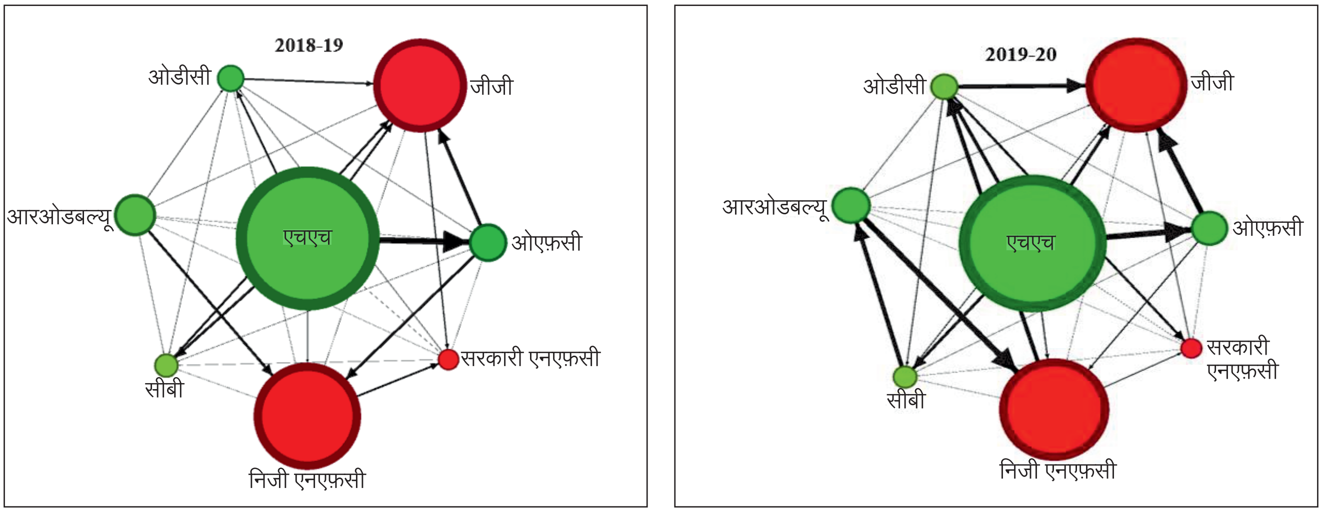

टिप्पणी: नोड का आकार अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों की सापेक्ष बकाया निवल ऋण/उधार की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। किनारों का वजन वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में सापेक्ष क्षेत्रीय प्रवाह के शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। निवल ऋणदाता हरे रंग में दिखाई देते हैं जबकि निवल उधारकर्ता लाल रंग में।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

2019-20 के दौरान वित्तीय आस्तियों और देयताओं के क्षेत्र-वार प्रवाह को निम्नलिखित उप-खंडों में विस्तारित किया गया है:

IV.1 वित्तीय निगम

ओडीसी एफसी के सबसे बड़े उप-क्षेत्र का गठन करते हैं। जिनका 2019-20 में एफसी की कुल वित्तीय आस्ति का 52.1 प्रतिशत था, इसके बाद ओएफसी (36.0 प्रतिशत) और केंद्रीय बैंक (11.9 प्रतिशत) थे। ओडीसी में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के पास एफसी की कुल वित्तीय आस्ति में एक बड़ा हिस्सा (44.2 प्रतिशत) है, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की बैंक-आधारित प्रकृति को उजागर करता है। ओएफसी के अंतर्गत, प्रमुख भाग बीमा क्षेत्र का, इसके बाद गैर-जमा एनबीएफसी

चार्ट 5: वित्तीय आस्तियों में लिखत-वार निवेश - 2019-20

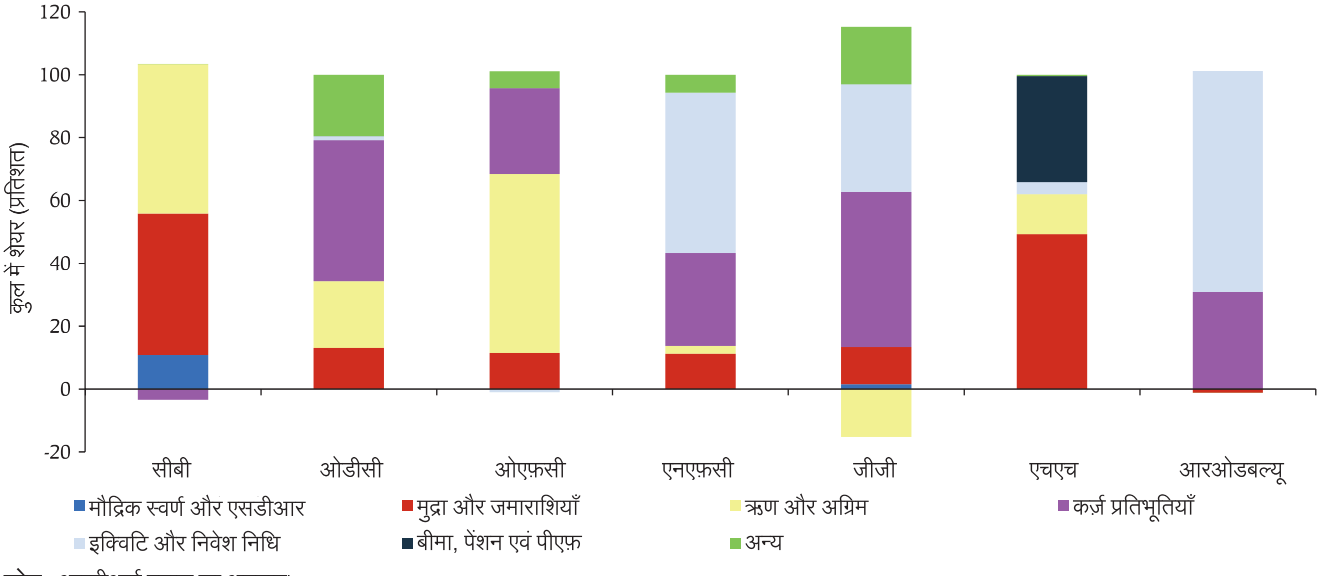

स्रोत : आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 6: वित्तीय निगम - कुल वित्तीय आस्तियों में शेयर - 2019-20

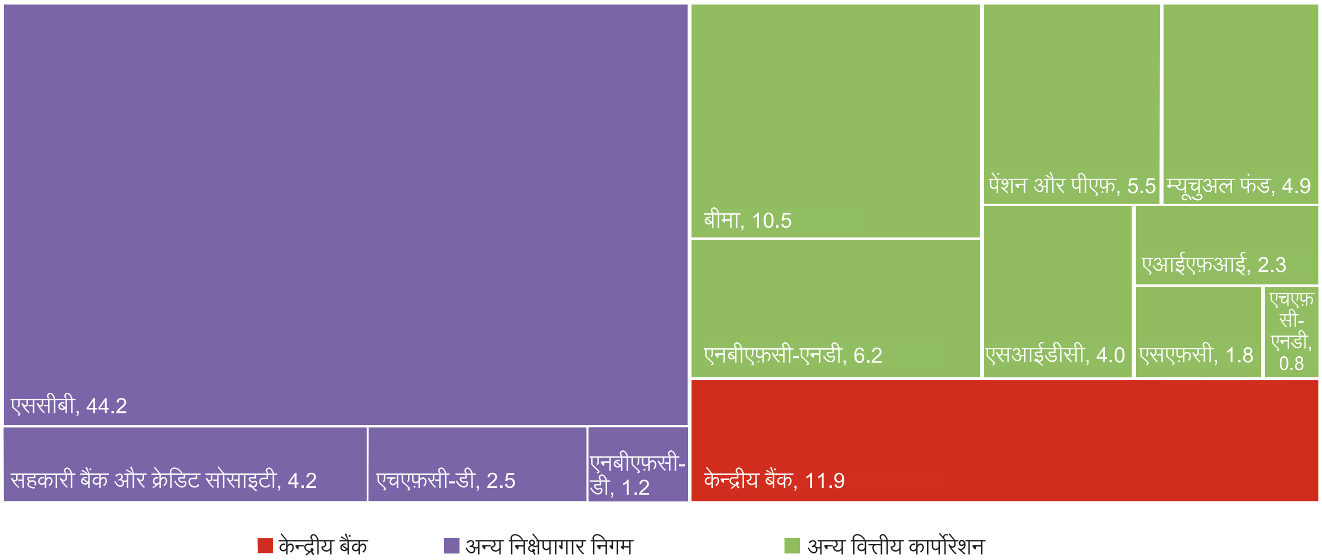

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(एनबीएफसी-एनडी), भविष्य और पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड का है (चार्ट 6)।

IV.1.1 सेंट्रल बैंक

रिज़र्व बैंक की वित्तीय निवल संपत्ति 2018-19 में 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 7.3 प्रतिशत हो गई, साथ ही संस्थान निवल ऋण देने वाले क्षेत्रों में से एक बना रहा। 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि में मंदी को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जून 2019 में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को तटस्थ से समायोजनात्मक कर दिया था। इससे बैंक की वित्तीय आस्ति में 2018-19 में जीडीपी के 21.7 प्रतिशत से 2019-20 में जीडीपी के 24.6 प्रतिशत तक का विस्तार हुआ। 2019-20 में जीडीपी। वित्तीय देयताएँ[13], हालांकि, 2019-20 में बढ़कर 18.2 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 16.4 प्रतिशत थी।

प्रचलन में मुद्रा का प्रवाह, जो एक साल पहले कम हुआ था, 2019-20 के दौरान मामूली रूप से बढ़ा, जिससे मुद्रा-जीडीपी अनुपात 12.1 प्रतिशत हो गया। रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियों में 2019-20 के दौरान वृद्धि हुई, मुख्य रूप से चलनिधि उपलब्ध कराने के कारण जिसकी वजह से रिवर्स रिपो दर में कमी के बावजूद ओडीसी के साथ रिवर्स रिपो हुआ[14]।

वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) की अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। स्वर्ण की होल्डिंग में वृद्धि और स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण मौद्रिक स्वर्ण भंडार में वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान एफ़सीए[15] के स्टॉक में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2018-19 में यह 2.7 प्रतिशत था। अन्य केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियों में अधिकतम वृद्धि देखी गई, इसके बाद ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का नंबर था। एफसीए ने महामारी के प्रकोप के साथ, 'सुरक्षा के लिए उड़ान' द्वारा संचालित मूल्यांकन लाभ अर्जित किया। विभिन्न चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के कारण पिछले वर्ष में 44.1 प्रतिशत

[13] आरक्षित मुद्रा में प्रचलन में मुद्रा, बैंकरों की जमा और रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमा शामिल हैं, हालांकि, जो एक साल पहले के 14.7 प्रतिशत से 2019-20 में जीडीपी का 15.1 प्रतिशत हो गया।

[14] रिवर्स रिपो दर को 27 मार्च, 2020 को घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया था, ताकि बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के पास निष्क्रिय रूप से धन जमा करना अपेक्षाकृत अनाकर्षक हो जाए और इसके बजाय, इन निधियों का उपयोग अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को उधार देने के लिए किया जाए (आरबीआई, 2020ए)।

[15] एफसीए में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियां; (ii) बीआईएस के पास जमा; (iii) विदेशों में वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियां; (iv) विदेशी टी-बिल और प्रतिभूतियों में निवेश; और (v) भारत सरकार से प्राप्त एसडीआर शामिल हैं।

की तुलना में 2019-20 में हाउसहोल्ड प्रतिभूतियों, जैसे दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और टी-बिलों में निवेश में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा कई चलनिधि बढ़ाने के उपायों में वृद्धि जैसे दीर्घकालिक रिपो परिचालन (एलटीआरओ) और वर्ष के उत्तरार्ध में लक्षित एलटीआरओ के कारण ओडीसी के ऋण और अग्रिम का विस्तार हुआ।

IV.1.2 अन्य निक्षेपागार निगम

कारकों का एक संगम, जैसे, आर्थिक मंदी, कॉर्पोरेट तुलन पत्रों के ऋण कम करना, बैंकों की ओर से जोखिम से बचने और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निरस्तीकरण से 2014-15 से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ओडीसी की वित्तीय आस्तियों में लगातार गिरावट आई थी। बेहतर आस्ति गुणवत्ता, मजबूत पूंजी और बफर प्रावधान और लाभप्रदता पर प्रतिफल के कारण 2019-20 के दौरान एक बदलाव आया (चार्ट 7)। हालांकि, 2018-19 की तुलना में, सकल हाउसहोल्ड उत्पाद की वृद्धि में मंदी की पृष्ठभूमि में, एससीबी, सहकारी समितियों और एनबीएफसी-डी में जमा वृद्धि ने गति दी, सबसे ज़्यादा कमी सहकारी बैंकों में आयी। ब्याज दरों में ढील के कारण प्रतिस्पर्धी आस्ति वर्ग आकर्षक हो गए और एक निजी क्षेत्र के बैंक से संबंधित ऋण-शोधन के मुद्दों ने भी फिर से थोड़ी जमाराशियाँ लाईं (आरबीआई, 2020बी)।

चार्ट 7: ओडीसी की वित्तीय आस्तियां और देयताएँ

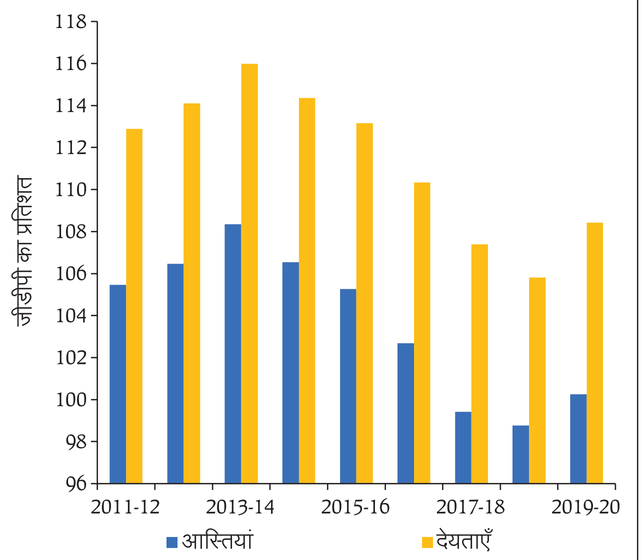

स्रोत : आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

आस्तियों के पक्ष में 2019-20 में धीमी अर्थव्यवस्था में जोखिम से बचने और सुस्त मांग दोनों को दर्शाते हुए, एससीबी द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में गिरावट आई, जबकि जोखिम मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेश में सुधार हुआ, जैसा कि

चार्ट 8: ओडीसी की वित्तीय आस्तियों का क्षेत्र-वार प्रवाह

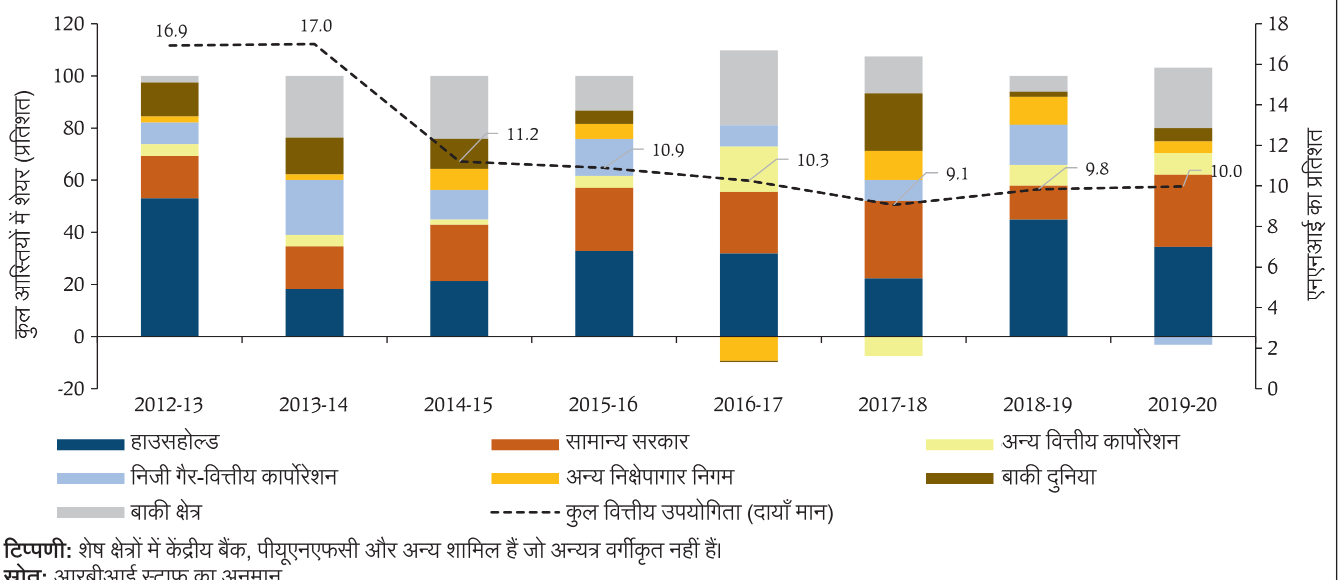

टिप्पणी: शेष क्षेत्रों में केंद्रीय बैंक, पीयूएनएफसी और अन्य शामिल हैं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान

चार्ट 9: ओडीसी द्वारा क्षेत्रवार वित्तीय देयताओं का भार

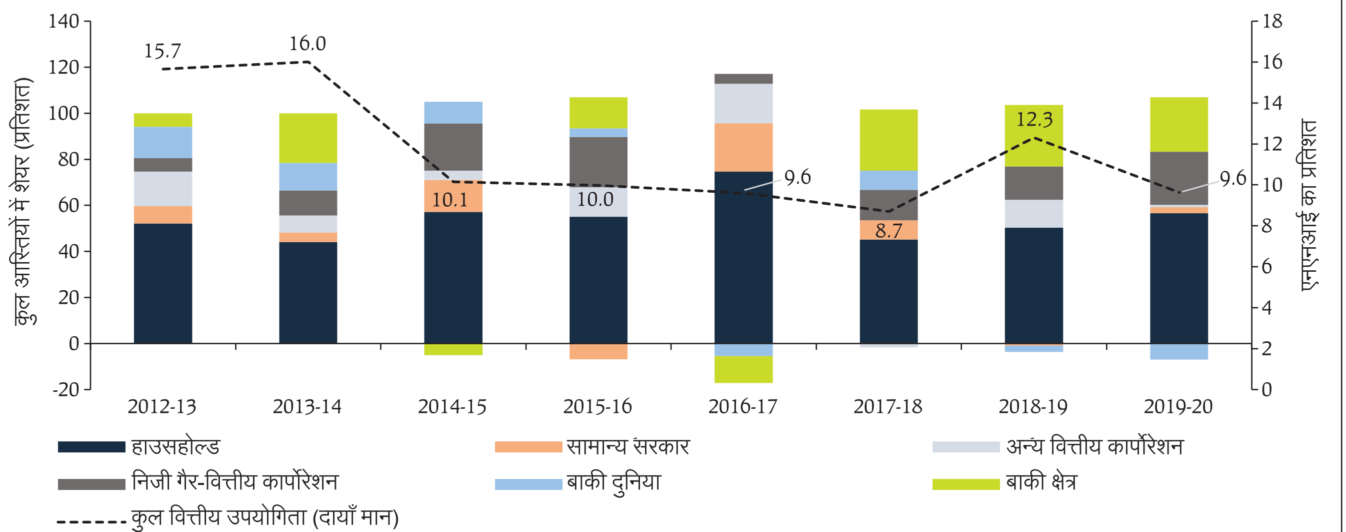

टिप्पणी: शेष क्षेत्रों में केंद्रीय बैंक, पीयूएनएफसी और अन्य शामिल हैं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

ओडीसी के समग्र रुझान में परिलक्षित होता है (चार्ट 8)। इसी स्वरूप अनुसार, एनबीएफसी-डी की ऋण वृद्धि में कमी आई, जबकि उनके निवेश - विशेष रूप से म्यूचुअल फंड में तेजी आई। एचएफसी-डी के मामले में, अचल संपत्ति क्षेत्र में बढ़ते दबाव से ऋण और अग्रिम में तेज़ी से कमी के कारण उनकी वित्तीय आस्तियों की वृद्धि में कमी आई है (आरबीआई, 2020बी)। सहकारी बैंकिंग संस्थानों की व्यापक पहुंच समाज के असंबद्ध और ऋण-वंचित वर्गों तक है, हालांकि, हाउसहोल्ड को दिए गए ऋणों और अग्रिमों द्वारा मुख्य रूप से संचालित 2018-19 में 3.1 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में वित्तीय आस्तियों में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

हाउसहोल्ड जमा सबसे महत्वपूर्ण लिखत है जिसमें ओडीसी की देयताएँ, इसके बाद पीवीएनएफसी से जमा शामिल हैं (चार्ट 9)। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी प्रवाह को 2019-20 में बढ़ावा मिला, जिससे एससीबी में सरकार की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 41.9 प्रतिशत से बढ़कर 56.6 प्रतिशत हो गई। यह सरकार के प्रति ओडीसी की बढ़ती देयता में परिलक्षित होता था।

सहकारी समितियों के अंतर्गत, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) मुख्य रूप से अपनी निधि के लिए हाउसहोल्ड जमा पर निर्भर थे, जबकि ओएफसी से उधार के साथ अन्य सहकारी समितियों से जमा ने ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को उनके कार्यों के वित्तपोषण में सहायता की। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) चूक और संबंधित नुकसान के संदर्भ में एनबीएफसी-डी और एचएफसी-डी दोनों के फंड के लिए बैंकों पर निर्भरता बढ़ी (आरबीआई, 2020 बी)। एचएफसी-डी द्वारा ऋणपत्र जारी करना भी 2019-20 के दौरान कम हुआ। चल रही वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण वर्ष के दौरान आरओडब्ल्यू के प्रति ओडीसी की देयताएँ कम हो गई और भारत उभरते बाजार वाले देशों के बीच उच्चतम बहिर्वाह करने वालों में से एक होने का अनुभव कर रहा है (आरबीआई, 2020 ए)।

IV.1.3 अन्य वित्तीय निगम

ओएफसी की वित्तीय आस्तियां और देयताएँ, जो पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रही थीं, 2019-20 में जीडीपी के क्रमशः 1.0 और 0.6 प्रतिशत अंक पर सिमट गईं (चार्ट 10)। हालांकि, ओएफसी की वित्तीय आस्तियों और देयताओं की वृद्धि में कमी को वर्ष के दौरान दर्ज की गई कम जीडीपी वृद्धि के मुकाबले देखा जाना चाहिए।

एचएफसी-एनडी ने अपनी वित्तीय आस्तियों और देयताओं में मामूली संकुचन देखा, जबकि एनबीएफसी-एनडी के मामले में

चार्ट 10: ओएफसी की वित्तीय आस्तियां और देयताएँ

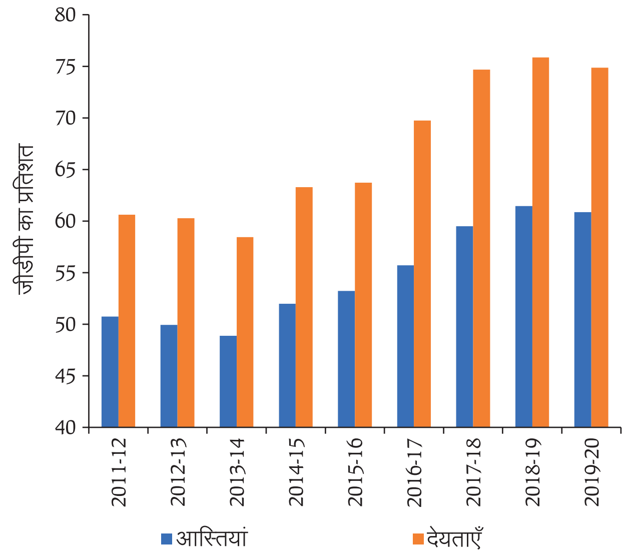

स्रोत : आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

वृद्धि पिछले दो वर्षों में दोहरे अंकों की वृद्धि की तुलना में 2019-20 में घट गई। एनबीएफसी-डी के रुझानों का अनुसरण करते हुए, आईएलएंडएफएस चूक और संबंधित डाउनग्रेड के बाद एनबीएफसी-एनडी के लिए ऋण पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। एनबीएफसी-एनडी की विदेशी देयताओं में बढ़ोतरी रिज़र्व बैंक द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मानदंडों में ढील के कारण आसान हुई, इससे उन्हें विदेशी फंड तक पहुंचने में मदद मिली (आरबीआई, 2020 बी)। चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई)[16] की देयताएँ जो ओएफसी का एक हिस्सा हैं, मुख्य रूप से ओडीसी की जमा राशि, ओएफसी, ओडीसी और सीजी की ऋण प्रतिभूतियों और सीजी के इक्विटी शेयरों द्वारा संचालित होती हैं। जबकि सिडबी में बहुसंख्यक इक्विटी होल्डिंग (लगभग 85 प्रतिशत) ओडीसी और ओएफसी के पास है, अन्य तीन के मामले में सीजी का पूरा स्वामित्व है।

फरवरी-मार्च 2019-20[17] में शेयर बाजार में गिरावट के कारण ओएफसी के तुलन पत्र में इक्विटी और निवेश फंड की बाजार कीमतों में काफी कमी आई है। जीजी प्रतिभूतियाँ साथ ही 2019-20 में अंतर-क्षेत्रीय उधार हाल के वर्षों में ओएफसी के लिए अनुकूल निवेश का मार्ग बने रहे(चार्ट 11)। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की चपेट में आने पर आईएल एवं एफ़एस प्रकरण के बाद आत्मविश्वास में कमी, चलनिधि दबाव और रेटिंग में गिरावट

चार्ट 11: ओएफसी की वित्तीय आस्तियों का क्षेत्रवार प्रवाह

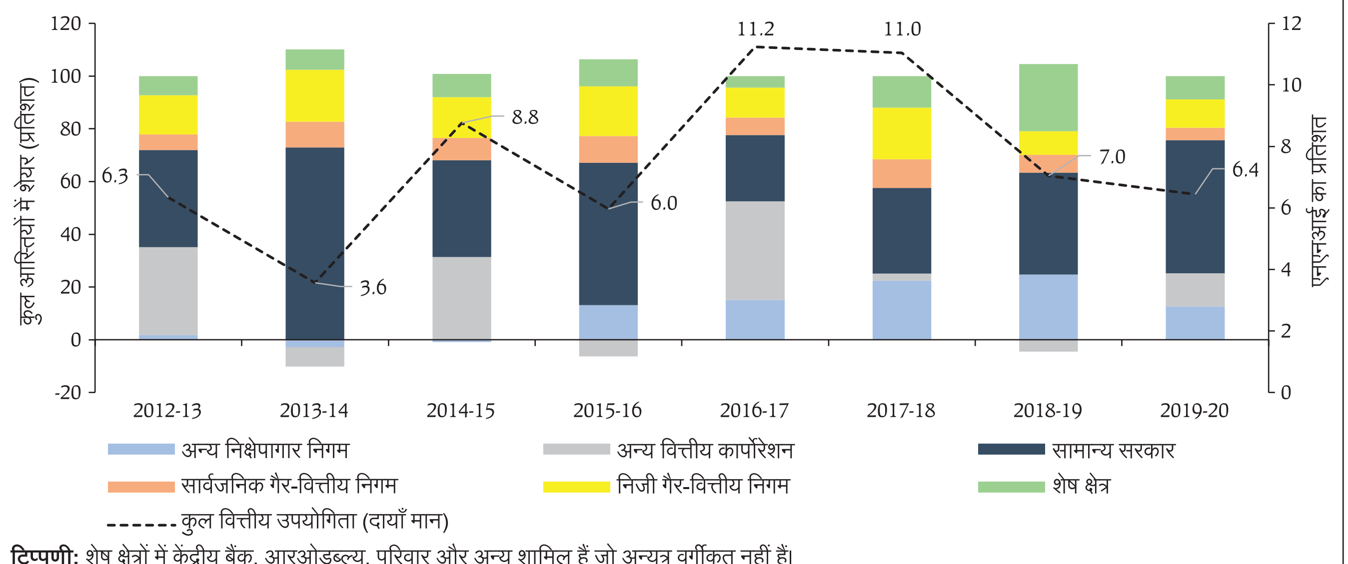

टिप्पणी: शेष क्षेत्रों में केंद्रीय बैंक, आरओडब्ल्यू, परिवार और अन्य शामिल हैं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

---

16 नाबार्ड, एक्जिम बैंक, सिडबी और एनएचबी एआईएफआई हैं।

17 https://www.thehindubusinessline.com/markets/stock-markets/market-rout-mutual-funds-equity-assets-halve-in-march/article31273736.ece; https://www.paytmmoney.com/blog/amfi-mutual-fund-report-march/

और तेज हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 में एनबीएफ़सी-एनडी की आस्ति वृद्धि में पर्याप्त गिरावट आई (आरबीआई, 2020बी)। मुख्य रूप से सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा संचालित, बीमा और भविष्य निधि की सकल वित्तीय आस्तियों ने 2019-20 में अपनी बढ़ती प्रवृत्ति को जारी रखा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निवेश पर अधिसूचना[18] के बाद, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की ओर निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) दोनों ने अपने ग्राहक आधार में वृद्धि दर्ज करते हुए 2019-20 में पेंशन फंड की वित्तीय संपत्ति में वृद्धि की। एआईएफआई के मामले में, हाउसहोल्ड को छोड़कर सभी क्षेत्रों में ऋण और अग्रिम में व्यापक रूप से वृद्धि हुई।

IV.2 गैर-वित्तीय निगम

अधिकांश आस्तियां गैर-वित्तीय प्रकृति की होने के कारण, एनएफसी की वित्तीय निवल संपत्ति उनकी कुल निवल संपत्ति से काफी कम है। समग्र स्तर पर, पीयूएनएफसी का वित्तीय संसाधन अंतराल 2018-19 में (-) 0.4 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में (-) 1.6 प्रतिशत हो गया, जबकि पीवीएनएफसी में सुधार हुआ जो पिछले वर्ष के (-)5.1 प्रतिशत से (-) 3.9 प्रतिशत हो गया। 2019-20 में, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा बढ़ी हुई उधारी ने पीयूएनएफ़सी की वित्तीय देयताओं को उपर खींचा। दूसरी ओर, इक्विटी निवेश और अन्य खाता प्राप्तियों के मूल्य में गिरावट के कारण वित्तीय आस्तियों में वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है।

पीवीएनएफसी - कुल वित्तीय आस्तियों और देयताओं के आकार के मामले में एफसी और हाउसहोल्ड के बाद तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र - 2019-20 में अर्थव्यवस्था की वित्तीय आस्तियों का 20.2 प्रतिशत था। पीवीएनएफ़सी द्वारा वित्तीय देयताओं की वृद्धि ने आस्ति अधिग्रहण के साथ-साथ 2018-19 से वृद्धि का प्रदर्शन किया। लिखतों के संदर्भ में, एफसी से ऋण और उधार, इक्विटी के बाद पीवीएनएफसी के लिए वित्त का प्रमुख स्रोत रहा है।

[18] श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। भारत की अधिसूचना संख्या 1071 (ई) दिनांक 23 अप्रैल 2015 ने ईपीएफओ द्वारा इक्विटी और संबंधित निवेश में 5 से 15 प्रतिशत निवेश निर्धारित किया है (निफ्टी और सेंसेक्स के ईटीएफ)।

IV.3 सामान्य सरकार[19]

जीजी और एनएफसी नकारात्मक संसाधन शेष वाले केवल दो क्षेत्र हैं। जबकि जीजी की वित्तीय आस्ति सकल हाउसहोल्ड उत्पाद के 25 प्रतिशत तक मामूली रूप से सुधरी, वित्तीय देयताएँ 2019-20 में बढ़कर 80 प्रतिशत हो गईं, जिनमें से सीजी की देयताएँ सकल पारिवारिक उत्पाद के 53 प्रतिशत तक थी। इसके अलावा, वित्तीय देयताओं में वृद्धि वित्तीय आस्तियों में उल्लेखनीय 3.4 प्रतिशत अंक से आगे निकल गई।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने अधिकांश ऋणों को विपणन योग्य ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से वित्तपोषित करती हैं, जिन्हें मुख्य रूप से ओडीसी, ओएफसी और हाउसहोल्ड द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है (चार्ट 12)। पिछले वर्षों की तरह, 2019-20 के दौरान ऋण प्रतिभूतियों का सब्सक्रिप्शन स्वरूप समान रहा। भारतीय खाद्य निगम (एफ़सीआई) जो बिना लाभ और हानि के आधार पर काम करता है और सरकार से सब्सिडी और अनुदान के माध्यम से भी समर्थन प्राप्त करता है, उसे सीजी[20] के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2016-17 के बाद से एफसीआई द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) उधार, जिसे सीजी द्वारा उधार माना जाता है, मार्च 2020 के अंत तक ₹ 2,54,600 करोड़ था। राज्य सरकारों के मामले में, जबकि उनकी निवल बाजार उधारी में वृद्धि हुई लगभग 40 प्रतिशत, सकल बाजार उधार 32.7 प्रतिशत बढ़ा (आरबीआई, 2020सी)।

सीजी की आस्ति संरचना पर तीन लिखतों का प्रभुत्व है, अर्थात् इक्विटी निवेश (35.9 प्रतिशत); ऋण और अग्रिम (28.6 प्रतिशत); और ऋण प्रतिभूतियां (18.0 प्रतिशत)। पिछले एक दशक में, सीजी का निवेश पोर्टफोलियो ऋण प्रतिभूतियों से हटकर इक्विटी और ऋण और अग्रिम में चला गया। विशेष रूप से, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों (आरबीआई को छोड़कर) में सीजी की इक्विटी 21.9 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में लगभग ₹3.6 लाख करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹4.4 लाख करोड़ हो

[19] जीजी में केवल सीजी और राज्य सरकारें शामिल हैं

[20] एसएनए 2008 एक सार्वजनिक निगम, या सरकार द्वारा नियंत्रित निगम को किसी अन्य सार्वजनिक इकाई/सरकार द्वारा नियंत्रित निगम के रूप में परिभाषित करता है और यह एक बाजार निर्माता भी है, यानी एक इकाई जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीमतों पर अपने सभी या अधिकांश उत्पादन दूसरों को प्रदान करती है। एफसीआई का शत-प्रतिशत स्वामित्व सीजी के पास है और यह लाभ कमाने वाला निगम नहीं है जिसमें संपूर्ण निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए है। उपरोक्त वर्गीकरण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, एफसीआई को सीजी के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

चार्ट 12: सामान्य सरकार के वित्तीय संसाधन अंतराल

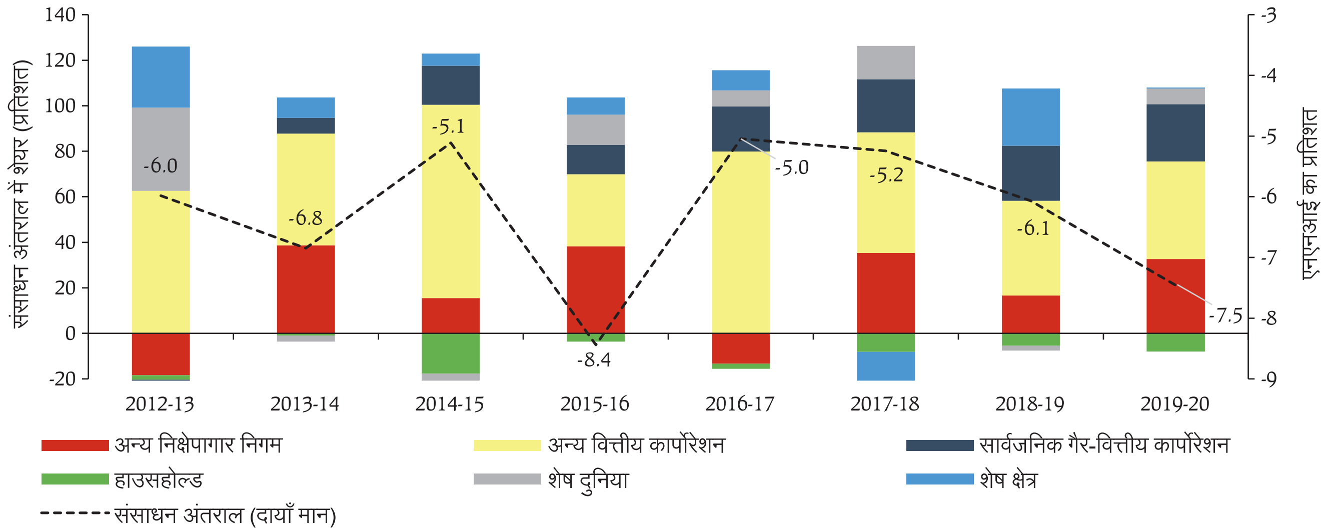

टिप्पणी: शेष क्षेत्रों में केंद्रीय बैंक, जीजी, पीवीएनएफसी और अन्य शामिल हैं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

गई। राज्य सरकारों के लिए, उनकी अधिकांश वित्तीय आस्तियां जमा के रूप में होती है, उसके बाद इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों का स्थान होता है।

IV.4 हाउसहोल्ड (एनपीआईएसएच सहित)

हाउसहोल्ड, उपभोग व्यय का सबसे बड़ा स्रोत होने के अलावा, अर्थव्यवस्था में वित्तीय और गैर-वित्तीय आस्तियों में निवेश के लिए वित्तीय अधिशेष में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वित्तीय आस्तियों में तेज गिरावट के साथ वित्तीय आस्तियों और हाउसहोल्ड क्षेत्र की देयताओं दोनों में वृद्धि 2019-20 में कमजोर हुई। परिणामस्वरूप, 2019-20 में हाउसहोल्ड क्षेत्र का वित्तीय अधिशेष 0.1 प्रतिशत अंक से थोड़ा कम होकर एनएनआई के 9.3 प्रतिशत हो गया (चार्ट 13)।

चार्ट 13: हाउसहोल्ड का वित्तीय अधिशेष

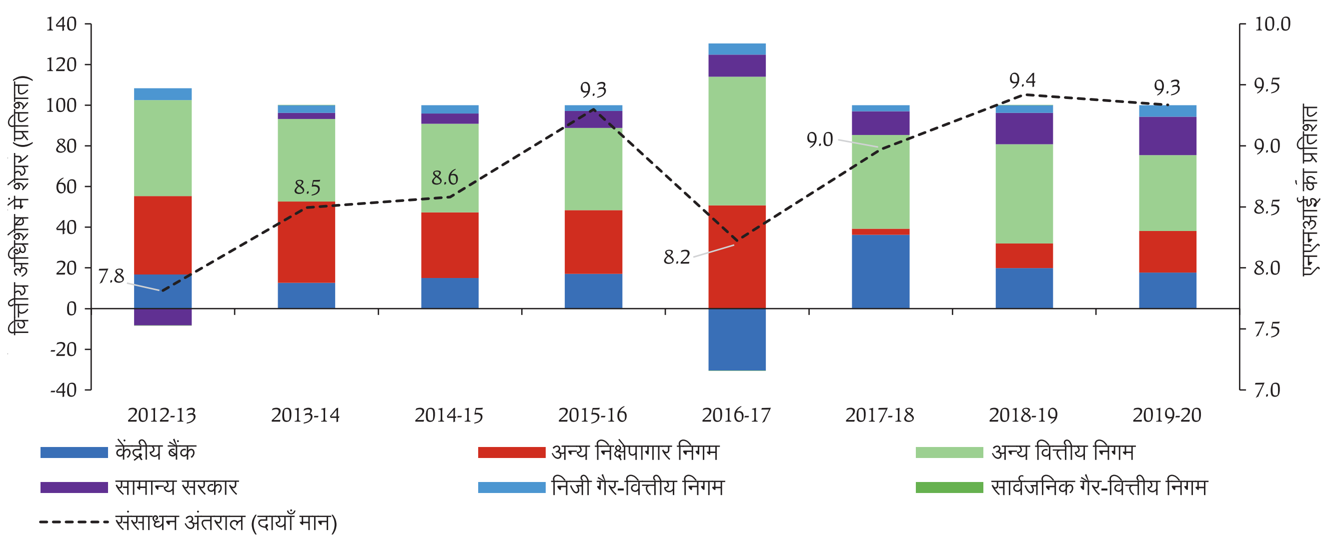

स्रोत : आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

विवेकाधीन व्यय में कमी और स्थिर/कम आय के बावजूद एहतियाती/जबरन बचत में संबंधित वृद्धि के कारण 2020-21 में हाउसहोल्ड वित्तीय बचत में जीडीपी के 11.6 प्रतिशत की वृद्धि ने पहले ही हाउसहोल्ड वित्तीय आस्तियों में बढ़ोतरी की पुष्टि कर दी है। वित्तीय आस्तियों के प्रवाह में ओडीसी की हिस्सेदारी, जो 2017-18 में एक नगण्य स्तर तक कम हो गई - पुनर्मुद्रीकरण के कारण हाउसहोल्ड द्वारा बड़ी मात्रा में नकदी की निकासी हुई – जो 2019-20 में लगभग 21 प्रतिशत तक बढ़ गई। विशेष रूप से पहली तिमाही में, गैर-आवश्यक उपभोग व्यय के कारण, 2020-21 में इस उछाल के और मजबूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा, परिवारों से बीमा क्षेत्र तक संसाधनों का एक स्थिर प्रवाह बनाए रखा जाता है, जिसके 2020-21 में और बढ़ने की संभावना है।

जमा और बीमा की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है, 2019-20 में हाउसहोल्ड वित्तीय आस्तियों का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद इक्विटी, मुद्रा, ऋण प्रतिभूतियां और म्यूचुअल फंड में निवेश है। निवेश फंडों के प्रति हाउसहोल्ड की प्राथमिकता में बदलाव उनके बकाया आस्ति मूल्य में दीर्घकालिक वृद्धि में भी परिलक्षित होता है, हालांकि, मार्च 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिकवाली के बाद गिरावट आई है।

IV.5 शेष विश्व

भारत 2019-20 में आरओडबल्यू से निवल कर्जदार बना रहा। हालांकि, विदेशी संसाधनों पर निर्भरता एक साल पहले की तुलना में 2019-20 में कम हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच कम व्यापार घाटे और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों की वजह से और वैश्विक निवेश चिंताओं में वृद्धि के कारण भारत के चालू खाते के घाटे (सीएडी) को 2018-19 में (-) 2.1 प्रतिशत से कम करके 2019-20 में जीडीपी के (-)0.9 प्रतिशत तक सीमित करने की पुष्टि की गई है। अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, विदेशी पूंजी के प्रमुख स्रोतों में वृद्धि हुई और निवल पूंजी अंतर्वाह निम्न सीएडी को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था।

मार्च 2020 के अंत तक, आरओडब्ल्यू की कुल वित्तीय देयताओं का दो-तिहाई रिज़र्व बैंक के लिए आरक्षित आस्ति[21], विशेष रूप से प्रतिभूतियों और अन्य केंद्रीय बैंकों के पास जमा के रूप में था। आरक्षित आस्तियों के अलावा, लगभग एक तिहाई ऋण प्रतिभूतियों और इक्विटी के रूप में एनएफसी की ओर था। आरओडब्ल्यू की देयताएँ 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में 20.8 प्रतिशत बढ़ी, जिसका मुख्य कारण विदेशों में जारी ऋण प्रतिभूतियों में रिज़र्व बैंक की सब्स्क्रिप्शन में वृद्धि थी(चार्ट 14)।

आरओडब्ल्यू द्वारा एनएफसी की इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों का अधिग्रहण 2019-20 में मजबूत रहा। इसके अलावा, भारत निरंतर आर्थिक सुधारों के बल पर, 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गति को बनाए रखने में सक्षम था। हालाँकि, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ़पीआई) प्रवाह बड़े पैमाने पर वैश्विक विकास से प्रभावित था और सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा कई विश्वास निर्माण उपायों के बावजूद, 2019-20 की शुरुआत से अस्थिर रहा। कोविड-19 के मद्देनजर वैश्विक जोखिम से बचने की एक अभूतपूर्व लहर के कारण वित्तीय वर्ष के अंत तक निवल बिकवाली हुई। वास्तव में, 2019-20 की चौथी तिमाही में ईएमई से बहिर्वाह सुरक्षा के लिए अब तक की सबसे बड़ी उड़ान थी। विदेशी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए, जैसे, एफपीआई निवेश की सीमा में वृद्धि, विदेशी निवेशकों के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना, एफ़पीआई द्वारा सीजी प्रतिभूतियों (टी-बिल सहित) और राज्य विकास ऋणों में अल्पकालिक निवेश में वृद्धि। इन उपायों ने मार्च 2020 के अंत तक एफपीआई बहिर्वाह को काफी हद तक उलटने में मदद की। प्रचुर मात्रा में वैश्विक चलनिधि, अनुकूल विदेशी ब्याज दरों और उदारीकरण उपायों जैसे कारकों के संयोजन से 2019-20 में मजबूत ईसीबी अंतर्वाह हुआ। कुल मिलाकर, 2019-20 में

[21] आरक्षित आस्तियों में मौद्रिक स्वर्ण, एसडीआर होल्डिंग्स, आईएमएफ में आरक्षित स्थिति, मुद्रा और जमा, प्रतिभूतियां और अन्य दावे शामिल हैं।

चार्ट 14: आरओडबल्यू द्वारा वित्तीय देयताओं का निवल भार

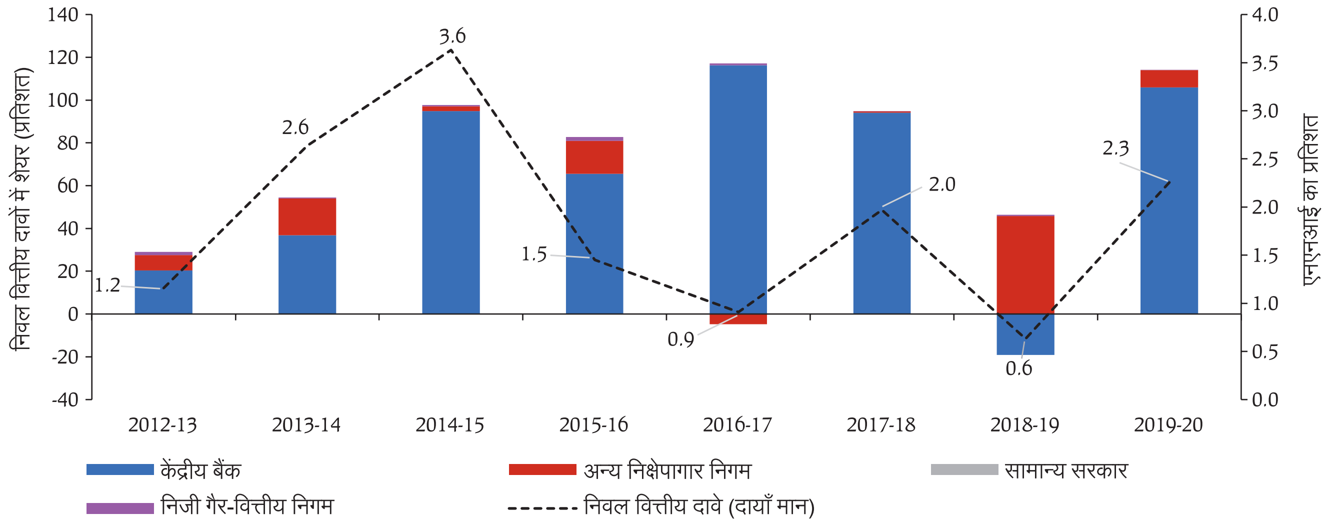

टिप्पणी: ओएफसी, पीयूएनएफसी और एचएच सहित शेष क्षेत्रों के साथ आरओडबल्यू की वित्तीय देयताओं का कोई निवल भार नहीं है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

आरओडबल्यू द्वारा आस्तियों का निवल अधिग्रहण 2018-19 के स्तर पर लगभग स्थिर रहा (चार्ट 15)।

V. निष्कर्ष

वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण से वित्तीय देयताओं में निवल वृद्धि को घटाने से प्राप्त, अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधन अंतराल में 2019-20 में कमी आयी। हाउसहोल्ड और वित्तीय निगमों ने घाटे वाले क्षेत्रों को बाह्य निधिकरण की कम आवश्यकता के साथ चलनिधि प्रदान करना जारी रखा। 2019-20 में आरओडबल्यू से निवल उधारी में तेजी से गिरावट आई। रिज़र्व बैंक का वित्तीय संसाधन संतुलन सकारात्मक क्षेत्र में रहा – जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में

चार्ट 15: आरओडबल्यू द्वारा वित्तीय आस्तियों का निवल अधिग्रहण

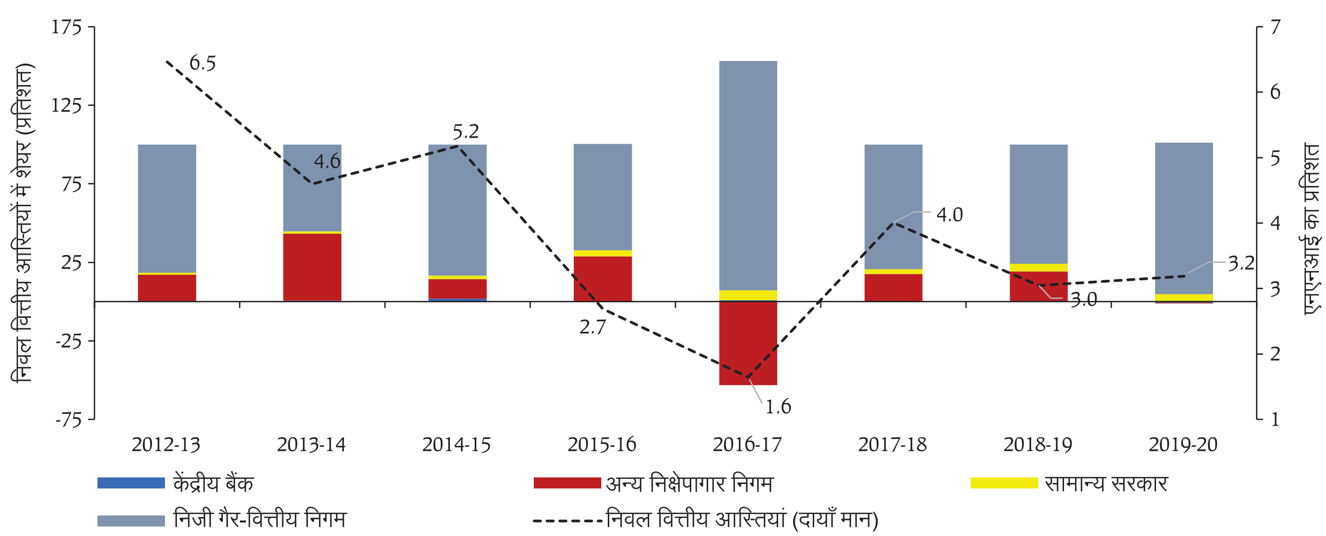

टिप्पणी: आरओडबल्यू के पास ओएफसी, पीयूएनएफसी और एचएच सहित शेष क्षेत्रों के साथ वित्तीय आस्तियों का कोई निवल अधिग्रहण नहीं है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सामान्य मंदी की पृष्ठभूमि में समय पर और उचित चलनिधि सहायता सुनिश्चित करता है। अधिशेष संसाधन उत्पन्न करने के मामले में अन्य निक्षेपागार निगमों के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय आस्ति गुणवत्ता में वृद्धि और बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए में गिरावट को दिया जा सकता है। गैर-जमा लेने वाले खंड के भीतर, एनबीएफसी-एनडी के मामले में विकास पिछले दो वर्षों में दर्ज दो अंकों की वृद्धि की तुलना में 2019-20 में कम हो गया। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की वित्तीय देयताएँ बढ़ गईं जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा राज्य सरकारों की तुलना में अधिक रहा।

आगे बढ़ते हुए, महामारी वर्ष 2020-21 में व्यवधानों से निपटने के लिए शुरू किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय, क्षेत्रों की निवल ऋण/उधार की स्थिति को प्रभावित करेंगे। सरकारी क्षेत्र के संसाधन कई महामारी लहरों के मद्देनजर किए गए व्यापक राजकोषीय सहायता उपायों के प्रभाव को दर्शाएंगे। अप्रत्याशित आर्थिक और वित्तीय आघातों से निपटने के लिए एक अवरोध प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बफर की प्रासंगिकता अधिक स्पष्ट हो सकती है और यह रिज़र्व बैंक के वित्तीय खातों में परिलक्षित होगी। 23 अगस्त, 2021 को आईएमएफ द्वारा भारत को आबंटित एसडीआर 12.57 बिलियन का तदनुसार संबंधित क्षेत्रों जैसे केंद्रीय बैंक, केंद्र सरकार और बाकी दुनिया के वित्तीय खातों पर असर होगा। केंद्र सरकार द्वारा आस्ति मुद्रीकरण और उच्च बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय जैसी नीतिगत पहल सार्वजनिक और निजी दोनों गैर-वित्तीय निगमों की आस्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। महामारी प्रतिबंधों के कारण, कृषि को छोड़कर, बैंक ऋण को व्यापक रूप से मंदी का सामना करना पड़ा। हालांकि, देयताओं के पक्ष में, बैंकों ने उच्च जमा वृद्धि दर्ज की, जो विवेकाधीन खर्च में गिरावट के कारण हाउसहोल्ड क्षेत्र की वित्तीय बचत में वृद्धि में परिलक्षित हुई। 2020-21 में महामारी से प्रेरित मंदी के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था ने संकुचित व्यापार घाटे के कारण 2003-04 के बाद पहली बार चालू खाता अधिशेष दर्ज किया।

जबकि हाउसहोल्ड और वित्तीय निगमों से उच्च वित्तीय अधिशेष उत्पन्न करना जारी रखने की उम्मीद है, कॉर्पोरेट और बैंकों की बेहतर तुलन पत्र स्थिति अधिक डिजिटलीकरण द्वारा समर्थित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों के उच्च प्रवाह की सुविधा प्रदान कर सकती है।

संदर्भ

FSB (2021), *"G20 Data Gaps Initiative (DGI-2) The Sixth Progress Report – Countdown to December 2021"* International Monetary Fund and Financial Stability Board, https://www.fsb.org/2021/10/g20-data-gaps-initiative-dgi-2-the-sixth-progress-report-countdown-to-december-2021/

Government of India (2020), *"Union Budget 2020-2021"*, Ministry of Finance, Government of India, https://www.indiabudget.gov.in/budget2020-21/index.php

NABARD (2020), *"Annual Report 2019-20"*, National Bank for Agriculture and Rural Development, https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/1008203730Nabard%20English%20Annual%20Report%20for%20Website.pdf

National Statistical Commission (2018), *"Report of the Committee on Financial Sector Statistics"*, Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India, https://mospi.gov.in/documents/213904/0/Report_of_the_Committee_on_Financial_Sector_Statistics-2182018+%281%29.pdf/4d759d97-08d8-425e-4ea8-71474ac2f8c7?t=1595174128318

OECD (2017), *"Understanding Financial Accounts"*, Edited by Peter Van De Ven and Daniele Fano, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264281288-en.

Prakash, Anupam, Anand Prakash Ekka, Kunal Priyadarshi, Chaitali Bhowmick and Ishu Thakur (2020), "*Financial Stocks and Flows of the Indian*

Economy:2016-17 to 2018-19", RBI Bulletin, July 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/1FINANCIALSTOCKS76894282D5104115A83911082958A7B9.PDF

RBI (2015), *"Manual on the Compilation of Flow of Funds Accounts of the Indian Economy"*, Reserve Bank of India, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/FM2190C3DC5C5442C587DF978335851933.PDF

RBI (2020a), *"Annual Report 2019-20"*, Reserve Bank of India, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/0RBIAR201920DA64F97C6E7B48848E6DEA06D531BADF.PDF

RBI (2020b), *"Report on Trend and Progress of Banking in India 2019-20"*, Reserve Bank of India, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0RTP2020_F3D078985540A4179B62B7734C7B445C9.PDF

RBI (2020c), *"State Finances: A Study of Budgets of 2020-21"*, Reserve Bank of India, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0SF_271020FCF77451F1DF744B2B244875C785B8EF3.PDF

SNA (2008), *"System of National Accounts"*, United Nations, the European Commission, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the International Monetary Fund, and the World Bank Group, https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf

अनुबंध I:
भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक की रूपरेखा और निधियों का प्रवाह

अर्थव्यवस्था के संस्थागत क्षेत्र

विस्तृत क्षेत्रीय वर्गीकरण प्रदर्श 1 में प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय निगम क्षेत्र में ऐसे निगम शामिल हैं जो मुख्य रूप से वित्तीय मध्यस्थता या बीमा और पेंशन फंड सहित सहायक वित्तीय गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह बचतकर्ताओं से निवेशकों के लिए फंड को चैनलाइज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रदर्श1: वित्तीय खातों का क्षेत्रवार खाका

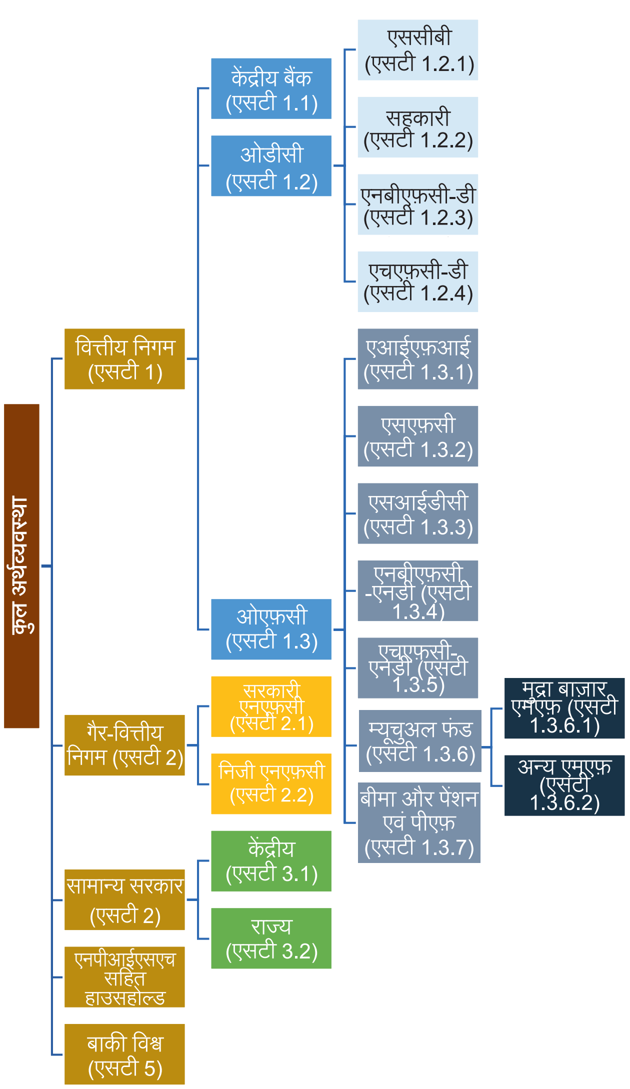

टिप्पणी: कोष्ठक में संबंधित कथनों का संदर्भ दिया गया है।

इस क्षेत्र को उनके कार्य और वित्तपोषण के प्रकार के आधार पर उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है - केंद्रीय बैंक जो वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखता है; ओडीसी जो जमा के रूप में देयताओं के माध्यम से वित्तीय मध्यस्थता में संलग्न हैं; और ओएफसी।

गैर-वित्तीय निगम क्षेत्र में निगमित कानूनी संस्थाएं शामिल हैं जो गैर-वित्तीय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में शामिल हैं। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों गैर-वित्तीय निगम शामिल हैं जो सीमित देयता के साथ सूचीबद्ध या असूचीबद्ध हो सकते हैं।

सामान्य सरकारी क्षेत्र में सभी सरकारी विभाग, कार्यालय और अन्य निकाय शामिल होते हैं जो मुख्य रूप से सरकार द्वारा स्वयं के सामूहिक उपभोग के लिए (जैसे, लोक प्रशासन, सुरक्षा पुलिस, आदि) और जनता द्वारा व्यक्तिगत उपभोग के लिए (जैसे, स्वास्थ्य और शिक्षा) वस्तुओं और सेवाओं के गैर-बाजार उत्पादन में शामिल होते हैं । इस क्षेत्र को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में वर्गीकृत किया गया है।

हाउसहोल्ड क्षेत्र अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में और वित्तीय और गैर-वित्तीय आस्तियों में एक निवेशक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, इसमें एनपीआईएसएच शामिल है जो गैर-बाजार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती है।

आरओडबल्यू क्षेत्र में सभी अनिवासी संस्थागत इकाइयाँ शामिल हैं, चाहे वह अनिवासी सरकारें हों, निगम हों, या व्यक्ति हों, जो निवासी इकाइयों के साथ लेन-देन करते हों, या जिनके निवासी इकाइयों के साथ अन्य आर्थिक संबंध हों।

वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण

एफएसएफ खाते को संकलित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय लिखत (सारणी ए.1) एसएनए 2008 में निर्दिष्ट लिखतों की सूची के अनुरूप हैं, जिन्हें समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ समूहीकृत किया गया है।

सारणी ए.1: वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण

एसएनए 2008 संहिता	वित्तीय लिखत
F1	**मौद्रिक स्वर्ण और एसडीआर**
एफ़11	मौद्रिक स्वर्ण
एफ़12	एसडीआर
F2	**मुद्रा और जमा**
एफ़21	मुद्रा
एफ़22 + एफ़29	जमा
F3	**कर्ज़ प्रतिभूतियों**
F4	**ऋण**
F5	**इक्विटी और निवेश फंड शेयर/इकाइयाँ**
एफ़51	इक्विटी
एफ़52	निवेश फंड शेयर/इकाइयाँ
F6	**बीमा, पेंशन और मानकीकृत गारंटी योजनाएं**
एफ़61	गैर-जीवन बीमा तकनीकी भंडार
एफ़62	जीवन बीमा और वार्षिकी पात्रताएं
एफ़63	पेंशन पात्रता
एफ़64	पेंशन प्रबंधकों पर पेंशन निधि का दावा
एफ़66	मानकीकृत गारंटी के तहत कॉल के लिए प्रावधान
F8	**प्राप्य/देय अन्य खाते**
एफ़81	व्यापार क्रेडिट और अग्रिम
एफ़89	प्राप्य/देय अन्य खाते

मौद्रिक स्वर्ण केंद्रीय बैंक द्वारा विशेष रूप से स्वर्ण बुलियन के रूप में बिना किसी दायित्व के आरक्षित आस्ति है। इसी तरह, एसडीआर अंतरराष्ट्रीय आरक्षित आस्तियां हैं, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में हैं और मौद्रिक प्राधिकरण मौद्रिक स्वर्ण के पूरक हैं।

नोट और सिक्कों से युक्त मुद्रा केंद्रीय बैंक (घरेलू मुद्रा) और अनिवासी अधिकारियों (विदेशी मुद्रा) की देयताएँ हो सकती है। जमा में बैंक खाते, मांग जमा, बचत और सावधि जमा जैसे लिखत शामिल हैं। यह केंद्रीय बैंक, ओडीसी और आरओडब्ल्यू की देयताएँ हो सकती है।

ऋण प्रतिभूतियों में परक्राम्य लिखत शामिल हैं, जैसे, टी-बिल, वाणिज्यिक पत्र, बांड, और आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियां जो ऋण के प्रमाण के रूप में काम करती हैं।

ऋण गैर-परक्राम्य वित्तीय आस्तियां हैं जिनमें ओवरड्राफ्ट, किस्त ऋण, आईएमएफ पर दावे या देयताएँ, और रिपो समझौते जैसे उपकरण शामिल हैं।

इक्विटी और निवेश फंड शेयर के मालिक को पूर्व निर्धारित राशि का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि इन लिखतों के जारीकर्ता की आस्ति पर केवल एक अवशिष्ट दावे के लिए प्रदान करते हैं। निवेश फंड शेयर सामूहिक निवेश वाहनों द्वारा जारी किए जाते हैं जो वित्तीय और गैर-वित्तीय आस्तियों में निवेश के लिए धन जमा करते हैं और मुद्रा बाजार और गैर-मुद्रा बाजार फंड शेयरों में विभाजित होते हैं।

बीमा, पेंशन और मानकीकृत गारंटी योजनाओं में जीवन और गैर-जीवन बीमा और वार्षिकी पात्रताएं, पेंशन और गैर-पेंशन पात्रताएं शामिल हैं। ये बीमा और पेंशन फंड उप-क्षेत्रों में देयताएँ हैं और योजनाओं में प्रतिभागियों की आस्तियां हैं।

प्राप्य या देय अन्य खातों में व्यापार ऋण और निगमों, सरकार, हाउसहोल्ड और एनपीआईएसएच, और आरओडब्ल्यू को दिए गए अग्रिम और कर, लाभांश, सामाजिक योगदान, मजदूरी और वेतन से संबंधित अन्य प्राप्य या देय शामिल हैं।

अनुबंध II:
कार्यप्रणाली और डेटा स्रोतों में परिशोधन

वित्तीय स्टॉक और निधियों के प्रवाह का संकलन, जिसमें डेटा स्रोतों की एक विशाल विविधता शामिल है, यह जानकारी की अनुपलब्धता, माप त्रुटियों और असंगतताओं के कारण कुछ सीमाओं के अधीन है। नतीजतन, सांख्यिकीय विसंगतियां कुल स्रोतों और भले ही उन्हें कम करने के प्रयासों के बावजूद धन के उपयोग के बीच अंतर के रूप में उभरती हैं। फिर भी, विसंगतियों को कम करने के लिए लिखत-वार विवरण के साथ संस्थागत आंकड़ों का समय पर संकलन और उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। संकलन के इस दौर में, पेश किए गए प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं:

- एसएनए 2008 के अनुसार, आरक्षित निधियों को वित्तीय लेनदेन के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे प्रतिपक्ष देयता नहीं बनाते हैं। तदनुसार, आरक्षित निधियों को वित्तीय देयताओं के रूप में नहीं माना गया है।
- ऋण और अग्रिम, और इक्विटी निवेश के लिए डेटा के बेहतर स्रोतों का उपयोग करके सीजी की वित्तीय आस्तियों को संशोधित किया गया है। एसएनए 2008 के अनुरूप, संपूर्ण एसडीआर आवंटन को सीजी की देयता के रूप में माना गया है।
- मौजूदा प्रथा के अनुसार, आरआरबी खातों को भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति (आरटीपी) पर रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट से एकत्रित योगों का उपयोग करके संकलित किया जाता था। क्षेत्रीय मानचित्रण के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र से परिकलित शेयरों का इस्तेमाल किया गया था। इस आलेख में, नाबार्ड की रिपोर्ट - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख सांख्यिकी और वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है।
- आरआरबी के समान, आरसीबी के लिए एफएसएफ खाते का संकलन आरटीपी से योग का उपयोग करके किया गया था। वर्तमान आलेख में इसके बजाय आरसीबी के विभिन्न स्तरों के लिए क्षेत्रीय शेयरों की गणना के लिए एनएएफ़एससीओबी की जानकारी का उपयोग किया गया है।
- एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, व्यक्तिक (खुदरा), उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति (एचएनआई) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ़) श्रेणियों की निवल बिक्री को जोड़कर म्यूचुअल फंड में हाउसहोल्ड क्षेत्र का निवल प्रवाह निकाला गया है।।

*भारत का संवृद्धिवर्धक बाह्य ऋण**

यह आलेख बाह्य ऋण और संवृद्धि के बीच संबंधों की पड़ताल करता है जिसका दृष्टिकोण भारत के लिए अधिकतम संवृद्धि हेतु बाह्य ऋण की अधिकतम सीमा की पहचान करना है। अनुभवजन्य परिणामों से पता चलता है कि भारत के वर्तमान 20 प्रतिशत की बाह्य ऋण और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में, अनुमानित सीमा स्तर सकल घरेलू उत्पाद के 23 प्रतिशत और 24 प्रतिशत के बीच की सीमा में अधिक है, जो लगभग 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के ऋण प्रवाह को आकर्षित करने की संभवता का संकेत देता है। बाह्य ऋण के उच्च एक्सपोजर के कारण बाहरी कमजोरियाँ बढ़ने के जोखिम को देखते हुए, अनुमानित स्थान का उपयोग संवृद्धि और समष्टि-स्थिरता में संतुलन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

भूमिका

घरेलू बचत के साथ-साथ बाह्य ऋण, देशों को तेज संवृद्धि में मदद कर सकता है। लेकिन बाह्य ऋण का बड़ा स्टॉक संभावित रूप से कमजोरियाँ पैदा कर सकता है और संवृद्धि की संभावनाओं को कम कर सकता है। महामारी की शुरुआत के बाद से, कई देशों ने आर्थिक बहाली में सहयोग के लिए सार्वजनिक खर्च बढ़ाया है, जिससे उनके बाह्य ऋण (आईएमएफ, 2022) में इज़ाफा हुआ है। चीन को छोड़कर, निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए, 2020 में बाह्य ऋण और जीएनआई का अनुपात औसतन 42 प्रतिशत था जो 2019 से 4.9 प्रतिशत की अधिक था। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान बाह्य ऋण और निर्यात का अनुपात 126 प्रतिशत से बढ़कर 154 प्रतिशत हो गया (विश्व बैंक, 2022)।

इस उभरती हुई वैश्विक पृष्ठभूमि में, यह आलेख भारत में बाह्य ऋण और संवृद्धि के बीच संबंधों की पड़ताल करता है और क्वाड्रेटिक रिग्रेसन के अलावा, विभिन्न मॉडलों, जैसे- स्पलाइन रिग्रेशन, थ्रेशोल्ड रिग्रेशन और स्मूद ट्रांजिशन रिग्रेशन को नियोजित करके बाह्य ऋण के इष्टतम सीमा स्तर की वृद्धि का अनुमान लगाता है। शेष आलेख छह खंडों में व्यवस्थित है। खंड 2 ऐतिहासिक और हाल के रुझानों के संदर्भ में भारत के बाह्य ऋण की संरचनागत विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। खंड 3 में साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा की गई है। खंड 4 में कार्यप्रणाली और आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि खंड 5 में अनुभवजन्य परिणामों पर चर्चा की गई है। अंत में, खंड 6 के साथ यह आलेख समाप्त होता है।

II. भारत के बाह्य ऋण की संरचनागत विशेषताएं

ऐतिहासिक रुझान

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, भारत पर बहुत कम बाह्य ऋण था। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने आर्थिक वृद्धि और विकास के एक नियोजित युग को अपनाया, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन के एक व्यापक थीम के साथ अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मार्च 1955 के अंत में भारत का बाह्य ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से कम से बढ़कर मार्च 1970 के अंत तक लगभग 13 प्रतिशत हो गया। बाह्य ऋण और अनुदान रूपी बाहरी अंतरण के साथ घरेलू बचत को पूरक बनाकर अर्थव्यवस्था की निवेश दर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1970 के दशक के दौरान, बाह्य ऋण अनुपात केवल 15 प्रतिशत के आस-पास सीमित रहा। हालांकि, 1980 के दशक के दौरान चालू खाते के घाटे के बढ़ने को महंगे बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), आईएमएफ ऋण और एनआरआई जमाराशि के रूप में ऋण पूंजी द्वारा तेजी से वित्त पोषित किया गया था। तदनुसार, 1991 के अंत में बाह्य ऋण और जीडीपी का अनुपात बढ़कर 38.7 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 1991 के भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट से प्राप्त सबक और भुगतान संतुलन पर उच्च स्तरीय समिति, 1993 की सिफारिशों के आधार पर बाह्य ऋण पर एक नई नीति अस्तित्व में आई (अध्यक्ष: डॉ. सी. रंगराजन)। नई नीति (i) ईसीबी के आकार, परिपक्वता और अंतिम उपयोग पर प्रतिबंध द्वारा निर्देशित थी; (ii) ऐसी जमाराशियों के अस्थिर घटक को हतोत्साहित करने के

---

*यह आलेख डॉ. गोपीनाथ तुलसी, निदेशक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (बाह्य ऋण प्रबंध इकाई (ईडीएमयू), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर) और थंगजाम राजेश्वर सिंह, सहायक परामर्शदाता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

लिए अनिवासी जमाराशियों पर लिबोर आधारित ब्याज सीमा; (iii) उच्च लागत वाले बाह्य ऋण का पूर्व भुगतान और पुनर्वित्त; और (iv) प्रत्यक्ष बाह्य निवेश (एफडीआई) और बाह्य पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) जैसे गैर-ऋण सृजित वित्तीय प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उपाय। नई नीति के बाद, सकल घरेलू उत्पाद और बाह्य ऋण का अनुपात उल्लेखनीय रूप से और लगातार कम हुआ और 2005 के अंत तक लगभग 17.0 प्रतिशत तक रह गया। भले ही 2005 के बाद इसमें तेजी आई हो, लेकिन यह अनुपात 1990 के दशक के शुरुआती (चित्र 1) स्तरों की तुलना में कम रहा।

विश्व बैंक बाह्य ऋण को दीर्घकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण और आईएमएफ क्रेडिट में वर्गीकृत करता है। लंबी अवधि के ऋण को आगे सार्वजनिक और सार्वजनिक गारंटीकृत ऋण (पीपीजी) और निजी गैर-गारंटीकृत ऋण (पीआरएनजी) में विभाजित किया गया है। कुल बाह्य ऋण में हिस्सेदारी के संदर्भ में, पीपीजी ने 1980 के दशक को छोड़कर, 2000 तक दशकों तक 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। पीपीजी मूल रूप से बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से उधार लिया गया था। 2000 के दशक की पहली छमाही के दौरान, ये उच्च लागत वाले बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण एक सचेत नीति विकल्प के हिस्से के रूप में प्रीपेड थे। इसके अलावा, आधिकारिक लेनदारों से रियायती उधार पर निर्भरता को कम किया गया था। परिणामस्वरूप, पीपीजी की हिस्सेदारी 2000 में लगभग 80 प्रतिशत से घटकर 2006 में लगभग 38.0 प्रतिशत हो गई। 2020 के अंत तक, कुल बाह्य ऋण में पीपीजी की हिस्सेदारी 34.2 प्रतिशत थी। दूसरी ओर, 1990 के दशक के दौरान सुधारों और उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ, अधिक से अधिक निजी कॉर्पोरेट भागीदारी के लिए जगह खुल गई, जिसमें बाह्य प्रौद्योगिकी और बाह्य पूंजी तक अधिक पहुंच की अनुमति देकर विनिर्माण क्षेत्र के आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। नतीजतन, इसी अवधि के दौरान पीआरएनजी की हिस्सेदारी लगभग 15.0 प्रतिशत से बढ़कर 46.0 प्रतिशत हो गई। 2020 के अंत तक, कुल बाह्य ऋण में पीआरएनजी की हिस्सेदारी 46.5 प्रतिशत थी (चित्र 2)।

निम्न और मध्यम आय वाले देशों को शामिल करते हुए अंतर-देशीय परिप्रेक्ष्य से एक अन्य संरचनागत विशेषता यह है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देश कुल बाह्य ऋण में (चित्र 3ख) आम तौर पर सार्वजनिक और सार्वजनिक गारंटीकृत ऋण (चित्रा 3 ए) के कम हिस्से और निजी गैर-गारंटीकृत ऋण के उच्च हिस्से वाले होते हैं। भारत के मामले में, पूर्व अनुपात नीचे है, जबकि बाद वाला अनुपात अंतर-देशीय ट्रेंड लाइन से ऊपर है। इसका तात्पर्य शायद यह है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, भारत ने सक्रिय रूप से, हालांकि सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड तरीके से,

चित्र 1 : भारत का बाह्य ऋण और जीडीपी अनुपात

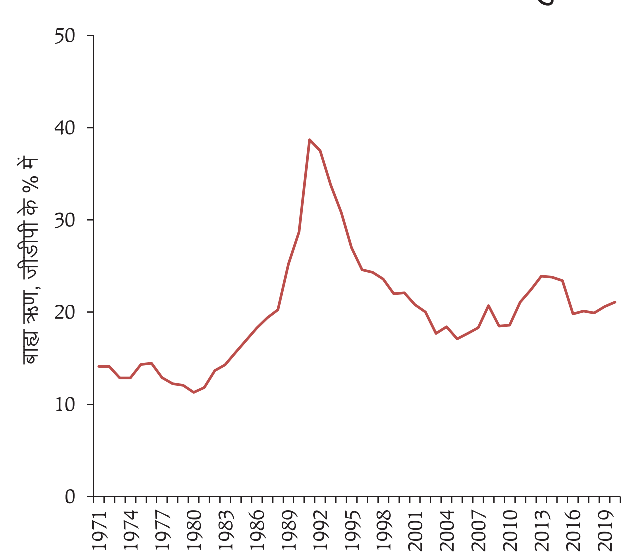

स्रोत : आरबीआई, वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक

चित्र 2 : लंबी अवधि के बाह्य ऋण : पीपीजी बनाम पीआरएनजी

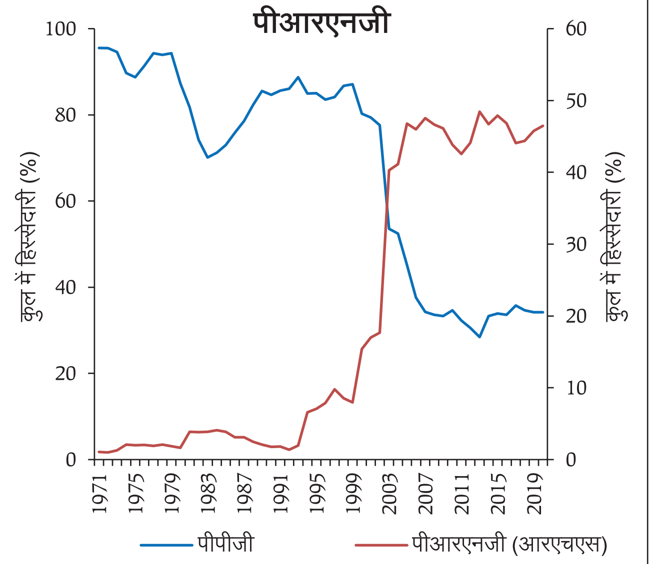

स्रोत : विश्व बैंक

चित्र 3: बाह्य ऋण और प्रति व्यक्ति आय : अंतर-क्षेत्रीय दृष्टि

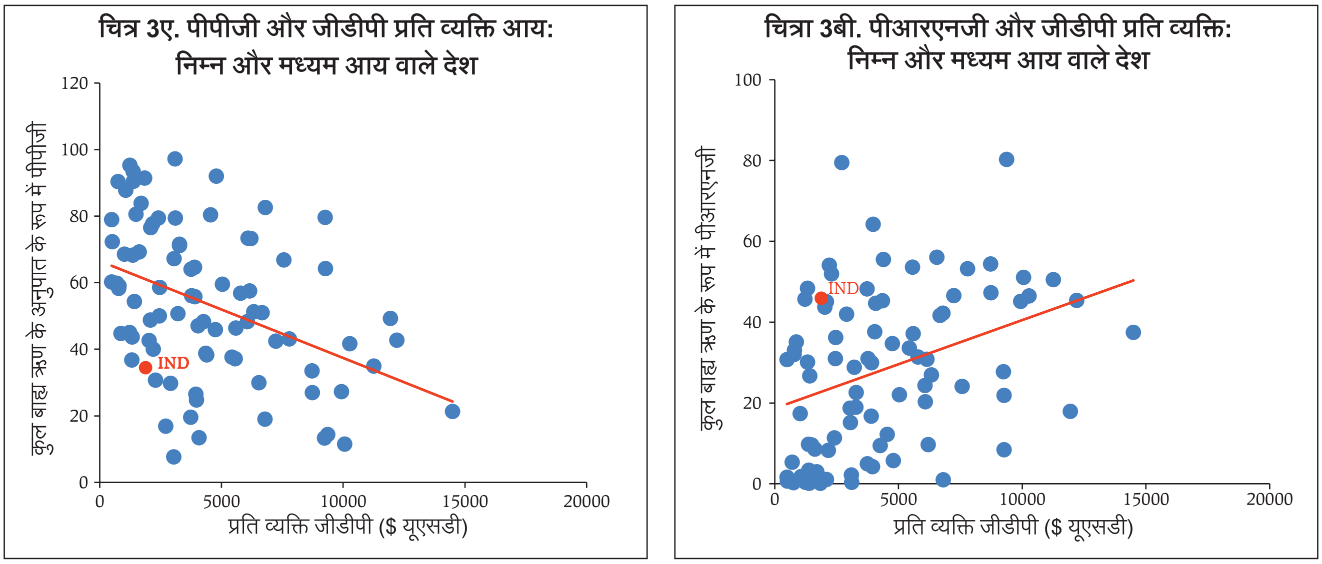

स्रोत: विश्व बैंक; और लेखकों की गणना

निजी क्षेत्र को बाह्य ऋण पूंजी तक पहुंच को प्रोत्साहित किया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को ऐसी पूंजी तक पहुंच प्रदान करने में रूढ़िवादिता का प्रयोग किया। पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर व्यापक नीति के अंतर्गत बाह्य ऋण के प्रति इस नीतिगत दृष्टिकोण से वास्तव में देश का भला हुआ है।

हाल के रुझान

31 मार्च, 2022 को, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए भारत के बाह्य ऋण आँकड़े प्रकाशित किए। इन अनुमानों के अनुसार, दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण 614.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वाणिज्यिक उधार (सीबी) 226.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, एनआरआई जमा 141.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक व्यापार ऋण 110.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कुल बाह्य ऋण का लगभग 78 प्रतिशत है (चित्र 4)। दिसंबर 2021 के अंत में जीडीपी अनुपात में बाह्य ऋण 20.0 प्रतिशत था।

महामारी / ग्रेट लॉकडाउन (जीएलडी) और वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद भारत के बाहरी ऋण के सापेक्ष प्रदर्शन के विश्लेषण से दिलचस्प अंतर्दृष्टि का पता चलता है। पूर्व-संकट तिमाही के अंत में बकाया बाह्य ऋण को 100 पर पुन: आधारित किया गया है। 2008 की दूसरी तिमाही और 2019 की चौथी तिमाही को क्रमशः जीएफसी और जीएलडी के लिए पूर्व-संकट तिमाही के रूप में पहचाना गया है। जैसा कि चित्र 4 से देखा जा सकता है, कुल बाह्य ऋण, जो जीएलडी के तत्काल बाद के संकट-पूर्व स्तरों से नीचे गिर गया, दिसंबर 2020 के अंत तक महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर गया और एनआरआई जमाकर्ताओं के कारण और मज़बूत होकर जून 2020 के अंत तक

चित्र 4: बाह्य ऋण के घटक

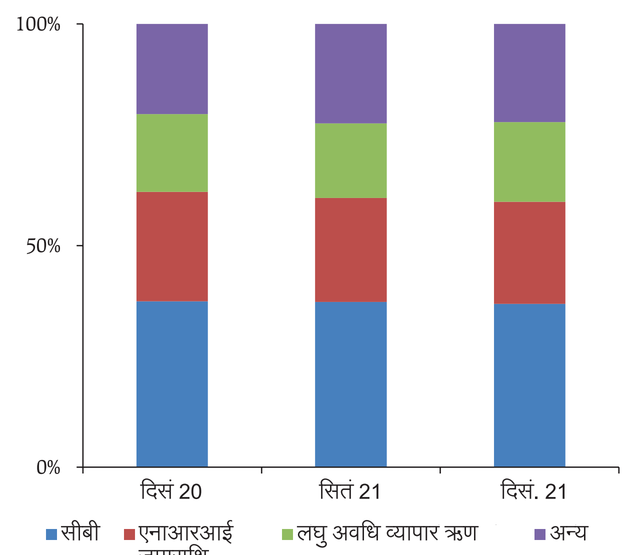

स्रोत : वित्त मंत्रालय

चित्र 5: भारत के बाह्य ऋण का प्रदर्शन: जीएफसी बनाम जीएलडी (जीएफसी, 2008: क्यू2=100; जीएलडी, 2019: क्यू4=100)

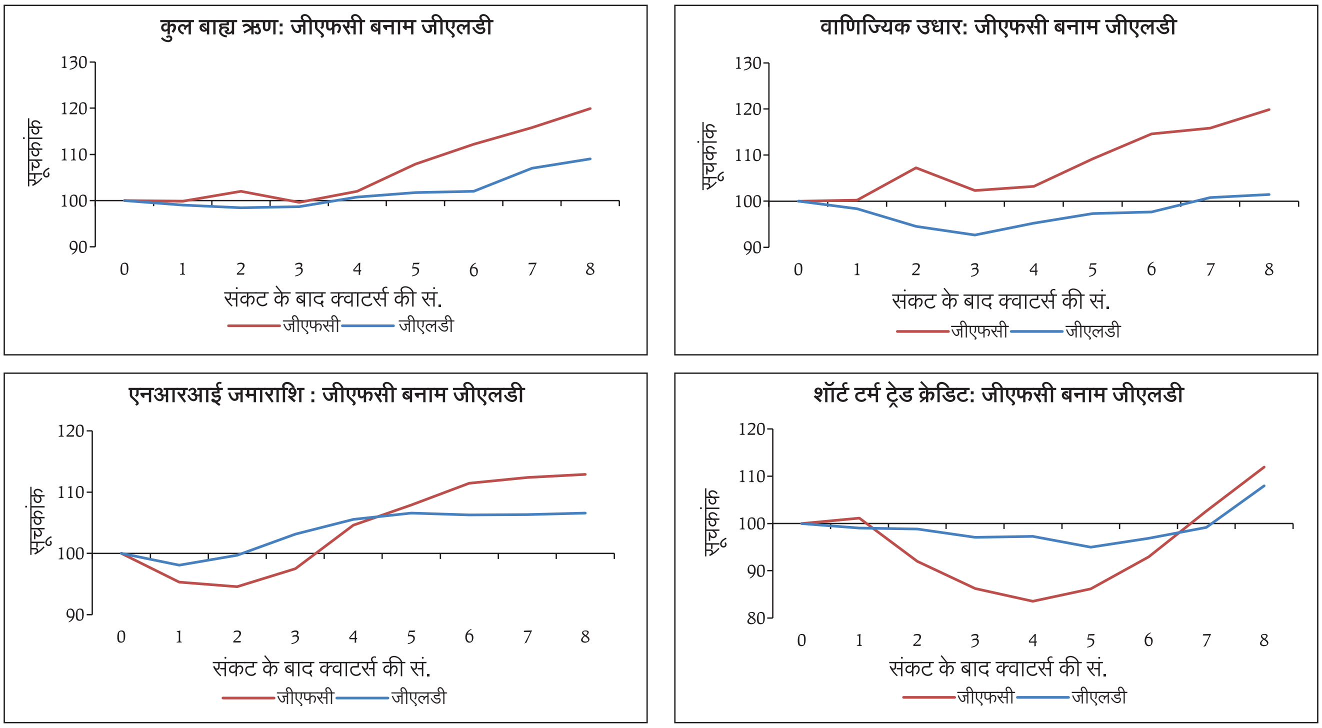

स्रोत: आरबीआई, वित्त मंत्रालय और लेखकों की गणना।

महामारी के स्तर को पार कर गया; वाणिज्यिक उधार सितंबर 2021 के अंत तक महामारी-पूर्व स्तरों को पार कर गया; और अल्पकालिक व्यापार ऋण दिसंबर 2021 के अंत में महामारी से पहले के स्तरों को पार कर गया। इसके विपरीत, भारत का बाह्य ऋण जीएफसी के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरक्षित रहा, जो वाणिज्यिक उधारों के लचीलेपन को दर्शाता है, जो सबसे अधिक विकास-संवेदनशील और भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक है। जीएफसी के मद्देनज़र वाणिज्यिक उधारों का लचीलापन काफी हद तक जीएलडी के दौरान वृद्धि पर जीएफसी के अपेक्षाकृत कम प्रभाव से उपजी है (चित्र 5)।

III. साहित्य की समीक्षा

एक विशिष्ट नव-शास्त्रीय ढांचे में, पूंजी की कमी का सामना कर रहे देश के लिए, अपनी घरेलू बचत को ऋण के रूप में बाहरी पूंजी के साथ पूरक करने से बड़े निवेश को वित्तपोषित किया जा सकता है, जिससे उच्च आर्थिक वृद्धि हो सकती है। कुछ अंतर्जात वृद्धि मॉडल के समान निहितार्थ हैं। फिर, संचित बाह्य ऋण के बड़े स्तर के परिणामस्वरूप कम वृद्धि क्यों होती है? साहित्य में दो चैनल दिखाए गए हैं: ओवरहैंग और क्राउडिंग-आउट। ऋण ओवरहैंग और क्राउड-आउट चुनौतियां तब उत्पन्न होती हैं जब किसी देश का ऋण स्तर भविष्य में चुकाने की क्षमता से अधिक हो जाता है, जिससे देश के उत्पादन में ऋण सेवा में अपेक्षित वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, देश में निवेश पर रिटर्न जो अन्यथा निवेशकों को प्राप्त हो सकता था, इसके बजाय विदेशी लेनदारों द्वारा कर लगाया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, नए निवेश को हतोत्साहित होते हैं (क्रुगमैन, 1988; सैक्स, 1989)। जिन चैनलों के माध्यम से बाह्य ऋण ओवरहैंग और वृद्धि पर भीड़ के प्रतिकूल प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, वे निवेश की कम मात्रा और निवेश की दक्षता के माध्यम से हैं। इसके अलावा, बड़े ऋण स्टॉक से उत्पन्न अनिश्चितता निवेश, उत्पादन, खपत और काम के घंटे/रोजगार को कम कर सकती है (मूर, 2016; बसु और बर्डिक 2015; लेडुक एंड लाई, 2016)।

कम निवेश और निवेश की उत्पादकता (कोहेन, 1994) के माध्यम से वृद्धि पर ऋण के गैर-रेखीय प्रभावों को रेखांकित करने वाले मॉडल हैं। गैर-रेखीय मॉडल वृद्धि पर ऋण के लाफ़र वक्र प्रकार के प्रभाव के अस्तित्व की वकालत करते हैं। वक्र के बाईं ओर (या अच्छे पर) बाहरी ऋण के स्टॉक में वृद्धि निवेश और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से उच्च वृद्धि से जुड़ी है। दूसरी ओर, वक्र के दाईं ओर (या खराब) बाहरी ऋण के स्टॉक में वृद्धि कम निवेश और उत्पादकता के साथ कम वृद्धि में प्रकट होगी। इस तरह के एक बाहरी ऋण लाफ़र वक्र का टिपिंग/इनफ़्लेक्शन बिंदु वृद्धि-अधिकतम सीमा है।

विकास पर बाहरी ऋण के प्रभाव पर अनुभवजन्य अध्ययन नहीं हुए हैं। अनुभवजन्य साहित्य में, आमतौर पर एक कम रूप में बैरो-प्रकार की वृद्धि मॉडल को नियोजित किया जाता है, जो विकास पर बाहरी ऋण के प्रभाव को पकड़ने के लिए प्रासंगिक बाहरी ऋण चर के साथ संवर्धित होता है। इसके अलावा, ये अध्ययन मूल रूप से प्रकृति में अंतर-देशीय हैं (पट्टिलो और अन्य 2002, 2004, 2011; क्लेमेंट्स, और अन्य।, 2003; जयरामन और अन्य 2009; लाउ और अन्य 2014; सिद्दीकी और अन्य।, 2016; कुरैशी और अन्य 2019)। ; और फेलिक्स, 2020)।

पैटिलो और अन्य (2002, 2004, 2011) ने 1969-98 में 93 विकासशील देशों के एक बड़े पैनल डेटा सेट का उपयोग करके वृद्धि पर बाहरी ऋण के अरेखीय प्रभाव का आकलन किया। निष्कर्ष इस बात का समर्थन करते हैं कि जहां ऋण का औसत प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 30-40 प्रतिशत पर नकारात्मक हो जाता है, वहीं सीमांत प्रभाव उपर्युक्त सीमा के लगभग आधे पर नकारात्मक हो जाता है। क्लेमेंट्स और अन्य (2003) उन चैनलों की जांच करता है जिनके माध्यम से बाह्य ऋण 1970-99 की अवधि को कवर करते हुए 55 कम आय वाले देशों में वृद्धि को प्रभावित करता है। परिणाम सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 30-37 प्रतिशत के प्रारंभिक स्तर का संकेत देते हैं। सिद्दीकी और अन्य (2016) ने विश्लेषण किया है कि 1970-2007 के आंकड़ों के आधार पर 40 भारी ऋणग्रस्त गरीब देशों में बाह्य ऋण का बोझ किस हद तक वृद्धि को प्रभावित करता है, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में। ये परिणाम, ऋण ओवरहैंग परिकल्पना का समर्थन करते हैं। कुरैशी और अन्य (2019) 1990 से 2015 तक 23 देशों के डेटा का उपयोग करके बाह्य ऋण के प्रकार (कुल, सार्वजनिक और निजी बाहरी ऋण) और आय वृद्धि के बीच संबंधों की जांच करता है। जहाँ, कुल बाह्य ऋण का वृद्धि दर पर सामान्य स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह सकारात्मक रूप से निम्न और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में आय वृद्धि से संबंधित है। इसके अलावा, सार्वजनिक बाह्य ऋण सभी देशों की आर्थिक वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि निजी बाह्य ऋण का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ऊपर उद्धृत अन्य अध्ययनों के विपरीत, लेखकों को बाहरी ऋण के लिए एक सामान्य सीमा स्तर का प्रमाण नहीं मिलता है। जयरामन और अन्य (2009) ने 1988-2004 की 17-वर्ष की अवधि को कवर करते हुए छह प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसीएस) के लिए पैनल डेटा का उपयोग किया। परिणाम इस बात को रेखांकित करते हैं कि दीर्घकाल में बाह्य ऋण और वृद्धि के बीच कोई संबंध नहीं होता है, अल्पावधि में, बाह्य ऋण वृद्धि को बढ़ावा देता है। लाउ और अन्य (2014) 1988 से 2006 के दौरान 17 एशियाई देशों में बाह्य ऋण और वृद्धि के बीच गठजोड़ की जांच करते हैं। परिणाम इस बात का सबूत देते हैं कि बाह्य ऋण इन देशों में वृद्धि में योगदान देता है। फेलिक्स (2020) 1990 से 2016 के डेटा का उपयोग करके पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ईसीओडब्ल्यूएएस) में आर्थिक वृद्धि पर बाह्य ऋण के प्रभाव को निर्धारित करता है। परिणाम समर्थन करते हैं कि अल्पावधि में, सीमा 45 प्रतिशत थी, जबकि लंबी अवधि में यह 42.5 फीसदी पर था।

इस प्रकार, एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करने के अलावा, अनुभवजन्य साहित्य ज्यादातर अंतर-देशीय अध्ययनों से भरा हुआ है, जो देश-विशिष्ट प्रभावों के लिए उत्तरदायी नहीं है। पद्धतिगत रूप से, अधिकांश अनुभवजन्य अध्ययन उपकरण चर, निश्चित प्रभाव, सिस्टम जीएमएम, पैनल वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव (पीवीएआर) मॉडल, या ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग मॉडल के आधार पर आकलन विधियों को नियोजित करते हैं।

साहित्य की पूर्वोक्त समीक्षा की पृष्ठभूमि में, वर्तमान अध्ययन भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विरल देश-विशिष्ट अनुभवजन्य साहित्य में, शासन परिवर्तन का पता लगाने के लिए सुचारू संक्रमण प्रतिगमन द्वारा पूरक अरैखिकता को नियोजित करके, योगदान करने का प्रयास करता है। कार्यप्रणाली का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है।

IV. कार्यप्रणाली और डेटा

अरेखीय मल्टीवैरियेट रिग्रेशन:

ऊपर समीक्षा किए गए अनुभवजन्य साहित्य पर चित्रण, एक मानक बैरो वृद्धि मॉडल को वृद्धि पर बाहरी ऋण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए द्विघात फ़ंक्शन ऋण चर के साथ संवर्धित किया गया है।

$$y = \alpha + \Theta' X + \beta D + \phi D^2 + u \qquad ...(1)$$

जहां y वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय वृद्धि है, X नियंत्रण चरों का एक सदिश है और उनके गुणांकों का संबद्ध सदिश है; डी बाहरी ऋण चर है जिसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाहरी ऋण द्वारा दर्शाया गया है, और u एक त्रुटि शब्द है जो एक स्वतंत्र और समान रूप से वितरित (आईआईडी) है जिसका मतलब शून्य और भिन्नता σ^2 है। मापदंडों का अनुमान साधारण न्यूनतम वर्ग (ओएलएस) पद्धति के आधार पर लगाया जाता है।

बाह्य ऋण की इष्टतम सीमा का एक मजबूत अनुमान लगाने के लिए जो आर्थिक वृद्धि को अधिकतम बनाता है, दो व्यवस्थाओं के साथ स्पलाइन रिग्रेशन पर आधारित विभिन्न अर्थमितीय दृष्टिकोण, थ्रेशोल्ड रिग्रेशन मॉडल और स्मूथ ट्रांजिशन रिग्रेशन विधि जो संरचनात्मक ब्रेक पर आधारित हैं, पर इस लेख में विचार किया गया है।

स्प्लाइन रिग्रेशन मॉडल:

एक स्प्लाइन प्रतिगमन मॉडल स्लोप में परिवर्तन की अनुमति देता है, अनुमानित रेखा निरंतर होती है और इसमें दो या दो से अधिक सीधी रेखा खंड हो सकते हैं। इस प्रकार, मॉडल निरंतर है, एक संरचनात्मक विराम के साथ। इस लेख में, तदनुसार दो खंडों वाली रेखा को दहलीज का अनुमान लगाने के लिए माना जाता है और इसे निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है:

$$y = \alpha + \Theta' X + \beta_1 I(D \le D^*) D + \beta_2 I(D > D^*) D + u$$

कुछ हेरफेर के बाद, निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है:

$$y = \alpha + \Theta' X + \beta_1 [I(D \le D^*) + I(D > D^*)] D + (\beta_2 - \beta_1) I(D > D^*) D + u$$

$$y = \alpha + \Theta' X + \beta_1 D + \delta I(D > D^*) D + u \qquad ...(2)$$

जहां, D* बाह्य ऋण सीमा को दर्शाता है और I(D > D*) एक संकेतक चर है जो मान 1 लेता है यदि D > D*, और 0, अन्यथा। यहां गुणांक को β_1 से स्लोप में परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है, यह जांचने के लिए कि ढलान में परिवर्तन महत्वपूर्ण है या नहीं। दी गई दहलीज पर ढलान में इस परिवर्तन का महत्व इष्टतम सीमा को इंगित करेगा। इस लेख में, मॉडल के अन्य गुणांकों के साथ थ्रेशोल्ड का अनुमान अरेखीय न्यूनतम वर्ग (एनएलएलएस) विधि का उपयोग करके लगाया गया है।

थ्रेसोल्ड रिग्रेशन मॉडल

मुद्रास्फीति-वृद्धि संयोग मॉडल में मुद्रास्फीति सीमा का अनुमान लगाने के लिए सरेल (1996) और खान और सेन्हादजी (2001) द्वारा थ्रेसहोल्ड रिग्रेशन दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। सरेल (1996) दिए गए थ्रेशोल्ड स्तर के लिए प्रतिगमन मॉडल की एक शृंखला चलाता है और अधिकतम आर-वर्ग या न्यूनतम मूल माध्य वर्ग त्रुटि (आरएमएसई) के आधार पर इष्टतम सीमा का चयन किया जाता है। हालांकि, खान और सेन्हादजी (2001) ने तर्क दिया कि चूंकि सीमा अज्ञात है, इसलिए इसका अनुमान मॉडल के अन्य मापदंडों के साथ लगाया जाना चाहिए न कि सरेल (1996) में सुझाई गई प्रक्रिया के साथ। खान और सेन्हादजी (2001) द्वारा सुझाए गए मॉडल का उपयोग इस लेख में बाह्य ऋण की इष्टतम सीमा का अनुमान लगाने के लिए किया गया है और इसे नीचे प्रस्तुत किया गया है।

$$\left.\begin{array}{l} y = \alpha + \Theta' X + \beta_1 (D - D^*) + u \quad if \ D \le D^* \\ y = \alpha + \Theta' X + \beta_2 (D - D^*) + u \quad if \ D > D^* \end{array}\right\} \qquad ...(3)$$

$H_0 : \beta_1 = \beta_2$ का परीक्षण H1 के विरुद्ध किया जाता है: $H_1 : \beta_1 \ne \beta_2$ इष्टतम थ्रेशोल्ड के अस्तित्व की जाँच के लिए। मॉडल का अनुमान अरेखीय न्यूनतम वर्ग (एनएलएलएस) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

स्मूद ट्रांजीशन रिग्रेशन मॉडल

अधिकांश आर्थिक चर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बदलते हैं, एक शासन से दूसरे शासन में संक्रमण के साथ कुछ समय लगता है। स्मूथ ट्रांजिशन रिग्रेशन (एसटीआर) मॉडल शासन स्विचिंग व्यवहार को शामिल करने की अनुमति देता है, जब शासन परिवर्तन का सही समय निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता

है और जब एक नए शासन के लिए एक छोटी संक्रमण अवधि होती है। इसलिए, एसटीआर मॉडल चर की गतिशीलता पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं जो संक्रमण अवधि के दौरान भी अपना मूल्य दिखाते हैं। इसके अलावा, अचानक स्विच की तुलना में शासनों के बीच सहज परिवर्तन अक्सर यथार्थवादी होते हैं। इस लेख में, एस्पिनोज़ा और अन्य में वर्णित मॉडल (2010) और दीपक और अन्य (2011) को थोड़े संशोधन के साथ अपनाया गया है और नीचे दिया गया है।

$$y = \alpha + \Theta' X + \beta_1 G(\gamma, c; d)(D - D^*) + \beta_2 G(\gamma, c; d)(D - D^*) + u \qquad ...(4)$$

जी (.) एक सतत संक्रमण फ़ंक्शन को व्यक्त करता है जो आमतौर पर 0 और 1 के बीच होता है। सबसे लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाने वाले संक्रमण फ़ंक्शन लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन हैं और इन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

$$Logistic: \quad G(\gamma, c; d) = \frac{1}{1 + e^{-\gamma(d-c)}}, \quad \gamma > 0$$

$$Exponential: G(\gamma, c; d) = 1 - e^{-\gamma(d-c)^2}, \quad \gamma > 0$$

स्लोप पैरामीटर $\gamma > 0$, 0 और 1 के बीच संक्रमण की गति का एक संकेतक है, जबकि थ्रेशोल्ड पैरामीटर c इंगित करता है कि संक्रमण कहाँ होता है, और संक्रमण चर को d द्वारा दर्शाया जाता है। इस आलेख में, लॉजिस्टिक स्मूथ ट्रांज़िशन रिग्रेशन (एलेसटीआर) और एक्सपोनेंशियल स्मूद ट्रांज़िशन रिग्रेशन (ईएसटीआर) मॉडल दोनों का उपयोग किया गया है। संक्रमण पैरामीटर और थ्रेशोल्ड सहित मॉडल के मापदंडों का अनुमान अरेखीय न्यूनतम वर्ग (एनएलएलएस) पद्धति का उपयोग करके लगाया जाता है। सुचारू संक्रमण का लॉजिस्टिक स्पेपेसीफिकेशन संचयी लॉजिस्टिक फ़ंक्शन पर आधारित होता है, जबकि घातीय स्पेपेसीफिकेशन यदि उल्टे सामान्य घनत्व फ़ंक्शन पर आधारित होता है।

यह लेख 1970 से 2020 तक के वार्षिक डेटा का उपयोग करता है जो मूल रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई), भारतीय रिज़र्व बैंक से लिया गया है1। हालाँकि, जहाँ भी आरबीआई से डेटा उपलब्ध नहीं है, ऐसे डेटा को वैश्विक विकास संकेतक, विश्व बैंक के डेटाबेस से पूरित किया जाता है।

V. अनुभवजन्य परिणाम

शुरुआत में, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति संवृद्धि को उनके बीच संबंधों का आकलन करने के लिए चित्र 6 में बाह्य ऋण से जीडीपी अनुपात के खिलाफ प्लॉट किया गया है। भारत में बाह्य वृद्धि और वृद्धि के बीच एक अरेखीय संबंध प्रतीत होता है (चित्र 6)।

बाहरी ऋण और आर्थिक विकास के बीच मौजूद गैर-रेखीय संबंध के प्रकार को बेहतर ढंग से समझने के लिए, और विवर्तन बिंदु की संवेदनशीलता, द्विघात सहित विभिन्न शक्ति कार्यों के साथ एक द्विभाजित बहुपद प्रतिगमन की जांच की जाती है। विभिन्न शक्तियों के साथ बहुपद प्रतिगमन के अनुमानित गुणांक उनकी इष्टतम बाहरी ऋण सीमा के साथ तालिका 1 में प्रस्तुत किए गए हैं और परिणाम अनुलग्नक में चित्र A.1 में चित्रित किए गए हैं।

विभिन्न कार्यात्मक रूपों को लागू करने के परिणाम बताते हैं कि बाहरी ऋण और आर्थिक वृद्धि के बीच संबंध अरेखीय (अवतल) रहता है और यह एक उल्टे यू-आकार के संबंध को

चित्र 6: बाह्य ऋण और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति वृद्धि के बीच संबंध

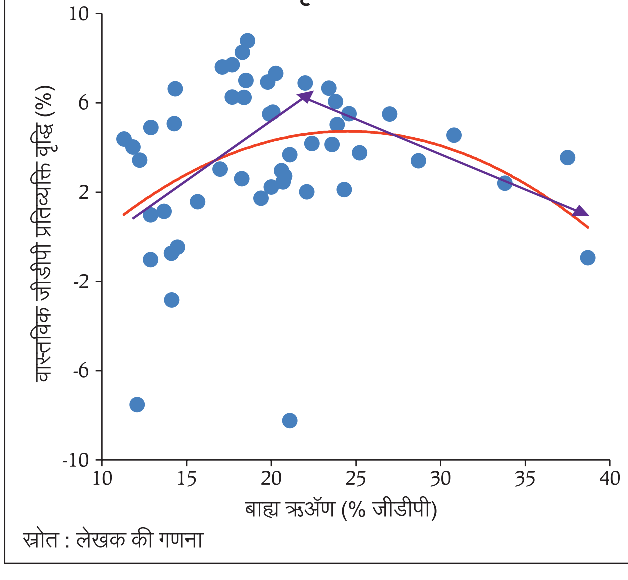

स्रोत : लेखक की गणना

1 हमारे अनुभवजन्य विश्लेषण के लिए, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की पिछली शृंखला स्प्लिसिंग विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। सीपीआई मुद्रास्फीति के मामले में, सीपीआई-आईडब्ल्यू पर विभाजन करके सीपीआई-संयुक्त की पिछली शृंखला प्राप्त की जाती है।

सारणी 1: बाह्य ऋण के टर्निंग पॉइंट की संवेदनशीलता

पावर	स्थिर	बाह्य ऋण के गुणांक	पावर के रूप में बाह्य ऋण के गुणांक	इष्टतम बिंदु
1.2	-15.20** (7.12)	5.02** (1.95)	-2.22** (0.87)	23.77
1.4	-12.66** (6.17)	2.53** (0.98)	-0.51** (0.20)	23.95
1.6	-10.77* (5.47)	1.71** (0.66)	-0.16** (0.06)	24.14
1.8	-9.30* (4.94)	1.30** (0.50)	-0.06** (0.02)	24.32
2.0	-8.12* (4.52)	1.05** (0.41)	-0.02** (0.01)	24.51
2.2	-7.17* (4.181)	0.88** (0.343)	-0.01** (0.003)	24.69
2.4	-6.38 (3.907)	0.77** (0.299)	-0.004** (0.001)	24.87
2.6	-5.71 (3.679)	0.68** (0.266)	-0.002** (0.001)	25.05
2.8	-5.14 (3.4888)	0.61** (0.2409)	-0.001** (0.0003)	25.23
3.0	-4.65 (3.3277)	0.56** (0.2213)	-0.0003** (0.0001)	25.41

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटि हैं। (2) * 10% पर मान, ** 5% पर मान और *** 1% पर मान इंगित करता है।

दर्शाता है, जो एक लाफ़र-वक्र प्रकार के संबंध की उपस्थिति की पुष्टि करता है। उच्चतर शक्ति से बाह्य ऋण का थोड़ा अधिक इष्टतम स्तर प्राप्त होता है। विभिन्न कार्यात्मक रूपों का उपयोग करके अनुमानित बाहरी ऋण का अनुमानित इष्टतम स्तर लगभग 23.8 से 25.4 प्रतिशत की सीमा में है। शक्ति 2 के साथ अनुमानित बाह्य ऋण का इष्टतम स्तर 24.51 प्रतिशत है।

इन्फ्लेक्सियन पॉइंट का एक मजबूत अनुमान लगाने के लिए, अरेखीय मल्टीवेरिएट रिग्रेशन पर साहित्य से तैयार किए गए नियंत्रण चर के एक सेट को समायोजित माना जाता है जैसे कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का अंतराल (प्रति व्यक्ति आय का प्रारंभिक स्तर) 3, प्रतिशत में परिवर्तन व्यापार की शर्तें, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू निवेश, खुलापन संकेतक (जीडीपी के अनुपात के रूप में निर्यात प्लस आयात), जनसंख्या वृद्धि दर, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन दर, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामान्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा, सीपीआई-संयुक्त मुद्रास्फीति दर, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य ऋण सेवा और बाह्य ऋण संकेतक (जीडीपी के लिए बाहरी ऋण)। इस आलेख में विचार किए गए अन्य गैर-रेखीय मॉडल में नियंत्रण चर का एक ही सेट शामिल है। प्रति व्यक्ति का प्रारंभिक स्तर (वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का लॉग) एक नकारात्मक गुणांक होने की उम्मीद है, जो आय अभिसरण परिकल्पना से प्राप्त होता है। जनसंख्या वृद्धि और निवेश दर उत्पादन के पारंपरिक कारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि प्राथमिक स्कूल नामांकन दर मानव पूंजी की गुणवत्ता के लिए निकट है। जनसंख्या दर पर गुणांक आम तौर पर अनुभवजन्य साहित्य में नकारात्मक पाया जाता है जबकि निवेश और प्राथमिक विद्यालय नामांकन पर सकारात्मक होने की उम्मीद है। व्यापार चर की शर्तें बाहरी आघात को मापने के लिए हैं। भारत जैसे वस्तु-आयात करने वाले देश के लिए, व्यापार की शर्तों पर गुणांक नकारात्मक होने की उम्मीद है। खुलेपन का संकेतक साहित्य में उस स्ट्रैंड को प्रतिबिंबित करने के लिए है कि अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय में उच्च दीर्घकालिक वृद्धि होती है। राजकोषीय संतुलन चर वृद्धि में राजकोषीय भूमिका को दर्शाते हैं और गुणांक सकारात्मक होने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति चर वृद्धि पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए यह नकारात्मक गुणांक होने की उम्मीद है। चूंकि 1990-91 से डीबीआईई में बाह्य ऋण अनुपात और ऋण सेवा अनुपात के आंकड़े उपलब्ध हैं, 1990-91 से पहले प्राथमिक विद्यालय में नामांकन सहित इन चरों के आंकड़े विश्व बैंक से एकत्र किए जाते हैं।

अरेखीय मल्टीवैरियेट रिग्रेशन:

प्रारंभ में सभी नियंत्रण चरों का उपयोग करके गैर-रेखीय मल्टीवैरियेट रिग्रेशन का अनुमान लगाया जाता है। तथापि, जनसंख्या वृद्धि और सकल राजकोषीय घाटा नगण्य पाया गया है। इसलिए, थ्रेशोल्ड का अनुमान लगाने का एक अधिक पारदर्शी मॉडल रखने के लिए, इन दो चरों को आगे की जांच में बाहर रखा गया है क्योंकि इन सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन चरों को शामिल करने से मॉडल में अन्य गुणांक का अनुमान प्रभावित हो सकता है, जो बदले में अनुमानित सीमा को प्रभावित करता है। मॉडलों का साधारण न्यूनतम वर्ग अनुमान सीरियल स्वसहसंबंध और हेटरोस्केडैसिटी की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। इसलिए, इन समीकरणों का अनुमान ओएलएस रिग्रेशन द्वारा अनुमानित

[2] $y = a + bx + cx^{power}$ के रूप के एक कार्यात्मक संबंध में, 1.0 की शक्ति रैखिकता को इंगित करती है, जबकि 1.0 से अधिक की शक्ति द्विघात रूप का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति 2.0 के साथ गैर-रैखिकता को दर्शाती है।

[3] सशर्त अभिसरण को दर्शाता है।

गुणांक के लिए न्यू-वेस्ट मानक त्रुटियों का उपयोग करके लगाया जाता है क्योंकि न्यू-वेस्ट मानक त्रुटि अनुमान हेटेरोस्केडैस्टिकी और स्वसहसंबंध के लिए मजबूत हैं। जनसंख्या वृद्धि और सकल राजकोषीय घाटे को छोड़कर गैर-रेखीय मल्टीवैरियेट रिग्रेशन के परिणाम तालिका 2[5] में प्रस्तुत किए गए हैं।

सशर्त वृद्धि अभिसरण परिकल्पना का समर्थन करने वाले, नकारात्मक संकेत वाले प्रारंभिक आय, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। निवेश दर और स्कूली शिक्षा नामांकन दर भी सकारात्मक संकेत के कारण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, वृद्धि साहित्य के अनुरूप एक अनुभवजन्य खोज। व्यापार की शर्तों पर गुणांक नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत एक वस्तु आयातक देश है। खुलेपन संकेतक पर गुणांक नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति गुणांक में उचित नकारात्मक संकेत और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बाहरी ऋण (डी) इंगित करता है कि बाहरी ऋण के संचय से एक निश्चित स्तर तक उच्च वृद्धि होती है और बाह्य ऋण-वर्ग (डी 2) के नकारात्मक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण गुणांक से पता चलता है कि बाहरी ऋण के स्टॉक में एक सीमा से परे कम वृद्धि होती है। डी और डी2 के गुणांकों के आधार पर, भारत के लिए विदेशी ऋण का प्रारंभिक स्तर सकल घरेलू उत्पाद[6] का लगभग 27 प्रतिशत होने का अनुमान है।

सारणी 2: वृद्धि पर बाह्य ऋण का रैखिक और द्विघात प्रभाव

	रेखीय	द्विघात
स्थिर	38.264** (7.893)	42.941*** (6.140)
लॉग (आय) टी $_{-1}$	-7.681*** (0.911)	-8.829*** (0.980)
व्यापार वृद्धि की अवधि	-0.050** (0.014)	-0.043*** (0.014)
निवेश की दर	0.472* (0.243)	0.506** (0.244)
खुलापन	-0.125 (0.039)	-0.189** (0.049)
स्कूलिंग	0.396** (0.156)	0.394** (0.150)
मुद्रास्फीति	-0.199*** (0.036)	-0.168*** (0.034)
(ऋण सेवा/जीडीपी)	0.001 (0.022)	-0.104*** (0.029)
डी	0.021 (0.037)	0.858*** (0.130)
डी^{2}		-0.016*** (0.002)

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटि हैं। (2) * 10% पर मान, ** 5% पर मान और ***1% पर मान इंगित करता है।

स्पलाईन और थ्रेशोल्ड रिग्रेशन:

कार्यप्रणाली में वर्णित स्पलाईन और थ्रेशोल्ड रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करते हुए, इष्टतम थ्रेशोल्ड बाहरी ऋण के अस्तित्व का परीक्षण किया जाता है। एनएलएलएस पद्धति का उपयोग करके अनुमानित स्पलाईन और थ्रेशोल्ड रिग्रेशन से अनुभवजन्य परिणाम तालिका 3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 3: बाह्य ऋण अनुपात का अनुमानित टर्निंग पॉइंट: स्प्लाइन और थ्रेशोल्ड रिग्रेशन मॉडल

	स्प्लाइन रिग्रेशन	थ्रेशोल्ड रिग्रेशन
स्थिर	46.595*** (6.203)	47.742*** (6.091)
लॉग (आय) टी $_{-1}$	-8.873*** (1.401)	-8.990*** (1.307)
व्यापार वृद्धि की अवधि	-0.042*** (0.015)	-0.042*** (0.015)
निवेश की दर	0.550** (0.259)	0.539** (0.266)
खुलापन	-0.195*** (0.043)	-0.198*** (0.051)
स्कूलिंग	0.400** (0.165)	0.403** (0.161)
मुद्रास्फीति	-0.179*** (0.045)	-0.180*** (0.049)
(ऋण सेवा/जीडीपी)	-0.073 (0.050)	-0.089* (0.046)
β_1	0.273** (0.122)	0.297** (0.118)
δ	-0.057*** (0.017)	
β_2		-0.438*** (0.107)
थ्रेशोल्ड (डी*)	23.40*** (5.057)	23.60*** (2.736)
परख (H_0: $\beta_1 = \beta_2$)		16.72*** (p = 0.0002)

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटि हैं। (2) * 10% पर मान, ** 5% पर मान और *** 1% पर मान इंगित करता है।

[4] ब्रुश-गॉडफ्रे परीक्षण का उपयोग करके सीरियल सहसंबंध की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है और गैर-रेखीय प्रतिगमन के मामले में वे महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। हेटेरोस्केडैस्टिसिटी के लिए ब्रूस-पैगन/कुक-वीसबर्ग परीक्षण दोनों प्रतिगमन मॉडल में महत्वपूर्ण हेटेरोस्केडैस्टिसिटी की उपस्थिति को दर्शाता है।

[5] जैसा कि तालिका 2 से देखा जा सकता है, वृद्धि पर D का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन है जो रैखिक रूप में गैर-रैखिक संबंध को रेखांकित करता है।

[6] सूत्र का उपयोग करके इष्टतम सीमा का अनुमान लगाया गया है: $[-D/2D^2]$।

स्पलाईन और थ्रेशोल्ड रिग्रेशन दोनों में ढलान परिवर्तन का महत्व बताता है कि बाह्य ऋण-वृद्धि संबंध में एक संरचनात्मक विराम है। स्पलाईन और थ्रेशोल्ड रिग्रेशन से बाहरी ऋण की अनुमानित सीमा क्रमशः 23.4 प्रतिशत और 23.6 प्रतिशत है। यह इस बात का प्रमाण प्रदान करता है कि वृद्धि पर बाह्य ऋण का प्रभाव तब बदल जाता है जब बाह्य ऋण और जीडीपी अनुपात 23.4 से 23.6 प्रतिशत को पार कर जाता है।

स्मूद ट्रांजीशन रिग्रेशन:

लॉजिस्टिक्स और एक्सपोनेंशियल ट्रांजीशन फंक्शन दोनों का उपयोग करते हुए स्मूद ट्रांजिशन रिग्रेशन के अनुभवजन्य परिणाम तालिका 4 में प्रस्तुत किए गए हैं। लॉजिस्टिक स्मूद ट्रांजिशन रिग्रेशन (एलएसटीआर) और एक्सपोनेंशियल स्मूथ ट्रांजिशन रिग्रेशन (ईएसटीआर) से अनुमानित बाहरी ऋण की सीमा 23.5 प्रतिशत और 23.6 है। प्रतिशत, क्रमशः एलएसटीआर और ईएसटीआर के निष्कर्ष स्मूद ट्रांजीशन रिग्रेशन से अनुमानित सीमा का समर्थन करते हैं।

लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ट्रांजिशन फंक्शन के आधार पर अनुमानित सीमा स्तर पर एक अभिशासन से दूसरे अभिशासन में बाह्य ऋण-वृद्धि संबंध का संक्रमण चित्र 7 में दिखाया गया है।

सारणी 4: स्मूद टर्निंग रिग्रेशन (एसटीआर) के आधार पर बाह्य ऋण अनुपात का अनुमानित टर्निंग पॉइंट

	लॉजिस्टिक एसटीआर	**घातीय एसटीआर**
स्थिर	48.263*** (5.346)	42.567*** (6.325)
लॉग (आय) टी $_{-1}$	-9.021*** (1.330)	-8.273*** (0.741)
व्यापार वृद्धि की अवधि	-0.047*** (0.012)	-0.058*** (0.013)
निवेश की दर	0.547** (0.262)	0.546* (0.314)
खुलापन	-0.191** (0.044)	-0.154** (0.066)
स्कूलिंग	0.402** (0.172)	0.404** (0.178)
मुद्रास्फीति	-0.189*** (0.042)	-0.227*** (0.048)
(ऋण सेवा/जीडीपी)	-0.072 (0.046)	0.009 (0.046)
β_1	0.257*** (0.116)	0.160*** (0.008)
β_2	-0.117** (0.043)	-0.149*** (0.026)
γ	58.150 (2159)	7.233 (6.714)
थ्रेषोल्ड (डी*)	23.49*** (3.637)	23.57*** (0.022)

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटि हैं। (2) * 10% पर महत्व, ** 5% पर महत्व और *** 1% पर महत्व इंगित करता है।

उपर्युक्त मॉडलों के आधार पर बाह्य ऋण और वृद्धि के बीच संबंध में प्रवृत्ति व्यवहार अनुलग्नक के चित्र ए.2 में प्रस्तुत किया

चित्र 7 : ट्रांजिशन फंशन

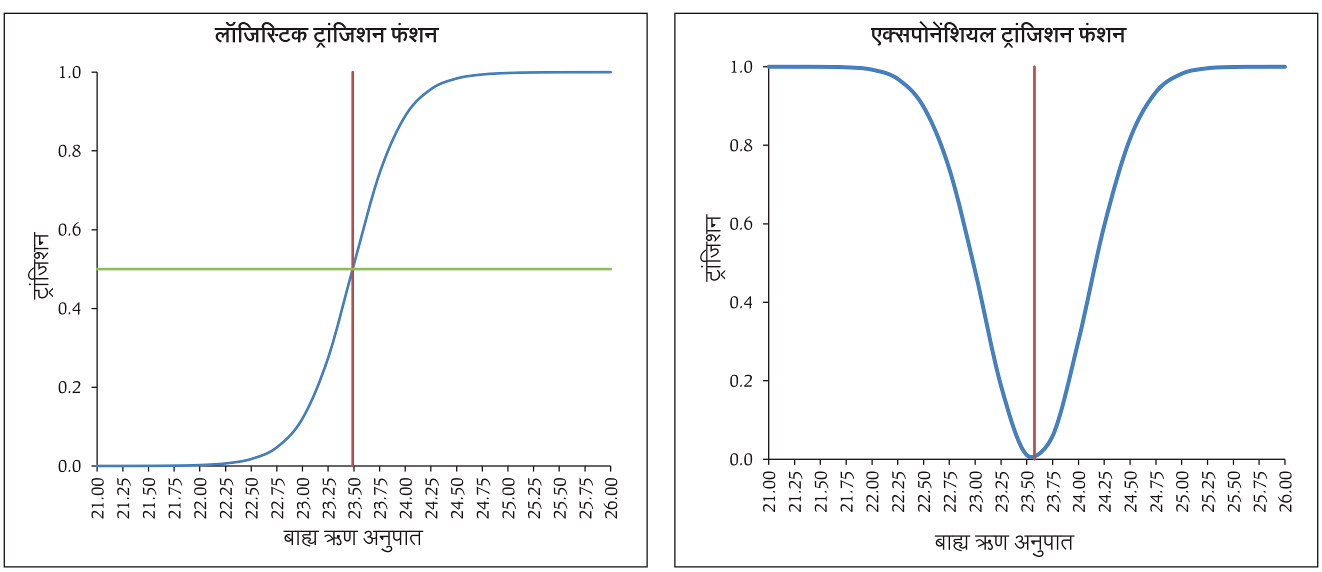

स्रोत : लेखकों की गणना

गया है। शासन परिवर्तन और थ्रेशोल्ड स्तर स्पलाइन रिग्रेशन, थ्रेशोल्ड रिग्रेशन और स्मूथ ट्रांजिशन रिग्रेशन से स्पष्ट हैं क्योंकि वे स्ट्रक्चरल ब्रेक पर आधारित हैं। दूसरी ओर, गैर-रेखीय द्विघात मल्टीवैरियेट रिग्रेशन की प्रवृत्ति स्मूद है, जिससे थ्रेशोल्ड की पहचान करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। द्विघात बहुपद शायद एक गैर-रेखीय संबंध का उपर्युक्त प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है, यह देखते हुए कि थ्रेशोल्ड अनुमान मॉडल में शामिल नॉनलाइनियर फ़ंक्शन के रूप के प्रति संवेदनशील हैं और उनके अनुमानित गुणांक जैसा कि तालिका 1 में देखा गया है। उपर्युक्त संरचनात्मक से निकलने वाली थ्रेसहोल्ड के आधार पर ब्रेक मॉडल, मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद अनुपात (इष्टतम सीमा) के लिए बाह्य ऋण को अधिकतम करने वाली वृद्धि 23.4 प्रतिशत और 23.6 प्रतिशत के बीच हो सकती है। [7,8]

VI. निष्कर्ष

यह आलेख भारत में बाह्य ऋण और आर्थिक वृद्धि के बीच संबंधों की जांच करता है। इस बात का प्रमाण मिलता है कि पारंपरिक सापेक्ष वृद्धि अभिसरण ढांचे के भीतर उनके बीच एक अरेखीय संबंध है, जो एक विशिष्ट उल्टे यू-आकार के बाह्य ऋण लाफ़र वक्र को दर्शाता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट या संवृद्धिवर्धक बाह्य ऋण और जीडीपी अनुपात थ्रेशोल्ड 23.4 फीसदी से 23.6 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है। दिसंबर 2021 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वास्तविक बाह्य ऋण का अनुमान 20 प्रतिशत है, जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक संभावित स्थान को दर्शाता है, जो वर्तमान में अतिरिक्त यूएस $ 90 बिलियन के ऋण के बराबर है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर।

भारत के ऋण बाजार को सावधानीपूर्वक और अंशांकित तरीके से विदेशी पूंजी के लिए उत्तरोत्तर खोला जा रहा है। 2020 में वार्षिक बजट के हिस्से के रूप में, सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों की एक सूची की घोषणा की जो पूरी तरह से विदेशी निवेशकों के लिए पूरी तरह से सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत सीमा के बिना खुली हैं। 10 फरवरी, 2022 को आरबीआई द्वारा घोषित विकासपरक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य ने स्वैच्छिक प्रतिधारण रूट (वीआरआर) के तहत निवेश सीमा को ₹1 लाख करोड़ बढ़ा दिया। इसके अलावा, वैश्विक बांड सूचकांकों में भारतीय सरकारी प्रतिभूति को संभावित रूप से शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं। ऐसे अनुमान हैं कि इस तरह के समावेश से एफएआर प्रतिभूतियों के बढ़ते आकार को देखते हुए भारतीय ऋण बाजार में अतिरिक्त बांड प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। इन नीतिगत विकासों को इस अध्ययन के निष्कर्षों के संदर्भ में देखा जा सकता है। वर्तमान में, सकल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत पर बाह्य वाणिज्यिक उधारों के बकाया स्टॉक के लिए नियम-आधारित गतिशील सीमा लागू है। जैसा कि भारत का लक्ष्य उच्च, टिकाऊ और समावेशी संवृद्धि है, अनुमानित सीमा के भीतर बड़े बाह्य ऋण प्रवाह को आकर्षित करने की आवश्यकता का आकलन अन्य बाहरी भेद्यता मापदंडों के साथ किया जा सकता है ताकि समग्र समष्टि-स्थिरता को संरक्षित करते हुए संवृद्धि के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।

संदर्भ:

Basu, Susanto and Bundick Brent. 2017. "Uncertainity stocks in model of effetive demands." *Econometrica, Volume-85, No-3.* 937-958.

Clements, B., Bhattacharya, R., & Nguyen, T. 2003. "External debt, public investment, and growth in low-income countries." *IMF (IMF Working Paper No.249, WP/03/249).* 249.

Cohen, D. 1993. "Low investment and large LDC debt in the 1980's." *American Economic Review.* 437-449.

[7] परिणामों की मजबूती की जांच के लिए नियंत्रण चर के बिना स्पलाईन प्रतिगमन, दहलीज प्रतिगमन और सुचारू संक्रमण प्रतिगमन का भी अनुमान लगाया गया था। जैसा कि उपर्युक्त परिणामों में बताया गया है, इनफ्लेक्सियन पॉइंट्स में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

[8] इन उपर्युक्त मॉडलों में, बाह्य ऋण चर (D) को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बाह्य ऋण द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि बाह्य ऋण सेवा को ऋण सेवा द्वारा जीडीपी के रूप में दर्शाया जाता है। अतीत में संचित बाह्य ऋण के प्रभाव की जांच करने के लिए (अर्थात, विदेशी ऋण से जीडीपी अनुपात में पिछड़ा हुआ) वर्तमान अवधि में वृद्धि पर, बाह्य ऋण चर को वैकल्पिक रूप से पिछड़े विदेशी ऋण से जीडीपी अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है। इसी तरह, एक बाहरी भेद्यता के दृष्टिकोण से, ऋण सेवा दायित्वों का मूल्यांकन निर्यात आय की तुलना में किया जाना चाहिए। तदनुसार, बाह्य ऋण सेवा को वैकल्पिक रूप से निर्यात के लिए ऋण सेवा के अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है। मॉडलों के इन वैकल्पिक सेटों से बाहरी ऋण के अनुमानित सीमा स्तर के परिणाम मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहे।

Espinoza, R.,Leon, H., & Prasad, A. 2010. "Esatimating the Inflation-Growth Nexus - A Smooth Transition Model." *IMF Wroking Papers, WP/10/76.*

Jayaraman, T.K., & Lau, E. 2009. "Does external debt lead lead to economic growth in Pacific Island countries." *Jounal of Policy Modelling, 31*, 272-288.

Khan, M.S., & Senhadji, A.S,. 2001. "Threshold effects in the relationship between inflation and growth." *IMF Staff Papers, SP/01/48* 1-21.

Krugman, P. 1987. "Financing vs. forgiving a debt overhang: some analytical notes." *Journal of Development Economics, 29,* 253-268.

Lau, E., & Thain-Ling, K. 2014. "External Debt, Exports." *Journal of Applied Sciences 14 (18)* 2170-76.

Patillo, C., Poirson, H., & Ricci, L. A. 2011. "External debt and growth." *Review of Economics and Institutions 2 (3).*

Patillo, C., Poirson, H., Ricci L.,. 2004. "What are the channels through which external debt affects growth?" *IMF (IMF Working Paper No-WP/04/15).*

Patillo, C., Poirson, H., Ricci, L.,. 2002. "External debt & growth." *IMF (IMF Working Paper No-WP/02/69).*

Qureshi, Irfan and Liaqat, Zara. 2020. "The Long-term consequences of external debt: Revisiting the evidence and inspecting the mechanism using panel VARs." *Journal of Macroeconomics. 63.*

Sachs, J.D.,. 1989. *Developing country debt and economic performance. Volume 1.* Chicago: University of Chicago Press.

Sarel, M. 1996. "Non-linear effects of inflation on economic growth." *IMF Working Staff Papers, WSP/96/43* 199-215.

Schclarek, A.,. 2004. "Debt and economic growth in developing and industrial countries." *Lund University Department of Economic,* 34 Working Paper,.

Siddique, Abu, Selvanathan, E.A. and Selvanathan, Saroja. 2016. "The impact of external debt on growth: Evidence from highly indebted poor countries." *Journal of policy modeling 38* 874-894.

Sylvain, Leduce and Liu, Zheng. 2015. "Uncertainty shocks are aggregate demand shocks." *Federal reserve bank of san franscisco working paper 2012-10. WP/12/10.*

अनुबंध

चित्र ए.1: अल्टरनेटिव फंशन फार्म का उपयोग कर इष्टतम बाह्य ऋण स्तर

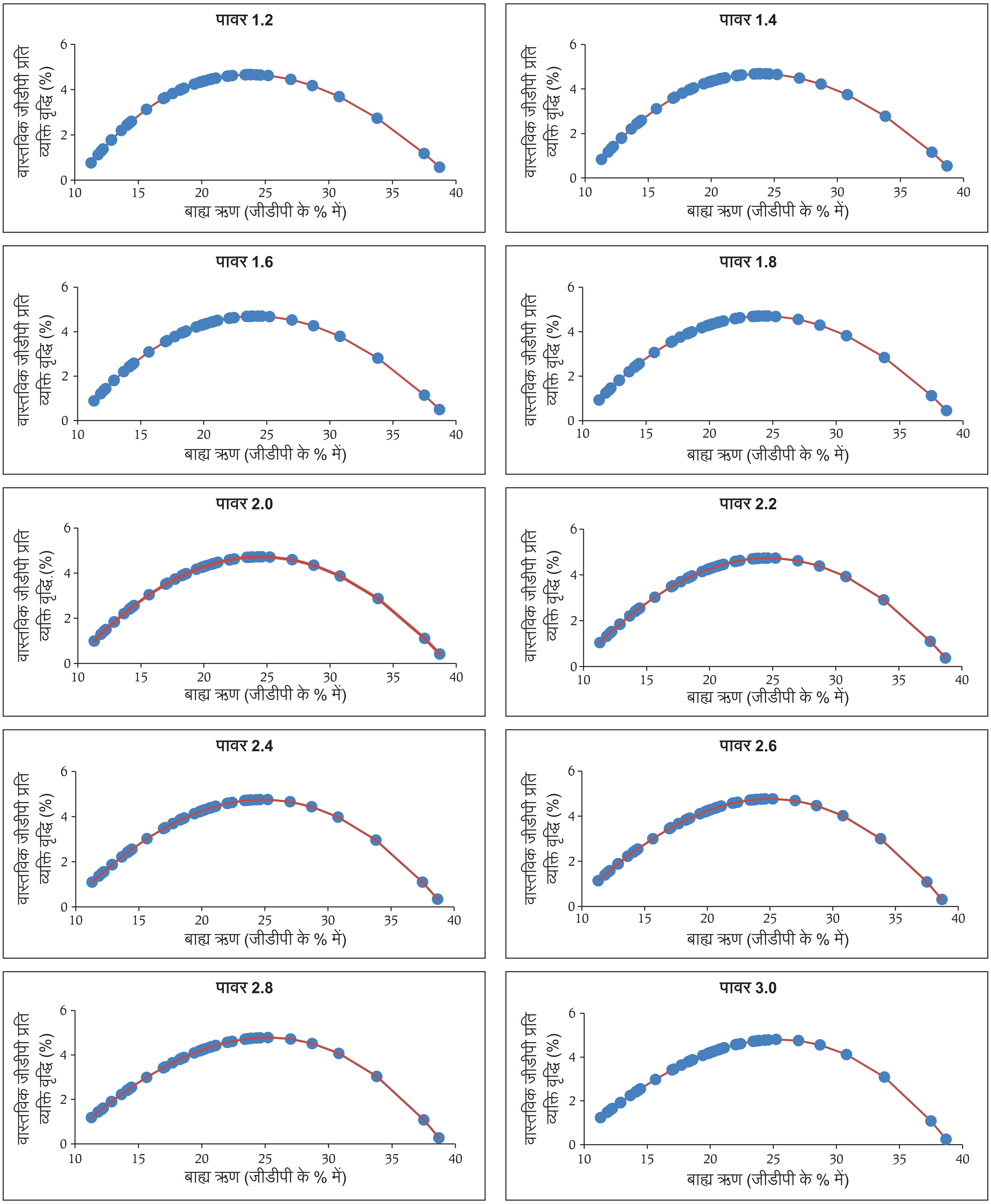

चित्र ए.2 : अनुमानित थ्रेशोल्ड और ट्रेंड व्यवहार

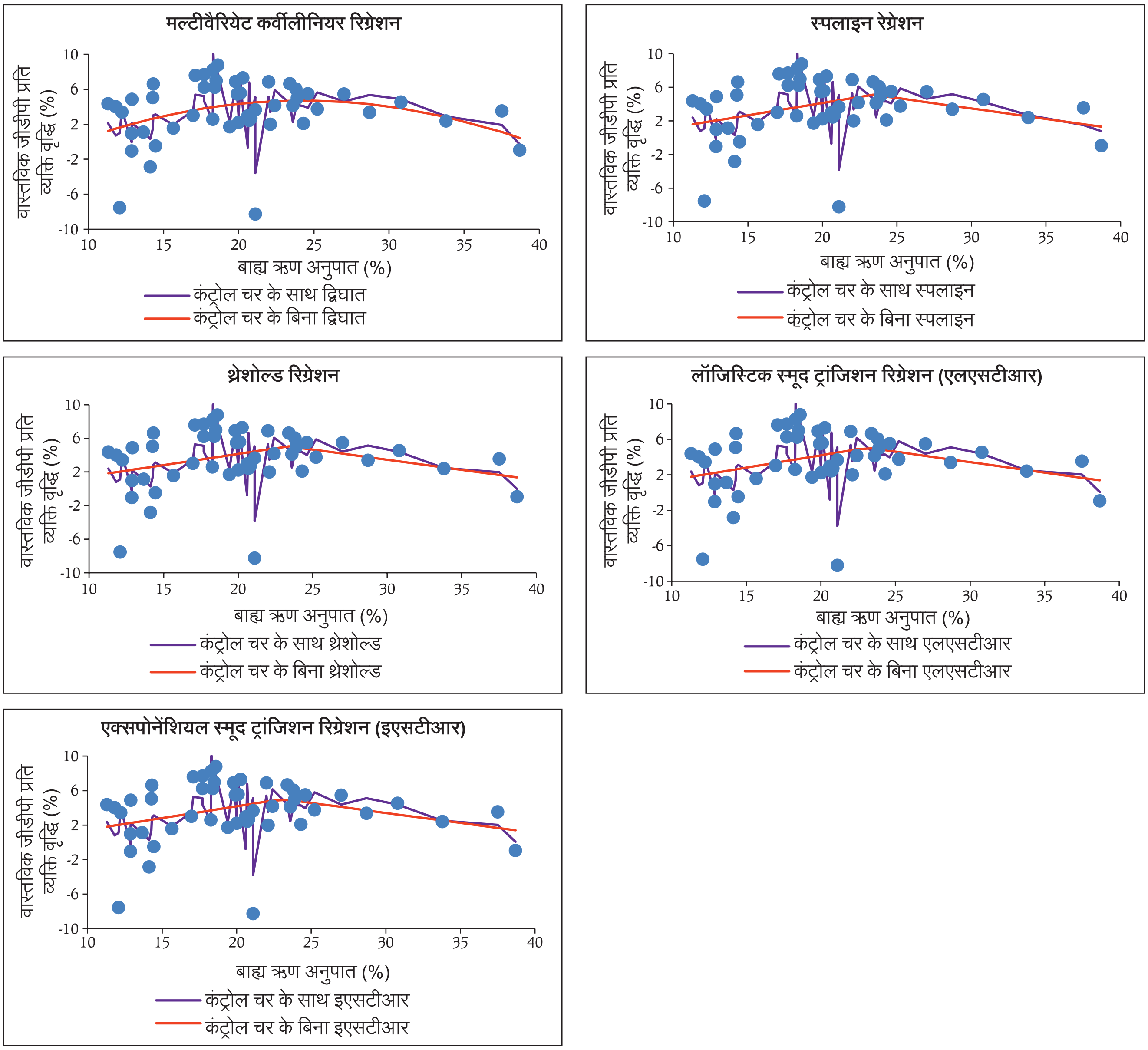

*धारणीय कृषि के लिए सिंचाई प्रबंधन**

कृषि और कृषीतर क्षेत्रों से भूजल की बढ़ती मांग के साथ, धारणीय कृषि के लिए सिंचाई दक्षता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। यह आलेख सिंचाई की क्षेत्र-भारित लागत की गणना करता है और सिंचाई की तकनीकी दक्षता का अनुमान लगाता है तथा भारत में कृषि रूप से महत्वपूर्ण 19 राज्यों के लिए तकनीकी दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करता है। अध्ययन से पता चलता है कि सिंचाई की क्षेत्र-भारित लागत में गिरावट का रुझान रहा है, जो आंशिक रूप से इन राज्यों में सब्सिडी-प्राप्त बिजली आपूर्ति और निम्न सिंचाई दक्षता को दर्शाती है। कृषि क्षेत्र को ऊर्जा की लागत और उपलब्धता के साथ-साथ भूजल स्तर की गहराई, सिंचाई दक्षता को प्रभावित करती है। अंतर-राज्यीय सिंचाई असंतुलन को ठीक करने के लिए उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने सहित सिंचाई नीति को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है।

भूमिका

वैश्विक स्तर पर, जल की पर्याप्त उपलब्धता और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसका संतुलित वितरण एक प्रमुख चिंता के रूप में उभर रहा है। घरों में पीने और साफ-सफाई; कृषि क्षेत्र से सिंचाई उद्देश्यों के लिए; और ऊर्जा क्षेत्र[1] के साथ कृषीतर क्षेत्रों की बढ़ती मांग के कारण जल संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, 17 देशों में रहने वाली दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी 'अत्यंत उच्च' जल दबाव का सामना करती है (विश्व संसाधन संस्थान के एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस के अनुसार)। अन्य 16 देशों की संयुक्त जनसंख्या के तीन गुना से अधिक जनसंख्या के साथ भारत इस सूची में 13वें पायदान पर रहा (भारत सरकार, 2019)।

स्वच्छ और उपयोग-योग्य जल की आपूर्ति विभिन्न क्षेत्रों की मांग के अनुरूप नहीं रही है, जिससे इन क्षेत्रों के बीच संतुलित आबंटन एक नीतिगत चुनौती बन गयी है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में, विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, जहां भले ही भूजल पुनःपूर्ति की दर कम रहती है, में कृषि क्षेत्र जल के सबसे बड़े हिस्से को अवशोषित करता है (चार्ट 1)। जल की समग्र मांग में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी भारत में

चार्ट 1: सिंचाई जल की मांग और भूजल पुनःपूर्ति की दर (वर्ष 2018)

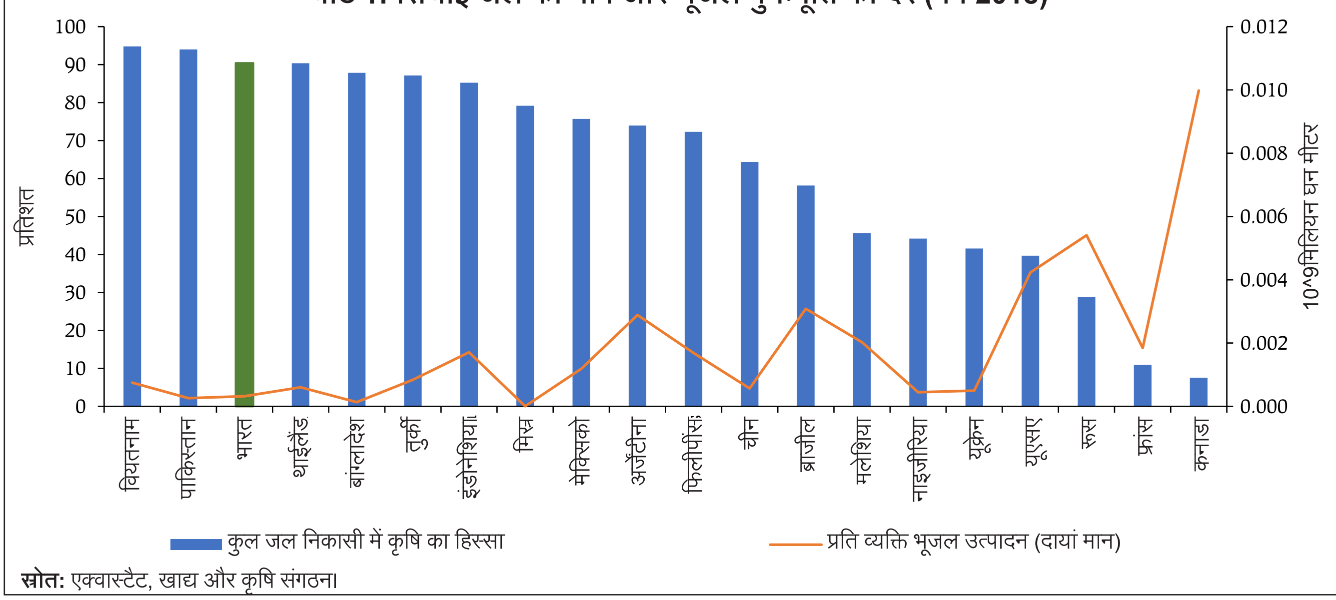

स्रोत: एक्वास्टैट, खाद्य और कृषि संगठन।

* यह आलेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के ऋषभ कुमार, जोबिन सेबेस्टियन और अरुण विष्णु कुमार द्वारा तैयार किया गया है। डॉ. सितिकंठ पट्टनायक, कार्यपालक निदेशक और सुश्री डी. सुगंधी, प्रबंधक के सहयोग के लिए लेखक उनके बहुत आभारी हैं। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] समस्या की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस (22 मार्च) की पूर्व संध्या पर विश्व जल विकास रिपोर्ट: 2022 के लिए "ग्राउंडवॉटर: मेकिंग दि इनविसिबल विसिबल" विषय निर्धारित किया है।

भी सबसे अधिक है, जबकि प्रति व्यक्ति भूजल पुनःपूर्ति दर बहुत कम है।

भारत में भले ही स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से अर्थव्यवस्था में कुल योजित सकल मूल्य (जीवीए) में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही है, फिर भी यह क्षेत्र सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल के एक बड़े हिस्से को अवशोषित कर रहा है। जल की समग्र मांग में सिंचाई का हिस्सा 2010 में 85 प्रतिशत से कम होकर 2050 तक लगभग 74 प्रतिशत होने का अनुमान है; हालाँकि, निरपेक्ष रूप से मांग की गई जल की मात्रा में 1.6 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है (भारत सरकार, 2019) (चार्ट 2)।

कृषि क्षेत्र से जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सिंचाई के आधारभूत ढांचे का महत्वपूर्ण गति से विस्तार हुआ है, जिससे भारत की मानसून पर निर्भरता कम हुई है और यह एक खाद्य-पर्याप्त राष्ट्र बन गया है। हालाँकि, 1950 के दशक में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि नहरों, टैंकों और कुओं के माध्यम से प्रेरित थी, जबकि 1960 के दशक से सिंचाई के आधारभूत ढांचे का विस्तार नलकूपों (ट्यूबवेल) के तहत क्षेत्र में वृद्धि होने से हुआ, जिसके कारण भूजल का स्तर तीव्रता से कम हुआ है (चार्ट 3)।

चार्ट 2: भारत में जल की पूर्वानुमानित मांग (विभिन्न उपयोगानुसार)

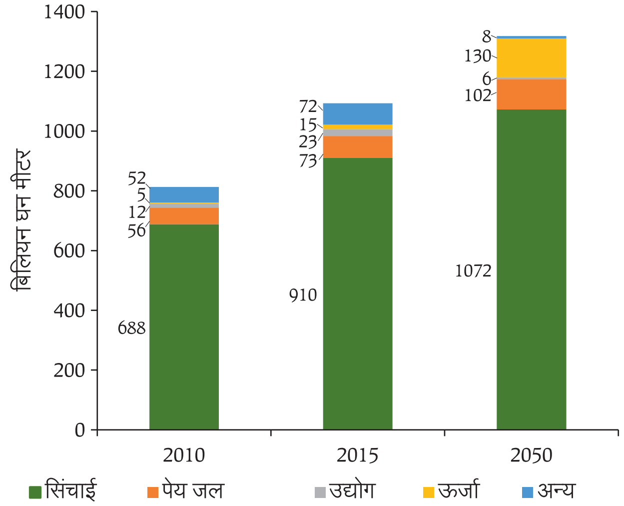

स्रोत: जल संसाधन मंत्रालय की स्थायी उप-समिति।

यद्यपि नई तकनीकों जैसे स्वचालित सिंचाई, जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई, गहन कृषि तकनीक और धान और गन्ना जैसी जल की गहन फसलों से धीरे-धीरे बदलाव इस समस्या के संभावित समाधान के रूप में सामने आए हैं, जिनका प्रभाव वांछनीय से कम रहता है।

चार्ट 3: भारत में भू-जल स्तर की स्थिति

(भूमि के नीचे जलस्तर की गहराई मीटर में)

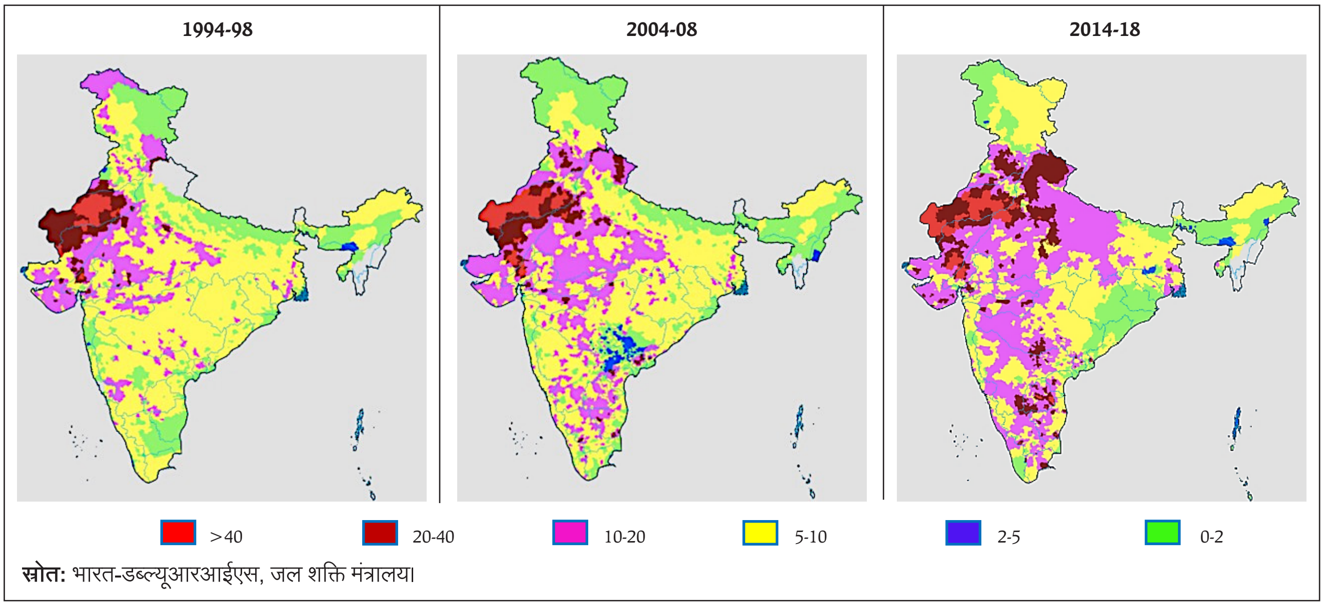

स्रोत: भारत-डब्ल्यूआरआईएस, जल शक्ति मंत्रालय।

चार्ट 4ए: सिंचाई कवरेज में प्रवृत्ति

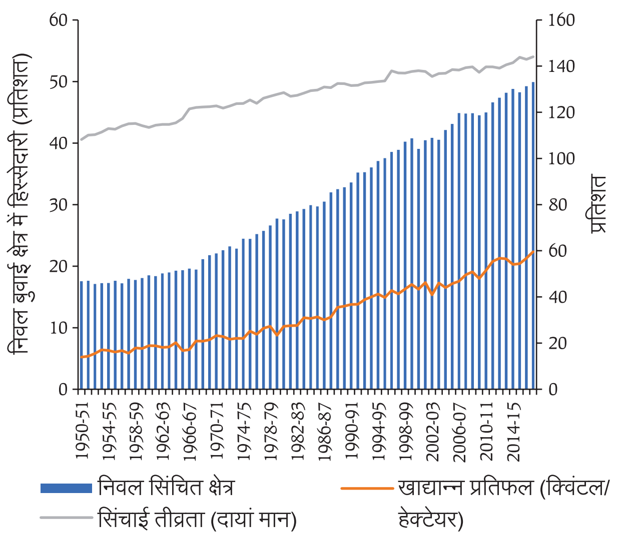

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

चार्ट 4बी. फसल उत्पादकता *बनाम* सिंचाई की हिस्सेदारी (2017)

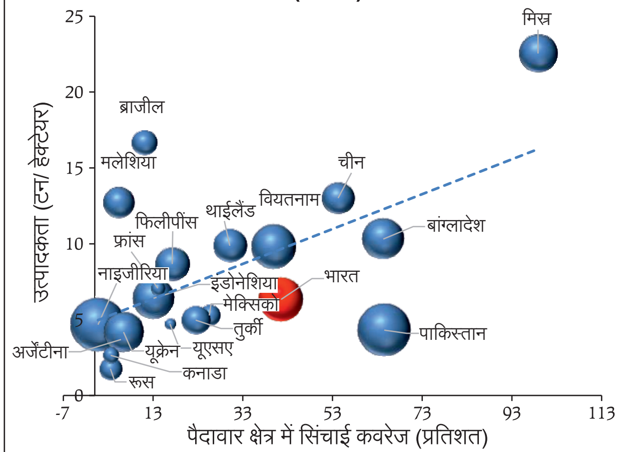

टिप्पणियां: 1. बुलबुलों का आकार समग्र जीडीपी में कृषि के अनुपात को दर्शाता है।
2. शीर्ष 20 कृषि उत्पादक देशों को यहां शामिल किया गया है।

स्रोत: खाद्य और कृषि संगठन।

भूजल स्तर के तेजी से घटने के साथ, जहां एक ओर सिंचाई की लागत और जल के उपयोग की दक्षता से संबंधित मुद्दों ने हाल के वर्षों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्ता हासिल की है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय धारणीयता बनाए रखने के परस्पर विरोधी उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए महत्व प्राप्त किया है।

यद्यपि मौजूदा साहित्य में सिंचाई की लागत और जल उपयोग दक्षता से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया गया है, उनमें से अधिकांश विशिष्ट वर्षों और समय अवधि से संबंधित हैं। भविष्य में जल की मांग के पूर्वानुमानों का अनुमान है कि सिंचाई दक्षता 35-40 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत (भारत सरकार, 2019) हो जाएगी। यह एक भविष्योन्मुख परिप्रेक्ष्य के साथ सिंचाई दक्षता की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए संदर्भ प्रदान करता है। जल की खपत, फसल पैटर्न और सिंचाई प्रौद्योगिकियों में गतिशील परिवर्तनों के बीच, सिंचाई सेवाओं की लागत और दक्षता में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और दक्षता में सुधार के लिए कारक निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में, आलेख तीन प्रमुख मुद्दों की जांच करता है। सबसे पहले, यह 19 राज्यों के लिए सिंचाई की क्षेत्र-भारित लागत की गणना करता है। दूसरा, यह डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस (डीईए) का उपयोग करके राज्य-वार सिंचाई दक्षता का अनुमान लगाता है। अंत में, यह एक रैंडम पैनल टोबिट रिग्रेशन के आधार पर सिंचाई दक्षता के निर्धारकों की पहचान करता है। यह अध्ययन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 19 राज्यों के लिए वर्ष 2002-03 से 2017-18 की अवधि के लिए प्रकाशित- खेती की समग्र लागत के आंकड़ों का उपयोग करता है। हालाँकि इसकी कुछ सीमाएँ हैं, यह सूचना के मामले में एक समृद्ध डेटासेट है (भारत सरकार, 2008; नॉन, 2013)।

शोध का शेष भाग इस प्रकार से संरचित हैं: खंड II भारत में सिंचाई और कृषि उत्पादकता की प्रगति पर कुछ शोधपरक तथ्य प्रस्तुत करता है। राज्य-वार क्षेत्र-भारित सिंचाई की औसत लागत की गणना खंड III में की गई है। खंड IV में सिंचाई दक्षता का अनुमान लगाया गया है और इसके बाद खंड V में इसके कुछ निर्धारकों की पहचान की गई है। अंतिम खंड कुछ नीतिगत सुझावों के साथ आलेख का समापन करता है।

II. शोधपरक तथ्य

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई के अभिगम को मजबूत बनाने में काफी प्रगति की है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई क्षेत्र का कवरेज निवल बोए गए क्षेत्र (एनएसए) के लगभग 17 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में लगभग 50 प्रतिशत हो गया (नवीनतम

चार्ट 5ए: विभिन्न सिंचाई स्रोतों की हिस्सेदारी में प्रवृत्ति

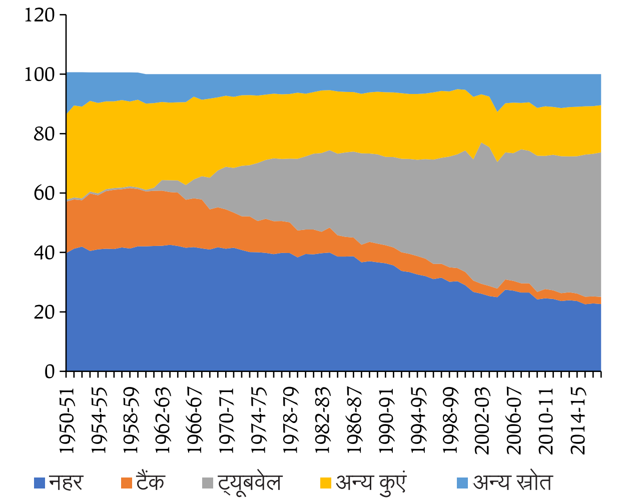

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

चार्ट 5बी. भूजल निकासी *बनाम* खाद्यान्न उत्पादकता के चरण

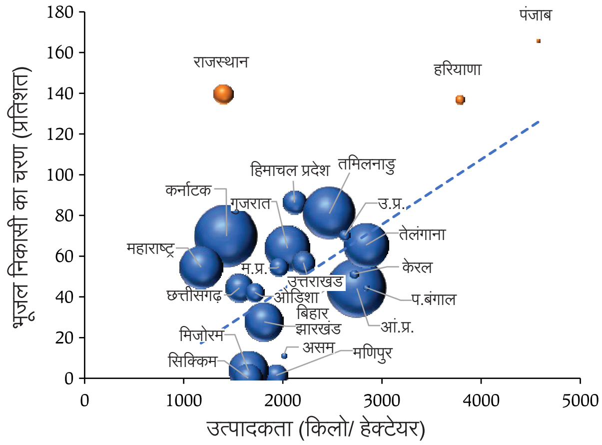

टिप्पणी: 1. बुलबुलों का आकार सकल सिंचित क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज को दर्शाता है।

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) (चार्ट 4ए)। इसी तरह, सिंचाई की सघनता (सकल सिंचित क्षेत्र के लिए निवल सिंचित क्षेत्र का अनुपात) ने 1950-51 में 110 प्रतिशत से 2017-18 में लगभग 144 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सिंचाई में उन्नति और अधिक उपज देने वाली किस्मों को अपनाने के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सिंचाई और उत्पादकता संबंध के संदर्भ में, अन्य देशों में देखे गए मामलों की भांति, भारत को सिंचाई *के माध्यम से* उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है (चार्ट 4बी)।

हालांकि, सिंचाई के आधारभूत ढांचे का विकास सिंचाई के कुछ स्रोतों, राज्यों और फसलों के प्रति पक्षपाती प्रतीत होता है। सबसे पहले, समग्र सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर में नलकूपों का प्रभुत्व 1960 के दशक से लगातार बढ़ा है और वर्तमान में यह कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है (चार्ट 5ए)। इसके परिणामस्वरूप भूजल भंडार पर दबाव बढ़ रहा है और भूजल निकालने के लिए ऊर्जा की अधिक मांग है। साथ ही, पहले उपयोग किए जाने वाले कई कुशल और टिकाऊ संरचनाएं जैसे टैंक और तालाब अपना महत्व खो रहे हैं।

इसके अलावा, भारत में कृषि क्षेत्र द्वारा सूक्ष्म सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को अभी बड़े पैमाने पर अपनाया जाना बाकी है।

दूसरा, भूजल की उपलब्धता और कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली दरों में राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की सीमा के आधार पर वहनीय सिंचाई सुलभता के मामले में भी राज्यों में व्यापक भिन्नता है (गुलाटी *और अन्य,* 2019)। जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में कृषि के लिए बिजली आपूर्ति पर टैरिफ दरें लगभग शून्य हैं, अन्य राज्यों में प्रभारित दरें अलग-अलग हैं (भारत सरकार, 2019ए)। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, जल स्तर की गहराई और सस्ती बिजली और महंगे डीजल पंपों द्वारा चलाए जाने वाले नलकूपों के सापेक्ष अनुपात के मामले में भी राज्यों में व्यापक भिन्नताएं हैं। विशेष रूप से, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पुनःपूर्ति योग्य स्तरों से अधिक भूजल निकासी की जा रही है (चार्ट 5बी)। इसके अलावा, भूजल विलुप्त होने के कगार पर इन राज्यों का सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवरेज न्यूनतम है।

चार्ट 6ए. फसल-वार सिंचाई कवर में प्रवृत्ति

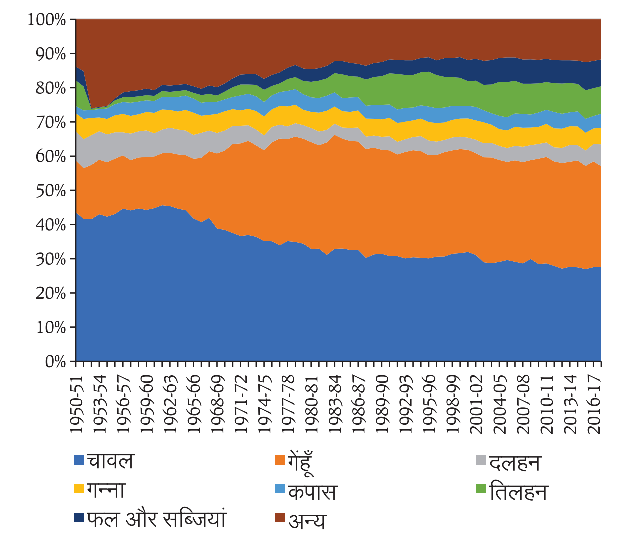

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

चार्ट 6बी. फसल-वार औसत जल आवश्यकता

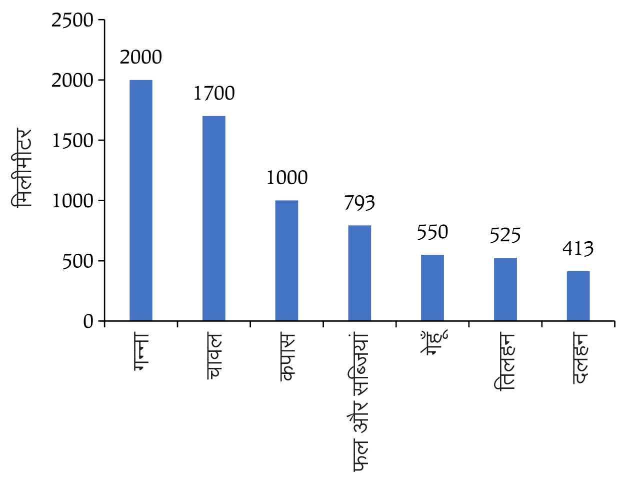

स्रोत: सिंह (2010)

तीसरा, यद्यपि प्रति फसल चक्र में अपेक्षाकृत कम मात्रा में जल की आवश्यकता वाली फसलों, जैसे गेहूँ, तिलहन, फल और सब्जियों के तहत सिंचित क्षेत्र की हिस्सेदारी में समय के साथ बढ़ोतरी हुई हैं (चार्ट 6ए), अभी भी गन्ना, चावल और कपास जैसी जल आधारित गहन फसलों को सिंचित जल की पर्याप्त मात्रा में जल की खपत जारी है। (चार्ट 6बी)। दालें, फल और सब्जियां, जिनकी अपेक्षाकृत अधिक जल उत्पादकता होती है, अभी भी सिंचित क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपनायी नहीं जाती हैं।

III. सिंचाई की लागत

सिंचाई कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाले कारकों में से एक है। भारत में कृषि उत्पादन का बड़ा हिस्सा वर्षा-पोषित क्षेत्रों की तुलना में उच्च उत्पादकता के कारण सिंचित क्षेत्रों से आता है। इसके अलावा, सिंचाई के विभिन्न स्रोतों के अनुसार उत्पादकता व्यापक रूप से भिन्न होती है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि नलकूप सिंचित क्षेत्रों में अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक फसल उत्पादकता पायी गई है (धवन, 1987)।

सिंचाई की लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है - जैसे सिंचाई आपूर्ति की आवृत्ति, भूजल स्तर, स्रोतों (समुदाय या व्यक्ति) का स्वामित्व और जल बाजारों के प्रकार (प्राथमिक या द्वितीयक)। इन कारकों का संवितरण राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई की लागत में अंतर होता है। सिंचाई की लागत पर अधिकांश अध्ययन विशिष्ट वर्षों के लिए चयनित क्षेत्रों में प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं (शंकरनारायणन *और अन्य*, 2011; नारायणमूर्ति और जोथी, 2019)।

अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा खेती की लागत पर व्यापक योजना - राज्यों के लिए सिंचाई की लागत (सिंचाई शुल्क[2] के रूप में) सहित विभिन्न लागतों और प्रतिफल पर फसल-वार डेटा प्रदान करती है। इस डेटा समूह का उपयोग करते हुए, हम डेटा उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2002-03 से 2017-18 तक 19 राज्यों में राज्यवार क्षेत्र-भारित औसत सिंचाई शुल्क की गणना करते हैं। सिंचाई की क्षेत्र-भारित लागत की गणना निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग करके की गई है:

$$IC = \frac{\sum_n^{i=1} c_i * GIA_i}{\sum_n^{i=1} GIA_i}$$

जहां, आईसी (IC)= सिंचाई की क्षेत्र-भारित लागत; सी$_{आई}$ (c_i) = i^{th} फसल के लिए सिंचाई शुल्क; जीआईए$_{आई}$ (GIA_i) = i^{th}

[2] सिंचाई शुल्क का मूल्यांकन निजी सिंचाई के मामले में उपगत परिचालन लागत और किराए की सिंचाई सेवाओं के मामले में भुगतान की गई वास्तविक राशि के आधार पर किया जाता है (भारत सरकार, 2008)।

फसल के तहत सकल सिंचित क्षेत्र ; और आई (i)= फसलों की संख्या (1, 2, 3, …, n)

वर्ष 2017-18 के क्रॉस-सेक्शनल डेटा से पता चलता है कि केरल, असम और ओडिशा में क्षेत्र-भारित सिंचाई शुल्क सबसे कम था, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुल्क था, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश में यह सबसे अधिक था (चार्ट 7)। पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में सिंचाई की अपेक्षाकृत कम लागत को आंशिक रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी वाली बिजली द्वारा समझाया जा सकता है (भारत सरकार, 2019)।

प्रवृत्ति से पता चलता है कि बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अधिकांश राज्यों में सिंचाई की क्षेत्र-भारित औसत लागत में धीरे-धीरे गिरावट आयी है (चार्ट ए3, अनुबंध I)। हालांकि घटते जल स्तर की स्थिति में, सब्सिडी प्राप्त बिजली आपूर्ति के कारण, सिंचाई की बढ़ती लागत किसानों द्वारा वहन नहीं की जाती है (गुलाटी *और अन्य,* 2019)।

बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सिंचाई की बढ़ती लागत विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है। सबसे पहले, कई किसानों के पास स्वयं की सिंचाई सुविधा नहीं होती है और वे आम तौर पर इसे अन्य किसानों से उच्च दरों पर खरीदते हैं (द्वितीयक सिंचाई बाजार)। दूसरा, इन

चार्ट 7: सिंचाई की राज्यवार क्षेत्र भारित लागत (2017-18)

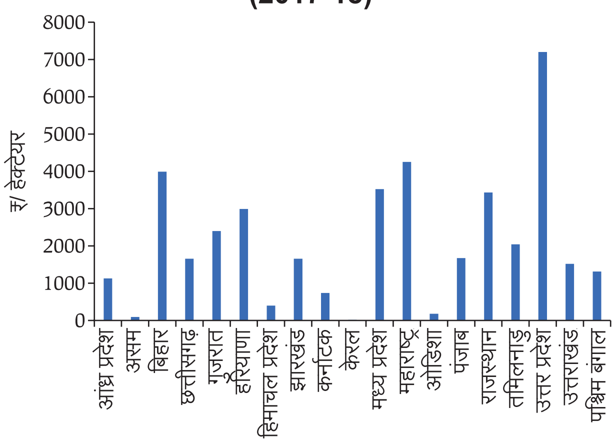

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित खेती की लागत के आंकड़ों के आधार पर लेखकों द्वारा की गई गणना।

राज्यों में घटते जल स्तर के कारण जल निकासी के लिए ऊर्जा की लागत बढ़ सकती थी। तीसरा, किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति तक अभिगम की कमी के कारण अक्सर मजबूरी में सिंचाई के लिए डीजल से चलने वाले पंपों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे उनका अधिक व्यय होता है।

IV. सिंचाई दक्षता

डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस (डीईए) पद्धति का उपयोग करके सिंचाई दक्षता का अनुमान लगाया गया है (चार्नेस, कूपर एंड रोड्स, 1978; और बैंकर, चार्नेस एंड कूपर, 1984)। डीईए एक अप्राचलिक विधि रैखिक प्रोग्रामिंग दृष्टिकोण है, यह निर्णय लेने वाली इकाइयां (यहां, राज्य) कहलाने वाली समकक्ष संस्थाओं के एक समूह के निष्पादन का मूल्यांकन करती है।

यह अनुमानित सर्वोत्तम-अभ्यास या कुशल सीमा, या पारेतो-कुशल राज्यों (दक्षता स्कोर = 1) के एक सेट द्वारा बनाई गई लिफाफा सतह के आधार पर तकनीकी दक्षता को कैलिब्रेट करता है। इसके संबंध में राज्यों की दक्षता की गणना की गई है और स्कोर 0 और 1 के बीच प्राप्त होता है।

अध्ययन में दो इनपुट चरों का उपयोग किया गया है, अर्थात् सिंचाई की क्षेत्र-भारित लागत[3] और सिंचाई के तहत क्षेत्र कवरेज और एक आउटपुट चर, जो तकनीकी दक्षता का आकलन करने के लिए 'उत्पादन का मूल्य' है। हमने स्केल पर निरंतर रिटर्न की धारणा के तहत सिंचाई की उत्पादन उन्मुख तकनीकी दक्षता (आईई) का अनुमान लगाया है।

अनुमान के परिणामों से पता चलता है कि अधिकतम तकनीकी दक्षता के साथ केरल और असम अग्रणी राज्य हैं (सारणी 1)। परिणाम अपेक्षानुसार हैं क्योंकि सिंचाई कवरेज (क्रमशः 20.3 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत) और साथ ही सिंचाई शुल्क (क्रमशः ₹9.8/ हेक्टेयर और ₹70.5/ हेक्टेयर) अन्य राज्यों से तुलनात्मक रूप से कम हैं। उत्पादों के लिए अन्य फसलों की तुलना में, केरल में बागवानी और बागान फसलों [कुल क्षेत्रफल

[3] प्राथमिक सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन जैसे गौतम *और अन्य* (2020) ने विभिन्न लागत घटकों (जैसे श्रम, पाइप, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव) को अलग से लिया है। हालांकि, इस तरह के विस्तृत डेटा पर द्वितीयक आंकड़ों के अभाव के कारण, हमने सिंचाई की लागत पर एकल चर पर विचार किया है जिसमें इन सभी घटकों को शामिल किया जाएगा।

सारणी 1. प्रमुख सिंचाई संबंधित चरों की राज्यवार स्थिति (2018 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए)

राज्य	सिंचाई क्षमता	जल के अत्यधिक उपयोग के अधीन क्षेत्र[5] (%)	भूजल (मीटर)	चावल की अखिल भारतीय सार्वजनिक खरीद में हिस्सेदारी (%)	नलकूपों का हिस्सा (%)	अन्य सिंचाई स्रोतों का हिस्सा (%)	कृषीतर क्षेत्र द्वारा ऊर्जा खपत (%)	सिंचाई की क्षेत्र भारित लागत (₹/ हेक्टेयर)	सूक्ष्म सिंचाई कवरेज (%)	कृषि क्षेत्र के लिए ऊर्जा उपलब्धता (किलोवाट/ व्यक्ति)
आंध्र प्रदेश	0.4	62.3	8.6	6.1	42.3	13.0	72.2	771.3	19.5	167.36
असम	1.0	78.8	4.4	0.1	10.9	61.4	99.4	258.1	0.2	1.88
बिहार	0.2	44.5	5.6	2.0	62.6	6.3	97.6	2496.1	0.3	11.61
छत्तीसगढ़	0.3	76.5	8.7	6.6	33.7	8.5	77.6	634.9	4.6	34.29
गुजरात	0.4	11.1	16.4	0.0	26.5	55.3	80.4	1765.7	11.5	249.34
हरियाणा	0.4	25.6	16.3	16.9	63.0	0.0	71.9	2246.1	0.5	237.58
हिमाचल प्रदेश	0.5	24.1	7.0	0.0	21.8	75.0	99.3	194.2	3.3	3.15
झारखंड	0.5	20.9	8.1	0.2	12.4	85.6	99.4	706.3	8.6	1.81
कर्नाटक	0.3	33.7	8.9	0.0	44.8	25.2	62.8	895.2	21.7	157.99
केरल	1.0	27.1	7.7	0.5	10.8	69.4	98.4	47.6	0.5	5.69
मध्य प्रदेश	0.2	9.0	10.8	8.8	12.3	70.1	62.1	1746.9	2.0	83.28
महाराष्ट्र	0.6	27.3	9.2	0.5	66.7	0.0	76.7	3208.1	10.6	107.27
ओडिशा	0.3	94.4	5.9	5.9	13.7	4.5	98.1	104.1	2.0	4.59
पंजाब	0.5	41.0	17.4	35.5	72.0	0.0	72.3	1050.3	0.1	234.05
राजस्थान	0.3	1.3	25.2	1.2	47.6	28.2	58.1	2413.4	2.3	74.04
तमिलनाडु	0.4	57.7	10.6	0.2	19.8	57.8	86.0	1792.2	15.2	143.11
उत्तर प्रदेश	0.3	36.1	8.3	5.2	74.9	10.0	80.7	4108.8	0.7	28.08
उत्तराखंड	1.0	51.4	13.9	1.2	56.8	20.9	98.7	1189.0	3.1	42.38
पश्चिम बंगाल	0.3	43.9	7.4	3.1	0.0	100.0	96.7	1596.6	0.2	8.84

का 54 प्रतिशत हिस्सा नारियल, रबड़, और टैपिओका के तहत (जॉनसन, 2018)] की महत्वपूर्ण उपस्थिति के कारण उत्पादन का मूल्य उच्च स्तर पर है, जिनकी जल की खपत कम होने पर भी बाजार से उच्च मूल्य प्राप्त होता है। अन्य राज्यों की तुलना में उच्च जल स्तर के परिणामस्वरूप असम के संबंध में, उच्च सिंचाई दक्षता को सिंचाई की न्यूनतम लागत के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। शेष राज्यों के लिए सिंचाई दक्षता त्रैवार्षिक समाप्ति[4] (टीई) 2018 के लिए 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की सीमा में है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में औसतन सिंचाई क्षमता निम्न है।

प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चलता है कि विशेषकर हाल के वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सिंचाई दक्षता देखने को मिली है (चार्ट ए4, अनुबंध I)। दूसरी ओर, झारखंड और महाराष्ट्र में रुझान में वृद्धि दर्ज की गई है।

V. सिंचाई क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक

डीईए पद्धति का उपयोग करते हुए पिछले खंड में प्राप्त दक्षता स्कोर के आधार पर, संभावित कारकों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है जो एक रैंडम पैनल टोबिट रिग्रेशन का उपयोग करके राज्यों की दक्षता निर्धारित करते हैं (लुओमा *और अन्य*, 1996; चिलिंगेरियन 1995; किरजावेनन और लोइकानेन 1998; रोमाग्नोली *और अन्य*, 2021) [अनुबंध III])। विभिन्न निर्धारकों के साथ चार मॉडल फिट किए गए थे, यथा जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के अधीन क्षेत्र, सिंचाई के विभिन्न स्रोतों का हिस्सा, सार्वजनिक खरीद नीति, कृषि क्षेत्र के लिए ऊर्जा उपलब्धता और भूजल स्तर की गहराई। दो चर, यथा कृषि

4 तीन वर्षों का औसत (2015-16 से 2017-18)।

5 चावल और गन्ना।

क्षेत्र के लिए ऊर्जा उपलब्धता और भूजल स्तर की गहराई का सभी मॉडलों में सिंचाई दक्षता पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। सीमांत प्रभाव भी सिंचाई दक्षता पर इन चरों के नकारात्मक प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कृषि क्षेत्र द्वारा ऊर्जा की अधिक खपत से सिंचाई के लिए अत्यधिक जल के उपयोग से अक्षमता का पता चलता है। भूजल स्तर की अधिक गहराई से मोटर द्वारा जल खींचने की दक्षता कम होती है जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई की अक्षमता बढ़ जाती है।

यद्यपि सिंचाई दक्षता मूल्य आम तौर पर अधिकांश राज्यों में समान रुझान दिखाते हैं, सामाजिक-आर्थिक और भूवैज्ञानिक स्थितियों में व्यापक भिन्नताएं दर्शाती हैं कि "सभी के लिए उपयुक्त आकार" नीति भारत में कुशल सिंचाई प्रथाओं के विकास के लिए कारगर नहीं हो सकती है (सारणी 1)। सिंचाई की दक्षता को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों की चर्चा नीचे की गई है।

1. **जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के अधीन क्षेत्र:** ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में चावल और गन्ना जैसी जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में बहुत अधिक हिस्सेदारी है। स्थान-विशिष्ट जल उपलब्धता के अनुसार फसल पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है (जैन *और अन्य*, 2019; डांगर *और अन्य*, 2021; फिशमैन *और अन्य*, 2015)। चावल सघनता प्रणाली (एसआरआई) जैसी तकनीकों को किसानों के बीच विस्तारित और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिसमें न केवल चावल-आधारित फसल प्रणाली में भूमि उत्पादकता में 46 प्रतिशत तक सुधार करने की क्षमता है, बल्कि जल की आवश्यकता को भी 40 प्रतिशत तक कम करने की क्षमता है (नारायणमूर्ति और ज्योति, 2019)।

2. **भूजल का अत्यधिक दोहन:** राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में जल स्तर खतरनाक स्तर पर है। पारंपरिक बाढ़ सिंचाई तकनीकों के निरंतर प्रयोग से बिजली की सस्ती उपलब्धता के कारण भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिससे जल स्तर में भारी गिरावट आयी है। असीमित भूजल तक आसान पहुंच जल स्तर को कम करके अक्षमता को बढ़ाती है और इस प्रकार, सिंचाई के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को बढ़ाती है।

   इस ऊर्जा-सिंचाई संबंध से निपटने का एक समाधान इन राज्यों में बड़े पैमाने पर सूक्ष्म सिंचाई जैसी जल बचत आधारित प्रौद्योगिकियों की शुरूआत है (पलानीसामी *और अन्य*, 2011)। हालांकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर, राज्यों में कुल सिंचित क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज बहुत कम है। सूक्ष्म सिंचाई के अलावा, अन्य उपलब्ध नीति विकल्प हैं: दो फीडर बिजली आपूर्ति[6] (कृषि के लिए रियायती दरों पर और गैर-सब्सिडी दरों पर घरेलू खपत के लिए अलग फीडर); और हाइब्रिड टैरिफ नीतियां (एकसमान और मापे गए टैरिफ का स्थान विशिष्ट मिश्रण) (सिद्धू *और अन्य*, 2020)। अधिशेष बिजली की वापसी-खरीद (बायबैक) योजना के साथ सौर सिंचाई पंपों के उपयोग का भी प्रयोग किया गया है और आवश्यकता से अधिक भूजल के उपयोग को रोकने के लिए सरकार[7] द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।

3. **नलकूप सिंचाई का हिस्सा:** भूजल की कमी और सिंचित क्षेत्र में नलकूप कवरेज में वृद्धि का महत्वपूर्ण अंतर्संबंध है। विशेष रूप से राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां नलकूपों की हिस्सेदारी अभूतपूर्व दर से बढ़ी है- सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जिसमें

---

[6] *दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना*

[7] वर्ष 2018-19 में लॉन्च किया गया, प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) सौर सिंचाई पंपों को बढ़ावा देने के लिए एकछत्र योजना है। इस योजना में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, एक घटक अतिरिक्त सौर ऊर्जा का वापसी-खरीद (बायबैक) है। यह किसानों को अतिरिक्त बिजली बेचकर पैसा बनाने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें अपनी फसलों की प्रभावशाली तरीके से सिंचाई करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा, इस प्रकार भूजल और ऊर्जा के उपयोग को बचाने में मदद मिलेगी।

टैंक, खेत के तालाब, *डिग्गी* [8] और बड़े पैमाने पर अन्य जल संचयन सह सिंचाई संरचनाएं शामिल हैं। ये संरचनाएं मांग से कहीं अधिक सिंचाई आपूर्ति प्रदान कर सकती हैं और वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण में भी मदद करेंगी (चिन्नासामी और श्रीवास्तव, 2021)। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, जहां सिंचाई की लागत उच्च है, डीजल-चालित नलकूपों की निर्भरता को कम करने और ग्रिड से जुड़े खेतों में पर्याप्त बिजली के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तक पहुंच बढ़ाने और शेष खेतों में सौर सिंचाई पंप को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

4. **खाद्यान्न खरीद नीतियां:** पंजाब और हरियाणा (और हाल ही में आंध्र प्रदेश) जैसे राज्यों की सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चावल की खरीद में अपेक्षाकृत अधिक हिस्सेदारी है। यह किसानों को भूजल का उपयोग करके बड़े क्षेत्रों में चावल की खेती के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे सिंचाई की आपूर्ति अक्षम और अधारणीय हो जाती है। अध्ययनों ने अक्सर दालों के एमएसपी में वृद्धि के लिए तर्क दिया है क्योंकि उनकी जल के उपयोग के मामले में कम सामाजिक लागत उपगत होती हैं (भारत सरकार, 2016)।

5. **बागवानी फसलों के लिए फसल विविधीकरण:** केरल में उच्च सिंचाई दक्षता, सिंचाई की कम लागत के साथ-साथ प्रति हेक्टेयर प्राप्त उत्पादन के उच्च मूल्य से प्रेरित प्रतीत होती है। बागवानी फसलें प्रति हेक्टेयर खेती में अपेक्षाकृत कम मात्रा में जल की खपत करती हैं, हालांकि जल आपूर्ति सारणी के संदर्भ में गुणवत्ता, उत्पादन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसके अलावा, ये फसलें खाद्यान्न की तुलना में अधिक लाभकारी हैं। इस प्रकार क्षेत्र-विशिष्ट बागवानी फसलों की ओर बढ़ने से न केवल सिंचाई दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि यह पर्यावरण और आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ भी होगी। सरकार ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किया है; हालाँकि प्रगति नगण्य रही है (मुखर्जी, 2022)।

हमने सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के चरण, सिंचाई स्रोतों की संरचना और फसल पैटर्न के आधार पर राज्यवार मुद्दे और संबंधित नीतिगत सुझाव निर्धारित किए हैं (सारणी 2)। केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों को सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है। बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति से जूझ रहे राज्य सौर सिंचाई पंपों का उपयोग कर सकते हैं जो खेतों के ग्रिड कनेक्शन की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं, जबकि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर सूक्ष्म सिंचाई की आवश्यकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में डीजल से चलने वाले पंपों पर निर्भरता कम करके और सिंचाई के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति की पहुंच बढ़ाकर सिंचाई लागत को कम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में, कठोर शिला जलभृत (रॉक एक्वीफर्स) के कारण लागत अधिक बनी हुई है, जिसके कारण कुओं से बार-बार पानी का बहाव बंद हो जाता है और कुओं में खराबी आ जाती है (गुलाटी *और अन्य*, 2019)। यद्यपि यह समस्या कर्नाटक और तमिलनाडु में भी दर्ज की गई थी, जो कम सिंचाई दक्षता मूल्यों में परिलक्षित होती है, यद्यपि अधिक सब्सिडी के कारण लागत पर इसका प्रत्यक्ष भार नहीं दिखता है। ऐसे क्षेत्रों में जलभृतों का कृत्रिम पुनर्भरण सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, मूल्य निर्धारण नीति में फसल विविधीकरण को निर्देशित करने के लिए भूजल निकासी की सामाजिक लागत को शामिल करने की आवश्यकता है। इन नीतिगत उपायों के अलावा, एसआरआई खेती, सूखा सहिष्णु और जल की निम्न खपत वाली फसल किस्मों का उपयोग, और *स्वस्थानी* और *बाहरी* जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न अन्य तकनीकी नवाचारों का विस्तार करने की भी आवश्यकता है।

[8] छोटे तालाब जैसी संरचनाएं।

सारणी 2. सिंचाई के विकास के लिए राज्यवार मुद्दे और नीतिगत प्राथमिकताएं

राज्य	मुद्दे	नीतिगत प्राथमिकता
आंध्र प्रदेश	चावल की अधिक खरीद; टैंकों की हिस्सेदारी में गिरावट	फसल प्रणाली में धान के हिस्से को कम करना और टैंकों को पुनर्जीवित करना।
असम	जल के अत्यधिक उपयोग के अधीन अधिक क्षेत्र तथा नलकूपों की कम संख्या	सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार
बिहार	सिंचाई की अधिक लागत	बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता
छत्तीसगढ़	जल के अत्यधिक उपयोग के अधीन अधिक क्षेत्र	जल के अत्यधिक उपयोग से इतर तरीके से फसल विविधीकरण
गुजरात	निम्न जल स्तर	सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार
हरियाणा	निम्न जल स्तर, चावल की खरीद में उच्चतर हिस्सेदारी, लघु सिंचाई स्रोतों की निम्न हिस्सेदारी	चावल आधारित फसल प्रणाली में परिवर्तन। सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार
हिमाचल प्रदेश	निम्न सिंचाई कवरेज	सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार
झारखंड	निम्न सिंचाई कवरेज	सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार
कर्नाटक	निम्न जल स्तर (हालांकि खतरनाक स्तर पर नहीं), कठोर सतह जलभृत।	सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार; कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं
केरल	निम्न सिंचाई कवरेज	सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार
मध्य प्रदेश	निम्न जल स्तर (हालांकि खतरनाक स्तर पर नहीं)	सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार
महाराष्ट्र	निम्न जल स्तर (हालांकि खतरनाक स्तर पर नहीं), कठोर सतही जलभृत, निम्न सिंचाई कवरेज, लघु सिंचाई स्रोतों की निम्न हिस्सेदारी।	सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार; कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं
ओडिशा	जल के अत्यधिक उपयोग के अधीन अधिक क्षेत्र, निम्न सिंचाई कवरेज	चावल आधारित फसल प्रणाली से दूर जाना; सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार
पंजाब	निम्न जल स्तर, धान की अधिक खरीद, लघु सिंचाई स्रोतों की निम्न हिस्सेदारी	चावल आधारित फसल प्रणाली से दूर जाना; सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार
राजस्थान	निम्न जल स्तर, सिंचाई की उच्च लागत	सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार; महंगे डीजल पंपों को सौर सिंचाई पंपों से बदलना।
तमिलनाडु	निम्न जल स्तर (हालांकि खतरनाक स्तर पर नहीं), कठोर सतह जलभृत।	सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार; कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं
उत्तर प्रदेश	लघु सिंचाई स्रोतों में वृद्धि, सिंचाई की उच्च लागत	लघु सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली आपूर्ति का संवर्धन
उत्तराखंड	निम्न जल स्तर	सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार

VI. निष्कर्ष और भविष्य के लिए संभावित मार्ग

भारत में कृषि उत्पादन प्रक्रिया अत्यधिक जल गहन बनी हुई है। घटते भूजल और कृषीतर क्षेत्रों की बढ़ती मांग ने स्थायी कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस आलोक में, राज्य-वार और फसल-वार डेटा का उपयोग करते हुए यह आलेख सिंचाई की राज्य-वार क्षेत्र-भारित औसत लागत में रुझानों की गणना और जांच करता है; डेटा एनवेलपमेंट विश्लेषण की पद्धति का उपयोग करते हुए सिंचाई की राज्य-वार तकनीकी दक्षता में रुझानों का अनुमान और विश्लेषण; और रैंडम पैनल टोबिट रिग्रेशन मॉडल के आधार पर आईई के निर्धारकों को निर्धारित करता है।

निष्कर्ष बताते हैं कि राज्य-वार क्षेत्र भारित सिंचाई की औसत लागत में आमतौर पर कई वर्षों से गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो शायद सब्सिडी-प्राप्त बिजली तक पहुंच में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाती है। हालांकि कुछ राज्यों में लागत अभी भी अधिक है। सिंचाई की अनुमानित तकनीकी दक्षता से पता चलता है कि कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारतीय राज्यों में से अधिकांश की उत्पादकता दक्षता सीमा से बहुत दूर हैं और समय के साथ दक्षता में भी गिरावट दर्ज की गई है। रैंडम पैनल टोबिट रिग्रेशन मॉडल सुझाव देते हैं कि कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता और भूजल की उपलब्धता- दक्षता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

यदि ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार और कृषि के लिए निम्न बिजली दरों के साथ-साथ वर्तमान निम्न दक्षता वाली जल प्रबंधन प्रथाएं जारी रहती हैं, तो यह कृषि में असंतुलन को और बढ़ा सकती है। विशेष रूप से उन राज्यों में, जहां दक्षता में गिरावट आ रही है, जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों से इतर

सूक्ष्म सिंचाई और फसल पैटर्न विविधीकरण जैसी कुशल सिंचाई प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित नीति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ:

Atkinson, S. E., & Wilson, P. W. (1995). Comparing mean efficiency and productivity scores from small samples: a bootstrap methodology. *Journal of Productivity analysis*, *6*(2), 137-152.

Badiani, R., & Jessoe, K. (2013). The impact of electricity subsidies on groundwater extraction and agricultural production. *Department of Agriculture and Resource Economics Working Paper, University of California Davis. Retrieved.*

Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. *Management science*, *30*(9), 1078-1092.

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). *A Data Envelopment Analysis Approach to Evaluation of the Program Follow through Experiment in US Public School Education.* Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh Pa Management Sciences Research Group

Chilingerian, J. A. (1995). Evaluating physician efficiency in hospitals: A multivariate analysis of best practices. *European journal of operational research*, *80*(3), 548-574.

Dangar, S., Asoka, A., & Mishra, V. (2021). Causes and implications of groundwater depletion in India: A review. *Journal of Hydrology*, *596*, 126103.

Dhawan, V. (2017). Water and agriculture in India. In *Background paper for the South Asia expert panel during the Global Forum for Food and Agriculture* (Vol. 28).

Fishman, R., Devineni, N., & Raman, S. (2015). Can improved agricultural water use efficiency save India's groundwater? *Environmental Research Letters*, *10*(8), 084022.

Gautam, T. K., Paudel, K. P., & Guidry, K. M. (2020). An evaluation of irrigation water use efficiency in crop production using a data envelopment analysis approach: A case of Louisiana, USA. *Water*, 12(11), 3193.

GoI (2008). *Manual on Cost of Cultivation Surveys.* Department of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare.

GoI (2016). *Incentivising Pulses Production Through Minimum Support Price (MSP) and Related Policies.* Ministry of Finance. September 16, 2016. https://taxindiaonline.com/RC2/pdfdocs/Pulses_report_16th_sep_2016.pdf

GoI (2019). *Water and Related Statistics.* Annual Publication. Central Water Commission, Ministry of Jal Shakti and Ganga Rejunevation.

GoI (2019a). Electricity Tariff & Duty and Average Rates of Electricity Supply in India (March 2019), pp. 8.

Greene, W. H. (2003). *Econometric analysis.* Pearson Education India.

Gulati, A., Sharma, B., Banerjee, P and Mohan, G. (2019): Getting More from Less: Story of India's Shrinking Water Resources, NABARD and ICRIER report, Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi. pp170.

Jain, R., Kishore, P., & Singh, D. K. (2019). Irrigation in India: Status, challenges, and options.

Johnson, D. (2018). Cropping Pattern Changes in Kerala, 1956–57 to 2016–17. *Review of Agrarian Studies*, *8*(2369-2020-2003).

Kirjavainen, T., & Loikkanen, H. (1998). What explains the differences in cost and efficiency between schools? In *More Efficient Public Finances: VATT Yearbook 1998.* State Economic Research Center VATT.

Luoma, K., Järviö, M. L., Suoniemi, I., & Hjerppe, R. T. (1996). Financial incentives and productive efficiency in Finnish health centres. *Health Economics*, *5*(5), 435-445.

Mukherjee, S. (2022). *Farmers gaining from paddy buy up 80% in 6 years, but Punjab needs more.* Business Standard (February 19).

Narayanamoorthy, A., & Jothi, P. (2019). Water saving and productivity benefits of SRI: a study of tank, canal, and groundwater irrigated settings in South India. *Water Policy*, *21*(1), 162-177.

Nawn, N. (2013). Using cost of cultivation survey data: changing challenges for researchers. *Economic and Political Weekly*, 139-147.

Oulmane, A., Ali, C., & Frija, A. (2019). The water use efficiency and its determinants in small horticultural farms in Algeria. *SN Applied Sciences*, *1*(10), 1-9.

Palanisami, K., Mohan, K., Kakumanu, K. R., & Raman, S. (2011). Spread and economics of micro-irrigation in India: evidence from nine states. *Economic and Political Weekly*, 81-86.

Romagnoli, L., Giaccio, V., Mastronardi, L., & Forleo, M. B. (2021). Highlighting the drivers of italian diversified farms efficiency: A two-stage dea-panel tobit analysis. *Sustainability*, *13*(23), 12949.

Shah, T. (2005). Groundwater and human development: challenges and opportunities in livelihoods and environment. *Water Science and Technology*, *51*(8), 27-37.

Sidhu, B. S., Kandlikar, M., & Ramankutty, N. (2020). Power tariffs for groundwater irrigation in India: A comparative analysis of the environmental, equity, and economic tradeoffs. *World Development*, *128*, 104836.

Simar, L., & Wilson, P. W. (1998). Sensitivity analysis of efficiency scores: How to bootstrap in nonparametric frontier models. *Management science*, *44*(1), 49-61.

Simar, L., & Wilson, P. W. (2000). A general methodology for bootstrapping in non-parametric frontier models. *Journal of applied statistics*, *27*(6), 779-802.

Singh, J.V. (2010). Water Requirement of Different Crops. *Agropedia.* Retrivied from: http://agropedia.iitk.ac.in/content/water-requirement-different-crops

Srivastava, A., & Chinnasamy, P. (2021). Water management using traditional tank cascade systems: a case study of semi-arid region of Southern India. *SN Applied Sciences*, *3*(3), 1-23.

Wang, F., Yu, C., Xiong, L., & Chang, Y. (2019). How can agricultural water use efficiency be promoted in China? A spatial-temporal analysis. *Resources, Conservation and Recycling*, *145*, 411-418.

Wang, X. Y. (2010). Irrigation water use efficiency of farmers and its determinants: Evidence from a survey in northwestern China. *Agricultural Sciences in China*, *9*(9), 1326-1337.

Watto, M. A., & Mugera, A. W. (2014). Measuring Production and Irrigation Efficiencies of Rice Farms: Evidence from the Punjab Province, Pakistan. *Asian Economic Journal*, *28*(3), 301-322.

Xue, M., & Harker, P. T. (1999). Overcoming the inherent dependency of DEA efficiency scores: a bootstrap approach. *Unpublished Working Paper, Wharton Financial Institutions Center, University of Pennsylvania.*

अनुबंध I

चार्ट ए1: सिंचाई कवरेज में राज्यवार रुझान (वर्ष 2002-03 से 2017-18)

(निवल बुवाई क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में निवल सिंचित क्षेत्र)

सिंचाई कवरेज

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त डेटा पर आधारित लेखकों द्वारा की गई गणना।

चार्ट ए2: फसल उत्पादन के औसत मूल्य में राज्यवार रुझान (वर्ष 2002-03 से 2017-18)

(₹/ हेक्टेयर – वर्ष 2011-12 की कीमतों पर)

प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मूल्य

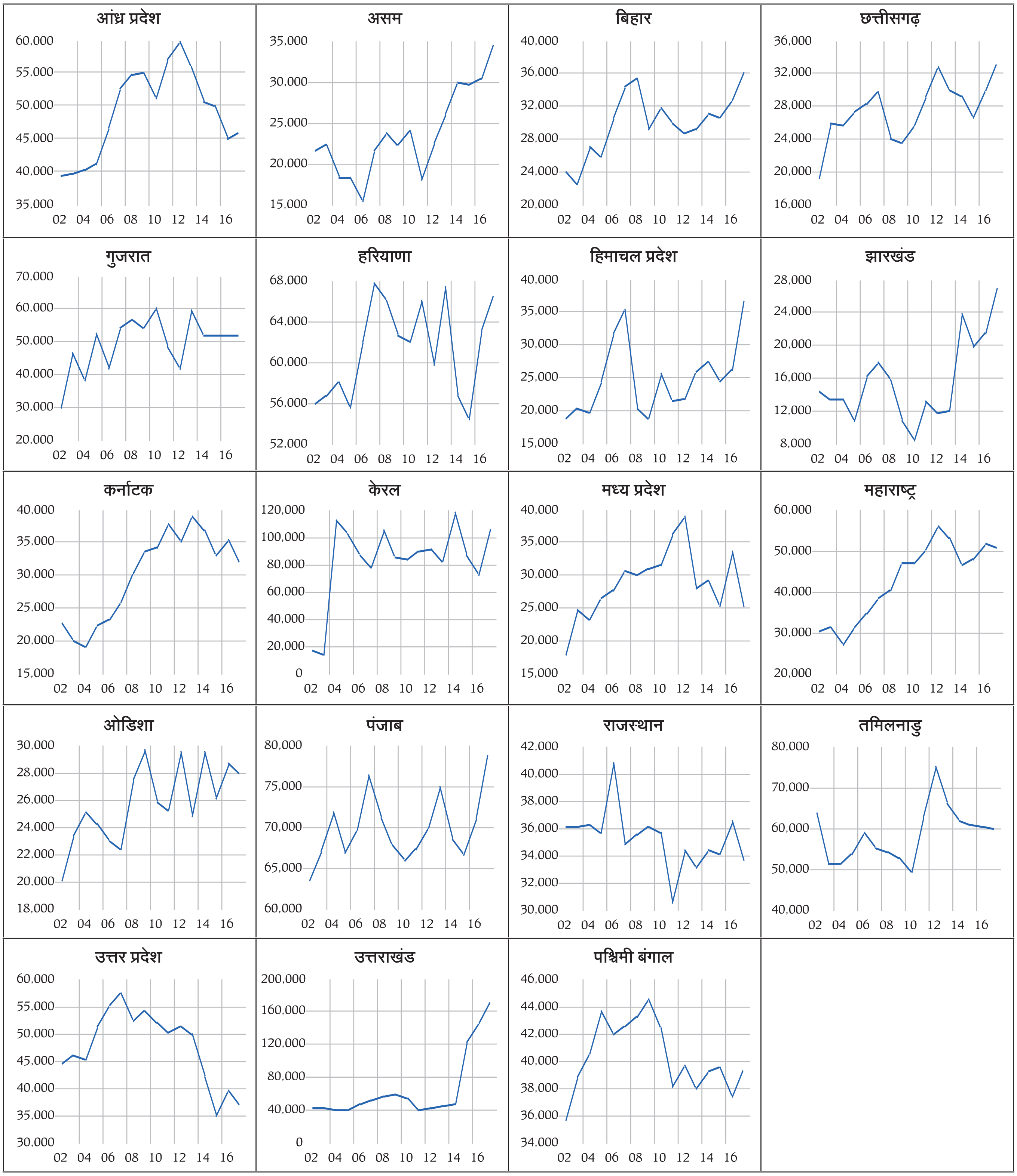

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त खेती की लागत के डेटा पर आधारित लेखकों द्वारा की गई गणना।

चार्ट ए3: सिंचाई की लागत में राज्यवार रुझान (वर्ष 2002-03 से 2017-18)

(₹/ हेक्टेयर – वर्ष 2011-12 की कीमतों पर)

सिंचाई प्रभार

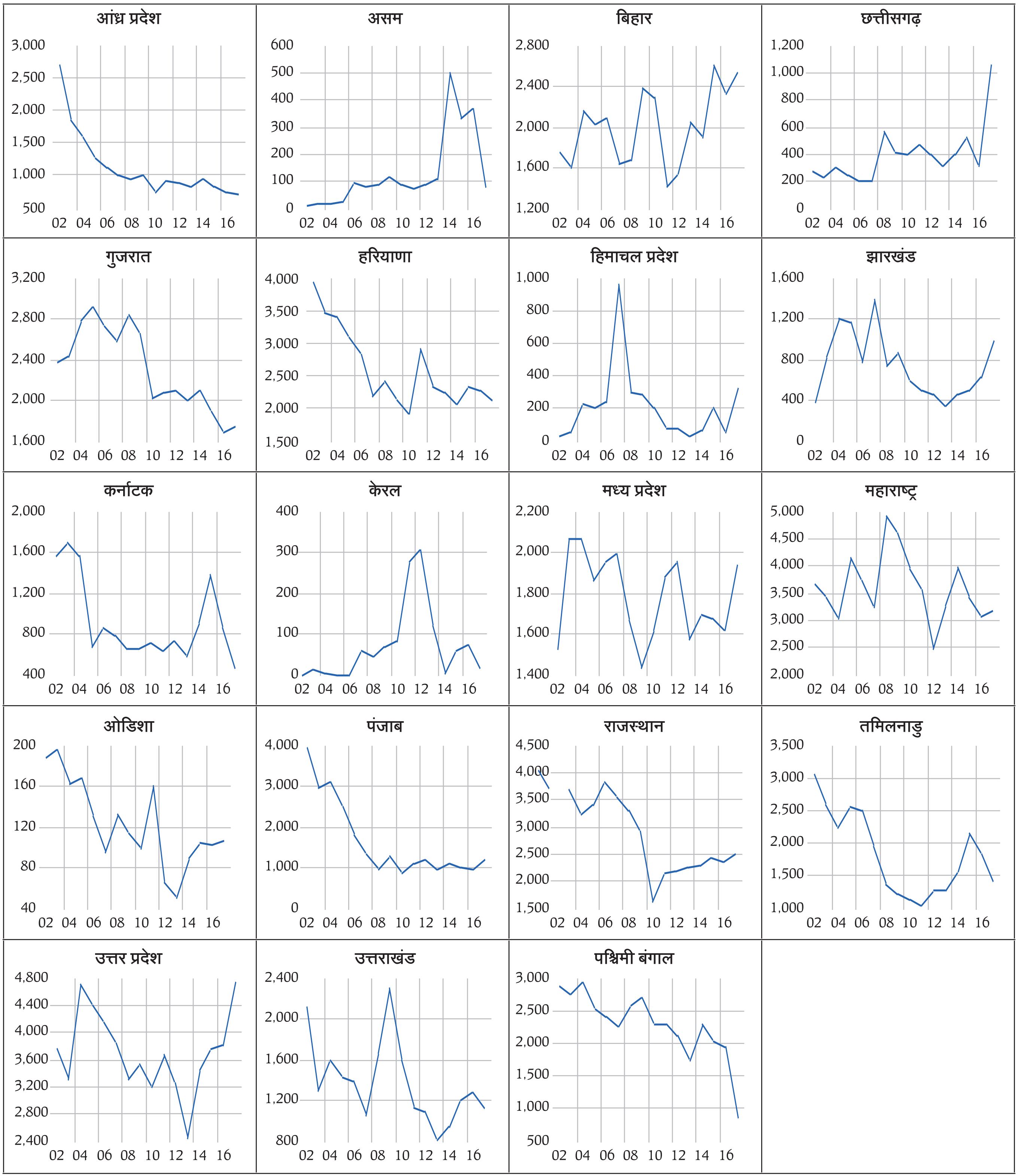

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त खेती की लागत के डेटा पर आधारित लेखकों द्वारा की गई गणना।

चार्ट ए4: सिंचाई की अनुमानित तकनीकी दक्षता में राज्यवार रुझान

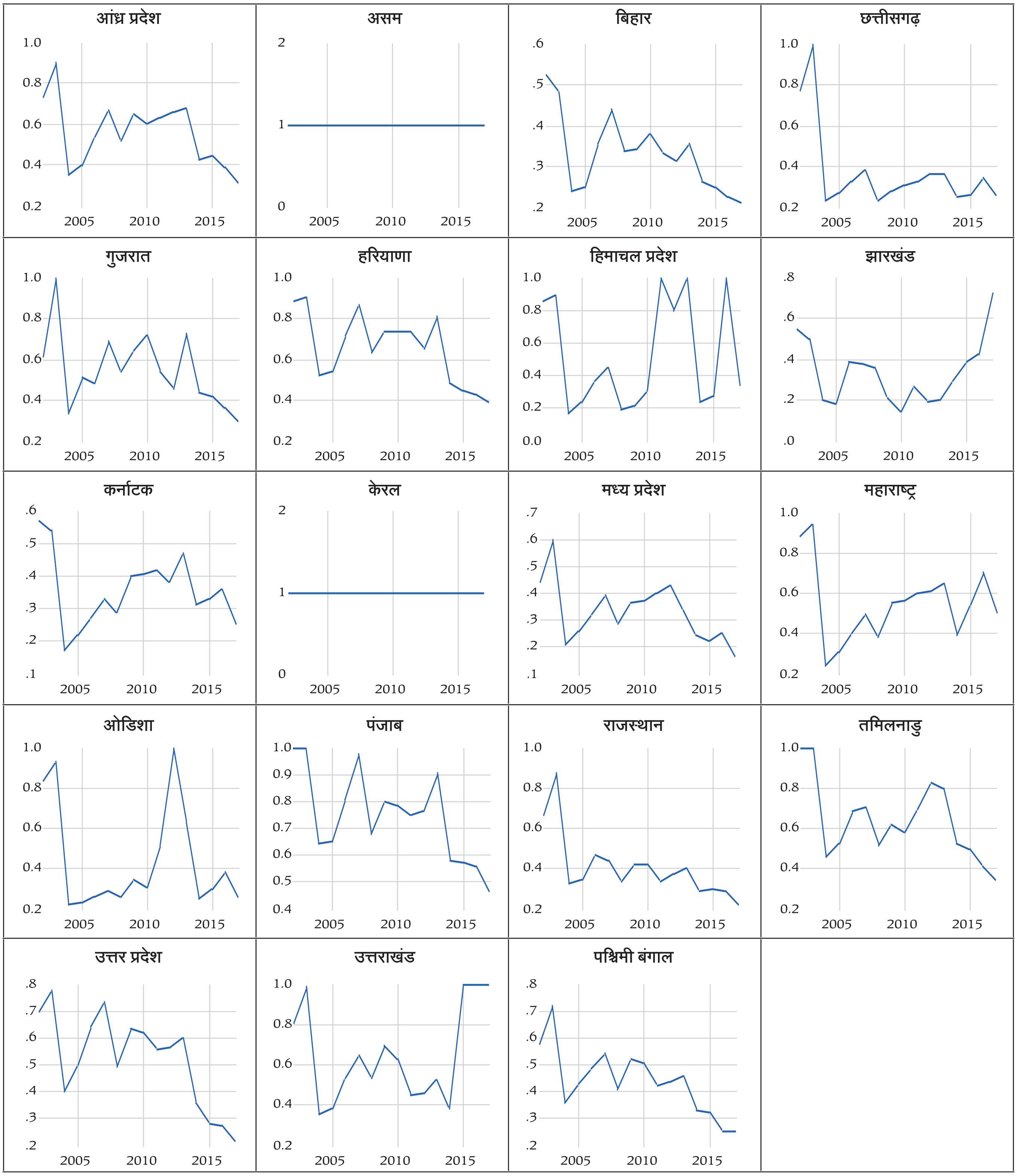

स्रोत: लेखकों द्वारा अनुमान।

अनुबंध II

सारणी ए1: डीईए पद्धति को नियोजित करने वाले अन्य अध्ययनों की समीक्षा

अध्ययन	उद्देश्य	डेटा और कार्यप्रणाली	प्रमुख निष्कर्ष
चिलिंगेरियन (1995)	एक अस्पताल में चिकित्सकों की नैदानिक दक्षता की जांच करने और उच्च निष्पादन से जुड़े कारकों की पहचान करने के लिए	डीईए और मल्टीफैक्टर टोबिट विश्लेषण	नमूने से 24 अक्षम चिकित्सकों का पता चला और टोबिट विश्लेषण से तकनीकी रूप से कुशल चिकित्सकों की दो व्यापक श्रेणियां सामने आईं। इसके अलावा, अध्ययन द्वारा यह तथ्य सामने आया कि सेंसर किए गए प्रतिगमन के साथ डीईए का सम्मिश्रण बेहतर परिणाम देगा।
लुओमा *और अन्य* (1996)	फिनलैंड के स्वास्थ्य केंद्रों की दक्षता और उसके निर्धारक कारकों की जांच करना	डीईए और टोबिट मॉडल	अधिक उदार संसाधनों से अक्षमता बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों की अधिक हिस्सेदारी और सहायक कर्मचारियों की निम्न हिस्सेदारी से दक्षता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, निम्न प्रौढ़ आबादी नजदीकी अस्पताल से लंबी दूरी की दक्षता से सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है।
किरजावैनेन और लोइकानेन (1998)	फिनलैंड के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बीच दक्षता अंतर का अनुमान	डीईए और टोबिट मॉडल	औसत दक्षता 82-84 प्रतिशत के मध्य रही। छोटे वर्ग, विषम छात्र निकाय दक्षता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं जबकि सुशिक्षित माता-पिता स्कूल की क्षमता को बढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूल अधिक अक्षम पाए गए।
वांग *और अन्य* (2019)	चीन में जल उपयोग दक्षता और इसके प्रभावकारी कारकों का आकलन	डीईए और टोबिट मॉडल	चीनी प्रांतों में कुल जल उपयोग दक्षता 0.582 अनुमानित है और पूर्वी चीन में उच्च जल क्षमता वाले प्रांतों की अधिकतम संख्या है। निर्यात निर्भरता, तकनीकी प्रगति और शैक्षिक मूल्य के रूप में निर्दिष्ट सकारात्मक प्रभावकारी कारक हैं। औद्योगिक संरचना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक के रूप में पहचाना गया जबकि सरकारी हस्तक्षेप का जल दक्षता पर बहुत कम प्रभाव पड़ा।
गौतम *और अन्य* (2020)	लुइसियाना, यूएसए में सोयाबीन की सिंचाई जल उपयोग दक्षता।	रसेल माप के साथ पूरक के रूप में डीईए	उत्पादक सिंचाई के जल का 37 प्रतिशत अधिक उपयोग कर रहे हैं। अध्ययन पुनर्निर्धारण, इनपुट प्रबंधन और अन्य सर्वोत्तम सिंचाई प्रबंधन प्रथाओं सहित उपयुक्त प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता का सुझाव देता है।

अध्ययन	उद्देश्य	डेटा और कार्यप्रणाली	प्रमुख निष्कर्ष
बडियानी और जेसो (2013)	भारतीय परिदृश्य में बिजली सब्सिडी, भूजल निकासी और कृषि उत्पादकता के मध्य संबंध का पता लगाने की कोशिश की।	अध्ययन के लिए प्रासंगिक चर लेकर कृषि उत्पादन मॉडल।	बिजली सब्सिडी के भार में कमी काफी कम है और मूल्य और फसल संरचना, दोनों के संदर्भ में सकारात्मक कृषि प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह गहन-जल वाली फसलों की ओर अधिक स्थानांतरित हो रहा है। अध्ययन से पता चलता है कि कृषि सब्सिडी में 10% की कमी से भूजल निकासी में 6.7% की कमी आती है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन अत्यधिक भूजल निकासी के कारण पर्यावरणीय लागत और संभाव्य धारणीयता के मुद्दों को इंगित करता है।
फिशमैन *और अन्य* (2015)	उत्तर देने का प्रयास किया, 'क्या कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार से भारत के भूजल को बचाया जा सकता है'?	परिदृश्य विश्लेषण (उपयुक्त तकनीकी मिश्रण के साथ सहज और यथार्थवादी परिदृश्य)	परिणामों से पता चला कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों में भूजल निकासी को दो-तिहाई कम करने की क्षमता है। किसान द्वारा खेत में तकनीकी हस्तक्षेप से अधिक के जल उपयोग के निर्णय जल स्तर में कमी को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, अध्ययन तकनीकी हस्तक्षेपों के साथ-साथ संरक्षण प्रोत्साहन के महत्व को जोड़ता है।
जैन *और अन्य* (2019)	चुनौतियों और संभावित विकल्पों के साथ भारत में सिंचाई की स्थिति के बारे में विहंगम दृष्टि	मेटा-विश्लेषण के साथ-साथ वर्णनात्मक और सारणीबद्ध विश्लेषण, दोनों का मिश्रण।	पेपर ने दर्शाया कि भूजल पर बेहिसाब निर्भरता के कारण टीई 2002 से 2016 के बीच देश के 64% जिलों में जल स्तर में कमी आयी है। इसके अतिरिक्त, जल उपयोग दक्षता को पेपर देश में खुली/ सतही सिंचाई के बजाय सूक्ष्म सिंचाई के महत्व की ओर इंगित करता है। जल दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने का निर्धारण करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के रूप में दो पूर्व शर्तें निर्दिष्ट की गईं।
सिद्धू *और अन्य* (2020)	भारत में भूजल निकासी और इसके पर्यावरण, आर्थिक और इक्विटी ट्रेड-ऑफ पर बिजली शुल्क (एकसमान टैरिफ और मापे गए टैरिफ) का प्रभाव।	सारणीबद्ध, चित्रमय और वर्णनात्मक विश्लेषण।	हालांकि एकसमान टैरिफ में निम्न प्रशासनिक लागत और समान वितरण परिणाम होते हैं, लेकिन यह किसानों को जल संरक्षण के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता है। दूसरी ओर, मापे गए टैरिफ विवेकपूर्ण खपत को बढ़ावा देता है, लेकिन कम आय वाले किसानों के लिए यह नुकसानदेह है क्योंकि बड़े भूजल मालिकों पर उनकी अधिक निर्भरता है। देश में कृषि पद्धतियों की विविधता और भूजल उपलब्धता पर विचार करते हुए, यह पेपर स्थान-विशिष्ट टैरिफ नीतियों को लचीले ढंग से अपनाने का सुझाव देता है।

अध्ययन	उद्देश्य	डेटा और कार्यप्रणाली	प्रमुख निष्कर्ष
डांगर और मिश्रा (2021)	गंगा नदी बेसिन में भूजल की कमी के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक और मानव-निर्मित कारकों की पहचान करना	हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन मॉडल	बेसिन में भूजल की कमी में अनवीकरणीय भूजल अवशोषण (80%) के रूप में पहचाने गए परिणाम का बहुत योगदान है। क्षेत्र में गंभीर और लगातार सूखे ने निकासी को तेज कर दिया और पुनर्भरण को धीमा कर दिया। अध्ययन ने सुझाव दिया कि फसल पैटर्न में उचित बदलाव, भूजल स्तर की पैमाइश और जल उपयोग दक्षता में वृद्धि क्षेत्र में स्थायी भूजल उपयोग के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक हैं।
रोमाग्नोली *और अन्य* (2021)	इतालवी विविधीकृत खेतों की दक्षता और प्रमुख चालकों का अनुमान लगाना	दो चरण डीईए-टोबिट विश्लेषण	विविधीकरण करने वाली फर्मों की घटनाओं में सुधार की बहुत गुंजाइश है। इसके अलावा, प्रतिगमन परिणाम यह दर्शाते हैं कि अन्य लाभकारी गतिविधियों से उत्पादन की घटनाओं से दक्षता में काफी वृद्धि होती है। हालांकि, बढ़ती मध्यवर्ती लागतों का दक्षता मानकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक और प्रबंधकीय कारक कई तरह से दक्षता स्कोर को प्रभावित करते पाए गए।
वाटो और मुगेरा (2014)	पंजाब, पाकिस्तान में भूजल सिंचित कपास खेतों की तकनीकी दक्षता और सिंचाई जल उपयोग दक्षता का आकलन	स्टोकेस्टिक फ्रंटियर मॉडल	अध्ययन के परिणामों ने प्रस्तावित किया कि ट्यूबवेल मालिक और जल के खरीदार दोनों क्रमशः उत्पादन में 19% और 28% की वृद्धि कर सकते हैं। सिंचाई के जल के उपयोग की अक्षमता तकनीकी अक्षमताओं की तुलना में अधिक गंभीर है।
ओल्मने *और अन्य* (2019)	अल्जीरिया में लघु बागवानी किसानों में जल उपयोग दक्षता और इसके निर्धारकों का आकलन।	डीईए और टोबिट विश्लेषण	सीआरएस और वीआरएस अनुमानों के लिए प्राप्त औसत तकनीकी दक्षता स्कोर क्रमशः 68% और 79% हैं। जल उपयोग दक्षता का निर्धारण शिक्षा के स्तर और तकनीकी जानकारी, खेती वाले घरों और जल संसाधनों की कुल संख्या, ऋण पहुंच, ग्रीन हाउस आदि जैसे चरों द्वारा किया जाता है।
वांग (2010)	उत्तर-पश्चिमी चीन में सिंचाई जल उपयोग दक्षता और इसके निर्धारक	डीईए और टोबिट रिग्रेशन	औसत तकनीकी दक्षता 0.62 पर अनुमानित है। अध्ययन ने सुझाव दिया कि इनपुट के कुशल उपयोग से गेहूं उत्पादन के 38.49% और विस्तार की गुंजाइश है। किसान की उम्र, खेत का आकार, शिक्षा और आय सिंचाई की जल दक्षता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

अनुबंध III
सिंचाई दक्षता का निर्धारण करने वाले कारक

पैनल टोबिट रिग्रेशन

पहले चरण से प्राप्त दक्षता स्कोर को बाद के चरण में आश्रित चर माना गया है। चूंकि आश्रित चर सिंचाई दक्षता मापदंड 0 से 1 के मध्य भिन्न-भिन्न होता है, सामान्य न्यूनतम वर्ग (ओएलएस) सिद्धांत से पक्षपाती और असंगत अनुमान उत्पन्न होंगे (ग्रीन, 2003)। इसके अलावा, डीईए मान सापेक्ष दक्षता मान हैं जिनके परिणामस्वरूप सूचकांकों के बीच सहसंबंध हो सकता है जिससे ओएलएस प्रतिगमन अप्रभावी हो जाता है (एटकिंसन और विल्सन, 1995)। इस प्रकार, हमने अधिकतम संभावना अनुमान प्रक्रिया का उपयोग करके मापदंडों का अनुमान लगाया। सुसंगत और निष्पक्ष मापदंड अनुमानों का उत्पादन करने के लिए डीईए स्कोर को एक मसृणन समवर्गीय बूटस्ट्रैपिंग प्रक्रिया का उपयोग करके ठीक किया जाता है (सिमर और विल्सन, 1998, 2000)। यह मूल रूप से एक पुन: नमूनाकरण तकनीक है जो दक्षता स्कोर की अंतर्निहित निर्भरता समस्या का समाधान कर सकती है (ज़ू और हार्कर, 1999)

टोबिट मॉडल के यादृच्छिक प्रभाव[9] का सामान्य रूप निम्न है:

$$y_{it} = \begin{cases} c, & \text{if } y^*_{it} \le c \\ y^*_{it}, & \text{if } y^*_{it} > c \end{cases}, \text{ with}$$

$$y^*_{it} = x'_{it}\beta + \alpha_i + \nu_{it}$$

The marginal effect on y_{it} is

$$\frac{\partial E[y_{it}|x_{it}]}{\partial x_{it}} = \hat{\beta}\,\Phi\left(\frac{x'_{it}\hat{\beta}}{\sqrt{\sigma^2_\alpha + \sigma^2_\nu}}\right)$$

छह प्रासंगिक चरों[10] का चयन किया गया था जिसमें नलकूपों का हिस्सा, कृषि क्षेत्र के लिए ऊर्जा उपलब्धता, भूजल स्तर, नहरों का हिस्सा, जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र और खाद्यान्न की खरीद; और पैनल टोबिट विश्लेषण द्वारा अनुमानित चार अलग-अलग मॉडल शामिल थे। चयनित पैनल चरों की वर्णनात्मक सांख्यिकी सारणी ए2

सारणी ए2: पैनल चरों की वर्णनात्मक सांख्यिकी

(एन=304)

चर	विवरण	माध्य	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम	अपेक्षित संकेत
तकनीकी दक्षता	-	0.58	0.26	0.15	1.00	ला.न.
नलकूपों का हिस्सा	कुल बुवाई क्षेत्र में से सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	34.20	23.88	0.00	74.92	-
कृषि क्षेत्र के लिए ऊर्जा उपलब्धता	किलो वाट प्रति घंटा/ प्रति व्यक्ति	115.09	116.87	0.51	416.71	-
भूजल स्तर	डमी चर = 1 यदि >/= राष्ट्र औसत[11]; अन्यथा =0	0.47	0.50	0.00	1.00	-
नहरों का हिस्सा	प्रतिशत	28.02	18.45	0.00	82.74	+/-
जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र	प्रतिशत	40.82	24.12	0.58	94.43	-
खाद्यान्न खरीद	अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सेदारी	5.19	9.12	0.00	50.65	-

9 हमने निश्चित प्रभाव मॉडल के बजाय यादृच्छिक प्रभाव अपनाया है क्योंकि निश्चित प्रभाव मॉडल, टोबिट जैसे गैर-रैखिक मॉडल में तकनीकी रूप से अनुपलब्ध हैं (ग्रीन, 2004)।

10 चरों के लिए पैनल यूनिट रूट टेस्ट (क्रॉस सेक्शन में स्वतंत्र) का महत्वपूर्ण परीक्षण किया गया था, इस प्रकार निराकरणीय परिकल्पना (समय-श्रृंखला में यूनिट रूट का अस्तित्व) को अस्वीकृत कर दिया गया था।

11 माध्यिका

में सूचीबद्ध है, जो डीईए से गणना की गई दक्षता मापदंड को 0.142 से 1 तक दर्शाते हैं और कर्नेल डेंसिटी प्लॉट वितरण की द्विविध प्रकृति को दर्शाता है (चार्ट ए5)।

पैनल टोबिट रैंडम इफेक्ट मॉडल के परिणाम सारणी ए3 में दिए गए हैं जो 16 वर्षों (2002-2017) की अवधि के लिए 19 भारतीय राज्यों की सिंचाई दक्षता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करते हैं।

सारणी ए3: दूसरा चरण पैनल टोबिट रिग्रेशन परिणाम

मॉडल 1				*लॉग संभावना=65.4*	*वाल्ड ची स्क्वा.= 11.7*
चर	**आकलन**	**एसई**	**जेड मान**	**पी>जेड**	**सीमांत प्रभाव**
स्थिर	0.809	0.148	5.450	0.000	
नहरों का हिस्सा	-0.001	0.003	-0.360	0.721	-0.001
कृषि क्षेत्र के लिए ऊर्जा उपलब्धता	-0.001	0.000	-2.760	0.006	-0.001
नलकूपों का हिस्सा	-0.002	0.003	-0.820	0.411	-0.002
भूजल स्तर	-0.062	0.031	-1.990	0.046	-0.055

मॉडल 2				*लॉग संभावना=67.1*	*वाल्ड ची स्क्वा.= 11.3*
चर	**आकलन**	**एसई**	**जेड मान**	**पी>जेड**	**सीमांत प्रभाव**
स्थिर	0.699	0.089	7.890	0.000	
नहरों का हिस्सा	-0.001	0.002	-0.380	0.707	-0.001
कृषि क्षेत्र के लिए ऊर्जा उपलब्धता	-0.001	0.000	-2.830	0.005	-0.001
खाद्यान्न खरीद	0.008	0.006	1.420	0.156	0.007
भूजल स्तर	-0.061	0.034	-1.800	0.072	-0.056

मॉडल 3				*लॉग संभावना=65.2*	*वाल्ड ची स्क्वा.= 14.5*
चर	**आकलन**	**एसई**	**जेड मान**	**पी>जेड**	**सीमांत प्रभाव**
स्थिर	0.772	0.135	5.730	0.000	
नलकूपों का हिस्सा	-0.002	0.002	-1.060	0.288	-0.002
कृषि क्षेत्र के लिए ऊर्जा उपलब्धता	-0.001	0.000	-3.030	0.002	-0.001
जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र	0.000	0.001	0.000	0.997	0.000
भूजल स्तर	-0.060	0.028	-2.170	0.030	-0.053

मॉडल 4				*लॉग संभावना=68.2*	*वाल्ड ची स्क्वा.= 16.6*
चर	**आकलन**	**एसई**	**जेड मान**	**पी>जेड**	**सीमांत प्रभाव**
स्थिर	0.760	0.146	5.200	0.000	
नलकूपों का हिस्सा	-0.002	0.002	-1.160	0.244	-0.002
कृषि क्षेत्र के लिए ऊर्जा उपलब्धता	-0.001	0.000	-2.990	0.003	-0.001
जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र	0.000	0.002	0.210	0.833	0.000
भूजल स्तर	-0.059	0.035	-1.690	0.090	-0.054
नहरों का हिस्सा	-0.001	0.003	-0.420	0.678	-0.001
खाद्यान्न खरीद	0.009	0.006	1.380	0.169	0.008

चार्ट ए5: दक्षता वितरण

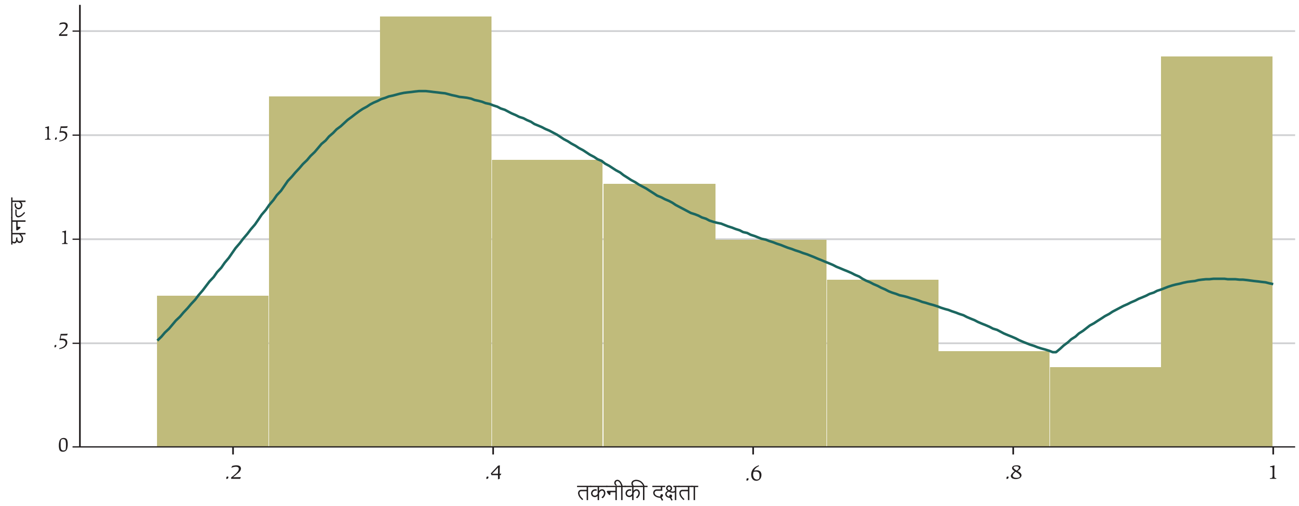

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक शृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	111
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	112
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	113
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	114
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	115
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	115
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	116
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	117
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	118
9	कुल चलनिधि राशियां	118
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	119
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	119
12	वाणिज्यिकिक बैंक सर्वेक्षण	120
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	120
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	121
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	122
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	123
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	124
	कीमत और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	125
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	125
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	125
21	थोक मूल्य सूचकांक	126
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	130
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	130
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	131
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	131
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	132
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	133
28	वाणिज्यिकिक पत्र	133
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	133
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	134

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	135
32	विदेशी मुद्रा भंडार	135
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	135
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	136
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	136
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	137
37	बाह्य वाणिज्यिकिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	138
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	139
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	140
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	141
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	142
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	143
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	144
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	146
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	147
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	148
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	149
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	150
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	151
50 (ए)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार	152
50 (बी)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक	155

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम   आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2021-22	2020-21		2021-22	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	8.3	-5.9	2.1	8.4	4.7
1.1.1 कृषि	3.3	3.2	4.1	3.7	2.6
1.1.2 उद्योग	10.4	3.0	6.2	6.6	1.4
1.1.3 सेवाएं	8.8	-10.4	0.04	10.0	6.7
1.1ए अंतिम खपत व्यय	7.2	-10.8	0.4	10.1	6.5
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	14.6	-4.5	-0.6	14.6	2.0
	2021-22	2021		2022	
		फर.	मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	11.3	-3.2	24.2	1.5	1.9
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	8.9	12.1	11.4	8.6	8.9
2.1.2 ऋण	9.6	6.6	5.6	9.1	9.6
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9.7	6.6	5.5	9.2	9.7
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6.0	18.3	19.3	4.7	6.0
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	8.9	13.6	18.8	13.9	8.9
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.7	12.8	12.2	8.7	8.7
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.50	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.7	3.7	4.2	4.6	4.7
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.2	72.2	72.4	71.8	72.2
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	77.2	29.6	37.4	72.1	77.2
3.6 निवेश-जमा अनुपात	28.7	29.9	29.5	28.8	28.7
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	19.7	52.8	46.8	18.8	19.7
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.5 आधार दर	7.25/8.80	7.30/8.80	7.40/8.80	7.25/8.80	7.25/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.45/7.00	6.55/7.05	6.55/7.05	6.45/7.00	6.45/7.00
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	5.00/5.60	4.90/5.50	4.90/5.50	5.00/5.60	5.00/5.60
4.8 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.34	3.25	3.25	3.30	3.34
4.10 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.84	3.17	3.32	3.70	3.84
4.11 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.27	3.48	3.47	4.19	4.27
4.12 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.58	3.70	3.83	4.52	4.58
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.86	6.34	6.34	6.78	6.86
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	76.18	73.04	72.40	75.28	76.18
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.01	88.80	85.31	84.38	84.01
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमिआ 1-माह (%)	5.67	5.59	6.80	4.30	5.67
3-माह (%)	4.46	5.59	5.64	4.41	4.46
6-माह (%)	4.10	5.19	5.47	4.20	4.10
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.51	5.0	5.5	6.1	7.0
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.13	4.5	5.7	5.0	5.4
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	12.94	4.8	7.9	13.1	14.5
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	10.17	3.0	7.3	13.4	15.5
6.3.2 ईंधन और पावर	32.79	2.0	9.7	31.5	34.5
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	11.02	6.1	7.8	9.8	10.7
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	55.13	7.5	55.4	39.9	24.2
7.2 निर्यात	43.81	-0.4	64.1	34.4	19.8

स्तंभ (1) और (5) के लिए डेटा अनंतिम हैं।

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

2. #: 3 दिसंबर, 2021 से सभी पखवाड़ों के लिए बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2021-22	2021	2022				
		अप्रै.	अप्रै. 1	अप्रै. 8	अप्रै. 15	अप्रै. 22	अप्रै. 29
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3107637	2887884	3105703	3148104	3172815	3181381	3182321
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	15	14	17	15	18	17	13
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3107652**	**2887898**	**3105721**	**3148119**	**3172833**	**3181398**	**3182334**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	128208	110440	125887	125535	127853	127258	123547
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2978927	2776759	2979325	3022105	3044519	3053708	3058380
1.2.3 रुपया सिक्का	518	699	508	479	461	432	407
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1794574	1507507	1733548	1692610	1705269	1647280	1654833
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	100	100	100	101	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	43	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	683437	579344	748612	673528	706313	684949	740234
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7123	6487	7634	8659	7462	7832	7650
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4121	3311	5151	4339	4411	4149	4156
2.1.1.7 अन्य बैंक	37589	32482	41322	38276	38551	38419	38403
2.1.1.8 अन्य	988819	885731	856476	897072	879588	853370	804385
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	73343	8	74209	70593	68801	58417	59862
2.1.2 अन्य देयताएं	1359254	1458976	1301575	1268422	1273278	1265376	1237355
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**3153828**	**2966482**	**3035123**	**2961032**	**2978547**	**2912656**	**2892188**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	15	14	17	15	19	17	13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1243853	1296637	1134111	1084649	1070654	1056752	1040173
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	–	33892	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	670	4506	2384	4184	4677	2698	4380
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	94299	89934	94934	94281	98638	94388	94306
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	24927	17077	23010	23010	23010	23010	23010
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	8077	6729	14507	11702	11702	8701	6498
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	72741	8	73725	70067	68244	57784	59307
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	1491042	1397597	1490818	1471944	1462775	1465168	1464756
2.2.6 अन्य आस्तियां	218203	153979	201618	201179	204936	204139	199745
2.2.6.1 स्वर्ण	201354	152269	197709	197157	200797	199862	194425

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घावधि रिपो परिचालन एवं	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घावधि रिपो परिचालन	विशेष पुनः क्रय रिपो £	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12-2-4-7-8-13)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मार्च 1, 2022	-	39102	-	-	1203	–	-	-	-	-	-	-	-	-37899
मार्च 2, 2022	-	225644	-	-	1090	–	-	-	-	-	-	-	-	-224554
मार्च 3, 2022	-	222710	-	-	1114	–	-	-	-	-	-	-	-	-221596
मार्च 4, 2022	-	82076	-	225096	1243	–	-	-	-	-	-	-	-	-305929
मार्च 5, 2022	-	39782	-	-	414	–	-	-	-	-	-	-	-	-39368
मार्च 6, 2022	-	11191	-	-	66	–	-	-	-	-	-	-	-	-11125
मार्च 7, 2022	-	132145	-	-	1156	–	-	-	-	-	-	-	-	-130989
मार्च 8, 2022	-	66700	-	-	952	–	-	-	-	-	-	-	-	-65748
मार्च 9, 2022	-	85565	-	-	804	–	-	-	-	-	-	-	-	-84761
मार्च 10, 2022	-	59695	-	-	5437	7000	-	-	-	-	-	-	-	-47258
मार्च 11, 2022	-	378843	-	353944	897	-7000	-	10	10	-	-	-	-	-738890
मार्च 12, 2022	-	18112	-	-	328	–	-	-	-	-	-	-	-	-17784
मार्च 13, 2022	-	6181	-	-	6	–	-	-	-	-	-	-	-	-6175
मार्च 14, 2022	-	394312	-	-	1547	–	-	-	-	-	-	-	-	-392765
मार्च 15, 2022	-	377532	-	-	870	–	-	-	-	-	-	-	-	-376662
मार्च 16, 2022	-	249620	-	-	609	–	-	-	-	-	-	-	-	-249011
मार्च 17, 2022	-	89155	-	57120	1559	2800	-	-	-	-	-	-	-	-141916
मार्च 18, 2022	-	12087	-	-	1320	–	-	-	-	-	-	-	-	-10767
मार्च 19, 2022	-	73795	-	-	1857	–	-	-	-	-	-	-	-	-71938
मार्च 20, 2022	-	8453	-	-	42	–	-	-	-	-	-	-	-	-8411
मार्च 21, 2022	-	164783	-	-	491	–	-	-	-	-	-	-	-	-164292
मार्च 22, 2022	-	115964	-	114612	248	–	-	-	-	-	-	-	-	-230328
मार्च 23, 2022	-	115888	-	-	227	–	-	-	-	-	-	-	-	-115661
मार्च 24, 2022	-	138413	-	-	2608	2000	-	-	-	-	-	-	-	-133805
मार्च 25, 2022	-	340351	-	231258	11	3200	-	-	-	-	-	-	-	-568398
मार्च 26, 2022	-	32222	-	-	128	–	-	-	-	-	-	-	-	-32094
मार्च 27, 2022	-	5052	-	-	26	–	-	-	-	-	-	-	-	-5026
मार्च 28, 2022	-	430596	-	-	344	–	-	-	-	-	-	-	-	-430252
मार्च 29, 2022	-	251541	-	218762	0	2300	-	-	-	-	-	-	-	-468003
मार्च 30, 2022	-	353471	-	-	5	1920	-	-	-	-	-	-	-	-351546
मार्च 31, 2022	-	399200	-	-	52	200	-	-	-	-	-	-	-	-398948

टिप्पणियां: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ), लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) और मांग के अनुसार लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन।
ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा लिए गए पुर्नभुगतान को दर्शाता है।
& ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।
£ 07 मई 2021 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/177 के अनुसार। 18 जून 2021 से, 4 जून 2021 के प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/323 के अनुसार डेटा में राशि शामिल है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2020-21	2021	2022	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	68315	-5699	771	-20101
1.1 क्रय (+)	162479	20250	5946	4315
1.2 विक्रय (-)	94164	25949	5175	24416
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	510516	-41123	6459	-153010
3 संचयी (मार्च के के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	68315	68315	37413	17312
(करोड़ ₹)	510516	510516	287639	134629
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	72751	72751	49106	65791

ii) मुद्रा वायदा भाग में परिचालन

मद	2020-21	2021	2022	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	12118	830	0	570
1.2 विक्रय (-)	12118	830	0	570
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	690	690	0	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 मार्च 2022 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	11965	5000	6965
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	14345	0	14345
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	39346	0	39346
4. 1 वर्ष से अधिक	5135	0	5135
कुल (1+2+3+4)	**70791**	**5000**	**65791**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद		अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति						
	2021-22	2021			2022			
		अप्रै. 26	नवं. 22	दिसं. 19	जन. 31	फर. 28	मार्च 25	अप्रै. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	11	149	7201	8176	38	1858	11	140
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	–	0	0	0	734	0	0	0
4.1 सीमा	76000	75000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	32401	27122	24196	24401	24401	24401	32401	31021
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32412	27271	31397	32577	25173	26259	32412	31161

टिप्पणीः 1. अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा अर्थात एक्ज़िम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित सुविधा, अर्थात आरबीआई अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू /एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2021-22	2021	2022		
		मार्च 26	फर. 25	मार्च 11	मार्च 25
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3037622	2756705	2980565	3018879	3037622
1.1 संचलन में नोट	3107637	2831727	3052620	3087949	3107637
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	27270	26170	27139	27139	27270
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	98028	101935	99937	96951	98028
2 जनता की जमाराशियां	2265371	2042467	2157809	2095752	2265371
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	2212992	1995120	2103056	2044072	2212992
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	52379	47347	54752	51680	52379
3 एम$_1$ (1 + 2)	**5302993**	**4799173**	**5138374**	**5114631**	**5302993**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	170853	170853	170853	170853	170853
5 एम$_2$ (3 + 4)	**5473846**	**4970026**	**5309227**	**5285484**	**5473846**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	15186605	14050278	15045154	15164344	15186605
7 एम$_3$ (3 + 6)	**20489597**	**18849451**	**20183528**	**20278975**	**20489597**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	510435	509544	510435	510435	510435
9 एम$_4$ (7 + 8)	**21000032**	**19358995**	**20693963**	**20789410**	**21000032**

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/ रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		मार्च 26	फर. 25	मार्च 11	मार्च 25
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**6204211**	**5732751**	**6232004**	**6339925**	**6204211**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1177178	982063	1267912	1294485	1177178
1.1.1 सरकार पर दावे	1490166	1332127	1498132	1493337	1490166
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1489496	1330453	1497945	1487128	1489496
1.1.1.2 राज्य सरकारें	670	1674	186	6209	670
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	312988	350065	230220	198852	312988
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	312946	350022	230177	198810	312946
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	43	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	5027033	4750689	4964092	5045441	5027033
2 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**12610042**	**11668281**	**12350302**	**12421076**	**12610042**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिकिक क्षेत्र को ऋण	10092	8524	1853	2086	10092
2.2 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	12599950	11659757	12348448	12418990	12599950
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	11891314	10949509	11643717	11712341	11891314
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	690201	694758	686893	688748	690201
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18435	15490	17838	17900	18435
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**4850355**	**4560899**	**4881815**	**4904843**	**4850355**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4551499	4181453	4582959	4605987	4551499
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4551740	4181689	4583200	4606228	4551740
3.1.2 विदेशी देयताएं	241	237	241	241	241
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	298856	379446	298856	298856	298856
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**28013**	**26913**	**27882**	**27882**	**28013**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**3203024**	**3139393**	**3308475**	**3414751**	**3203024**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1346960	1331957	1324383	1387918	1346960
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1856064	1807436	1984092	2026834	1856064
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**20489597**	**18849451**	**20183528**	**20278975**	**20489597**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31/ माह के लिए अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/ रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		मार्च 26	फर. 25	मार्च 11	मार्च 25
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	5302864	4799173	5138374	5114631	5302864
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	12076789	11053150	11848308	11877938	12076789
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	20630625	18940924	20326078	20429724	20630625
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3037491	2756705	2980565	3018879	3037491
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	17266162	15892847	17014022	17073643	17266162
1.2.1 मांग जमाराशियां	2212994	1995121	2103056	2044072	2212994
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	15053167	13897727	14910965	15029571	15053167
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6773925	6253977	6709934	6763307	6773925
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	176718	78702	128295	151931	176718
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	8279242	7643750	8201031	8266264	8279242
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	52379	47347	54752	51680	52379
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	274594	244025	276739	285522	274594
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	19802634	18402138	19568630	19744987	19802634
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	6204211	5732751	6232004	6339925	6204211
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1177178	982063	1267912	1294485	1177178
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	5027033	4750689	4964092	5045441	5027033
2.1.2 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को बैंक ऋण	13598423	12669387	13336626	13405062	13598423
2.1.2.1 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	35020	34946	26706	27014	35020
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13563403	12634441	13309920	13378048	13563403
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	952195	951313	952639	948251	952195
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	27882	26913	27882	27882	27882
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4814212	4420255	4763868	4796337	4814212
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4551499	4181453	4582959	4605987	4551499
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	262713	238802	180908	190350	262713
2.4 पूंजी खाता	3111573	2790207	3053964	3132979	3111573
2.5 अन्य मदें (निवल)	902530	1118174	980337	1006502	902530

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2021-22	2021	2022		
		अप्रै.	फर.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4	5
1 एन एम3	**20630625**	**19001607**	**20326078**	**20630625**	**20994980**
2 डाकघर जमाराशियां	510435	510435	510435	510435	510435
3 एल1 (1 + 2)	**21141060**	**19512042**	**20836513**	**21141060**	**21505415**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	49578	28937	44627	49578	41050
4.1 सावधि मुद्रा उधार	1824	3563	2082	1824	1758
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	39170	20275	34185	39170	39170
4.3 सावधि जमाराशियां	8584	5099	8360	8584	122
5 एल2 (3 + 4)	**21190639**	**19540979**	**20881140**	**21190639**	**21546464**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	66542	..	..	66542	..
7 एल3 (5 + 6)	**21257181**	..	..	**21257181**	..

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31/ माह के लिए अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/ रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		मार्च 26	फर. 25	मार्च 11	मार्च 25
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3135649	2858640	3080502	3115831	3135649
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	732270	584246	712237	717331	732270
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	683437	542693	664473	669083	683437
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	52379	47347	54752	51680	52379
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3920298	3490233	3847491	3884842	3920298
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	687746	613825	561032	638891	687746
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	1177178	982063	1267912	1294485	1177178
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1176550	980431	1267768	1288318	1176550
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1488978	1329707	1497537	1486766	1488978
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1488978	1329707	1497537	1486766	1488978
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	518	746	409	362	518
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	312946	350022	230177	198810	312946
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	628	1632	144	6167	628
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-524452	-403183	-733586	-682608	-524452
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-499524	-376761	-708733	-657680	-499524
2.1.3 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	35020	34946	26706	27014	35020
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	24927	26422	24853	24927	24927
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	26913	27882	27882	28013
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4551499	4181453	4582959	4605987	4551499
2.3.1 सोना	329562	253128	319800	335721	329562
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4221955	3928343	4263177	4270283	4221955
2.4 पूंजी खाता	1344369	1187995	1290045	1366888	1344369
2.5 अन्य मदें (निवल)	2592	143962	34338	21030	2592

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	मार्च 31/ माह के लिए अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/ शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2021	2022				
		फर. 26	फर. 25	मार्च 4	मार्च 11	मार्च 18	मार्च 25
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3920298	3490233	3847491	3907213	3884842	3938734	3920298
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3135649	2858640	3080502	3092827	3115831	3125325	3135649
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	732270	584246	712237	759525	717331	761301	732270
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	52379	47347	54752	54861	51680	52108	52379
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1177178	982063	1267912	1332489	1294485	1121968	1177178
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-499524	-376761	-708733	-728973	-657680	-435164	-499524
2.3 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	10092	8524	1853	1640	2086	4833	10092
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4551499	4181453	4582959	4649951	4605987	4543959	4551499
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	26913	27882	27882	27882	27882	28013
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1346960	1331957	1324383	1375776	1387918	1324744	1346960

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		मार्च 26	फर. 25	मार्च 11	मार्च 25
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	16331876	14960961	16083340	16141913	16331876
1.1.1 मांग जमाराशियां	2072747	1861193	1963976	1904694	2072747
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	14259129	13099768	14119364	14237219	14259129
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6416608	5894896	6353714	6406748	6416608
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	176718	78702	128295	151931	176718
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7842521	7204873	7765650	7830470	7842521
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	274594	244025	276739	285522	274594
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	17575016	16378019	17266721	17413901	17575016
2.1.1 सरकार को ऋण	4728179	4461632	4669023	4750085	4728179
2.1.2 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को ऋण	12846837	11916387	12597698	12663815	12846837
2.1.2.1 बैंक ऋण	11891314	10949509	11643717	11712341	11891314
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	11836304	10888255	11575493	11651434	11836304
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11522	23633	9095	11070	11522
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	769	894	1209	1116	769
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	943233	942351	943677	939289	943233
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	262713	238802	180908	190350	262713
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	465464	454866	384970	393190	465464
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	133437	152552	134189	134772	133437
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	69314	63512	69873	68068	69314
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1268887	1010202	1461464	1411947	1268887
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	683437	542693	664473	669083	683437
2.3.2 उपलब्ध नकदी	85926	90748	88258	85184	85926
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-499524	-376761	-708733	-657680	-499524
2.4 पूंजी खाता	1743033	1578041	1739748	1741920	1743033
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	757113	843995	809267	846843	757113
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	571534	593095	568393	578592	571534
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	26533	80681	28229	32994	26533

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	25 मार्च 2022 की स्थिति	2021	2022		
		मार्च 26	फर. 25	मार्च 11	मार्च 25
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4728948	4462526	4670231	4751201	4728948
2 वाणिज्यिकिक पत्र	55317	82584	49155	48966	55317
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	7642	9840	8384	7576	7642
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	73808	64035	73319	73791	73808
3.3 अन्य	5152	5210	5014	5009	5152
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	117860	121008	117941	118063	117860
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	326206	308904	336955	332398	326206
4.3 अन्य	148754	149325	142778	145028	148754
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	34404	31142	43286	36341	34404
5.2 वित्तीय संस्थाएं	174090	167130	166879	172116	174090

टिप्पणी: स्तंभ संख्या (2) और (3) के समक्ष डेटा अंतिम है और स्तंभ संख्या (1), (4) और (5) के लिए डेटा अनंतिम हैं।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2021-22	2021	2022		2021-22	2021	2022	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	212	209	212	212	136	133	136	136
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**262674**	**259530**	**255874**	**262674**	**258649**	**254589**	**251956**	**258649**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	194143	200585	185500	194143	190570	195866	182114	190570
1.2 बैंकों से उधार राशि	38369	40886	44491	38369	38317	40880	44343	38317
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	30162	18059	25883	30162	29762	17843	25499	29762
2 अन्य के प्रति देयताएं	**17832491**	**16457782**	**17569489**	**17832491**	**17380755**	**16014145**	**17132534**	**17380755**
2.1 कुल जमाराशियां	16899604	15540152	16638218	16899604	16465313	15113512	16217529	16465313
2.1.1 मांग	2117542	1899343	2006907	2117542	2072747	1861193	1963976	2072747
2.1.2 मीयादी	14782062	13640809	14631311	14782062	14392567	13252320	14253553	14392567
2.2 उधार	278985	248271	281772	278985	274594	244025	276739	274594
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	653902	669359	649500	653902	640848	656607	638266	640848
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**94299**	**90275**	**96123**	**94299**	**94299**	**90275**	**96123**	**94299**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	94299	90275	96123	94299	94299	90275	96123	94299
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	788723	650745	771413	788723	769363	633440	752731	769363
4.1 उपलब्ध नकदी	88731	92793	90640	88731	85926	90748	88258	85926
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	699993	557951	680772	699993	683437	542693	664473	683437
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**314857**	**265729**	**296277**	**314857**	**243637**	**197541**	**232823**	**243637**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	199109	179430	196853	199109	164240	143294	161886	164240
5.1.1 चालू खाते में	19408	16796	23926	19408	16691	14226	21250	16691
5.1.2 अन्य खातों में	179701	162634	172927	179701	147549	129068	140636	147549
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36805	36716	27515	36805	6982	10654	6053	6982
5.3 बैंकों को अग्रिम	39340	19908	36348	39340	35802	16764	32138	35802
5.4 अन्य आस्तियां	39602	29675	35561	39602	36613	26829	32746	36613
6 निवेश	**4874070**	**4598924**	**4810498**	**4874070**	**4728948**	**4462526**	**4670231**	**4728948**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4866337	4591896	4803361	4866337	4728179	4461632	4669023	4728179
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7732	7029	7136	7732	769	894	1209	769
7 बैंक ऋण	**12258948**	**11297014**	**12003700**	**12258948**	**11891314**	**10949509**	**11643717**	**11891314**
7क खाद्यान्न ऋण	90827	91653	104041	90827	55011	61254	68224	55011
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	12016385	11081668	11774926	12016385	11651337	10736491	11417404	11651337
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	36070	30896	34151	36070	36055	30531	34138	36055
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	155796	128831	146599	155796	154212	127883	145123	154212
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	19537	20762	19676	19537	19157	20394	19269	19157
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	31160	34857	28348	31160	30554	34210	27783	30554

टिप्पणी: स्तंभ संख्या (1), (4) और (5) लिए डेटा अनंतिम हैं।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	अप्रै. 26, 2021	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		मार्च 26	फर. 25	मार्च 25	2021-22	2022
	1	2	3	4	%	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	**10847288**	**10847288**	**11627008**	**11890638**	**9.6**	**9.6**
II. खाद्यान्न ऋण	**61254**	**61254**	**68224**	**55011**	**-10.2**	**-10.2**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**10786033**	**10786033**	**11558783**	**11835628**	**9.7**	**9.7**
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**1334022**	**1334022**	**1448928**	**1466514**	**9.9**	**9.9**
2. उद्योग	**2962332**	**2962332**	**3135271**	**3171909**	**7.1**	**7.1**
2.1 सूक्ष्म और लघु[1]	407675	407675	484465	495281	21.5	21.5
2.2 मझौले	141339	141339	235050	242269	71.4	71.4
2.3 बड़े	2413318	2413318	2415757	2434359	0.9	0.9
3. सेवाएं	**2788463**	**2788463**	**2966593**	**3036122**	**8.9**	**8.9**
3.1 परिवहन परिचालक	142898	142898	149178	155220	8.6	8.6
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	19671	19671	20134	20497	4.2	4.2
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	59519	59519	64607	64408	8.2	8.2
3.4 शिपिंग	7747	7747	7480	8603	11.1	11.1
3.5 नौवहन	26043	26043	23221	23292	-10.6	-10.6
3.6 पेशेवर सेवाएं	107236	107236	113204	115756	7.9	7.9
3.7 व्यापार	628246	628246	687305	697194	11.0	11.0
3.7.1 थोक व्यापार	318582	318582	336982	341795	7.3	7.3
3.7.2 खुदरा व्यापार	309663	309663	350322	355399	14.8	14.8
3.8 वाणिज्यिकिक स्थावर संपदा	289129	289129	288221	291580	0.8	0.8
3.9 गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	955311	955311	1027183	1054200	10.4	10.4
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	218619	218619	235080	239287	9.5	9.5
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	78987	78987	118244	119364	51.1	51.1
3.10 अन्य सेवाएं[3]	552665	552665	586058	605372	9.5	9.5
4 व्यक्तिगत ऋण	**3001645**	**3001645**	**3306650**	**3374876**	**12.4**	**12.4**
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	17265	17265	26587	27618	60.0	60.0
4.2 आवास	1493906	1493906	1578125	1589326	6.4	6.4
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	68731	68731	76579	79315	15.4	15.4
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	5236	5236	5968	6042	15.4	15.4
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	131193	131193	144004	147782	12.6	12.6
4.6 शिक्षा	62645	62645	63130	62622	0.0	0.0
4.7 वाहन ऋण	301445	301445	329636	329753	9.4	9.4
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	60907	60907	71408	73743	21.1	21.1
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	860316	860316	1011213	1058675	23.1	23.1
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र *(मेमो)*						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां[4]	1277989	1277989	1375748	1393313	9.0	9.0
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम[5]	1186591	1186591	1312435	1312705	10.6	10.6
5.3 मध्यम उद्यम[6]	222591	222591	298107	304724	36.9	36.9
5.4 आवास	491495	491495	487611	493562	0.4	0.4
5.5 शिक्षा ऋण	48053	48053	45643	45040	-6.3	-6.3
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1244	1244	2573	3726	199.6	199.6
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2666	2666	2480	2421	-9.2	-9.2
5.8 निर्यात ऋण[7]	31910	31910	29721	30638	-4.0	-4.0
5.9 अन्य	15795	15795	40603	37376	136.6	136.6
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	870584	870584	933147	912822	4.9	4.9

टिप्पणी : 1. डेटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर -खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डाटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण(एसआईबीसी) रिटर्न, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल खाद्येत्तर ऋण के लगभग 90 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं। टिप्पणी 3: चुनिंदा एससीबी द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए बैंक ऋण वृद्धि को समायोजित किया जाता है।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋणऔर पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	26 मार्च, 2021	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		मार्च 26	फर. 25	मार्च 25	2021-22	2022
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	2962332	2962332	3135271	3171909	7.1	7.1
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	43635	43635	49824	48972	12.2	12.2
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	156502	156502	169669	173530	10.9	10.9
2.2.1 चीनी	26263	26263	23848	26159	–0.4	–0.4
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18892	18892	18678	19360	2.5	2.5
2.2.3 चाय	5252	5252	5709	6189	17.8	17.8
2.2.4 अन्य	106095	106095	121434	121821	14.8	14.8
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	17708	17708	17948	18266	3.2	3.2
2.4 वस्त्र	204521	204521	225098	225096	10.1	10.1
2.4.1 सूती वस्त्र	89881	89881	96904	95271	6.0	6.0
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	2825	2825	3558	3710	31.3	31.3
2.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38877	38877	42153	43196	11.1	11.1
2.4.4 अन्य वस्त्र	72938	72938	82482	82920	13.7	13.7
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	10524	10524	11449	11491	9.2	9.2
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	13778	13778	15102	15037	9.1	9.1
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	35185	35185	39242	38505	9.4	9.4
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	67253	67253	83255	87615	30.3	30.3
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	196958	196958	200420	214141	8.7	8.7
2.9.1 उवर्रक	32584	32584	28907	33243	2.0	2.0
2.9.2 औषधि और दवाइयां	54136	54136	59181	61398	13.4	13.4
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	45765	45765	36667	40297	–11.9	–11.9
2.9.4 अन्य	64473	64473	75665	79202	22.8	22.8
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	56018	56018	70840	72088	28.7	28.7
2.11 कांच और कांच के सामान	6687	6687	5967	6071	–9.2	–9.2
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	55445	55445	48886	47925	–13.6	–13.6
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	326284	326284	295886	296427	–9.2	–9.2
2.13.1 लोहा और स्टील	228834	228834	195855	192658	–15.8	–15.8
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	97450	97450	100031	103769	6.5	6.5
2.14 सभी अभियांत्रिकी	149191	149191	161443	162205	8.7	8.7
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	34162	34162	38789	37763	10.5	10.5
2.14.2 अन्य	115030	115030	122654	124441	8.2	8.2
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	86053	86053	90744	91364	6.2	6.2
2.16 रत्न और आभूषण	73291	73291	77923	79747	8.8	8.8
2.17 निर्माण	100430	100430	104617	104700	4.3	4.3
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1100774	1100774	1194553	1202694	9.3	9.3
2.18.1 पावर	569015	569015	605572	609773	7.2	7.2
2.18.2 दूरसंचार	115861	115861	134285	137381	18.6	18.6
2.18.3 सड़क	231487	231487	264088	270806	17.0	17.0
2.18.4 हवाई अड्डा	8573	8573	6638	6646	–22.5	–22.5
2.18.5 बंदरगाह	10154	10154	8828	8886	–12.5	–12.5
2.18.6 रेलवे	12471	12471	13954	10512	–15.7	–15.7
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	153212	153212	161188	158691	3.6	3.6
2.19 अन्य उद्योग	262095	262095	272405	276036	5.3	5.3

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग की स्थिति								
	2020-21	2021				2022			
		फर. 26	दिसं. 03	दिसं. 17	दिसं. 31	जन. 14	जन. 28	फर. 11	फर. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	33	33	33	33	33	33	33
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**125859.6**	**124513.6**	**126775.8**	**126250.1**	**125717.1**	**127755.5**	**127431.3**	**126324.0**	**126531.5**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**23736.9**	**21473.4**	**24362.4**	**24175.7**	**25194.1**	**24360.8**	**24041.4**	**26573.3**	**24733.8**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	3526.9	5644.8	5476.8	4992.8	5599.7	5534.4	5468.9	5237.4
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	13379.6	13711.9	13239.2	13529.3	13388.7	13490.3	13829.4	13918.4
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	353.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	294.9	499.9
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	4214.0	5005.7	5459.6	6642.1	5372.5	5016.7	6980.0	5078.1
2.2 मीयादी देयताएं	**179957.5**	**173903.3**	**174844.3**	**176049.4**	**175645.6**	**177700.6**	**178141.3**	**176359.3**	**177613.0**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	59862.2	58648.8	59937.1	60369.4	60244.0	61099.8	60724.4	61880.2
2.2.1.2 अन्य	111960.2	111134.0	113063.8	113010.9	112187.8	114366.9	113941.1	112494.5	112613.1
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	629.9	910.1	900.5	879.7	877.6	876.9	876.8	859.4
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	2277.1	2221.5	2200.8	2208.6	2212.1	2223.6	2263.6	2260.3
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	60792.5	62643.7	62867.4	65323.6	64801.9	64328.2	65375.2	64466.5
4.1 मांग	15691.8	14579.3	12696.3	13148.7	12617.5	12576.2	12684.0	13311.1	12992.3
4.2 मीयादी	47868.0	46213.1	49947.4	49718.6	52706.1	52225.7	51644.2	52064.0	51474.2
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**8151.1**	**6871.4**	**9590.4**	**9918.8**	**9710.1**	**9513.9**	**9868.9**	**9040.8**	**9228.6**
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	572.5	636.1	673.2	706.3	681.3	705.8	691.6	743.8
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	6298.9	8954.3	9245.6	9003.8	8832.7	9163.0	8349.1	8484.8
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**1148.1**	**834.6**	**1245.1**	**1141.8**	**1419.1**	**1186.3**	**1275.4**	**1284.4**	**1310.3**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**64455.2**	**61913.1**	**73860.5**	**72595.8**	**71870.3**	**72279.7**	**71991.8**	**71964.6**	**71262.5**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**28835.7**	**26344.9**	**21465.8**	**23039.9**	**24601.8**	**24189.3**	**25584.6**	**24200.2**	**24875.8**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**114631.6**	**114409.0**	**108518.7**	**109958.7**	**109318.7**	**110344.5**	**110029.1**	**112313.6**	**111718.8**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**114612.1**	**114389.5**	**108497.9**	**109938.2**	**109298.1**	**110323.9**	**110008.5**	**112293.0**	**111698.2**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	91887.8	99615.8	100260.1	103321.6	102808.2	103697.0	104523.9	106973.7
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	19.5	20.9	20.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)

समूह/उप समूह	2021-22			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	मार्च '21	फर.'22	मार्च'22(अ)	मार्च'21	फर.'22	मार्च'22(अ)	मार्च'21	फर.'22	मार्च'22(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**162.8**	**168.7**	**165.0**	**154.5**	**163.9**	**166.6**	**160.4**	**170.2**	**171.5**	**156.7**	**166.2**	**168.4**
1.1 अनाज और उत्पाद	146.4	150.4	147.6	142.5	148.8	150.1	147.5	152.5	153.7	144.1	150.0	151.2
1.2 मांस और मछली	200.4	206.5	202.6	189.4	198.1	208.0	197.5	205.2	215.8	192.2	200.6	210.7
1.3 अंडा	173.3	176.0	174.4	163.2	175.5	168.0	164.7	176.4	167.6	163.8	175.8	167.8
1.4 दूध और उत्पाद	158.3	159.0	158.6	154.5	160.7	162.0	155.6	160.6	162.6	154.9	160.7	162.2
1.5 तेल और चर्बी	192.2	172.4	184.9	168.2	192.6	203.1	156.4	171.5	180.1	163.9	184.9	194.7
1.6 फल	155.3	163.5	159.2	150.5	151.4	155.9	157.3	156.4	159.6	153.7	153.7	157.6
1.7 सब्जी	156.1	192.8	168.5	141.0	155.2	155.9	166.1	198.0	188.3	149.5	169.7	166.9
1.8 दाल और उत्पाद	164.1	164.4	164.2	159.2	163.9	164.2	161.1	163.2	163.4	159.8	163.7	163.9
1.9 चीनी और उत्पाद	117.4	119.1	118.0	111.7	118.1	118.1	114.3	120.6	120.3	112.6	118.9	118.8
1.10 मसाले	171.2	167.5	170.0	164.0	175.4	178.7	162.6	172.2	174.7	163.5	174.3	177.4
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	167.8	154.7	162.3	160.6	170.5	171.2	150.7	156.7	157.1	156.5	164.7	165.3
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	173.0	175.8	174.3	166.4	176.3	177.4	170.3	180.0	181.5	168.2	178.0	179.3
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**190.3**	**196.5**	**191.9**	**186.1**	**191.5**	**192.3**	**193.5**	**196.5**	**197.6**	**188.1**	**192.8**	**193.7**
3 कपड़ा और जूते	**168.2**	**158.4**	**164.3**	**158.9**	**173.7**	**175.1**	**152.6**	**163.4**	**164.9**	**156.4**	**169.6**	**171.1**
3.1 कपड़ा	168.8	160.9	165.7	159.6	174.1	175.4	155.1	165.7	167.1	157.8	170.8	172.1
3.2 जूते	164.5	144.7	156.3	154.4	171.0	173.2	138.7	150.4	152.5	147.9	162.4	164.6
4 आवास	**--**	**163.0**	**163.0**	**--**	**--**	**--**	**159.9**	**165.5**	**165.3**	**159.9**	**165.5**	**165.3**
5 ईंधन और लाइट	**164.0**	**159.8**	**162.4**	**156.0**	**167.4**	**168.9**	**154.8**	**163.0**	**164.5**	**155.5**	**165.7**	**167.2**
6 विविध	**164.1**	**156.1**	**160.2**	**157.3**	**167.3**	**168.3**	**150.0**	**159.4**	**160.6**	**153.8**	**163.5**	**164.6**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	161.8	153.5	157.9	154.8	165.7	166.5	147.2	157.4	158.6	151.2	161.8	162.8
6.2 स्वास्थ्य	172.0	163.3	168.6	164.6	175.3	176.0	156.9	167.2	168.2	161.7	172.2	173.0
6.3 परिवहन और संचार	157.9	150.0	153.7	151.3	161.2	162.0	141.7	153.1	154.2	146.2	156.9	157.9
6.4 मनोरंजन	162.7	154.8	158.2	157.8	165.5	166.6	148.6	159.5	160.8	152.6	162.1	163.3
6.5 शिक्षा	168.4	160.1	163.5	163.8	170.3	170.6	157.6	162.0	162.6	160.2	165.4	165.9
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	161.3	160.8	161.1	153.1	164.5	167.4	154.9	164.2	166.8	153.8	164.4	167.2
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**164.5**	**163.1**	**163.8**	**156.7**	**166.7**	**168.7**	**156.9**	**165.5**	**166.5**	**156.8**	**166.1**	**167.7**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2021-22	2021	2022	
				मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	-	119.6	125	126
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1075	1035	1095	1098
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	1084	1043	1106	1109

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2020-21	2021	2022	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	48723	44648	49254	51750
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	59283	65981	63175	68286

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भारांक	2020-21	2020	2021		
			मार्च	जन.	फर. (अ)	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य वस्तुएँ	**100.000**	**139.4**	**129.9**	**143.8**	**144.9**	**148.8**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**160.5**	**147.4**	**167.5**	**166.8**	**170.3**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**167.3**	**156.4**	**172.0**	**170.4**	**169.0**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	163.5	158.1	165.5	165.9	169.1
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	187.5	154.6	201.8	192.1	178.5
1.1.1.3 दूध	4.440	156.7	155.2	157.4	157.8	159.7
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	164.0	155.0	165.6	167.3	169.6
1.1.1.5 मसाले	0.529	159.8	151.9	168.5	170.2	172.9
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	168.2	168.4	172.6	173.5	173.0
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**158.1**	**139.7**	**165.9**	**170.2**	**175.2**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	158.5	133.2	177.4	190.3	201.1
1.1.2.2 तिलहन	1.115	214.4	185.0	210.8	215.4	226.6
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	119.9	115.2	122.3	123.3	126.7
1.1.2.4 फूल	0.204	217.0	154.2	292.2	290.2	253.9
1.1.3 खनिज	**0.833**	**195.2**	**188.1**	**224.7**	**204.8**	**224.7**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	190.8	187.9	226.6	200.9	226.6
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	210.4	189.0	218.0	218.6	218.3
1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	**2.410**	**110.3**	**89.6**	**122.3**	**125.1**	**151.6**
1.2 ईंधन और विद्युत	**13.152**	**124.9**	**109.2**	**135.3**	**139.0**	**146.9**
1.2.1 कोल	**2.138**	**129.0**	**126.9**	**130.9**	**130.9**	**130.9**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	143.0	141.9	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.8	119.8	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	170.5	129.9	212.6	212.6	212.6
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**126.2**	**103.7**	**136.5**	**142.6**	**155.7**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**118.8**	**111.1**	**135.3**	**135.3**	**135.3**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**134.9**	**127.9**	**137.2**	**138.4**	**141.6**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**157.8**	**149.8**	**156.9**	**159.8**	**164.6**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	142.7	141.3	142.3	140.9	142.1
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	144.2	145.1	146.3	149.1	142.8
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	122.3	121.7	122.5	123.1	122.1
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	186.9	172.5	180.8	188.9	200.2
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	149.3	148.0	149.3	151.2	155.0
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	145.5	141.5	147.1	147.1	149.9
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	133.2	120.1	142.0	146.2	151.0
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	146.2	139.3	150.8	150.8	152.5
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	122.9	116.8	124.7	124.8	124.6
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	130.3	128.0	132.8	132.9	133.6
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	135.6	135.6	142.3	139.7	142.8
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	170.8	163.8	168.1	165.5	166.6
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	157.4	149.0	163.8	163.7	165.0
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	136.9	136.6	137.1	137.4	138.7
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	153.1	138.2	152.5	161.6	165.2
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	200.9	179.5	199.7	203.8	210.1
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**126.9**	**125.0**	**127.3**	**128.4**	**127.6**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	123.6	120.4	124.1	124.9	125.4
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	130.4	127.8	131.8	132.9	132.6
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	129.1	129.6	128.4	130.1	126.9
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**160.2**	**157.8**	**160.7**	**160.7**	**161.3**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	160.2	157.8	160.7	160.7	161.3

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भारांक	2020-21	2020	2021		
			मार्च	जन.	फर. (अ)	मार्च (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**135.2**	**127.4**	**140.2**	**142.4**	**143.5**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	128.1	120.0	135.2	138.1	138.3
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	146.8	138.5	149.7	151.6	154.1
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	125.5	119.0	130.3	130.1	127.7
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	138.6	133.6	141.7	142.0	146.6
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	168.5	167.4	167.6	166.1	162.9
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	126.2	117.9	128.8	130.3	132.3
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**143.1**	**140.0**	**144.7**	**145.2**	**145.2**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	142.1	139.2	143.3	144.0	143.7
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	145.9	142.4	148.3	148.4	149.0
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**119.3**	**117.6**	**120.9**	**121.3**	**121.7**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	103.7	96.6	105.6	107.4	108.2
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	141.5	140.2	143.7	144.4	144.5
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	121.0	121.7	122.4	122.1	122.3
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**141.0**	**137.7**	**141.9**	**142.4**	**144.1**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	128.9	123.5	132.1	131.1	135.5
1.3.7.2 विनियर शीट,प्लायवुड का विनिर्माण,लॅमिन बोर्ड,पार्टिकल बोर्डऔर अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	141.9	139.2	142.6	143.1	144.5
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	193.9	191.3	194.6	195.2	195.2
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	133.9	130.0	133.2	135.8	136.1
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**137.3**	**130.7**	**142.1**	**142.4**	**146.7**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	141.2	135.9	145.1	146.1	149.6
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	137.5	131.0	141.1	141.2	144.9
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	130.8	121.8	138.5	137.5	144.0
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**158.0**	**153.7**	**162.6**	**162.4**	**163.1**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	158.0	153.7	162.6	162.4	163.1
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**133.4**	**125.6**	**137.5**	**139.3**	**141.5**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	143.7	130.3	150.9	152.6	156.4
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	129.6	124.7	133.4	134.4	134.4
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	140.2	136.2	140.8	143.2	149.6
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	131.9	125.4	136.2	138.5	141.0
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	130.4	118.7	137.8	137.6	138.6
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट,सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	128.1	122.8	126.9	132.1	129.6
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	130.2	120.0	136.3	137.0	139.7
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	106.4	102.8	109.0	109.9	112.9
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**135.8**	**133.4**	**137.1**	**138.2**	**136.3**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	135.8	133.4	137.1	138.2	136.3
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**124.8**	**119.5**	**127.3**	**127.1**	**129.8**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब,रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	104.3	100.1	106.5	106.3	106.1
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	101.9	97.4	104.4	105.0	106.4
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	137.9	132.1	140.7	140.3	144.4
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**123.6**	**120.2**	**125.8**	**126.3**	**127.3**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	138.9	130.4	144.7	142.6	145.6
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	115.6	113.5	119.1	120.0	119.4
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	119.4	112.2	131.3	134.1	132.7
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.9	112.0	116.3	116.1	116.6
1.3.13.5 सीमेन्ट,चूना और प्लास्टर	1.645	126.3	123.6	127.0	127.9	129.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*
(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भारांक	2020-21	2020	2021		
			मार्च	जन.	फर. (अ)	मार्च (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	129.2	126.4	129.8	130.8	131.4
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	122.2	123.5	121.5	121.5	120.9
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	90.4	79.6	99.0	97.9	100.2
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**139.8**	**124.0**	**143.1**	**145.1**	**156.2**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	150.3	125.5	153.9	157.0	177.1
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	147.4	129.1	149.2	150.6	172.0
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	118.6	110.3	120.6	121.4	127.9
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	137.1	124.6	139.9	143.6	153.1
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	157.3	133.5	157.1	158.2	169.8
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	133.5	123.5	136.6	142.5	150.2
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	141.7	125.7	145.5	147.5	169.8
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	155.8	141.4	163.8	165.9	171.0
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	139.6	123.8	145.6	148.5	154.9
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	118.7	112.8	121.6	121.7	122.6
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	159.0	148.3	165.1	165.8	165.0
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**130.3**	**121.8**	**133.2**	**133.0**	**134.4**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	123.8	119.0	124.6	124.3	127.5
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	155.9	140.8	160.0	159.8	159.5
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	96.1	96.8	92.3	93.8	96.4
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	117.4	99.5	125.2	125.1	126.2
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.2	106.5	109.5	109.4	108.5
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	136.4	129.7	140.3	139.8	140.8
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**113.5**	**111.0**	**115.6**	**114.7**	**116.5**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	105.8	101.2	110.5	109.0	111.5
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.7	134.5	134.8	134.7	134.8
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	121.1	116.4	128.6	121.3	128.8
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	102.2	100.9	101.4	103.2	102.2
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	108.2	106.1	109.2	109.5	112.2
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	145.5	141.7	147.6	147.2	150.5
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	106.0	102.4	106.2	106.3	107.6
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	98.3	95.9	99.6	99.6	99.7
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**122.3**	**118.9**	**124.8**	**124.8**	**125.2**
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स,जनरेटर,ट्रांसफार्मरऔरबिजलीवितरणऔरनियंत्रणसंबंधीउपकरण	1.298	119.6	119.1	121.6	121.5	121.4
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	121.7	116.4	125.6	125.0	126.2
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	102.9	100.5	106.0	106.1	107.2
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	140.5	129.4	144.7	145.6	148.1
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	114.5	111.8	115.3	115.3	115.3
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	128.4	123.8	131.3	131.2	131.3
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	113.3	110.9	115.6	115.3	113.4
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**120.0**	**116.1**	**121.6**	**122.0**	**122.3**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन,एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	119.2	110.7	119.4	121.7	122.7
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	121.9	120.4	123.7	123.1	124.9
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	115.1	113.6	115.9	115.1	115.5
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	118.2	112.7	120.6	120.9	119.6
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	74.2	70.9	74.8	76.0	76.5
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने –उतारने वाले उपकरण	0.285	119.9	115.6	123.0	122.7	124.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(समाप्त)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भारांक	2020-21	2020	2021		
			मार्च	जन.	फर. (अ)	मार्च (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	133.4	131.5	133.5	135.1	134.0
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	128.4	122.7	131.9	132.0	132.8
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	114.0	108.7	114.6	115.4	116.5
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	78.1	76.6	79.4	79.2	79.7
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	130.1	131.2	130.7	131.1	130.5
1.3.18.13 कपड़ा,परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	125.3	120.2	128.0	128.1	126.6
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	134.8	132.6	136.4	136.2	137.4
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.6	66.4	66.9	67.2	67.3
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**122.7**	**120.1**	**125.3**	**125.8**	**126.3**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	122.7	122.0	125.7	125.9	126.4
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	122.7	118.0	124.8	125.6	126.1
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**131.7**	**128.7**	**133.4**	**133.9**	**133.8**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली –वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.9	158.9	158.9	158.9	159.0
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	104.3	104.0	105.3	103.3	103.7
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	131.0	127.5	133.1	133.8	133.6
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	137.1	134.8	138.2	138.2	138.3
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	135.9	132.6	138.6	139.3	142.0
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**150.1**	**143.2**	**153.3**	**154.9**	**157.2**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	150.1	143.2	153.3	154.9	157.2
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**137.7**	**134.2**	**138.3**	**139.2**	**146.6**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	135.9	132.4	136.5	137.6	145.0
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	192.3	192.3	195.0	185.1	180.7
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	140.4	134.2	143.8	144.3	145.9
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	150.6	146.7	152.7	148.7	154.8
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	171.8	168.8	170.8	169.6	177.8
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**163.7**	**153.9**	**166.3**	**166.4**	**167.3**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2019-20	2020-21	अप्रैल- फरवरी		फरवरी	
				2020-21	2021-22	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	129.0	118.1	115.6	130.0	129.9	132.1
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	109.6	101.0	97.5	110.4	117.9	123.2
1.2 विनिर्माण	77.63	129.6	117.2	114.8	129.6	129.7	130.8
1.3 बिजली	7.99	158.4	157.6	155.5	168.2	153.9	160.8
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	127.0	118.1	115.7	127.3	125.0	130.8
2.2 पूंजीगत माल	8.22	93.3	75.9	72.8	86.5	93.3	94.3
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	137.7	124.7	122.0	142.5	138.0	144.0
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	136.6	124.7	121.6	146.4	139.9	153.0
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.0	101.2	98.4	112.6	125.0	114.7
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.3	142.1	140.8	146.4	147.6	139.5

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23ः केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - फरवरी			
	2021-22 (बजट आकलन)	2021-22 (वास्तविक)	2020-21 (वास्तविक)	बजट आकलनों का प्रतिशत	
				2021-22	2020-21
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**2078936**	**1791017**	**1370272**	**86.2**	**88.1**
1.1 कर राजस्व (निवल)	1765145	1480886	1216086	83.9	90.4
1.2 करेतर राजस्व	313791	310131	154186	98.8	73.2
2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	**99975**	**36263**	**42824**	**36.3**	**92.1**
2.1 ऋण की वसूली	21975	22749	17156	103.5	118.3
2.2 अन्य प्राप्तियां	78000	13514	25668	17.3	80.2
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	**2178911**	**1827280**	**1413096**	**83.9**	**88.2**
4 राजस्व व्यय	3167289	2658694	2413375	83.9	80.1
4.1 ब्याज भुगतान	813791	670501	559483	82.4	80.7
5 पूंजी व्यय	602711	485181	405268	80.5	92.3
6 कुल व्यय (4+5)	**3770000**	**3143875**	**2818643**	**83.4**	**81.7**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**1088352**	**867677**	**1043103**	**79.7**	**71.6**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1591089**	**1316595**	**1405547**	**82.7**	**76.0**
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	**777298**	**646094**	**846064**	**83.1**	**73.2**

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2022-23।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	2021	2022					
		मार्च 26	फर. 18	फर. 25	मार्च 4	मार्च 11	मार्च 18	मार्च 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5310	5676	5396	4923	5158	5406	5485	5310
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16705	16740	15444	15781	15686	18645	18421	16705
1.3 राज्य सरकारें	31320	13347	76538	58638	53546	50731	41556	31320
1.4 अन्य	72109	52802	85652	80823	77882	75686	73307	72109
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	70130	67473	58097	58219	62566	66864	64912	70130
2.2 प्राथमिक व्यापारी	63669	30966	46019	49488	52764	54561	59703	63669
2.3 राज्य सरकारें	15763	9436	4826	8826	9826	10826	13326	15763
2.4 अन्य	69259	31800	46142	49752	53438	58348	66235	69259
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	112386	119024	115928	116951	119467	116330	117765	112386
3.2 प्राथमिक व्यापारी	160461	154197	121756	125294	127426	139278	138202	160461
3.3 राज्य सरकारें	22836	18510	23056	20551	22851	22851	22846	22836
3.4 अन्य	118392	174501	118826	117697	122944	121722	128739	118392
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	289362	220351	210094	367557	315325	276150	282842	289362
4.4 अन्य	659	747	813	976	1223	495	1352	659
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	758339	694471	717682	706943	723556	741248	750498	758339

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2021-22										
मार्च 2	7000	82	20988	4508	37	6994	4508	11502	99.08	3.7448
मार्च 9	7000	105	35863	4013	27	6987	4013	11000	99.06	3.8061
मार्च 16	7000	98	19007	2507	42	6993	2507	9500	99.07	3.7689
मार्च 23	7000	88	22625	3552	51	6948	3552	10500	99.06	3.7992
मार्च 30	7000	56	15499	21507	35	6996	21507	28504	99.05	3.8400
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2021-22										
मार्च 2	15000	143	37315	1000	75	15000	1000	16000	97.91	4.2889
मार्च 9	15000	169	40023	1001	78	14999	1001	16000	97.86	4.3800
मार्च 16	15000	244	60173	3001	44	14999	3001	18000	97.88	4.3345
मार्च 23	15000	205	47637	2448	62	14990	2448	17438	97.89	4.3199
मार्च 30	15000	181	49020	1001	47	14999	1001	16000	97.92	4.2669
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2021-22										
मार्च 2	16000	162	44760	2300	80	16000	2300	18300	95.59	4.6299
मार्च 9	15000	188	47615	0	34	15000	0	15000	95.52	4.7085
मार्च 16	15000	236	58748	0	43	15000	0	15000	95.57	4.6481
मार्च 23	15000	198	53266	0	12	15000	0	15000	95.60	4.6189
मार्च 30	15000	157	49888	1	47	14999	1	15000	95.63	4.5805

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
मार्च	2, 2022	2.20-3.45	3.27
मार्च	3, 2022	2.20-3.55	3.28
मार्च	4, 2022	2.00-3.50	3.28
मार्च	5, 2022	2.40-3.50	3.22
मार्च	7, 2022	2.00-3.65	3.29
मार्च	8, 2022	2.00-3.65	3.28
मार्च	9, 2022	2.00-3.65	3.32
मार्च	10, 2022	2.00-4.00	3.45
मार्च	11, 2022	2.00-3.50	3.29
मार्च	14, 2022	2.20-3.45	3.24
मार्च	15, 2022	2.20-3.45	3.25
मार्च	16, 2022	2.00-3.55	3.24
मार्च	17, 2022	2.25-3.75	3.39
मार्च	19, 2022	2.70-3.65	2.93
मार्च	21, 2022	2.00-3.60	3.33
मार्च	22, 2022	2.00-3.85	3.36
मार्च	23, 2022	2.00-3.70	3.29
मार्च	24, 2022	2.00-3.80	3.41
मार्च	25, 2022	2.20-3.65	3.30
मार्च	28, 2022	2.00-3.50	3.29
मार्च	29, 2022	2.20-3.60	3.31
मार्च	30, 2022	2.20-4.25	3.29
मार्च	31, 2022	2.20-4.10	3.56
अप्रै.	4, 2022	2.20-3.40	3.24
अप्रै.	5, 2022	2.20-3.55	3.26
अप्रै.	6, 2022	2.20-3.60	3.26
अप्रै.	7, 2022	2.20-3.55	3.27
अप्रै.	8, 2022	2.20-3.80	3.33
अप्रै.	11, 2022	2.20-3.80	3.44
अप्रै.	12, 2022	2.20-3.80	3.44
अप्रै.	13, 2022	2.20-3.90	3.52

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2021	2022			
	मार्च 26	फर. 11	फर. 25	मार्च 11	मार्च 25
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	80621.98	112564.73	127618.40	154363.89	181171.43
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	25590.02	17451.50	19096.55	33526.78	34878.78
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.28-5.12	4.01-5.44	3.86-5.62	3.77-5.44	3.82-5.49

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2021	2022			
	मार्च 31	फर. 15	फर. 28	मार्च 15	मार्च 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	364374.30	389950.70	364645.30	368090.45	352292.55
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	96417.25	64232.70	44435.25	44531.60	71015.75
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.32-13.37	3.67-12.29	3.64-11.51	3.84-12.15	3.79-12.17

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2021	2022					
		मार्च 26	फर. 18	फर. 25	मार्च 4	मार्च 11	मार्च 18	मार्च 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17461	25647	15742	16146	12428	13861	11830	17736
2 नोटिस मुद्रा	2604	575	643	383	4203	415	4911	1305
3 मीयादी मुद्रा	757	504	535	334	462	232	770	822
4 त्रिपक्षीय रिपो	421118	462956	845803	823707	772807	627893	705350	611595
5 बाजार रिपो	337341	358990	450982	492832	511933	465864	484255	427776
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2990	9399	112	358	265	418	274	191
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	90158	75825	87562	91065	93434	82757	96538
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	62490	55985	53123	39524	48664	43354	36039	41031
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5080	7252	6462	3982	7432	8111	5251	5734
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4970	5756	4253	2800	4175	3328	4913	4558
10.2 182-दिवसीय	4870	2971	2504	3479	4633	5523	4514	7723
10.3 364-दिवसीय	4010	11791	6098	1353	3766	3824	2513	5035
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1490							
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	82910	83755	72441	51137	68669	64140	53231	64080
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	4872	1038	615	1241	478	722	907

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2020-21		2020-21 (अप्रै-मार्च)		2021-22 (अप्रै-मार्च)*		मार्च 2021		मार्च 2022*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**74**	**102062**	**74**	**102062**	**164**	**138894**	**19**	**6454**	**16**	**1054**
1ए प्रीमियम	73	97648	73	97648	154	136893	18	6216	15	983
1.1 पब्लिक	53	38004	53	38004	121	112567	16	6382	10	175
1.1.1 प्रीमियम	53	34848	53	34848	119	111314	16	6163	10	142
1.2 राइट्स	21	64059	21	64059	43	26327	3	72	6	879
1.2.1 प्रीमियम	20	62800	20	62800	35	25580	2	53	5	841
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	**16**	**5806**	**16**	**5806**	**28**	**11589**	**2**	**900**	**1**	**178**
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	16	5806	16	5806	28	11589	2	900	1	178
3.1.1 पब्लिक	16	5806	16	5806	28	11589	2	900	1	178
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	**90**	**107868**	**90**	**107868**	**192**	**150484**	**21**	**7353**	**17**	**1231**
4.1 पब्लिक	69	43809	69	43809	149	124157	18	7281	11	353
4.2 राइट्स	21	64059	21	64059	43	26327	3	72	6	879

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।
2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकडे कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2021-22	2021			2022		
			मार्च	नवं.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	3129096	256643	236855	295992	262109	278563	321935
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	419654	35257	31794	39271	35210	37140	42224
1.1 तेल	करोड ₹	488381	29274	40936	50912	34022	51736	59281
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	65443	3609	5495	6755	4570	6898	7775
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	2640715	227369	195919	245080	228087	226827	262654
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	354211	31647	26299	32516	30640	30242	34449
2 आयात	करोड ₹	4563804	355949	397941	454508	388980	427704	463100
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	611894	48899	53417	60302	52253	57025	60739
2.1 तेल	करोड ₹	1201934	74768	109361	124323	91968	126186	143292
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	161070	10271	14680	16494	12354	16824	18794
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	3361870	281180	288580	330185	297012	301518	319809
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	450824	38627	38737	43807	39899	40201	41945
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1434708	-99306	-161086	-158516	-126871	-149141	-141165
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-192241	-13642	-21623	-21031	-17043	-19885	-18515
3.1 तेल	करोड ₹	-713553	-45495	-68425	-73410	-57946	-74449	-84010
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-95627	-6662	-9185	-9740	-7784	-9926	-11019
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-721155	-53811	-92661	-85106	-68925	-74691	-57155
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-96614	-6980	-12438	-11291	-9259	-9958	-7496

स्रोत: वाणिज्यिकिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2021	2022					
		अप्रै. 30	मार्च 25	अप्रै. 1	अप्रै. 8	अप्रै. 15	अप्रै. 22	अप्रै. 29
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	**करोड ₹**	**4355951**	**4707396**	**4592504**	**4583925**	**4598531**	**4592398**	**4568295**
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	**588020**	**617648**	**606475**	**604004**	**603694**	**600423**	**597728**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	4045137	4195294	4087017	4080361	4088715	4083917	4072243
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	546059	550454	539727	537645	536768	533933	532823
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	262709	329562	323596	322692	328649	327120	317972
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	35464	43241	42734	42519	43145	42768	41604
	मात्रा (मैट्रिक टन)	695.31	760.42	760.42	760.42	760.42	760.42	761.35
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1049	13657	13657	13657	13657	13657	13657
	करोड ₹	11168	143446	142960	142212	142400	142737	139857
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	1508	18821	18879	18738	18694	18662	18299
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	36936	39094	38931	38659	38767	38623	38222
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	4990	5132	5136	5101	5086	5060	5001

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2021-22	2021	2022		2020-21	2021-22
		मार्च	फर.	मार्च	अप्रै.-मार्च	अप्रै.-मार्च
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**139,020**	**141,895**	**139,572**	**139,020**	**7,364**	**3,232**
1.1 एफसीएनआर (बी)	16,918	20,473	17,293	16,918	–3,771	–3,555
1.2 एनआर (ई) आरए	100,801	102,579	101,116	100,801	8,845	3,332
1.3 एनआरओ	21,301	18,842	21,163	21,301	2,290	3,454

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2020-21	2021-22	2021	2022	
		अप्रै.-मार्च	अप्रै.-मार्च	मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**39,290**	**43,955**	**39,290**	**755**	**4,224**	**2,742**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**54,971**	**54,927**	**54,971**	**2,067**	**4,884**	**4,298**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**83,572**	**81,973**	**83,572**	**4,709**	**6,448**	**6,676**
1.1.1.1.1 इक्विटी	59,826	61,088	59,826	3,001	4,747	4,723
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	1,698	948	1,698	6	18	60
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	42,932	51,597	42,932	2,252	3,366	4,226
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	14,143	7,091	14,143	613	1,234	307
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	1,052	1,452	1,052	129	129	129
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	18,647	16,935	18,647	1,506	1,506	1,506
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5,100	3,950	5,100	202	195	446
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**28,602**	**27,046**	**28,602**	**2,643**	**1,564**	**2,378**
1.1.1.2.1 इक्विटी	27,184	26,983	27,184	2,631	1,480	2,106
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	1,417	63	1,417	11	84	272
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**15,680**	**10,972**	**15,680**	**1,311**	**660**	**1,556**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	8,788	5,583	8,788	570	216	993
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	2,744	3,013	2,744	251	251	251
1.1.2.3 अन्य पूंजी	7,539	6,688	7,539	1,061	334	1,128
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3,391	4,313	3,391	571	141	816
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**–17,225**	**36,137**	**–17,225**	**–792**	**–5,492**	**–5,251**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	–	–	–	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	–14,541	38,725	–14,541	–489	–5,372	–5,201
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2,683	2,589	2,683	303	121	50
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**22,066**	**80,092**	**22,066**	**–36**	**–1,268**	**–2,509**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021	2022		
		मार्च	जन.	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**19610.77**	**1547.80**	**2018.31**	**1823.35**	**1968.77**
1.1 जमाराशियां	830.05	151.49	66.27	54.20	182.61
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	112.90	11.07	8.58	8.07	16.35
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	746.57	89.54	73.53	60.39	104.51
1.4 उपहार	2336.29	224.75	200.23	201.36	276.19
1.5 दान	16.55	0.65	1.53	3.28	0.65
1.6 यात्रा	6909.04	335.95	989.05	980.45	776.64
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3302.37	330.04	315.61	282.61	391.02
1.8 चिकित्सा उपचार	37.79	2.98	3.77	3.69	4.21
1.9 विदेश में शिक्षा	5165.33	390.55	345.76	216.07	202.25
1.10 अन्य	153.88	10.77	13.98	13.23	14.33

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2020-21	2021-22	2021	2022	
			अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	93.92	93.13	92.26	92.74	93.31
1.2 रीर	103.46	104.66	100.90	103.39	103.64
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.59	93.55	92.40	93.72	94.48
2.2 रीर	102.96	103.48	99.84	102.30	102.62
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	88.45	87.03	86.56	86.42	87.59
1.2 रीर	101.84	102.27	99.72	100.92	103.58
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.00	98.39	97.86	97.70	99.03
2.2 रीर	100.00	100.42	97.92	99.10	101.71

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

मद	2020-21	2021	2022	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1063	106	71	115
1.2 राशि	26799	3883	805	3938
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	13	5	2	2
2.2 राशि	8456	5350	1523	1104
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1076	111	73	117
3.2 राशि	35255	9233	2328	5042
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.03	7.35	6.30	5.90
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.93	2.19	1.40	1.23
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-13.00	0.00-10.69	0.00-12.00	0.00-11.50
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12827	710	491	680
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	9985	3952	1324	2987
ए) परिवहन	636	27	1308	36
बी) ऊर्जा	2713	1425	7	1150
सी) पानी और सफ़ाई व्यवस्था	151	0	0	0
डी) संचार	757	750	0	750
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	161	0	0	0
एफ)अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	2946	1750	0	1051
जी) अन्य उप -क्षेत्र	2622	0	9	0
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1894	333	129	53
IV. अन्य संस्थाएं	1026	0	0	9
ए) एसई जेड़ में इकाई	26	0	0	9
बी) सिडबी	0			
सी) एक्जिम बैंक	1000	0	0	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबी एफ सी के अलावा)	2110	2110	0	0
VII. एनबीएफसी	6934	1809	372	1216
ए) एनबीएफसी -आई एफ सी/ए एफ सी	6024	1750	273	1118
बी) एनबी एफ सी -एमएफआई	84	9	0	27
सी) एनबीफसी - अन्य	827	50	99	71
VIII. गैर -सरकारी संगठन	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था	8	0	0	0
X. अन्य	470	319	12	97

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	अक्टू.-दिसं. 2020			अक्टू.-दिसं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**328716**	**296233**	**32483**	**427028**	**426562**	**465**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**156966**	**159200**	**-2235**	**205430**	**228454**	**-23024**
1.1 पण्य	**77218**	**111820**	**-34602**	**108970**	**169395**	**-60425**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**79748**	**47380**	**32367**	**96461**	**59059**	**37402**
1.2.1 सेवाएं	53339	30103	23237	67018	39207	27811
1.2.1.1 यात्रा	2170	2836	-667	2745	4335	-1590
1.2.1.2 परिवहन	5602	5147	455	8950	10037	-1088
1.2.1.3 बीमा	575	577	-2	845	644	201
1.2.1.4 जीएनआईई	179	260	-82	223	264	-41
1.2.1.5 विविध	44815	21282	23532	54256	23927	30329
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	25782	2312	23470	31740	3384	28356
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	12930	12807	123	15312	13722	1590
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1068	1192	-124	1354	1535	-181
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	738	381	357	801	276	524
1.2.2 अंतरण	20757	1498	19258	23528	2216	21312
1.2.2.1 आधिकारिक	62	298	-236	132	267	-135
1.2.2.2 निजी	20695	1200	19494	23396	1949	21447
1.2.3 आय	5652	15779	-10128	5914	17636	-11721
1.2.3.1 निवेश आय	4118	15063	-10945	4267	16841	-12574
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1534	717	818	1647	794	853
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**171174**	**137033**	**34141**	**221313**	**198108**	**23205**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**120012**	**81415**	**38597**	**147673**	**148394**	**-721**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	28407	11027	17380	19591	14471	5120
2.1.1.1 भारत में	26926	6932	19994	19015	10192	8823
2.1.1.1.1 इक्विटी	21843	6919	14924	12259	9936	2324
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4392		4392	5073		5073
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	691	13	678	1683	257	1426
2.1.1.2 विदेश में	1480	4094	-2614	576	4278	-3702
2.1.1.2.1 इक्विटी	1480	1949	-469	576	2215	-1639
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	753	-753	0	663	-663
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1392	-1392	0	1400	-1400
2.1.2 संविभाग निवेश	91605	70388	21217	128082	133924	-5842
2.1.2.1 भारत में	91216	69514	21703	127509	132213	-4704
2.1.2.1.1 एफआईआई	91216	69514	21703	127509	132213	-4704
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	80566	60741	19825	115423	119516	-4093
2.1.2.1.1.2 ऋण	10650	8772	1877	12086	12697	-611
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	389	875	-485	573	1711	-1138
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**19712**	**19393**	**319**	**29363**	**19137**	**10226**
2.2.1 बाह्य सहायता	2567	1383	1184	2692	1399	1293
2.2.1.1 भारत द्वारा	10	21	-11	13	16	-3
2.2.1.2 भारत को	2557	1362	1195	2680	1383	1297
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	6692	7786	-1094	6041	6092	-51
2.2.2.1 भारत द्वारा	970	484	486	352	241	111
2.2.2.2 भारत को	5722	7302	-1580	5689	5851	-162
2.2.3 भारत को अल्पावधि	10453	10224	229	20629	11645	8984
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	9538	10224	-686	12003	11645	357
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	915	0	915	8626	0	8626
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**21093**	**28707**	**-7614**	**25913**	**17707**	**8206**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	20700	28707	-8007	25913	17501	8412
2.3.1.1 आस्तियां	5384	15872	-10489	11213	6154	5058
2.3.1.2 देयताएं	15316	12834	2481	14700	11346	3353
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	14151	11183	2969	12141	10809	1332
2.3.2 अन्य	393	0	393	0	206	-206
2.4 रुपया ऋण चुकौती		0	0	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	10358	7519	2839	18365	12871	5494
3 भूल-चूक	**576**		**576**	**284**		**284**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**32483**	**-32483**	0	**465**	**-465**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		32483	-32483	0	465	-465

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	अक्टू.-दिसं. 2020			अक्टू.-दिसं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**2424516**	**2184933**	**239583**	**3199638**	**3196151**	**3487**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1157735**	**1174217**	**-16482**	**1539250**	**1711763**	**-172513**
1.1 पण्य	**569540**	**824754**	**-255214**	**816489**	**1269245**	**-452756**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**588196**	**349463**	**238733**	**722761**	**442518**	**280243**
1.2.1 सेवाएं	393415	222028	171388	502154	293770	208384
1.2.1.1 यात्रा	16002	20921	-4919	20568	32478	-11910
1.2.1.2 परिवहन	41319	37963	3355	67059	75208	-8149
1.2.1.3 बीमा	4238	4254	-17	6329	4826	1503
1.2.1.4 जीएनआईई	1317	1918	-601	1668	1976	-309
1.2.1.5 विविध	330540	156971	173569	406530	179282	227248
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	190159	17051	173108	237819	25352	212467
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	95368	94463	905	114730	102817	11913
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	7879	8793	-914	10149	11503	-1354
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	5440	2809	2632	6000	2071	3929
1.2.2 अंतरण	153095	11051	142044	176292	16607	159685
1.2.2.1 आधिकारिक	457	2199	-1742	991	2002	-1011
1.2.2.2 निजी	152638	8852	143786	175301	14605	160696
1.2.3 आय	41685	116384	-74699	44315	132141	-87826
1.2.3.1 निवेश आय	30370	111099	-80729	31975	126190	-94216
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	11315	5285	6030	12340	5951	6389
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1262531**	**1010716**	**251816**	**1658258**	**1484387**	**173871**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**885174**	**600491**	**284682**	**1106486**	**1111889**	**-5404**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	209519	81329	128190	146792	108426	38366
2.1.1.1 भारत में	198601	51132	147469	142477	76370	66107
2.1.1.1.1 इक्विटी	161110	51035	110074	91857	74446	17411
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	32393	0	32393	38013	0	38013
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5098	96	5002	12608	1925	10683
2.1.1.2 विदेश में	10918	30197	-19279	4315	32056	-27741
2.1.1.2.1 इक्विटी	10918	14377	-3459	4315	16597	-12282
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5556	-5556	0	4971	-4971
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	10264	-10264	0	10487	-10487
2.1.2 संविभाग निवेश	675655	519162	156492	959694	1003463	-43770
2.1.2.1 भारत में	672784	512712	160072	955401	990645	-35244
2.1.2.1.1 एफआईआई	672784	512712	160072	955401	990645	-35244
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	594234	448009	146225	864845	895510	-30665
2.1.2.1.1.2 ऋण	78550	64703	13847	90555	95135	-4580
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	2871	6450	-3580	4293	12818	-8525
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**145387**	**143035**	**2352**	**220011**	**143386**	**76625**
2.2.1 बाह्य सहायता	18933	10202	8731	20174	10483	9690
2.2.1.1 भारत द्वारा	71	153	-82	95	120	-26
2.2.1.2 भारत को	18862	10049	8813	20079	10363	9716
2.2.2 वाणिज्यिकिक उधार	49355	57424	-8070	45268	45646	-378
2.2.2.1 भारत द्वारा	7153	3567	3586	2638	1806	833
2.2.2.2 भारत को	42202	53857	-11655	42629	43840	-1211
2.2.3 भारत को अल्पावधि	77100	75409	1690	154570	87257	67313
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	70350	75409	-5059	89934	87257	2677
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	6749	0	6749	64636	0	64636
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**155574**	**211734**	**-56160**	**194158**	**132675**	**61483**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	152674	211734	-59060	194158	131130	63028
2.3.1.1 आस्तियां	39708	117071	-77362	84016	46113	37902
2.3.1.2 देयताएं	112966	94663	18303	110142	85016	25126
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	104375	82480	21896	90969	80991	9978
2.3.2 अन्य	2900	0	2900	0	1546	-1546
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	0	0	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	76397	55456	20941	137603	96436	41167
3 भूल-चूक	**4249**	0	**4249**	**2129**	0	**2129**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**239583**	**-239583**	0	**3487**	**-3487**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	239583	-239583	0	3487	-3487

टिप्पणी: पीः प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	अक्टू.-दिसं. 2020			अक्टू.-दिसं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**156961**	**159174**	**-2212**	**205419**	**228432**	**-23013**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**130557**	**141923**	**-11365**	**175988**	**208602**	**-32614**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**77218**	**111820**	**-34602**	**108970**	**169395**	**-60425**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिकिक वस्तुएं	76304	101812	-25508	108854	155340	-46486
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	914	0	914	116	0	116
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		10008	-10008		14055	-14055
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**53339**	**30103**	**23237**	**67018**	**39207**	**27811**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	49	5	45	129	17	112
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	38	291	-253	68	394	-326
1.अ.ख.3 परिवहन	5602	5147	455	8950	10037	-1088
1.अ.ख.4 यात्रा	2170	2836	-667	2745	4335	-1590
1.अ.ख.5 निर्माण	619	705	-86	750	592	158
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	575	577	-2	845	644	201
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1068	1192	-124	1354	1535	-181
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	359	2297	-1937	238	2363	-2125
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	26593	2810	23783	32638	3813	28825
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	12930	12807	123	15312	13722	1590
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	579	768	-190	834	1205	-371
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	179	260	-82	223	264	-41
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	2579	408	2171	2933	286	2647
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**5652**	**15779**	**-10128**	**5914**	**17636**	**-11721**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1534	717	818	1647	794	853
1.आ.2 निवेश आय	3126	14713	-11587	2886	16554	-13668
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1631	9693	-8062	1568	11635	-10067
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	67	1974	-1906	88	1941	-1853
1.आ.2.3 अन्य निवेश	130	3045	-2916	82	2976	-2893
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	1298	1	1297	1147	2	1144
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	992	349	642	1382	287	1094
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**20752**	**1472**	**19281**	**23516**	**2194**	**21322**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20695	1200	19494	23396	1949	21447
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	19969	847	19122	22443	1359	21084
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	725	353	373	953	590	363
1.इ.2 सामान्य सरकार	58	272	-214	121	245	-125
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	**98**	**265**	**-167**	**227**	**430**	**-202**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	4	109	-105	94	166	-71
2.2 पूंजी अंतरण	94	156	-62	133	264	-131
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**171080**	**169277**	**1803**	**221098**	**198166**	**22932**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**28407**	**11027**	**17380**	**19591**	**14471**	**5120**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	26926	6932	19994	19015	10192	8823
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	26235	6919	19316	17333	9936	7397
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	21843	6919	14924	12259	9936	2324
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4392		4392	5073		5073
3.1.अ.2 ऋण लिखत	691	13	678	1683	257	1426
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	691	13	678	1683	257	1426
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1480	4094	-2614	576	4278	-3702
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1480	2702	-1222	576	2879	-2303
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1480	1949	-469	576	2215	-1639
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		753	-753		663	-663
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1392	-1392	0	1400	-1400
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1392	-1392		1400	-1400
3.2 संविभाग निवेश	**91605**	**70388**	**21217**	**128082**	**133924**	**-5842**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	91216	69514	21703	127509	132213	-4704
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	80566	60741	19825	115423	119516	-4093
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	10650	8772	1877	12086	12697	-611
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	389	875	-485	573	1711	-1138
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**2748**	**3818**	**-1071**	**4851**	**6752**	**-1902**
3.4 अन्य निवेश	**48321**	**51562**	**-3241**	**68574**	**42554**	**26020**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	14544	11183	3362	12141	11015	1125
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	393	0	393	0	206	-206
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	14151	11183	2969	12141	10809	1332
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	15807	26693	-10886	22506	14183	8323
3.4.3अ भारत को ऋण	14827	26189	-11361	22141	13926	8215
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	979	504	475	365	257	108
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	55	44	11	70	89	-19
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	10453	10224	229	20629	11645	8984
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	7462	3418	4044	13229	5621	7607
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**32483**	**-32483**	0	**465**	**-465**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	32483	-32483	0	465	-465
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**171080**	**169277**	**1803**	**221098**	**198166**	**22932**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	111473	75100	36373	138825	140882	-2057
4.2 ऋण लिखत	52145	58277	-6131	69044	51197	17847
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	7462	35901	-28439	13229	6087	7142
5. निवल भूल-चूक	**576**		**576**	**284**		**284**

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	अक्टू.-दिसं. 2020			अक्टू.-दिसं. 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**1157704**	**1174021**	**-16317**	**1539162**	**1711598**	**-172436**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**962955**	**1046782**	**-83827**	**1318643**	**1563015**	**-244372**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**569540**	**824754**	**-255214**	**816489**	**1269245**	**-452756**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	562796	750936	-188140	815620	1163930	-348311
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	6744	0	6744	869	0	869
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		73819	-73819	0	105315	-105315
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**393415**	**222028**	**171388**	**502154**	**293770**	**208384**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	364	34	330	967	127	839
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	281	2143	-1863	506	2950	-2444
1.अ.ख.3 परिवहन	41319	37963	3355	67059	75208	-8149
1.अ.ख.4 यात्रा	16002	20921	-4919	20568	32478	-11910
1.अ.ख.5 निर्माण	4565	5197	-633	5621	4437	1183
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4238	4254	-17	6329	4826	1503
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	7879	8793	-914	10149	11503	-1354
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	2651	16941	-14290	1784	17709	-15926
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	196143	20727	175416	244549	28566	215983
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	95368	94463	905	114730	102817	11913
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	4269	5668	-1398	6250	9030	-2780
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1317	1918	-601	1668	1976	-309
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	19020	3006	16015	21975	2142	19833
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**41685**	**116384**	**-74699**	**44315**	**132141**	**-87826**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	11315	5285	6030	12340	5951	6389
1.आ.2 निवेश आय	23057	108522	-85465	21622	124037	-102415
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	12030	71495	-59464	11752	87181	-75429
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	497	14556	-14059	661	14541	-13881
1.आ.2.3 अन्य निवेश	957	22462	-21506	617	22297	-21679
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	9573	9	9564	8592	18	8574
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	7313	2577	4736	10353	2153	8199
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**153064**	**10855**	**142209**	**176205**	**16442**	**159763**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	152638	8852	143786	175301	14605	160696
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	147287	6249	141038	168163	10186	157977
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	5351	2603	2748	7138	4419	2719
1.इ.2 सामान्य सरकार	426	2003	-1577	903	1837	-933
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**724**	**1955**	**-1232**	**1704**	**3220**	**-1516**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	32	803	-772	707	1241	-535
2.2 पूँजी अंतरण	692	1152	-460	998	1979	-981
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1261839**	**1248540**	**13299**	**1656642**	**1484820**	**171822**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**209519**	**81329**	**128190**	**146792**	**108426**	**38366**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	198601	51132	147469	142477	76370	66107
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	193502	51035	142467	129870	74446	55424
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	161110	51035	110074	91857	74446	17411
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	32393	0	32393	38013	0	38013
3.1.अ.2 ऋण लिखत	5098	96	5002	12608	1925	10683
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	5098	96	5002	12608	1925	10683
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	10918	30197	-19279	4315	32056	-27741
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	10918	19933	-9015	4315	21568	-17253
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	10918	14377	-3459	4315	16597	-12282
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5556	-5556	0	4971	-4971
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	10264	-10264	0	10487	-10487
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	10264	-10264	0	10487	-10487
3.2 संविभाग निवेश	**675655**	**519162**	**156492**	**959694**	**1003463**	**-43770**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	672784	512712	160072	955401	990645	-35244
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	594234	448009	146225	864845	895510	-30665
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	78550	64703	13847	90555	95135	-4580
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	2871	6450	-3580	4293	12818	-8525
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**20265**	**28161**	**-7896**	**36345**	**50593**	**-14248**
3.4 अन्य निवेश	**356400**	**380304**	**-23904**	**513811**	**318850**	**194961**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	107275	82480	24796	90969	82537	8432
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	2900	0	2900	0	1546	-1546
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	104375	82480	21896	90969	80991	9978
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	116586	196880	-80294	168631	106268	62362
3.4.3अ भारत को ऋण	109363	193160	-83798	165898	104342	61555
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	7224	3720	3504	2733	1926	807
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	404	326	78	522	668	-146
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	77100	75409	1690	154570	87257	67313
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	55035	25209	29825	99120	42120	56999
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**239583**	**-239583**	**0**	**3487**	**-3487**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	239583	-239583	0	3487	-3487
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1261839**	**1248540**	**13299**	**1656642**	**1484820**	**171822**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	822194	553914	268280	1040190	1055603	-15414
4.2 ऋण लिखत	384610	429833	-45223	517332	383609	133724
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	55035	264793	-209758	99120	45607	53512
5. निवल भूल-चूक	**4249**		**4249**	**2129**	**0**	**2129**

टिप्पणी: पीः प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2020-21		2020		2021			
			दिसं.		सितं.		दिसं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	193929	482234	190857	480255	202675	506835	206378	514292
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	122726	456947	122489	454603	126945	480753	129248	487905
1.2 अन्य पूंजी	71203	25286	68368	25651	75730	26082	77130	26386
2 संविभाग निवेश	7936	278524	6277	270276	8578	282598	9716	277231
2.1 इक्विटी	2340	177278	2482	170630	4590	177034	6444	172794
2.2 ऋण	5596	101245	3795	99647	3988	105564	3272	104437
3 अन्य निवेश	80606	453950	69382	446978	84517	478419	76504	492569
3.1 व्यापार ऋण	5644	100343	3196	102598	11819	104450	12891	113463
3.2 ऋण	13335	197464	10610	192181	10831	201073	8871	203970
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	42436	143760	37343	142491	42302	142904	34796	143502
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	19191	12384	18234	9708	19565	29991	19946	31633
4 रिज़र्व्स	576984		585771		635363		633614	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	859454	1214707	852286	1197509	931134	1267851	926212	1284091
6 निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		**–355253**		**–345223**		**–336718**		**–357880**

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि का हिस्सा और पुनर्निवेशित आय शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2021-22	2021	2022		वि.व 2021-22	2021	2022	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	33.01	2.92	2.92	3.25	206873111	17383479	17994586	20588727
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	12.22	0.91	1.10	1.04	142072938	11182301	12914111	13682354
1.1.1 आउटराईट	6.21	0.42	0.58	0.46	8793301	678873	721038	660443
1.1.2 रेपो	3.09	0.26	0.25	0.30	51015712	4362390	4221392	5341282
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.92	0.23	0.27	0.27	82263925	6141037	7971681	7680629
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	19.90	1.95	1.73	2.11	59775826	5828078	4540145	6232193
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.88	0.06	0.10	0.11	5024347	373100	540330	674180
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	–	–	–	–	–	–	–	–
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2078.39	202.35	180.29	230.04	128657517	12982215	10324618	14458955
1.1 ग्राहक लेनदेन	2063.73	200.70	179.15	228.68	113319291	11427958	9277356	13069669
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	14.66	1.65	1.13	1.36	15338225	1554257	1047262	1389286
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	577631.89	37208.51	55283.72	66272.08	42722829	4053907	3806375	5062364
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	9.76	1.16	0.51	0.56	575	72	28	35
2.2 एपीबीएस $	12298.50	1128.83	629.87	1154.92	133052	11086	13043	15462
	4920.01	–	–	4920.01	462279	–	–	462279
2.3 आईएमपीएस	41705.24	3631.44	4209.31	–	3708759	327236	384404	–
2.4 एनएसीएच जमा $	18729.79	1648.84	1536.56	1825.88	1276801	164298	104998	131428
2.5 एनईएफटी	40407.29	3481.39	3632.58	4314.20	28725463	3046329	2477059	3492578
2.6 यूपीआई @	459561.30	27316.85	45274.89	54056.51	8415900	504886	826843	960582
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	11.99	0.94	0.68	0.91	177	15	10	12
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	12222.27	1038.84	1089.30	1136.67	1038335	86505	90746	98645
3.1 भीम आधार पे @	227.73	12.92	15.23	19.47	6114	346	506	640
	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 एनएसीएच नामे $	10787.53	920.42	948.20	979.27	1030532	86005	90056	97801
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1207.01	105.50	125.87	137.93	1690	154	184	204
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	61785.64	5650.32	4840.43	5515.40	1701900	139705	143106	171214
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	22398.83	1887.27	1884.24	2237.51	971632	72319	86041	107101
4.1.1 पीओएस आधारित $	11124.59	1012.86	963.40	1134.33	380640	33286	32500	38773
4.1.2 अन्य $	11274.23	874.41	920.84	1103.18	590992	39033	53541	68328
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	39476.78	3763.05	2956.19	3277.89	731368	67386	57065	64113
4.2.1 पीओएस आधारित $	23059.81	2229.12	1845.45	2081.16	452711	42816	36376	40831
4.2.2 अन्य $	16416.97	1533.93	1110.75	1196.73	278658	24570	20689	23282
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	65812.39	5201.05	5626.89	6567.09	293658	21372	24649	27865
5.1 वालेट	52683.01	4182.92	4386.09	5016.86	226645	14856	17259	20054
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	13129.38	1018.13	1240.79	1550.23	67014	6516	7390	7811
5.2.1 पीओएस आधारित $	1066.47	59.48	126.61	164.77	18123	1453	3360	2860
5.2.2 अन्य $	12062.91	958.65	1114.18	1385.46	48891	5063	4030	4951
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6999.12	806.59	581.98	702.93	6650332	722031	615321	694335
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6999.12	806.59	581.98	702.93	6650332	722031	615321	694335
6.2 अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	724451.29	49905.31	67422.32	80194.17	52407055	5023520	4680197	6054424
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	726529.68	50107.66	67602.60	80424.21	181064571	18005734	15004815	20513379
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	719530.55	49301.07	67020.62	79721.28	174414239	17283703	14389494	19819044

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2021-22	2021	2022		वि. व. 2021-22	2021	2022	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	507531	33082.40	48507.66	57378.43	14970883	1248779	1395093	1650284
1.1 इंट्रा-बैंक $	40806	4852.88	3626.98	4218.03	2723849	270764	246931	296045
1.2 इंटर-बैंक $	466726	28229.52	44880.68	53160.39	12247034	978015	1148163	1354239
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	35667	3390.80	2697.65	3574.14	49787576	4976087	3824220	8520751
2.1 इंट्रा-बैंक @	7032	707.26	552.69	654.75	23192702	2355028	1635618	5037166
2.2 इंटर-बैंक @	28635	2683.55	2144.96	2919.39	26594875	2621059	2188602	3483584
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	65084	6040.02	5300.30	5767.24	3105624	285268	256463	281048
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	62	5.92	5.29	6.80	3130	307	264	344
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	64695	6007.92	5266.81	5728.28	3091415	283955	255218	279567
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	327	26.18	28.20	32.16	11079	1007	981	1138
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	92	22.38	2.46	2.79	793	119	39	57
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	79	19.49	2.15	2.21	557	114	20	21
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	12	2.90	0.32	0.57	236	5	19	36
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11126	763.86	928.46	1032.68	299776	22276	24975	28479
5.1 एईपीएस @	11126	763.86	928.46	1032.68	299776	22276	24975	28479

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	वि.व 2021-22	2021	2022	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	118458.27	9602.51	10067.74	9912.93
1.1 क्रेडिट कार्ड	7983.22	620.49	717.08	736.27
1.2 डेबिट कार्ड	110475.05	8982.02	9350.66	9176.66
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	296736.79	21952.60	27320.10	27408.39
2.1 वालेट @	268372.27	20052.10	24605.03	24645.40
2.2 कार्ड @	28364.52	1900.51	2715.07	2762.98
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	29.21	2.39	2.47	2.48
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	25.82	2.14	2.16	2.17
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	3.39	0.25	0.31	0.32
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	65.95	4.04	7.16	7.81
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	615.09	47.20	58.34	60.70
6 भारत क्यूआर @	575.98	35.70	48.27	49.72
7 यूपीआई क्यूआर *	15324.59	925.22	1600.19	1727.34

#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा दिसंबर 2021 से शामिल हैं।
@: नवंबर 2019 से नया समावेश $: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड़ शामिल है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2020-21	2020	2021		
			मार्च	जन.	फर.	मार्च
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**181237**	**32210**	**14261**	**14405**	**34767**
	बकाया	**1259585**	**1078535**	**1210379**	**1224772**	**1259585**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**132687**	**18444**	**9820**	**10143**	**20375**
	बकाया	**867494**	**734807**	**836976**	**847119**	**867494**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	39748	9882	2049	2252	11150
	बकाया	205888	166140	192486	194738	205888
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	276	204	-26	-23	382
	बकाया	3419	3143	3060	3037	3419
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	166	32	0	57	135
	बकाया	175	9	-17	40	175
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	12211	2109	1162	1135	1102
	बकाया	221379	209168	219142	220277	221379
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	21009	2314	1886	1950	2301
	बकाया	97051	76042	92800	94750	97051
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41470	4972	3952	3798	3960
	बकाया	207557	166087	199799	203597	207557
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	108205	92618	105928	107099	108205
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7473	7097	7375	7418	7473
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7227	7536	7285	7267	7227
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	84652	58836	79211	81813	84652
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	17807	-1069	797	974	1346
	बकाया	132029	114222	129709	130683	132029
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	-1
	बकाया	-25	-25	-24	-24	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**34860**	**4609**	**3909**	**3647**	**4334**
	बकाया	**286863**	**252190**	**278848**	**282483**	**286863**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	17361	2860	1903	1843	2332
	बकाया	135348	117987	131173	133016	135348
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-3	450	-1	0	2
	बकाया	159	162	157	157	159
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-7911	-2814	-603	-470	-582
	बकाया	-6776	1135	-5724	-6194	-6776
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	25340	4095	2610	2274	2520
	बकाया	147942	122602	143148	145422	147942
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	41	25	0	0	33
	बकाया	-114	-155	-147	-147	-114
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	32	-7	0	0	29
	बकाया	-74	-106	-103	-103	-74
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10378	10565	10344	10332	10378
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**13690**	**9157**	**532**	**615**	**10058**
	बकाया	**105228**	**91538**	**94555**	**95170**	**105228**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं। अर्थात सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान
स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020	2021			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं	दिसं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**7357111**	**7635902**	**7882533**	**8235318**	**8439811**
1. वाणिज्यिक बैंक	37.81	37.77	35.99	37.82	35.40
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.25	0.27	0.34	0.35	0.27
3. बीमाकृत कंपनियां	25.64	25.30	25.83	24.18	25.74
4. म्यूच्युअल फंड	2.62	2.94	2.82	2.91	3.08
5. सहकारी बैंक	1.83	1.82	1.82	1.50	1.82
6. वित्तीय संस्थाएं	1.00	1.00	1.43	1.17	1.69
7. कॉरपोरेट	1.05	1.06	1.39	0.72	1.37
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	2.10	1.87	1.79	1.81	1.66
9. भविष्य निधियां	4.61	4.44	4.04	3.77	4.33
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	15.71	16.20	17.11	16.98	16.92
11. अन्य	7.37	7.33	7.43	8.79	7.73
11.1 राज्य सरकार	1.76	1.69	1.67	1.67	1.69

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020	2021			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**3721573**	**3879982**	**4028849**	**4153508**	**4257578**
1. वाणिज्यिक बैंक	34.19	33.69	33.75	35.94	34.41
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.36	0.48	0.39	0.44	0.40
3. बीमाकृत कंपनियां	30.25	30.04	29.67	27.50	28.85
4. म्यूच्युअल फंड	1.92	1.82	1.74	1.97	1.91
5. सहकारी बैंक	4.11	4.05	4.12	3.60	4.07
6. वित्तीय संस्थाएं	1.88	1.86	1.79	1.72	1.73
7. कॉरपोरेट	0.45	0.49	1.45	1.32	1.70
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
9. भविष्य निधियां	21.20	22.00	21.09	18.27	20.66
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.81	0.77	0.88	0.85	0.83
11. अन्य	4.82	4.77	5.10	8.38	5.40
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2020	2021			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**839729**	**690646**	**901327**	**763582**	**692869**
1. वाणिज्यिक बैंक	54.75	55.54	52.25	50.22	47.01
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.65	2.82	1.82	1.33	1.53
3. बीमाकृत कंपनियां	4.50	5.61	4.75	4.12	6.29
4. म्यूच्युअल फंड	18.98	17.80	19.93	17.72	13.72
5. सहकारी बैंक	1.61	2.43	1.60	1.32	1.49
6. वित्तीय संस्थाएं	1.11	1.24	2.56	2.12	2.36
7. कॉरपोरेट	2.01	3.16	3.00	2.40	3.13
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.15	0.72
9. भविष्य निधियां	0.09	0.22	0.10	0.37	0.85
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.68	0.49	2.58	2.63	0.00
11. अन्य	14.63	10.70	11.42	17.62	22.89
11.1 राज्य सरकार	13.27	5.98	7.97	12.64	18.92

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**4265969**	**4515946**	**5040747**	**5410887**	**6523916**	**7160694**
1.1 गतिविधियां	2537905	2635110	2882758	3074492	3906147	4254004
1.1.1 राजस्व	1878417	2029044	2224367	2446605	3259401	3242247
1.1.2 पूंजी	501213	519356	596774	588233	636062	922982
1.1.3 ऋण	158275	86710	61617	39654	10684	88775
1.2 गैर गतिविधियां	1672646	1812455	2078276	2253027	2526514	2810847
1.2.1 राजस्व	1555239	1741432	1965907	2109629	2334608	2602289
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	724448	814757	894520	955801	1082302	1244457
1.2.2 पूंजी	115775	69370	111029	141457	189487	177328
1.2.3 ऋण	1632	1654	1340	1941	2419	31230
1.3 अन्य	55417	68381	79713	83368	91255	95843
2. कुल प्राप्तियां	**4288432**	**4528422**	**5023352**	**5734166**	**6489736**	**7039032**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3132201	3376416	3797731	3851563	3834126	4682025
2.1.1 कर प्राप्तियां	2622145	2978134	3278947	3231582	3175594	3829889
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1652377	1853859	2030050	2012578	2100982	2514708
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	965622	1121189	1246083	1216203	1071552	1311449
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	4146	3086	2814	2800	3060	3732
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	510056	398282	518783	619981	658532	852135
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	33220	34224	36273	31137	39830	33198
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	69063	142433	140287	110094	54861	201138
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	20942	42213	44667	59515	21151	19581
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	48122	100219	95621	50578	33710	181557
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1064704**	**997097**	**1102729**	**1449230**	**2634928**	**2277532**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	617123	144792	387091	571872	890012	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	195816	-144847	325987	190241	107494	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	429585	844375	710119	868676	1690394	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	689821	794856	795845	971378	1778062	1620936
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	35038	71222	88961	209232	455724	367863
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	45688	42351	51004	38280	47300	45504
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-6436	18423	-18298	10411	-3450	5051
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	17792	25138	66289	-14227	29050	28868
3ख.1.6 नकद शेष	-22463	-12476	17395	-323279	34179	121663
3ख.1.7 अन्य	287268	49653	96014	548753	239540	86132
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*27.7*	*26.4*	*26.7*	*26.6*	*33.0*	*32.1*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*27.9*	*26.5*	*26.6*	*28.2*	*32.9*	*31.6*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*20.3*	*19.8*	*20.1*	*18.9*	*19.4*	*21.0*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*17.0*	*17.4*	*17.4*	*15.9*	*16.1*	*17.2*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*6.9*	*5.8*	*5.8*	*7.1*	*13.3*	*10.2*

…: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च 2022 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	391	23	1261	23	1040	2
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	72	4	926	4	23	1
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	980	14	545	6
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	79	4	496	4	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	9	16	276	30	146	12
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	33	5	39	2	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	-	-	-	-	-	-
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	487	22	913	17	539	1
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	मार्च 2022 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9360	922	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	2027	3	--	-
3	असम	2886	71	--	-
4	बिहार	6299	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	5578	--	1	4300
6	गोवा	712	350	--	-
7	गुजरात	7033	539	--	-
8	हरियाणा	1363	1364	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	506	--	--	-
12	कर्नाटक	10393	--	--	20000
13	केरल	2425	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	1035	--	-
15	महाराष्ट्र	52606	929	--	12000
16	मणिपुर	174	113	--	-
17	मेघालय	882	62	9	-
18	मिज़ोरम	440	53	--	-
19	नगालैंड	1863	38	--	-
20	उड़ीसा	14682	1646	95	28573
21	पुदुचेरी	381	--	--	861
22	पंजाब	3027	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	7100
24	तमिलनाडु	7492	--	40	13166
25	तेलंगाना	6389	1397	--	-
26	त्रिपुरा	684	15	--	1400
27	उत्तराखंड	3018	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3889	154	--	-
29	पश्चिम बंगाल	10145	708	214	-
	कुल	**154255**	**9399**	**675**	**87400**

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22						2021 -22 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						जनवरी		फरवरी		मार्च			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	42415	33444	50896	41915	2500	1920	4000	3420	3943	3363	46443	36692
2	अरुणाचल प्रदेश	1366	1287	767	767	163	163	-	-	-	-33	563	530
3	असम	12906	10996	15030	14230	653	153	2200	2200	600	600	12753	10753
4	बिहार	25601	22601	27285	24685	2000	719	2000	2000	1489	334	28489	24334
5	छत्तीसगढ़	11680	10980	13000	10500	-	-	-	-	-	-1587	4000	913
6	गोवा	2600	2000	3354	3054	100	100	-	-	200	150	2000	1450
7	गुजरात	38900	28600	44780	33280	4500	4500	4000	2500	5000	500	31054	13554
8	हरियाणा	24677	20677	30000	25550	1500	750	2500	2055	10000	5678	30500	20683
9	हिमाचल प्रदेश	6580	4460	6000	3755	-	-250	-	-660	-	-710	4000	1875
10	जम्मू और कश्मीर	7869	6760	9328	6020	-	-	600	600	1562	-52	8562	5373
11	झारखंड	7500	5656	9400	8900	-	-	-	-	3500	2691	5000	3191
12	कर्नाटक	48500	42500	69000	61900	20000	17500	17000	15000	-	-1500	59000	49000
13	केरल	18073	12617	28566	23066	-	-1380	-	-1400	7000	5900	27000	18120
14	मध्य प्रदेश	22371	16550	45573	38773	4000	1500	-	-	4000	1400	22000	13900
15	महाराष्ट्र	48498	32998	69000	50022	5500	-500	4500	-2960	4000	1500	68750	40790
16	मणिपुर	1757	1254	1302	1044	59	59	60	60	180	180	1476	1326
17	मेघालय	1344	1070	1777	1587	200	100	-	-	80	80	1608	1298
18	मिज़ोरम	900	745	944	677	150	150	73	73	90	40	747	447
19	नगालैंड	1000	423	1721	1366	-	-	-	-	440	185	1727	1222
20	उड़ीसा	7500	6500	3000	500	-	-	-	-1000	-	-1500	-	-6473
21	पुदुचेरी	970	470	1390	790	390	390	185	-215	300	167	1374	841
22	पंजाब	27355	18470	32995	23467	4532	3932	1000	317	6500	4497	25814	12428
23	राजस्थान	39092	24686	57359	44273	4500	3883	3500	3326	7380	2730	51149	38243
24	सिक्किम	809	481	1292	1292	201	201	-	-	382	382	1511	1471
25	तमिलनाडु	62425	49826	87977	76796	2900	-300	7500	4500	24600	23300	87000	72500
26	तेलंगाना	37109	30697	43784	37365	6187	5767	3000	2580	3029	2609	45716	38667
27	त्रिपुरा	2928	2578	1916	1631	-	-50	-	-	-	-100	300	-
28	उत्तराखंड	69703	52744	75500	59185	12500	11500	-	-1000	5000	2142	62500	42355
29	उत्तरप्रदेश	5100	4500	6200	5208	500	400	-	-	1000	700	3200	1800
30	पश्चिम बंगाल	56992	40882	59680	50180	6500	4700	-	-1000	13390	12722	67390	45199
	कुल	634521	487454	798816	651777	79535	55907	52118	30396	103665	66368	701626	492483

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि करोड़ में)

मद	2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**252658.0**	**513118.4**	**400437.3**	**446254.3**	**1612468.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.1*	*10.6*	*7.8*	*8.7*	*8.0*
I. वित्तीय आस्तियां	**413192.2**	**604322.7**	**538186.1**	**843385.9**	**2399086.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*8.4*	*12.4*	*10.5*	*16.4*	*12.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	13020.4	299089.8	138131.8	473183.4	923425.5
(ए) बैंक जमाराशि	-9769.4	280588.7	130328.0	465529.7	866677.0
i. वाणिज्यिक बैंक	-13293.8	269475.4	66666.7	446006.7	768855.0
ii. सहकारी बैंक	3524.4	11113.2	63661.3	19523.0	97822.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22789.9	18501.2	7803.7	7653.7	56748.5
2. जीवन बीमा निधियाँ	117394.9	107731.0	109895.6	37236.1	372257.5
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	110601.0	113593.0	113676.0	117235.0	455104.9
4. मुद्रा	61244.1	-26104.8	86832.6	160690.2	282662.1
5. निवेश	43936.8	43018.8	22655.1	-11953.8	97656.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	23303.5	38382.2	19191.1	-19191.1	61685.7
(बी) इक्विटि	18648.2	2172.4	936.2	4981.0	26737.8
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	65930.8	65930.8	65930.8	65930.8	263723.4
II. वित्तीय देयताएँ	**160534.2**	**91204.3**	**137748.8**	**397131.6**	**786618.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*3.2*	*1.9*	*2.7*	*7.7*	*3.9*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	160500.7	91170.8	137715.2	397098.1	786484.7
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	141332.5	58250.2	121754.0	200413.2	521749.9
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	135754.1	57135.0	87377.4	202214.2	482480.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	19168.2	32920.5	15961.2	196684.8	264734.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-519.7	22976.7	29930.7	198264.3	250652.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	17033.0	8093.1	-15710.4	-3093.1	6322.6
iii. बीमा कंपनियाँ	2655.0	1850.8	1740.9	1513.6	7760.2
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(जारी..)*

(राशि करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**623053.8**	**592327.3**	**506558.3**	**581769.1**	**2303708.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*16.1*	*12.5*	*9.3*	*10.1*	*11.6*
I. वित्तीय आस्तियां	**828447.4**	**630907.1**	**676131.6**	**973510.9**	**3108997.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*21.4*	*13.4*	*12.4*	*16.9*	*15.7*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	297376.2	278589.7	158113.5	533651.5	1267730.9
(ए) बैंक जमाराशि	281155.1	264523.3	147037.2	535157.5	1227873.0
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	471730.9	1156333.7
ii. सहकारी बैंक	2144.6	2489.6	3478.6	63426.6	71539.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	16221.1	14066.4	11076.3	-1506.0	39857.9
2. जीवन बीमा निधियाँ	122369.1	141443.4	155516.3	100812.3	520141.0
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	121582.5	124106.5	124949.5	130185.5	500824.0
4. मुद्रा	202432.7	21286.9	91456.0	66800.5	381976.1
5. निवेश	6249.8	-12956.4	67659.3	63624.0	124576.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटि	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	77381.6	77381.6	77381.6	77381.6	309526.3
II. वित्तीय देयताएँ	**205393.5**	**38579.8**	**169573.3**	**391741.8**	**805288.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.3*	*0.8*	*3.1*	*6.8*	*4.1*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	205436.7	38623.0	169616.5	391785.8	805462.1
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	211005.3	13211.7	139387.5	304100.8	667705.3
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	242476.0	607463.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-5568.6	25411.3	30229.0	87685.1	137756.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	61326.1	83424.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1022.9	2556.6
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.0	134.4
3. सामान्य सरकार	-77.0	-77.0	-77.0	-77.0	-308.0

सं. 50(ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में)

मद	2021-22	
	ति1	ति2
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**760273.0**	**388307.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*14.8*	*6.9*
I. वित्तीय आस्तियां	**631184.5**	**567403.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*12.3*	*10.1*
जिसमें:		
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	146933.8	207184.4
(ए) बैंक जमाराशि	124803.6	201833.5
i. वाणिज्यिक बैंक	123282.3	200159.7
ii. सहकारी बैंक	1521.3	1673.8
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22130.2	5350.9
2. जीवन बीमा निधियाँ	114617.8	127356.0
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	129821.9	132967.9
4. मुद्रा	128660.2	-68631.2
5. निवेश	24929.6	82305.4
जिसमें:		
(ए) म्यूचुअल फंड	14573.0	63151.3
(बी) इक्विटि	4502.5	13218.5
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	85163.8	85163.8
II. वित्तीय देयताएँ	**-129088.5**	**179095.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*-2.5*	*3.2*
ऋण (उधार)		
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	-129109.8	179074.5
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	-105750.5	124240.8
जिसमें :		
वाणिज्यिक बैंक	-98583.4	126251.1
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-23359.3	54833.7
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-31118.4	28880.1
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7132.0	24403.8
iii. बीमा कंपनियाँ	627.1	1549.8
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8
3. सामान्य सरकार	-12.5	-12.5

टिप्पणियां: 1. परिवारों की निवल वित्तीय बचत, निवल वित्तीय आस्तियों के प्रवाह को संदर्भित करती है, जो परिवारों द्वारा धारित वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन में से उनकी वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन को दर्शाती हैं।

2. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 28 फरवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।

3. हो सकता है कि कॉलम में दिए गए अंकों को पूर्णांकन के कारण कुल योग में न जोड़ा जाए

सं. 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2019	सितं-2019	दिसं-2019	मार्च-2020
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**16130869.8**	**16439609.3**	**16829228.1**	**17002698.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*83.7*	*84.4*	*85.3*	*84.7*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	8831785.7	9111489.5	9239027.3	9688573.4
i. वाणिज्यिक बैंक	8131543.2	8401018.6	8467685.3	8913692.0
ii. सहकारी बैंक	700242.5	710470.8	771341.9	774881.4
(बी) जीवन बीमा निधि	3883609.7	3930727.6	4049902.5	3884771.5
(सी) मुद्रा	2010842.9	1984738.1	2071570.7	2232261.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1404631.5	1412654.1	1468727.6	1197092.9
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**6490282.2**	**6581453.0**	**6719168.2**	**7116266.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*33.7*	*33.8*	*34.0*	*35.4*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5268304.7	5326554.9	5448308.9	5648722.1
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	4668496.4	4725631.3	4813008.7	5015222.9
ii. सहकारी बैंक	513013.7	513764.2	542994.4	529720.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1221977.5	1254898.1	1270859.3	1467544.1
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	451922.3	474899.0	504829.7	703094.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673312.1	681405.2	665694.8	662601.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(जारी.)*

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2019	सितं-2019	दिसं-2019	मार्च-2021
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**17850174.9**	**18408441.6**	**19129606.6**	**19979862.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*93.9*	*97.6*	*99.7*	*100.9*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	9969728.5	10234251.8	10381289.0	10916446.4
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10070025.7
ii. सहकारी बैंक	777026.0	779515.6	782994.2	846420.7
(बी) जीवन बीमा निधि	4102000.7	4274424.9	4551882.0	4718718.2
(सी) मुद्रा	2434693.7	2455980.6	2547436.6	2614237.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1343752.0	1443784.4	1648999.0	1730461.0
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7321703.0**	**7360326.0**	**7529942.6**	**7921728.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*38.5*	*39.0*	*39.3*	*40.0*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5859727.5	5872939.2	6012326.7	6316427.4
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5622686.4
ii. सहकारी बैंक	558551.1	558545.6	557545.8	608703.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1461975.5	1487386.9	1517615.9	1605301.0
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	786518.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9

. 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**20533386.0**	**21086975.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*97.4*	*98.1*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	11041250.0	11243083.5
i. वाणिज्यिक बैंक	10193308.0	10393467.7
ii. सहकारी बैंक	847942.1	849615.9
(बी) जीवन बीमा निधि	4894238.5	5105262.1
(सी) मुद्रा	2742897.3	2674266.1
(डी) म्यूचुअल फंड	1855000.1	2064363.5
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7793017.9**	**7972092.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*37.0*	*37.1*
ऋण (उधार)		
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	6210676.9	6334917.7
जिसमें:		
i. वाणिज्यिक बैंक	5524103.0	5650354.1
ii. सहकारी बैंक	596687.9	603180.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1582341.0	1637174.6
जिसमें:		
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	755399.6	784279.7
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	721510.0	745913.7

टिप्पणी: 1. डेटा को केवल चुनिंदा वित्तीय लिखतों के लिए संकलित किया गया है(बैंकिंग क्षेत्र, एनबीएफ़सी और एचएफ़सी से ऋण) जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।
2. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 28 फरवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।
3. हो सकता है कि कॉलम में दिए गए अंकों को पूर्णांकन के कारण कुल योग में न जोड़ा जाए।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थांओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकडें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओं/शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का सकेंतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -
- बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।
- जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए है, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिकिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया हैं।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिकिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत
कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बज़ट 2020-21 से लिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2022	₹350 एक प्रति (कांउटर पर) ₹400 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,800 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,600 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,840 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,880 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2021-22 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2021-22	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (कांउटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8 अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 2, 2020	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 42, सं. 1, 2021	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (कांउटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in)।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

@ इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेशः

1. बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक सस्थांओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अकं उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का सपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेलः spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001।

   एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम.......... अभिदाता सं...........

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' **2 महीने के अंदर भेजी जाए।**
7. **कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।**